राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 3 सोलहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र का सातवां दिवस संख्या: 4

गुरुवार,
6 फरवरी 2025

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: राम राम। प्रश्न काल। श्री चन्द्रभान सिंह चौहान।

चित्तौड़गढ़ में दर्ज साइबर प्रकरणों पर कार्यवाही

46. श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में विगत तीन वर्षो में साइबर अपराध के कितने प्रकरण दर्ज हुए तथा उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार चित्तौड़गढ़ जिले में साइबर थाने खोलने तथा साइबर टीम बनाकर अभियान चलाने का विचार रखती है? यदि हां तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): (1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में विगत 3 वर्ष (1 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2024 तक) में साइबर अपराध के कुल 36 मुकदमे दर्ज हुए, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.27(क)(1)गृह-2/2022 दिनांक 27.04.2022 के द्वारा जिला चित्तौड़गढ़ में साइबर पुलिस थाना खोला गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। साइबर थाने में साइबर प्रशिक्षित पुलिसकर्मी एवं प्राइवेट साइबर एक्सपर्ट्स के साथ समय-समय पर अभियान चलाया जाकर फ्रॉड की राशि रिकवर कर वापस दिलायी जा रही है एवं आमजन को जागरूक किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछें। एक मिनट मंत्री जी, मैं एक व्यवस्था दे दूं। मैंने कल यहां सदन में जब इस पर चर्चा आयी, सुझाव आये, मैंने बाकी विधान सभा, लोक सभा, राज्य सभा, इनकी जानकारी ली। राज्य सभा और लोक सभा में जिसका नाम मैं पुकारता हूं, वह अपने स्थान पर खड़े होकर प्रश्न की संख्या बताता है। मंत्री जी खड़े होकर सदन के पटल पर उत्तर रख दिया, ऐसा कहते हैं। तत्काल फिर पूरक प्रश्न और उनके उत्तर मिलते हैं। यह मैंने

राज्य सभा के जितने भी मैम्बर्स हैं, उनसे भी पूछा, राज्य सभा सचिवालय से भी पूछा और लोक सभा सचिवालय से भी पूछा। जो अपनी व्यवस्था दे रखी है कि प्रश्न का उत्तर अपन नहीं पढ़ेंगे और प्रश्न टेबल पर रख दिया है, उसके बाद पूरक प्रश्न पूछेंगे, यह व्यवस्था लागू रहेगी। अब इस पर कोई चर्चा का विषय है नहीं। बाकी चर्चा करनी है तो चैम्बर में।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या वहां पर भी कम्प्यूटर्स की वजह से यह है और यह जो हमारा वैज्ञानिक चाणक्य है, इससे तो अभी दोस्ती हुई ही नहीं हमारी।

श्री अध्यक्ष: इस पर सबका उत्तर आ जाता है, जिसकी रुचि होगी, इसमें पढ़ ले।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ओके।

श्री अध्यक्ष: चन्द्रभान सिंह। मंत्री जी, आप कह दें उत्तर रख दिया है। ...(व्यवधान)... नहीं बाद में। प्रश्न काल के बाद। नहीं, बाद में चैम्बर में। सत्ता पक्ष, बीच में व्यवधान नहीं। ...(व्यवधान)... आप भी न बोलें। जो इन पर लागू है, वह आप पर भी है। चन्द्रभान जी, आप पूरक प्रश्न पूछें।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि साइबर फ्रॉड की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रार्थी जब चित्तौड़गढ़ के साइबर थाने में जाता है तो उसे यह बताया जाता है कि 2 लाख या उससे ज्यादा का साइबर फ्रॉड आपके साथ हुआ हो तो आप एफआईआर साइबर थाने में दर्ज कराएं। 2 लाख से कम का फ्रॉड हो तो पीड़ित को सम्बन्धित थाने में ही जाकर एफआईआर करानी पड़ती है। यही सबसे बड़ा कारण है कि विगत 3 वर्षों में 36 मुकदमे ही साइबर थाने में दर्ज हुए हैं। मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि यह भेद-भाव क्यों है? साइबर थाने में साइबर एक्सपर्ट्स ढंग से सब टेक्निकल चीजें पता कर सकते हैं। सम्बन्धित थानों में पहले से ही पुलिस पर अतिरिक्त भार और जिम्मेदारी होती है। साइबर क्राइम्स को ट्रैक करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। अत: 2 लाख रुपये से कम का वहां साइबर थाने में दर्ज नहीं करते हैं। मंत्री महोदय से मेरी विनती है कि सभी साइबर थानों में 10 हजार, 20 हजार के भी अगर प्रकरण होते हैं तो उन्हें सम्बन्धित थानों की जगह साइबर थानों में दर्ज कराया जा सके।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ विधान सभा क्षेत्र में 01 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2024 तक 36 केसेज हुए। उनमें से 10 में चालान हुए, 17 एफआर मिलीं अनट्रेस्ड प्रॉपर्टी या व्यक्ति नहीं मिला, 9 अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं। यहां पर 2.70 करोड़ के जो केसेज थे, उनमें से 1.82 करोड़ रिकवरी हो गयी है, जो मैं सोचता हूं कि बहुत अच्छी रिकवरी हुई है आपके यहां।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): मंत्री महोदय, मैं तो इतना ही अर्ज कर रहा हूं आपसे कि 2 लाख से कम का साइबर क्राइम होता है तो उसे साइबर थाने में दर्ज नहीं किया जाता है। आप विधिवत अपनी अनुमति से ऐसा कुछ करवाएं कि अगर 10 हजार की भी

साइबर ठगी होती है तो एफआईआर साइबर थाने में ही दर्ज हो। वे उसे सम्बन्धित थाने में भेजते हैं दर्ज कराने के लिए। साइबर थाने में वे उस तरह की रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से पूरे राजस्थान में इस प्रकार की चीज होगी। मेरे बात करने पर भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस प्रकार की दिक्कत आ रही है। छोटे से छोटा अगर साइबर क्राइम होता है तो वह केस साइबर थाने में ही दर्ज हो जाये। इस बारे में आप बताएं।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ऐसा नहीं होना चाहिये। अभी बहुत बड़े अमाउंट के ऊपर वे नहीं दर्ज करते हैं। इसकी मैं पूरी जानकारी ले लूंगा। आपके पुलिस स्टेशन के बारे में भी पूरी जांच करके बता दूंगा आपको। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप बैठिये। मंत्री के उत्तर के समय कोई नहीं बोलेगा। ...(व्यवधान)... आप विराजें। आपके प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। आप विराजिये। मैंने कल व्यवस्था दी थी। ...(व्यवधान)... आप भी बैठिये। ...(व्यवधान)... हरिमोहन जी। मैंने व्यवस्था दी थी। वे पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। उनका उत्तर सुनें। उसके दो पूरक प्रश्न हो जाएं। विपक्ष का नेता यदि चाहेगा तो अनुमति दूंगा और वे उस पर प्रश्न पूछेंगे। बाकी कोई नहीं बोलेगा।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, साइबर थाने में 3 लाख रुपये की लिमिट है, 2 लाख की लिमिट नहीं है। कोई भी आपका ऐसा केस है जो दर्ज नहीं हुआ हो, आपने कहा 2 लाख की लिमिट है, 3 लाख तक के साइबर थाने जो हैं, वे अधिकृत हैं।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): मंत्री महोदय, अच्छा है, मेरे यहां तो सरकार ने साइबर थाना खोला, सब-कुछ हो गया, पर मेरी तो इतनी सी रिक्वेस्ट है, विनती है कि 2 लाख से कम का भी इस प्रकार का कोई साइबर क्राइम होता है तो उसे भी दर्ज कर लें। इसकी आप सरकार से अनुमति दिलवा दें। इतनी ही मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है।

श्री अध्यक्षः इनका सुझाव है।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 3 लाख का मैंने बोला। अब उसकी जांच कर लेंगे। 3 लाख से कम के जो भी रिफ्यूज किये, उन पर कड़ी कार्यवाही हम करेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है, वह गम्भीर है। 36 महीनों में 36 ही मामले दर्ज हुए तो फिर साइबर थाने का मतलब क्या है?

श्री अध्यक्षः तो क्या और ज्यादा साइबर प्रकरण होने चाहिये?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बात यह है साहब, इसका मतलब यह है कि लोगों को टरकाकर भेजा जा रहा है, मामले दर्ज नहीं हो रहे।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, साइबर क्राइम्स सबसे ज्यादा भारी तादाद में मेवात एरिया में है। आपके एरिया में हैं। बहुत ज्यादा होते हैं। एनसीआर एरिया है, वह इंडिया में नं 1, 52 परसेंट केसेज जो साइबर क्राइम के हैं,

वे एनसीआर के हैं और आपके एरिया में तो बहुत ही ज्यादा हैं नेता प्रतिपक्ष।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): विषय यह नहीं है कि कहां ज्यादा हैं, कहां कम हैं। कहने का मतलब यह है कि जब अपन ने साइबर थाना खोला है तो वहां लोगों को टरकाया नहीं जाये, रिपोर्ट दर्ज हो। यहां टरकाया जा रहा है। इन 36 महीनों में हमारा समय भी रहा 2 साल और 1 साल आपका है। यह तो 36 महीने का इन्होंने पूछा है। इसमें आपके समय की और हमारे समय की कोई बात नहीं है। बात यह है कि अगर नियमों में कोई इस प्रकार की बाउंडेशन लगा दी कि छोटे फ्रॉड का वहां पर मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, इसीलिए कम दर्ज हो रहे हैं तो वह लिमिट हटा देनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने सुन लिया।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 3 लाख का बोला है, उससे अगर कम कोई टरका दिया, उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। आश्वासन मैंने ऑलरेडी हाउस को दे दिया।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। धन्यवाद मंत्री जी।

अगला प्रश्न। श्री लक्ष्मण।

बस्सी में गारंटी अवधि की क्षतिग्रस्त सड़कें

47. श्री लक्ष्मण (बस्सी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की कौन-कौन सी सड़कें गारंटी अवधि में हैं? उक्त में से कितनी सड़कें वर्तमान में क्षतिग्रस्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु सम्बन्धित संवेदकों को नोटिस दिये गये हैं? यदि हां तो कब-कब व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त अवधि में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवायी गयी है? यदि हां तो कब-कब व किन-किन सड़कों की मरम्मत करवायी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (सुश्री दिया कुमारी): (1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में गारंटी अवधि की सड़कों एवं वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) संवेदकों की गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत करवाने हेतु समय-समय पर कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं। गारंटी अवधि में सड़क मरम्मत कार्य संवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर पूर्ण करवाये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: सदन के पटल पर रख दें।

श्री लक्ष्मण (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया है। मैं पूरक प्रश्न पूछ लेता हूं। मैंने पूछा, विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्तमान में कितनी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। इसमें 111 सड़कों का दिया है। सब में सन्तोषजनक बताया है। जिन सड़कों में 2-2 फीट

के गड्ढे हैं, बिलकुल टूटी-फूटी हैं, चलने योग्य नहीं हैं, उनकी भी स्थिति सन्तोषजनक बतायी है। यदि सभी 111 सड़कें सन्तोषजनक हैं तो यह तो मेरे ख्याल से जवाब सही नहीं है।

श्री अध्यक्षः आप पूछिये।

श्री लक्ष्मण (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्य मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि कब तक इन्हें ठीक कर दिया जायेगा? इसकला अलावा, दूसरा है कि ये तो गारंटी अवधि की सड़कें हैं, लेकिन जो बिना गारंटी की ग्रामीण सड़कें हैं, उनकी स्थिति तो बहुत खराब है, नॉन पैचेबल है। उन्हें कब तक ठीक करने का विचार रखती है सरकार?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि बस्सी विधान सभा क्षेत्र में कुल 111 सड़क कार्य दोष निवारण अवधि में हैं, जिनमें से 63 सड़कों का मरम्मत कार्य संवेदक द्वारा बिना नोटिस दिये ही पूर्ण कर दिया गया एवं शेष 48 सड़कों पर 126.92 किलोमीटर लम्बाई में संवेदक द्वारा नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त मरम्मत कार्य पूर्ण कर दिया गया। चूंकि नोटिस पर संवेदकों द्वारा मरम्मत कार्य करवा दिये गये हैं, अतः अन्य कोई कार्यवाही नहीं की गयी। यदि माननीय विधायक महोदय किसी सड़क को ध्यान में लाना चाहते हैं तो मुझे अवगत करवा दें, उसका मैं पुनः परीक्षण करवा दूंगी।

श्री लक्ष्मण (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि कोई भी ऐसी रोड हो, जो ध्यान में लाने योग्य हो, सारी सड़कें खराब हैं वहां की तो।

mkd/rtm/06.02.2025/11:10/1b

ग्रामीण क्षेत्र की टोटल सड़कें टूटी हुई हैं, दो-दो फीट के गड्ढे हैं, उनको सन्तोषजनक बताया गया है। दूसरा आपने बताया कि गारंटी अवधि में जो सड़कें हैं, वे सरकार ठीक नहीं करवाती, उनको संवदेक ठीक करवाता है, संवेदक को तो पैसा सरकार ही देती हैं। सरकार के इंजीनियर ही सुपरविजन करते हैं। अगर सरकार ही नहीं करवायेगी तो संवेदक तो कभी ठीक नहीं करवायेगा तो यह जवाब सन्तोषजनक नहीं है, वैसे जवाब दिया है, जवाब देने के नाम से। यह बताये कि संवेदक के द्वारा जो अभी तक ठीक नहीं करवाई गई हैं, उनको कब तक ठीक करवा दिया जायेगा? और नॉन पेचेबल को कब तक ठीक करवा दिया जायेगा?

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ये जो सड़कें हैं, डीएलपी पीरियड की, ये पिछली सरकार के समय ही बनवाई गई थीं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है सड़कों की, बिलकुल मैं मानती हूं। हमारे जो महोदय कह रहे हैं, यह बिलकुल सही है। जितनी भी सड़कें हैं, कांट्रेक्टर से रिपेयर भी करवा दी गई हैं। अभी पीडब्ल्यूडी विभाग ने सेवा ऐप भी शुरू किया है, उसके द्वारा भी हमारे अधिकारी समय-समय पर ये जितनी भी सड़कें चल रही हैं, जो डीएलपी पीरियड में हैं, उनकी फोटो सहित वे उस ऐप पर लोड कर रहे हैं। यहां जयपुर में

हमने डैश बोर्ड बना रखा है और रिपेयरिंग बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। दुर्भाग्यपूर्वक सड़कों की हालत पिछली सरकार में बहुत ही बेकार थी, गड्ढे मिले हैं, हमको आप लोगों से, सड़कें तो मिली ही नहीं, अब नॉन पेचेबल में हम पूरी तरह से काम करवा रहे हैं।

श्री लक्ष्मण (बस्सी): पिछली सरकार में खराब थी तो आप ठीक करवा दो, आपकी सरकार है अब तो।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): निश्चित रूप से, बिलकुल करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहरथाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण

48. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कामखेडा व रवासिया के भवन नहीं हैं? यदि हां, तो सरकार उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण हेतु राशि कब तक स्वीकृत करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): जी नहीं, विधानसभा क्षेत्र मनोहरथाना जिला झालावाड़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कामखेडा व रंवासिया स्वयं के भवन में संचालित है, जो कि नॉर्म्स अनुसार निर्मित है। वर्तमान में उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्मित है। अत: उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत करवाया जाना विचाराधीन नहीं है।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय मंत्री जी का जवाब आ चुका है और मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से सन्तुष्ट हूं, परन्तु जो भवन बने हुए हैं, वह काफी जर्जर है। इसके साथ-साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि भवन तो कम्प्लीट है, लेकिन कर्मचारियों के आवास हेतु क्या सरकार भवन बनाने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में माननीय सदस्य ने कहा कि हमारा भवन है ही नहीं। इन्होंने मूल प्रश्न में यह बताया था तो मैंने ऐसा कभी केस नहीं देखा, ये सब फोटोज हमारे पास हैं, भवन बन चुका है, टाइमली बन चुका है और ये कह रहे हैं कि जर्जर हालत में है। यह 2009 में तैयार हुआ है और अगर जर्जर हालत में यह हो गया है तो इसके लिए कलेक्टर की कमेटी के साथ बिठाकर और जो भी खामियां हैं, उनको दुरुस्त किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। अगला प्रश्न। श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

आहोर उप खण्ड मुख्यालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय का क्रमोन्नयन

49. श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आहोर के उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट

न्यायालय को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री (श्री जोगाराम पटेल): ''किसी स्थान पर न्यायालय की स्थापना/क्रमोन्नयन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार प्रकरण लम्बित होने पर की जा सकती है।''

वर्तमान में आहोर में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की माननीय कमेटी में विचारार्थ लंबित है।

भविष्य में आहोर में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त होने पर, निर्धारित मानदण्ड 1200-1500 प्रकरण लंबित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: सदन के पटल पर रख दें, फिर पूरक प्रश्न पूछें।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): नहीं-नहीं, जवाब देने दीजिये।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आहोर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने आहोर में स्थित सिविल जज को क्रमोन्नत करने की मांग की है। इनके क्रमोन्नत करने की जो मांग है, उस मांग का आधार तो वाजिब है, क्योंकि इनके क्षेत्र के जो मुकदमें हैं, सिविल नेचर के मुकदमे 1607 हैं, क्रिमिनल नेचर के मुकदमे वे 425 हैं, ये 1607 और 425 टोटल केसेज हैं, वे जालोर स्थित कोर्ट में सुने जा रहे हैं। सरकार की भी मंशा है कि अधिक से अधिक तीव्र न्याय मिले, नजदीक मिले, सस्ता मिले, परन्तु न्यायालय को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की सहमति भी आवश्यक है, क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की कमेटी होती है और कमेटी का अप्रूव्ल होता है, ऐसी स्थिति में माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आहोर में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी के समक्ष विचाराधीन है और ज्यों ही कमेटी का अप्रूव्ल मिलेगा, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका जो आहोर स्थित कोर्ट है, इसको क्रमोन्नत करने का प्रयास करेंगे, इतना ही मैं आपको आश्वासन देता हूं, धन्यवाद।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री ललित मीणा।

किशनगंज में राशन डीलरों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

50. श्री ललित मीणा (किशनगंज): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में विगत पांच वर्षों में राशन डीलरों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? सरकार द्वारा उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राशन वितरण व्यवस्था में अनियमितताओं को रोकने एवं व्यवस्था में सुधार हेतु कोई विशेष प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार 100 क्विंटल गेहूं से ज्यादा गबन के आरोपी राशन डीलरों को निलम्बित कर नए राशन डीलरों की नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): (1) विधानसभा क्षेत्र किशनगंज में विगत पांच वर्षो में 63 राशन डीलर्स के विरुद्ध 93 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश, 1976 के बिन्दु संख्या 08 के अंतर्गत राशन डीलर के प्राधिकार पत्र को जिला रसद अधिकारी द्वारा निलंबित या रद्द किया जा सकता है।

उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 22 के अंतर्गत जिला रसद अधिकारी के आदेश के विरुद्ध 30 दिवस में अपील जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है तथा जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेश की अपील 30 दिवस कि भीतर आयुक्त (खाद्य) के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य विशेष प्रावधान किये जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) उपरोक्त 93 शिकायतों में से 25 शिकायतें ऐसी हैं, जिनमें गबन का आरोप 100 क्विंटल गेंहू से अधिक का है, जिनका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

इनमें से इन सभी 25 उचित मूल्य दुकानदारों को नोटिस जारी कर प्रकरण दर्ज किये गए। इनमें से 07 नोटिसों पर वर्तमान में नोटिस स्तर ही कार्यवाही जैरकार है। 09 प्रकरणों में निलम्बन की कार्यवाही की गई थी, जिसमे से 07 प्रकरणों में विभागीय प्रकरण जैरकार रखते हुए बहाली की गई थी तथा 02 प्राधिकार पत्र वर्तमान में निलम्बित है तथा शेष 09 प्रकरणों में प्राधिकार पत्रों की शर्तो का उल्लंघन करने पर प्राधिकार पत्र निरस्त किये जा चुके हैं। निरस्त किये गये 09 प्राधिकार पत्र के स्थान पर नये राशन डीलरों की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में विगत पांच वर्षों में 63 राशन डीलर्स के विरूद्ध 93 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिन पर की गई कार्यवाही का विवरण...।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, ये उत्तर नहीं पढ़ना है। माननीय मंत्री जी, उत्तर नहीं

पढ़ना है, आप तो उत्तर रखा दिया है, वे पूरक प्रश्न पूछेंगे।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): साहब, ये सुनना चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: सुनना चाह रहे हैं, इनकी नहीं, व्यवस्था हो गई है। उनके सुनने से नहीं होगा, वे उसमें पढ़ ले। आप पूरक प्रश्न पूछ लें।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का मन्तव्य भी जनता के बीच में जाना चाहिए कि इन्होंने जवाब क्या दिया।

श्री अध्यक्ष: आपकी व्यवस्था हो गई है। अब आपको पूछना है तो पूछिये।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): पर, अध्यक्ष जी, उस बात का जवाब तो दें, सबको समझ में तो आये।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न आ जाये, फिर आप उसको इसी में जोड़ देना।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): फिर तो अध्यक्ष जी, सारा वैसे ही आ जायेगा, सबको ही पता है बात का।

श्री अध्यक्ष: आपको पूछना है?

श्री ललित मीना (किशनगंज): बताने दीजिये ना, जवाब सरकार को देने दीजिये।

श्री अध्यक्ष: आपको पूछना है, पूछो ना।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): साहब, वे जानना चाह रहे हैं, इनका किशनगंज सहरिया क्षेत्र है, वे प्रश्न जानना चाह रहे हैं, गम्भीर विषय है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जब आसन की तरफ से व्यवस्था दे दी गई है, तो इस प्रकार से आप जबर्दस्ती नहीं कर सकते हैं, आंसर सबके पास आया हुआ है।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जबर्दस्ती कौन कर रहा है। आप जबर्दस्ती कर रहे हो, सदन में पूछना उनका हक है, आप रोकेंगे उनका हक, आपको किसने हक दिया (..व्यवधान..)।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आसन की व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: दोनों पक्ष अपने स्थानों पर बैठिये। आप बैठिये, सब बैठिये। मैं कह रहा हूं, बैठिये, व्यवस्था लागू करना मेरा काम है। बैठिये, मेरा काम है, आपका काम थोड़े ही है। आपको अभी अध्यक्ष नहीं बनाया है। आप बैठिये, मिस्टर रफीक खान, सचेतक। इधर बैठिये सब, बैठिये।

एक बार व्यवस्था दे दी, उसके बाद उस पर कोई क्वश्चन नहीं होता। जब व्यवस्था हो गई कि लोक सभा, राज्य सभा व अन्य विधान सभाओं की आपको व्यवस्था दे दी कि वहां पर प्रश्न का उत्तर सबके टैब पर है और आपको जनता सुनना चाह रही है, जिसको जानना होगा, यू ट्यूब बाकी सबमें आ जाता है, यह सब टैब में है तो आप अपना पूरक प्रश्न पूछिये और उसका उत्तर आपको दिलायेंगे, दो पूरक प्रश्न पूछिये। मंत्री जी, नो कल मैंने कहा था, जिसको चर्चा करनी है, मेरे चैम्बर में आये, nobody came, इसका मतलब सर्वसम्मति हो

गई, कोई आना ही नहीं चाहता, इस कारण सब सहमत हैं। आपका, यदि किसी को दिक्कत थी तो मेरे चैम्बर में आ सकते थे, 12 घंटे बैठे हुए था nobody came, इसके बाद क्या आवश्यकता है?

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूं। मेरा कल भी..। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न तो पूछ ही रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप पूरक प्रश्न पूछ रहे हो या नहीं। आप पूरक प्रश्न पूछिये। अगला प्रश्न।

श्री ललित मीना (किशनगंज): अध्यक्ष जी, हां मैं पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उनको पूरक प्रश्न पूछने दीजिये, आप उत्तर दे देना।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सबका आता है, इसमें थोड़ी बात का है, विधायक का अधिकार है, हम भी पिछली बार सदन में थे, हम भी सदन में थे, क्यों नहीं अधिकार, क्यों नहीं अधिकार, कौन है बोलने वाला।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप लोग आसन की व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): क्या बात कर रहे हो, अध्यक्ष भी सदन का हिस्सा हैं।

श्री अध्यक्ष: सब बैठिये। नो, मंत्री जी, बैठिये। अगला प्रश्न। आपको उत्तर नहीं पूछना है। श्री विनोद कुमार। आप बैठिये, आपको किसने कहा, सचेतक हैं, संसदीय मंत्री हैं। आप बैठिये, नो मंत्री जी, नो मंत्री जी, सदन की व्यवस्था को भंग मत करिये। श्री विनोद कुमार। मेरी व्यवस्था को ही चैलेंज कर रहे हैं।

पीलीबंगा में पशु चिकित्सालय खोलने की योजना

51. श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): क्या पशुपालन एवं डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कहां-कहां खोले गये? नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की शेष ग्राम पंचायतों 6बी.एच.एम., 18एस.पी.डी., 45एन.डी.आर., 4एन.आर., 7एस.टी.बी., 26पी.बी.एन., 4सी.वाई.एम., 15-16के.डब्ल्यू.डी. निरवाल 4 डी.डब्ल्यू.एम. भेरूसरी व 10 के.डब्ल्यू.डी. में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, पुशपालन।

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) जी नहीं। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की ग्राम पंचायतों में स्वीकृत की गई पशु चिकित्सा संस्थाओं का स्थानवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	संस्था का प्रकार	संस्था का स्थान	स्वीकृत वर्ष

1.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र	भागसर (6 एसजीआर)	2019-20
2.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र	खेदासरी	2019-20
3.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र	खरलिया	2019-20
4.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र	अमरसिंहवाला(39 एलएलडब्ल्यू)	2020-21
5.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र	डबलीबासकुतुब	2020-21
6.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र	6-7 डी.डब्ल्यू.डी.	2021-22
7.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र	डींगवाला	2021-22

पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार खोली/स्वीकृत की जाती है।

(2) जी हां। पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार खोली/स्वीकृत की जाती है।

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): मेरे पास जवाब आ गया है। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। पिछले वर्ष 2024-25 के बजट के अन्दर पांच-पांच पशु उप-केन्द्र खोलने की घोषणा की गई थी। मंत्री महोदय जी बतायें कि एक पशु उप-केन्द्र खोला गया और नहीं खोला गया तो क्यों।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने जो बजट में घोषणा की थी।

Bhs/Rtm/06.02.25/11.20/1c

पंचायत स्तर पर चार सौ केन्द्र खोलेंगे। हर पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की घोषणा नहीं की गई थी और निश्चित रूप से हम भी, हमारे मुख्य मंत्री जी भी चाहते हैं, हमारी सरकार भी चाहती है कि हर पंचायत स्तर पर कोई न कोई चिकित्सा सुविधा हो तो इस दिशा में हमने पांच सौ चिकित्सा उप केन्द्र इस साल खोले हैं। पीलीबंगा क्षेत्र से हमारे पास प्रस्ताव नहीं आये हैं इसलिये पीलीबंगा क्षेत्र में हमने कोई केन्द्र नहीं खोले और वहां के क्षेत्र की आवश्यकता और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार केन्द्र खोले जाते हैं। वहां से अब जैसे इन्होंने डिमाण्ड की है तो अगले बजट में आवश्यकतानुसार और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार वहां केन्द्र खोले जायेंगे।

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): मंत्री महोदय, पंचायत हैडक्वार्टर्स पर कम से कम दस-पन्द्रह पंचायत हैडक्वार्टर्स पर पशु चिकित्सा उप केन्द्र बाकी हैं। प्रस्ताव कहां से आयेंगे? प्रस्ताव तो अपना विभाग ही मंगवायेगा कोई और तो भेजेगा नहीं। पशु उप केन्द्र बाकी हैं। आपने जवाब दिया कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, वित्तीय संसाधन सरकार उपलब्ध

करवाती है तो सरकार के पास कब तक वितीय संसाधन उपलबध हो जायेंगे? कुछ तय समय-सीमा बता दें तो हमारी भी जनता का भला हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इनके पीलीबंगा क्षेत्र में 13 पंचायतें ऐसी हैं जहां पर अभी भी उप केन्द्र नहीं हैं और हमारी सरकार की मंशा है कि हर पंचायत पर कोई न कोई चिकित्सा सुविधा मिले तो इस दिशा में वितीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार हम केन्द्र भी खोलेंगे। जन प्रतिनिधियों ने मांग की है, इनकी मांग के अनुसार भी हम केन्द्र खोलेंगे लेकिन अभी हमने गांव, ढाणी तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के लिए एक मोबाइल वेटरनरी युनिट की शुरूआत की है और उसमें डॉक्टर है, कम्पाउंडर है, सभी तरह की दवाइयां हैं और हर पशुपालक 1962 नम्बर पर सीधा फोन करता है तो पशुपालक के घर जाकर के इलाज करने की व्यवस्था सरकार ने की है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम चिकित्सा सुविधा को और बढ़ायेंगे और होम डिलीवरी तक हम चिकित्सा सुविधा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुरेश गुर्जर।

झालावाड़ में पौधारोपण पर व्यय

52. श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला झालावाड़ में विगत पांच वर्षों में कितने पौधे लगाये गये तथा उक्त पौधारोपण के लिए कितनी राशि का भुगतान किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पौधारोपण की निविदा किस-किस फर्म को जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला झालावाड़ में उक्त अवधि में लगाये गये पौधों में से वर्तमान में कितने पौधे जीवित हैं तथा कितने पौधे खराब हो गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री संजय शर्मा): (1) जिला झालावाड में विगत पांच वर्षों में विभाग में लगाये गये पौधे एवं उनके भुगतान का विवरण परिशिष्ट - 1 पर संलग्न है।

(2) उक्त कालावधि में किए गए पौधारोपण की निविदा जारी नहीं की गई है। स्थानीय ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति के माध्यम से पौधारोपण का कार्य सम्पादित किया गया है।

(3) उक्त पौधारोपण में जीवित पौधे एवं खराब पौधों का विवरण परिशिष्ट - 1 में समाहित है।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री जी का जवाब मिल गया है। मैं इनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने बताया कि जीवित पौधों का जो आंकड़ा दिया गया है वह वास्तविकता से परे है। सरकार ने जवाब दिया कि झालावाड़ जिले में पांच साल में 26 लाख से ऊपर पौधे लगाये हैं जिनमें से 18 लाख पौधे जीवित हैं करीबन 8 लाख पौधे खराब हो गये हैं। लगभग 13 करोड़ से ज्यादा की राशि पौधों के

वृक्षारोपण में खर्च की गयी है। अधिकारियों ने गलत आंकड़े भेजे हैं जो वास्तविकता से परे है केवल दस प्रतिशत पौधे ही अभी जीवित हैं।

श्री अध्यक्षः आप प्रश्न पूछें।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से पूरक प्रश्न है कि सरकार द्वारा प्लांटेशन में पौधे लगाने के बाद उनकी सुरक्षा और देखभाल सही तरीके से हो इसके लिए अधिकारियों द्वारा किस प्रकार से निरीक्षण किये जाते हैं? यदि हां, तो इतनी बड़ी संख्या में पौधे खराब होने के क्या कारण हैं? क्या सरकार जांच करा कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, खानपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो मेरे जवाब पर प्रश्न चिन्ह लगाया...।

श्री अध्यक्षः पूछा है, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): प्रश्न चिन्ह लगाया है मैं भी उससे संतुष्ट नहीं हूं।

श्री अध्यक्षः उत्तर दीजिये।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): मैं भी उससे संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि आप कोई ऐसा तरीका बता दें जिससे आप संतुष्ट हो सकें। पहली बात। ...(व्यवधान)... वही बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्षः जवाब दे रहे हैं।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): दूसरा, आपने प्रश्न किया कि किस प्रकार से हमारे पौधे लगाने के बाद हमारे विभाग द्वारा जांच की जाती है, समय-समय पर हमारे अधिकारियों द्वारा और थर्ड पार्टी ऑडिटेशन द्वारा हमारे विभाग द्वारा जांच की जाती है और मुझे बताते हुए खुशी है कि जो चिन्ता माननीय सदस्य ने सदन में व्यक्त की है, हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में इस वर्ष तीन प्रकार की जांच एजेंसियों के माध्यम से पौधारोपण की जांच हम करायेंगे, जिसके लिए मैं आपकी अनुमति से सदन के बीच में रखना चाहूंगा। सेन्टर फोर डवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड स्टडीज, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फोरेस्ट मैनेजमेंट और आफरी, जोधपुर, ए.आर.डी. फोरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट, दो तो भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की एजेंसी है, एक थर्ड पार्टी ऑडिटेशन को हमने काम सौंपा है। उसके अलावा ड्रोन के माध्यम से भी जो पौधारोपण किया जायेगा आने वाले समय में उसकी जांच की जायेगी और मैं सदन को विश्वास देता हूं कि इन तीन अलग-अलग एजेंसियों से अलग-अलग संभागवार पौधारोण की जांच होगी। हमारे जो सात सम्भाग हैं उनमें अलग-अलग ये तीनों एजेंसीज जांच करेंगी। उसके अलावा यदि आप कोई और दूसरी जांच एजेंसी से कराना चाहते हैं तो वह आप अवगत करा दें। हम आपको यह विश्वास देते हैं कि आने वाले समय में आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में जितने पौधे राजस्थान में लगाये जायेंगे उसमें से 85 से 90 प्रतिशत पौधे सुरक्षित रहेंगे, यह मैं सदन को विश्वास देता हूं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे दूसरा पूरक प्रश्न है। मेरे विधान सभा क्षेत्र खानपुर के ताराजीत गांव में आयुर्वेदिक औषधि के दो प्लांटेशन लगाये गये थे एक तीस हेक्टेयर का और एक पचास हेक्टेयर का, उनमें एक भी आयुर्वेदिक पौधा जीवित नहीं है, और तो और आपने जो पौधे लगाये थे उनके लिए जो सुरक्षा दीवार बनाई थी वह सुरक्षा दीवार भी अवैध रूप से पत्थर निकाल कर ट्रेक्टरों से लोग ले जाते हैं, रेंजर की मिलीभगत से कोट भी हटा दी गई हैं। एक भी पौधा जीवित नहीं है। मैं तो मान जाऊंगा आपको कि मैं जिस आयुर्वेदिक प्लांटेशन की बात कर रहा हूं उस प्लांटेशन की आप जांच करवा दें, कितने पौधे जीवित हैं और कितने मरे हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है, यह पौधारोपण माननीय नेता, प्रतिपक्ष आपकी सरकार के कार्यकाल में हुआ था और जिस प्रकार से उस वक्त ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे न बोलें।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): हमारी सरकार में हुआ हो तो मंत्री महोदय, जांच करवा दें आप तो इस प्लांटेशन की कि पौधे जीवित हैं या नहीं और उन अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करोगे कि नहीं?

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): पिछली सरकार के जो भी घोटाले चाहे वो पेपरलीक से सम्बन्धित हो चाहे ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप तो वन पर बोलिये।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष जी, पौधारोपण की बात करें मंत्री महोदय, पौधारोपण की।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी ने तय किया है कि पिछली सरकार के जो भी घोटाले होंगे उनकी निष्पक्ष जांच होगी और कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, वह जेल के सीख़चों के पीछे जायेगा, यह सदन को मैं विश्वास देता हूं।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): समय बताओ मंत्री महोदय, कब तक जांच करा दोगे, किस कमेटी से जांच कराओगे?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप तो सारी जांच करा ही दो वह कोई बात नहीं है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसकी जांच कराओगे कि नहीं? यह बता दो बस।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): मैंने कहा न कि पिछली सरकार के समय के घोटाले की समस्त जांच करायेंगे और माननीय सदस्य ने जो चिन्ता इस सदन में व्यक्त की है उसकी भी जांच करायेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो वो ही बात है। आप सक्षम हो क्या सारी जांच कराने के लिए?

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): नेता, प्रतिपक्ष उसकी भी जांच करायेंगे। मुख्य मंत्री जी करायेंगे। मैं बार-बार इंगित कर रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में होगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपकी पॉवर में नहीं है।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय नेता, प्रतिपक्ष कान के डाटे खोल कर बैठा करो। मैं बार-बार यह कह रहा हूं अध्यक्ष जी, कि मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में जांच करायी जायेगी, मुख्य मंत्री जी जांच बैठायेंगे। मैं अपने-आप से नहीं कह रहा हूं, कान को खोल कर बैठो। मैं बार-बार निवेदन यह कर रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा हर घोटाले की जांच करायी जायेगी और जो माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है उसकी जांच भी वन विभाग द्वारा करायी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: हो गया। वन विभाग की जांच आप करायें।

अगला प्रश्न। श्री डूंगर राम गेदर।

सूरतगढ़ में संचालित अवैध शराब की दुकानें

53. श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में ब्रांच के नाम पर अवैध शराब की दुकानें संचालित हैं? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में शराब की दुकानों के लाइसेंस धारकों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के कितने प्रकरण दर्ज किये गये तथा कितने लाइसेंस धारकों पर कार्यवाही की गई?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में रात्रि 8:00 बजे के पश्चात् शराब की दुकानें खुली पाए जाने पर कितने मामलों में कार्यवाही की गई?

(4) सरकार द्वारा अवैध शराब की बिक्री और नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): (1) जी नहीं।

(2) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में वर्ष 2024-25 में मदिरा दुकानों के 20 लाईसेंस-धारकों द्वारा नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कुल 20 अभियोग दर्ज किये गये हैं।

(3) वित्तीय वर्ष 2024-25 में रात्रि 8:00 बजे बाद मदिरा बेचान करते पाये जाने पर 01 प्रकरण में कार्यवाही की गई।

(4) मदिरा के अवैध विक्रय एवं नियमों के उल्लंघन को रोकने हेतु विभाग द्वारा निरन्तर रेड गश्त एवं नियमित जांच की कार्यवाही की जा रही है। विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उत्तर आ गया है, मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: पूछिये।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता

हूं कि राजस्थान प्रदेश के साथ-साथ सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में ब्रांच के नाम पर पक्की गुमटियां, लोहे के खोखे लगे हुए हैं जो रात को दस बजे तक शराब की बिक्री करते हैं। इन गुमटियों व खोखों को हटाने के लिए कौन अधिकारी सक्षम है और जानबूझ कर इन अवैध शराब के कारोबारियों पर कार्यवाही अधिकारी नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने की मंशा रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमों का उल्लंघन कर मंदिर विक्रय करने की स्थिति में विभाग द्वारा निरन्तर कार्यवाही की जाती है तथापि यदि आप द्वारा कोई स्पेसिफिक इश्यु कम्प्लेंट ध्यान में लायी जायेगी तो उस प्रकरण की पृथक जांच करवायी जायेगी और आपको सूचना दे दी जायेगी। यदि ऐसा कुछ चल रहा है जो कि इल्लीगल है तो निश्चित रूप से उस पर हम लोग बिलकुल करेंगे उस पर कार्यवाही भी होगी। गत एक वर्ष में विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में 373 गश्त की कार्यवाही की गई तथा 869 बार मदिरा दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण भी किया गया। विभाग द्वारा उक्त निरीक्षण के परिणामस्वरूप बीस अभियोग दर्ज कर राशि रुपये 2 लाख 10 हजार का जुर्माना आरोपित भी किया गया।

Kas/rtm/06.02.2025/11.30/1d

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से दूसरा पूरक प्रश्न है कि आप कह रहे हैं कि नियमित और निरंतर जांच करवाई जा रही है, सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में आबकारी विभाग के पास कितनी गाड़ियां हैं, कितना स्टाफ है जो निरंतर गश्त व नियमित जांच की कार्यवाही करते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला आबकारी अधिकारी जांच हेतु अधिकृत हैं, उनके पास गाड़ियां भी हैं और स्टाफ भी हैं। अगर आपका कोई इश्यू है तो आप बिलकुल बताएं, हम उसकी जांच करेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि कोई अवैध ब्रांच नहीं है। क्या विभाग के पास कोई शिकायत आई है, एक प्रश्न तो मेरा यह है। दूसरा, सब लोग जानते हैं कि हर विधान सभा क्षेत्र में अवैध ब्राचेंज खुली हुई हैं, चाहे गोदाम के नाम पर, चाहे कहीं पर भी। आप एक अभियान चलाकर इस पर कार्यवाही करा दें, जिससे अवैध ब्रांचों पर कार्यवाही हो जाये।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष जी को कहना चाहूंगी कि मैंने अपने उत्तर में भी कहा कि यदि ऐसी कोई बात है तो बिलकुल निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही भी करेंगे। मैंने अभी यह भी बताया कि हमारे सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुल 68 स्वीकृत दुकानें हैं और नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर वित्तीय वर्ष

2024-25 में दर्ज अभियोग 20 हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रात्रि 8 बजे बाद मदिरा बेचान करते हुए पाये गये प्रकरण 1 है। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा प्रकरण है, ऐसी कोई दुकानें हैं तो माननीय सदस्य बिलकुल बताएं, अगर वह इल्लीगल पाई गईं तो उस पर हम लोग कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्षः ठीक है। डा. जसवंत यादव।

बहरोड़ मिड-वे को प्रारम्भ करने की योजना

54. डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या सरकार बन्द पड़े बहरोड मिड-वे को पुनः प्रारंभ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मिड-वे बंद होने से सरकार को राजस्व की हानि हो रही है तथा यह जर्जर अवस्था में बदलता जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की मरम्मत करवाकर पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

पर्यटन मंत्री (सुश्री दिया कुमारी): (1) जी हां। बहरोड़ मिड-वे को आउटसोर्स पद्धति पर पुनः प्रारम्भ किए जाने की प्रक्रिया विचाराधीन है।

(2) राजस्थान पर्यटन विकास निगम के बहरोड़ मिड-वे पर यात्री बसों का ठहराव बंद होने के कारण राजस्व प्राप्ति लगभग बंद हो गई थी।

मिड-वे बहरोड़ द्वारा संचालन अवधि में पर्याप्त राजस्व अर्जन के अभाव में निरन्तर व्यावसायिक हानि कारित करने के फलस्वरूप राजकीय हित में इसे बंद करने का निर्णय लिया गया।

मिड-वे बहरोड़ की मरम्मत कराए जाने संबंधी कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। निगम द्वारा इस मिड-वे को आउटसोर्स पद्धति पर पुनः संचालित किए जाने की प्रक्रिया विचाराधीन है।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको आप अदर वाइज मत लेना, मंत्री मेहनत करता है, जवाब देता है।

श्री अध्यक्षः आप तो प्रश्न पूछो।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): वह भी चाहता है कि क्षेत्र में उसका हाईलाइट हो।

श्री अध्यक्षः आप पूरक प्रश्न पूछो।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आपने इस पर अंकुश ही लगा दिया, मंत्री क्या करें।

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न पूछिए।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैं तो पूछ लूंगा।

श्री अध्यक्षः आप पूछिए, नहीं तो मैं अगला प्रश्न पुकार लूंगा।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): हमारे बहरोड में मिड-वे बहुत ही महंगी प्रापर्टी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वहां नेशनल हाई-वे का पुल आ गया और यह सारा डीलक्स बसों पर और आने-जाने वाली गाड़ियों पर डिपेंड करता था। उस पुल के कारण अब वो वहां

उतर नहीं पातीं और इसके कारण यह घाटे में चला गया। अभी माननीय उप मुख्य मंत्री महोदया ने मुझे बताया है कि इसको दुबारा विचाराधीन कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि इसको विचाराधीन ना करें। इस प्रापर्टी को बचाने के लिये या तो इसे कहीं लीज पर दे दें या किसी विभाग को दे दें या किसी और चीज में इसका उपयोग तुरंत करें। जब तक यह विचाराधीन रहेगा, तब तक उसमें ईंट भी नहीं मिलेगी, उसके खिड़की-दरवाजे अभी से उखड़ने लग गये, लोग उठा ले जाते हैं। इतनी कॉस्टली प्रापर्टी पर तो तुरंत प्रभाव से आपको अपना डिसीजन लेना चाहिये, जिससे सरकार को बहुत बड़ा घाटा ना हो।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है मैं उससे बिलकुल सहमत हूं। हम जल्दी ही इस पर निर्णय लेंगे कि इसको किस दिशा में आगे बढ़ाना है। इसको आउटसोर्स करना है या ओ.एन.एम. पर करना है या लीज पर देना है, हम इस पर बिलकुल जल्द से जल्द कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्षः इनका प्रश्न जायज है, मुझे भी लगता है कि काफी समय से वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, जिसका कहीं न कहीं समाधान होना चाहिये। अगल प्रश्न। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्धन मेधावी छात्रों को देय छात्रवृत्ति

55. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में निजी और सरकारी सीटों के लिए वर्तमान शुल्क संरचना क्या है? क्या सरकार द्वारा उक्त शुल्क संरचना की समीक्षा की गई हैं? यदि हां, तो कब?

(2) राज्य व केंद्र सरकार द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्धन मेधावी छात्रों के लिए कौनसी छात्रवृत्ति व वित्तीय सहायता योजनाएं संचालित हैं तथा योजनाओं के लिए पात्रता के मानदंड क्या हैं?

(3) क्या सरकार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटों की संख्या में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) जी हॉं। सरकार द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्धारित शुल्क संरचना की समीक्षा लगातार की जा रही है। अतिंम शुल्क संरचना की समीक्षा वर्ष 2024 में की गयी है, विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हाँ। चिकित्सा महाविद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृति योजनाएं, जो राज्य सरकार द्वारा संचालित है, जिसमें केन्द्रयांश भी निहित है। छात्रवृतियों के मानदण्ड का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जैसलमेर एवं टोंक जिले में 100-100 एमबीबीएस सीट्स प्रवेश क्षमता (कुल 200 एमबीबीएस सीट्स) के नवीन कॉलेज खोले जाने के लिये एनएमसी

को आवेदन किया गया है, जो अनुमति उपरान्त प्रारम्भ किये जायेगें।

साथ ही केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत पीजी पाठ्यक्रमों में 527 नवीन सीट्स की चरणबद्ध रूप से अभिवृद्धि एनएमसी की स्वीकृति उपरांत की जायेगी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि गत तीन वर्षों में उक्त छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता राजसमन्द में कितने छात्रों को मिली एवं इन छात्रवृत्तियों की जागरूकता बढ़ाने के लिये क्या सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जितनी भी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, हमारे मेडिकल कॉलेजेज में एससी, एसटी, ओबीसी, लेडीज, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस का सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट स्कॉलरशिप तय करती है और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का डेटा मेरे पास अभी यहां पर उपलब्ध नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात हुई?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। ....(व्यवधान).... आपको पूछने के लिये नहीं कहा, आप बैठिए, आप बैठिए, यह आपका काम नहीं है। पहले दूसरा पूरक प्रश्न सदस्य पूछेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरी एक प्रार्थना है, आपने व्यवस्था दी कि बिना मेरी इजाजत के कोई नहीं बोलेगा और वैसे नियमों में भी यही नियम है और आप पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सभी सदस्यों को पूरा मौका मिले। लेकिन लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य अगर बार-बार खड़े होते हैं, तो नियमों में इनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान नहीं है क्या?

श्री अध्यक्ष: बैठिए, आपने ध्यान में ला दिया।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि राजसमन्द की बहुत बड़ी डिमांड कुवांरिया सी.एच.सी. और राजियावास पी.एच.सी., इन्होंने ने दोनों हमें दी हैं, लेकिन क्या सरकार राजसमन्द में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की मंशा रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे 6 बड़े हॉस्पिटल डिविजनल हैडक्वार्टस पर हैं, उसके अतिरिक्त हमारी राजमेस सोसाइटी के जरिए हमने 22 मेडिकल कॉलेजेज खोल दिये हैं। टोंक और जैसलमेर का अभी निर्माण चल रहा है और जो कुछ बच गये हैं, जिसमें प्रतापगढ़, राजसमन्द और जालोर, इनको हम पीपीपी मोड पर करेंगे। अभी राइजिंग राजस्थान में भी काफी निवेश आ रहा है। इसकी जो मॉडेलिटीज हैं, जमीन की रिक्वायरमेंट और मेडिकल कॉलेज में हमारा खुद का हॉस्पिटल होना भी बिलकुल अनिवार्य है। यह पॉसेबिलिटीज करके हमें इनको करना है। प्रश्न यह है कि इसकी मॉडेलिटीज

को हमें पीपीपी मोड पर फाइनलाइज करनी है।

आपने जो सी.एच.सी. की बात की है, आपको जो भी कमी पड़ती है, वह आप लिख कर हमें दें, हम फाइनेंस को जल्दी ही भेजेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री नाना लाल निनामा।

पीपलखूंट (घाटोल) में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना

56. श्री नाना लाल निनामा (घाटोल): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र घाटोल के उपखण्ड मुख्यालय पीपलखूंट में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री (श्री जोगाराम पटेल): (1) किसी स्थान पर नवीन सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा निर्धारित मानदण्ड 1700-2000 प्रकरण लम्बित होने पर ही की जा सकती है।

वर्तमान में पीपलखूंट में किसी भी प्रकार का न्यायालय खोले जाने का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचारार्थ लंबित नहीं है।

भविष्य में इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

श्री नाना लाल निनामा (घाटोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र घाटोल पंचायत समिति हैडक्वार्टर मुख्यालय पीपलखूंट में मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय खुलवाने की मैंने माननीय मंत्री महोदय से मांग की थी, लेकिन उन्होंने कोई नियम बताया, प्रकरणों के बारे में पूछा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि हमारे यहां कितने प्रकरण लंबित हैं?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की मांग की है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय और राजस्थान सरकार के नियम हैं कि एक इतनी निर्धारित संख्या में प्रकरण विचाराधीन हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जो कमेटी बनी हुई है, वो सहमति दे देती है, तो नया न्यायालय खोला जा सकता है या क्रमोन्नत किया जा सकता है।

जहां तक माननीय सदस्य के क्षेत्र का प्रश्न है, इनके क्षेत्र में सिविल नेचर के सिर्फ 24 मुकदमे हैं और क्रिमिनल नेचर के 281 मुकदमे हैं और ये जो राजस्थान सरकार ने और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने पैरामीटर्स तय किये हैं, उन पैरामीटर्स से बहुत ज्यादा दूर है। साथ ही साथ मैं यह भी माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में जब पैरामीटर्स तय नहीं करते तो न तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की समिति सहमति देगी और ना ही राजस्थान सरकार नियमों में इतनी ज्यादा शिथिलता दे सकती है, क्योंकि

कम से कम 700-800 मुकदमे होने चाहिये और आपके वहां करीब 200 मुकदमे ही हैं।

तीसरा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पीपलखूंट में सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट सृजन का मामला प्राप्त होने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी द्वारा लंबित प्रकरणों की संख्या को देखते हुए पीपलखूंट में ग्राम न्यायालय सृजन हेतु राज्य सरकार को जरिए पत्र दिनांक 18.12.2014 को लिखा गया था।

Msk/rtm/06.02.25/1140/1e

जिस पर राज्य सरकार द्वारा सहमति प्रदान नहीं की गयी। तत्पश्चात पीपलखूंट के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, अपर सिविल न्यायाधीश का ज्ञापन प्राप्त होने पर नये सिरे से लंबित प्रकरणों की संख्या मंगवायी जाकर प्रकरण माननीय कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखा गया है, जिस पर कमेटी द्वारा दिनांक 12.08.2023 को उक्त प्रकरण को अस्वीकार कर दिया गया है। वर्तमान में पीपलखूंट में किसी प्रकार का न्यायालय खोलने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है, क्योंकि हमने सरकार को लिखा तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मुकदमों की संख्या को देखते हुए उसे स्वीकार नहीं किया, मना कर दिया, इसलिए इस स्टेप पर आपके क्षेत्र में न्यायालय खोलने में असमर्थ हैं।

श्री अध्यक्षः उत्तर तो आ गया।

श्री नाना लाल निनामा (घाटोल): माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रकरण के बारे में पूछा था।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): बता दिया ना।

श्री अध्यक्षः आपके पृष्ठ में उसका उत्तर आ गया।

श्री नाना लाल निनामा (घाटोल): मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि मेरे सीओ सर्कल में तीन हजार से ऊपर प्रकरण लंबित हैं। आपने जो नियम बताये हैं, क्या सभी कोर्ट इसी नियम से हैं या कोई छूट दी गयी है? माननीय मंत्री महोदय, बताने की कृपा करें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सदस्य, राजस्थान सरकार और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय नियमों से ही चलते हैं और नियमानुसार जो भी कोर्ट खोले गये हैं या क्रमोन्नत किये गये हैं, मैं पुनः आपको दोहराता हूं, आपके क्षेत्र का प्रकरण मैंने आपको बताया, शायद आपने ध्यान से नहीं सुना। आपके क्षेत्र के सिविल प्रकरण सिर्फ 24 हैं और क्रिमिनल नेचर के 281 हैं। अगर आप यह मानते हैं कि हमारा आंकड़ा गलत है तो तथ्यात्मक लाकर दे सकते हैं। हम उसको वेरिफाई करायेंगे, गलत जवाब देगा तो उस पर कार्यवाही होगी। आज हमारे पास प्रमाणित आंकड़े हैं। जहां तक आपका कहना यह है कि क्या सभी क्षेत्रों में इसी तरह से होता है, पूरे राजस्थान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी की सहमति और राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार ही न्यायालय खोले जाते हैं या क्रमोन्नत किये जाते हैं या विचाराधीन प्रकरणों को इधर से उधर किया जाता है। एक समानता से, एक साथ न्याय होता है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न स्थगित है। वह केन्द्र से सम्बन्धित है।

प्रदेश में ज्वैलरी की जांच हेतु हॉलमार्क सेन्टर

57. श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): क्या उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के किन-किन जिलों में ज्वैलरी की जांच हेतु कितने हॉलमार्क सेन्टर स्थापित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा विगत एक वर्ष में ज्वैलरी की गुणवत्ता की जांच हेतु कोई अभियान शुरू किया गया है? यदि हां, तो अभियान के दौरान आभूषणों में मिलावट पाये जाने पर किन-किन व्यवसायियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त मिलावटकर्ताओं के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया है? यदि हां, तो किन-किन के विरूद्ध व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मेरी एक बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष: स्थगित हो गया। श्री गोपीचन्द मीणा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आप बात तो सुन लें। मैं एक निवेदन करता हूं कि जब यह प्रश्न अग्राह्य था तो लगा कैसे? दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जब सरकार की जानकारी में यह है कि चांदी, पायल, बिछिया, कड़े, छल्ले, 70 प्रतिशत गहनों में गिल्ट और एल्युमिनियम की चमक है तो इस पर सरकार कोई संज्ञान तो ले, कोई कानून तो बनाये।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, अब स्थगित हो गया।

अगला प्रश्न। श्री गोपीचन्द मीणा।

जहाजपुर में स्थित मंदिरों का विकास

58. श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में विगत 05 वर्षों के दौरान, मंदिरों का जीर्णोद्धार, सौन्दर्यकरण तथा विकास कार्य नहीं कराए गए हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्थित घाटारानी माताजी, कोटडी चारभुजानाथ, दातडा धाम, मांगटदेव लुहारीकलां, भूतेश्वर महादेव तथा चवलेश्वर पार्श्वनाथ जैन मंदिरों में विकास कार्य कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

देवस्थान मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) जी नहीं। देवस्थान विभाग के क्षेत्राधीन जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विभाग के 5 राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी के मंदिर हैं, जिनमें विगत पांच वर्षों के दौरान मंदिरों के मरम्मत एवं रंग रोगन पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राशि रुपये 4,75,215/- का व्यय विभाग द्वारा किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र सं.	मंदिर का नाम	व्यय राशि

1	मंदिर श्री गणेशजी के मंशापूर्ण जी जहाजपुर	98500/-
2	मंदिर श्री बृजनन्दन जी जहाजपुर	98450/-
3	मंदिर श्री शान्तेश्वर जी उर्फ सोमेश्वर जी एवं धर्मशाला	81290/-
4	मंदिर श्री राजराजेश्वर जी जहाजपुर	98025/-
5	मंदिर श्री बलदाऊजी ग्राम शक्करगढ जहाजपुर	98950/-

(2) प्रश्न में वर्णित मंदिर, देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिर नहीं है। इन मंदिरों के जीर्णोद्धार, विकास एवं सौन्दर्यकरण के कार्यों हेतु वर्तमान में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास प्रश्न का उत्तर आ गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्री महोदय ने जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में बहुत शानदार बजट दिया है, इसके लिए धन्यवाद है। मेरा प्रश्न है कि श्री गणेशजी के मंशापूर्ण जी जहाजपुर, श्री बृजनन्दन जी जहाजपुर, श्री शान्तेश्वर जी उर्फ सोमेश्वर जी जाहजपुर, श्री राजराजेश्वर जी जहाजपुर श्री बलदाऊजी ग्राम शक्करगढ़। ये सरकार के आत्मनिर्भर मन्दिर हैं। स्वयं के खर्च से ग्रामवासी चलाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इनके जीर्णोद्धार और रंग-रोगन की व्यवस्था क्या सरकार कराना चाहती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि राजस्थान में 593 मन्दिर आत्मनिर्भर के प्रभार के हैं, जिनका पूरा रख-रखाव, उनका जीर्णोद्धार की सारी व्यवस्था देवस्थान विभाग करता है। इनमें 552 मन्दिर राजस्थान में हैं, 41 मन्दिर अन्य प्रदेशों में हैं। इनमें से माननीय सदस्य के क्षेत्र में पांच मन्दिर श्री गणेशजी के मंशापूर्ण जी जहाजपुर, मन्दिर श्री बृजनन्दन जी जहाजपुर, मन्दिर श्री शान्तेश्वर जी उर्फ सोमेश्वर जी धर्मशाला, मन्दिर श्री राजराजेश्वर जी जहाजपुर, मन्दिर श्री बलदाऊजी ग्राम शक्करगढ़, जहाजपुर। ये पांच मन्दिर माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में हैं। हमने 2024-25 में इन मंदिरों पर 4,75,215/- रुपये वहां के रंग-रोगन के लिए, मंदिरों में पोशाक और मंदिरों के बोर्ड लगाने के लिए खर्च किये हैं। अभी माननीय सदस्य ने बताया कि वहां उन मंदिरों में जीर्णोद्धार के लिए रख-रखाव के लिए, रंग-रोगन के लिए और राशि की आवश्यकता है। निश्चित रूप से माननीय सदस्य की भावना को समझते हुए जितना भी हम परीक्षण करायेंगे और आवश्यकता के अनुसार हम काम करायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री भीमराज भाटी।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

59. श्री भीम राज भाटी (पाली): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल मुख्यालय को वर्ष 2022-2023 से वर्ष

2024-2025 तक अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई? उक्त शिकायतों में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों का रजिस्टर संधारित किया जाता हैं? यदि हां, तो उक्त अवधि में प्राप्त शिकायतों से संबंधित रजिस्टर की प्रति सदन की मेज पर रखें।

पर्यावरण मंत्री (श्री संजय शर्मा): (1) जी हां। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल मुख्यालय को वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक 14 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की सूचना परिशिष्ट अ पर संलग्न है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय में शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के संबंध में ठोस साक्ष्य/सबूत/दस्तावेज के अभाव में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई है। तथापि जिन कार्मिकों के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई है उनमें से 8 कार्मिकों का स्थानान्तरण अन्यत्र एवं 2 प्रतिनियुक्ति के कार्मिकों को मूल विभाग हेतु कार्यमुक्त किया गया है।

(2) जी नहीं।

श्री भीम राज भाटी (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे उत्तर प्राप्त हो गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे उत्तर में यह बताया गया है कि 14 अधिकारियों के विरूद्ध शिकायत हुई है। उन 14 अधिकारियों के विरूद्ध शिकायत में कोई ठोस सबूत नहीं पाया गया है, फिर भी उन 14 में से 10 अधिकारियों का निलंबित कर दिया गया है या अन्य जगहों पर ट्रांसफर कर दिया गया है या मूल विभाग में भेज दिया गया है। जब कोई भी ठोस सबूत नहीं पाया गया तो 14 में दस के विरूद्ध तो आपने एक्शन लिया। चार को आपने एज-इट-इज कायम रखा। जो चार सबसे ज्यादा भ्रष्ट थे, उन लोगों को आपने छेड़ा ही नहीं, उनको आपने टच ही नहीं किया। मेरा पहला प्रश्न तो यह है।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): दोबारा बोलना, क्या कह रहे हैं?

श्री भीम राज भाटी (पाली): 14 अधिकारियों के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी। 14 में से आपने जवाब दिया है कि कोई ठोस सबूत नहीं पाया गया। फिर भी आपने उन 14 में से 10 लोगों को, आठ का तो उनका ट्रांसफर किया, दो को उनके मूल विभाग में भेजा। जब कोई सबूत ही नहीं था तो फिर 14 में से 10 के खिलाफ एक्शन क्यों लिया? 14 में से 10 के खिलाफ एक्शन लिया तो जो चार सबसे ज्यादा भ्रष्ट थे, उन चार को आपने एज-इट-इज कायम रखा, उनको आपने टच ही नहीं किया। उसका क्या कारण है? नंबर एक। नंबर दो।

श्री अध्यक्ष: एक सैकेण्ड सुन लीजिये, एक-एक उत्तर आने दो।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य, जिन 14 अधिकारी/कर्मचारियों के बारे में सदन को अवगत कराया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ शिकायतों में कोई एड्रेस नहीं था, उनका कोई मोबाइल नंबर नहीं था। साथ ही साथ, जैसा कि इस उत्तर में भी आया है, आपने कहा कि स्थानांतरण

किया, स्थानांतरण एक सतत प्रक्रिया है। जो दूसरे डिपार्टमेंट से आते हैं, उनको भी भेजने का अधिकार पोल्यूशन बोर्ड का है। इसमें तो आपको कोई बनता नहीं है। सतत प्रक्रिया है और हमने डेप्यूटेशन वालों को वापस भेज दिया।

श्री भीम राज भाटी (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि जब उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं पाया गया, सबूत नहीं पाया गया। तो फिर 14 में से 10 के खिलाफ तो आपने एक्शन लिया, मूल विभाग में भेज दिया, वह आपका अधिकार है, सही है। लेकिन बाकी के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज दिया, स्थानांतरण कर दिया, लेकिन जो चार अधिकारी सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं, मुख्य अभियंता है, अतिरिक्त मुख्य अभियंता है, उनके खिलाफ आपने कुछ भी नहीं किया। इसका क्या कारण है?

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): मुख्य अभियंता का नाम बता देते तो ज्यादा अच्छा रहता।

श्री भीम राज भाटी (पाली): मुख्य अभियंता नवीन माथुर, नीरज माथुर, अतिरिक्त मुख्य अभियंता भुनेश माथुर। मैं दावे के साथ, August House में खड़ा हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिन चार अधिकारियों को आपने टच नहीं किया है, वह पर्यावरण मण्डल के सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्ट अभियंता हैं।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें, उत्तर आ रहा है।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, नीरज माथुर जी दिनांक 30.09.2023 को रिटायर्ड हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। भुनेश माथुर जी के सन्दर्भ में आपने सदन के अन्दर चर्चा की। यह ठीक है कि पाली की कुछ टैक्सटाइल मिलों से उनके सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उनके पास जो टैक्सटाइल का चार्ज था, वह पॉल्यूशन बोर्ड द्वारा टैक्सटाइल का चार्ज वापस ले लिया गया है और उनकी जगह एक वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती शशि चौधरी जी को वह चार्ज दिया गया है। आपने जिस इनक्वायरी की बात की है। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपने जो भी विषय सदन के अन्दर रखे हैं, उसके लिए हमारे पोल्यूशन बोर्ड के मेंबर, सेक्रेटरी द्वारा उन तमाम विषयों पर जांच करा ली जायेगी, क्योंकि पाली के अन्दर विशेष रूप से जो समस्या है, वह पोल्यूटेड पानी को लेकर है। किसान भी परेशान हैं, किसान की धरती का सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है, उद्योगपति भी चाहते हैं कि उनकी यूनिट ढंग से चले। इसके लिए माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, मैं सदन के अन्दर घोषणा करता हूं कि पोल्यूशन बोर्ड के हमारे जो मेंबर सेक्रेटरी हैं, उनके माध्यम से समस्त प्रकरण की जांच करा ली जायेगी।

श्री भीम राज भाटी (पाली): दूसरा पूरक प्रश्न यह है..।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, दो हो गये, आश्वासन दे दिया, जांच करायेंगे। श्री काली चरण सराफ।

mdp/rtm/06.02.2025/11:50/1f

श्री भीम राज भाटी (पाली): दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि जो भी शिकायतें आपको प्राप्त हुई हैं, उन शिकायतों का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल से एक सर्कूलर है, शिकायतों को मेन्टेन करने के लिए एक रजिस्टर रखा जाना चाहिए। वह रजिस्टर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आज दिन तक नहीं रखा गया। मुझे जवाब दिया गया कि कोई भी रजिस्टर नहीं है। ये डीओपी का सर्कूलर है जिसमें लिखा है कि इस तरह की कोई भी शिकायतें हों, वह मुख्य मंत्री जी को प्रेषित की जाए, मुख्य मंत्री जी को प्रस्तुत की जाए। क्यों नहीं शिकायतों का रजिस्टर मेन्टेन किया जा रहा है? आपके पासशिकायत आयी, आपके जांच अधिकारी ने लिखकर दे दिया कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूतनहीं है, जबकि ठोस सबूत है। रजिस्टर मेन्टेन करने में आपको क्या तकलीफ है? डीओपी का सर्कूलर है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, सदस्य। माननीय मंत्री जी।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है और हमने जवाब में भी कहा है कि कोई रजिस्टर मेन्टेन नहीं किया जाता, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आदरणीय भजन लाल जी की सरकार पारदर्शी सरकार है। मैं सदन में घोषणा करता हूं कि आने वाले समय में जो भी शिकायतें प्राप्त होंगी, उनको सूचीबद्ध करके हम रजिस्टर मेन्टेन करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कालीचरण सराफ।

भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की अभियोजन स्वीकृति

60. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) यह सही है कि सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर केस चलाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को अभियोजन स्वीकृति नहीं दे रही है? यदि हां] तो वर्ष 2022 से 2024 तक कितने प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु कब से एवं किन कारणों से लम्बित हैं?

(2) क्या सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लम्बित प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): (1) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों द्वारा अभियोजन स्वीकृति हेतु राज्य सरकार/संबंधित विभागाध्यक्ष को 01 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2024 के दौरान प्रेषित् किये गये 1592 अभियुक्तवार अभियोजन स्वीकृति प्रस्तावों में से 1189 अभियुक्तवार अभियोजन स्वीकृति प्रस्तावों में निर्णय प्राप्त हुए तथा 403 अभियोजन स्वीकृति प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं।

लम्बित अभियोजन स्वीकृति प्रस्ताव कब से लम्बित है, का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

एसीबी द्वारा जांच उपरांत जांच में दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रेषित

अभियोजन स्वीकृति प्रस्ताव संबंधित विभागाध्यक्षों और राज्य सरकार के स्तर पर परिक्षणाधीन होते हैं। संबंधित विभागाध्यक्षों और राज्य सरकार द्वारा एसीबी के अनुसंधान अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति के संबंध में विचार विमर्श हेतु बुलाया जाता है।

एसीबी के अनुसंधान से संतुष्ट नहीं होने एवं अन्य कुछ विषयों पर सहमत नहीं होने पर अभियोजन स्वीकृति में विलम्ब होता है। इसके अतिरिक्त आरोपी अधिकारी और कर्मचारी द्वारा अपनी अभियोजन स्वीकृति पर माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जाता है, अभियोजन स्वीकृति प्रस्ताव विभागीय स्तर पर परीक्षण एवं प्रक्रिया में लगने वाले समय के कारण लंबित रहते हैं।

(2) सरकार द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अभियोजन स्वीकृति के लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित विभागाध्यक्षों को समय-समय पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं जिससे प्रकरणो में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय मैंने पूछा तो क्या था, प्रश्न ही चेंज कर दिया मेरा। मैंने पूछा था कि यह सही है कि भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर केस चलाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सरकार अभियोजन स्वीकृति नहीं दे रही है? यदि हां] तो 31 दिसम्बर, 2024 तक कितने केसेज में एसीबी ने अभियोजन स्वीकृति हेतु सरकार से अनुरोध किया है। प्रश्न में कर दिया कि 2022 से 2024, यह लिमिट कर दी आपने। खैर, आपने कर दी कोई बात नहीं। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2024 तक आपके 1189 अभियोजन की स्वीकृति आपने दी, 1592 में से और 403 अभी-भी आपकी लंबित हैं। जबकि प्रदेश के सतर्कता आयुक्त ने सभी विभागों के एचओडी को पत्र लिखकर अधिकतम तीन महीने में अभियोजन स्वीकृति देने के आदेश दिए हुए हैं। ये क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब दीजिए, फिर दूसरा प्रश्न पूछूंगा।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे वरिष्ठ नेता सात बार विधान सभा में आ चुके, इन्होंने जो कहा कि प्रश्न पूछा कुछ और था और जवाब कुछ और दिया था तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बाद में आप स्वयं तय करें कि जो प्रश्न पूछा था, उसका हमने पिन-पाइंटेड जवाब दिया है, नंबर वन। नंबर दो, माननीय सदस्य ने बोला कि 01/01/2022 से लेकर 31/12/2024 इस अवधि के बीच में इन्होंने पूछा। इसका जवाब हमने इनको दे दिया था कि 1592 एसीबी के जो केसेज दर्ज हुए, उसमें से सरकार ने 1189 की पीएस दे दी, जो कि इसमें से एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इस 1189 में 1037 को ग्रांटेड परमिशन फॉर प्रोसीक्यूशन। साहब, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। 152 डिनाइ किए गए और 403 पेंडिंग हैं हैड ऑफ डिपार्टमेंट से, क्योंकि गजेटेड जितने भी आफिसर्स हैं, वह डीओपी के थ्रू होता है और नॉन-गजेटेड का डिपार्टमेंट से होता है।

यह मैं बता देता हूं कि हमारे 49 डिपार्टमेंट्स हैं। इसकी पूरी सूची आपके सदन पर मैं

भेज दूंगा कि कौनसे डिपार्टमेंट में कितने-कितने पेंडिंग हैं? ये जो 403 हैं, जब डिपार्टमेंट्स भेजेंगे तब इनकी कार्यवाही की जायेगी, लेकिन अगर आप रेशियो देखते हैं कि 1591 में 1189 को प्रोसीक्यूशन सेंक्शन दिया गया। उसमें से 1037 को ग्रांटेड प्रोसीक्यूशन सेंक्शन हो गया और 152 डिनाइड और 403 जो हैं, मैं सोचता हूं कि ये एक खराब एवरेज नहीं है और डिपार्टमेंट ने इसके अन्दर बहुत मेहनत की है।

इसके अलावा समय जो लगता है, डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समय लगता है। मेन विभाग जो है, उसमें भी समय लगता है। कोर्ट के भी कई जगह स्टे आ जाते हैं। कई एम्प्लोई कांट्रेक्ट बेस के हैं। कई लोगों की डैथ्स भी हो जाती हैं। इसके अन्दर मुख्य मंत्री जी और चीफ सेक्रेट्री जी जो हैं, इनकी रिव्यू लगातार चलती है। मैं माननीय सदस्य को कहूंगा कि हमने जो नंबर एक, आपका जो प्रश्न आपने पूछा, उसका पिन-पाइंट जवाब दिया और आप खुद ही देख लीजिएगा, अध्यक्ष महोदय, एसीबी की जो प्रोग्रेस रही है, मैं सोचता हूं कि उसके अन्दर कोई कमजोरी नहीं रही है। उसके अलावा आप सोचते हैं कि कोई पर्टिकूलर केसेज हैं, जो ड्रेग ऑन कर रहे हैं, उसके बारे में आप सूचना दीजिए तो और पिन-पाइंटेड जांच करके हम आपको दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो केवल इतना-सा पूछा कि तीन महीने के निर्देश आपके सतर्कता आयुक्त ने दिए हुए हैं और दो-दो साल हो गये, इतना ही नहीं 16-16 साल से केस पेंडिंग पड़े हैं। एसीबी ने आपको लिखकर दिया और नहीं हुए। वह इसलिए नहीं हो रहे कि अधिकारी आपस में मिले हुए रहते हैं। मोदी जी का कहना है कि न खाऊंगा, न खाने दूंगा। भ्रष्टाचार की जीरो टोलरेंस के आधार पर हमारी सरकार चल रही है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि जितने भी केस पेंडिंग हैं, इनके बारे में क्या सरकार विचार रखती है कि एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बना दे तीन लोगों की और वह सारे केसेज की समीक्षा करे और समीक्षा करके जो केस पेंडिंग हैं, उनकी अभियोजन स्वीकृति तीन महीने के अन्दर-अन्दर दे दें, जिससे भ्रष्ट अधिकारी कोई बच नहीं पाए, क्योंकि पिछली सरकार में पांच साल में जितना भ्रष्टाचार हुआ, उनके केसेज पेंडिंग हैं। इसकी समीक्षा जब तक नहीं होगी, मेरा कहना है, मेरा सुझाव है कि आप तीन सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाइए। उसमें सारे केसेज जो पेंडिंग हैं, उनकी समीक्षा कीजिए और जो केसेज अनुमति देने लायक हैं, उनके अभियोजन की स्वीकृति दीजिए, जिससे कि उनको दंडित किया जा सके।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। माननीय मंत्री जी। आप बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मोदी जी और माननीय हमारे सीनियर सराफ साहब की मैं सराहना करता हूं कि आपका जो मोटो है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, आपके और मोदी जी के जो मोरल्स हैं, इनकी मैं सराहना करता हूं, नंबर एक। नंबर दो, ये जो 403 केसेज हैं, इनके ऊपर हम तुरंत एक्शन

लेंगे, आपको आश्वासन देता हूं। तीसरी बात, आपने जो बोला इसके अन्दर मंत्रिमंडल कमेटी, ये लीगली पोसिबल नहीं है। कानून अलाऊ नहीं करता इसको। लेकिन चीफ सेक्रेट्री साहब को कह दूंगा उनकी कमेटी थोड़ी मजबूत करके ये जो 403 हैं, फोकस 403 पर हैं, इनको हम टाइम बाउंड करके जल्दी से जल्दी करेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): चीफ सेक्रेट्री की अध्यक्षता में बना दीजिए कमेटी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य बैठिए। आपका हो गया, आप बैठिए। मेरा इसमें एक है माननीय मंत्री जी, कौनसा प्रकरण कितने समय से हैं, जो बहुत पुराने हैं, उन पर सरकार निर्णय करें तो अच्छा रहेगा।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री):: अध्यक्ष महोदय, एजिंग कर लेंगे, उसकी सूची ले आएंगे।

श्री अध्यक्ष: सबसे पुराने पहले हों।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एजिंग करके आपको भी कॉपी दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। डा. ऋतु बनावत।

बयाना शहर में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की योजना

61. डा. ऋतु बनावत (बयाना): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बयाना के बयाना शहर के 10 वार्डों में आंगनबाडी केन्द्र संचालित नहीं हैं ? यदि हां, तो सरकार उक्त वार्डों में कब तक उक्त केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री दिया कुमारी): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र बयाना के बयाना शहर के 35 वार्डों में कुल 25 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। उक्त संचालित 25 आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बयाना शहर के सभी पात्र एवं इच्छुक लाभार्थियों को विभागीय सेवाऐं प्रदान की जा रही हैं। वर्तमान में बयाना शहर के उक्त वार्डों में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने हेतु परीक्षण करवाया जाकर गुणावगुण एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर पारस्परिक प्राथमिकतानुसार निर्णय किया जाता है।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): मेरा उत्तर आ चुका है।

श्री अध्यक्ष: पूछिए।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): मेरा मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि बयाना विधान सभा के बयाना कस्बे में 35 वार्ड हैं और जनसंख्या की दृष्टि से और समुचित व्यवस्था की दृष्टि से भी, क्योंकि आंगनबाड़ी केन्द्रों से बच्चे व महिलाएं जुडे होते हैं, अगर 10 आंगनबाड़ी केन्द्र बयाना कस्बे में और खोले जाएंगे तो ज्यादा अच्छी व्यवस्था रहेगी, ऐसा मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि शहर के सभी वार्डों के पात्र बच्चों को आंगनबाड़ी की समस्त सेवाएं उपलब्ध कराई जा रहीं हैं। आंगनबाड़ी केन्द आबादी के आधार पर खोले जाते हैं। नियमों में वार्ड के अनुसार आंगनबाड़ी खोलने का प्रावधान नहीं है। बयाना विधान सभा क्षेत्र में पिछले बजट में 5 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत कर प्रारम्भ भी हो चुके हैं। यदि ऐसा कुछ आपको लगता है कि किसी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता है, अगर आप बताएं तो वहां पर खोलने का आगे प्रयास करेंगे कि वहां पर खुले।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): धन्यवाद, मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बालमुकुन्दाचार्य। सिर्फ प्रश्न पूछ सकते हैं, हो गया समय।

जयपुर शहर में नीम हकीम क्लिनिकों पर कार्यवाही

62. श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के विभिन्न मोहल्लों में अवैध रूप से नीम हकीम क्लिनिक संचालित हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा विगत एक वर्ष में उक्त क्लिनिकों को बंद करने तथा इनके संचालकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) जी नहीं, अवैध रूप से अपंजीकृत चिकित्सकों (नीम हकीम) क्लिनिक संचालकों की सूचना विभाग के संज्ञान में आने पर राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी के माध्यम से वांछित कार्यवाही की जाती है।

(2) विगत एक वर्ष में जयपुर जिले में अपंजीकृत चिकित्सकों को नोटिस जारी करते हुए उनके द्वारा संचालित क्लिनिकों को बंद करवाया गया।

विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 62, मेरे को जवाब मिल चुका हूं। मैं संतुष्ट हूं।

श्री अध्यक्ष: जल्दी पूछिए।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): निवेदन करना चाहूंगा.....

Ans/rtm 12.00 1g 06.02.2025

श्री अध्यक्ष: बैठ जाओ, प्रश्न काल समाप्त।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न....

श्री अध्यक्ष: घड़ी के अनुसार चल रहे हैं। ...(व्यवधान)... नहीं, कल वापस आ जाइये।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री थावर चन्द, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धरियावद में यूरिया खाद की कालाबाजारी से किसानों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर लाइट एवं साउंड शो दो माह से बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री गणेश घोगरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 की छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) डॉ. प्रियंका चौधरी, सदस्य की ओर से बाड़मेर की नगर परिषद सीमा का विस्तार नहीं किये जाने से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री डूंगरराम गेदर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के किसानों को खातेदारी अधिकार दिये जाने के संबंध में।

(6) श्री रफीक खान, सदस्य की ओर से कानोता थाना क्षेत्र में भटेसरी गांव के पास महिला का जला हुआ शव मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री उमेश मीणा, सदस्य की ओर से डूंगरपुर ज़िले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र साबला में चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से बाडमेर निवासी भारतीय सेना में कोर्स कंट्री रेस में गोल्ड मेडल विजेता स्व. दाऊ प्रजापत को शहीद का दर्जा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के कस्बा छापर में डी.एल.सी. रेट को कम किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(10) श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में टाइगर्स की संदिग्ध मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) डॉ. सुभाष गर्ग, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के शहरी क्षेत्र में जल भराव की रोकथाम एवं सी.एफ.सी.डी. परियोजना का कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री सुरेश मोदी एवं 30 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश के नवगठित तीन संभाग एवं 09 ज़िलों को निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री हरिमोहन शर्मा, डॉ. सुभाष गर्ग, श्री सुरेश मोदी एवं श्री रामकेश को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्षः मैं पूरा कर लूं, उसके बाद।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्षः मेरी पूरी व्यवस्था हो जाए उसके बाद। ...(व्यवधान)... मैं बोल लूं उसके बाद आप। मेरा सभी पक्षों से है, जब मैं खड़ा हूं ना बोलें। एक मिनट में कोई तूफान नहीं आने वाला।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री विद्याधर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की ग्राम पंचायत सूण्डो का बास के पंचायत भवन में कार्य संचालन प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी द्वारा मौका काबिज भूमि महाविद्यालय के नाम दर्ज किये जाने के संबंध में।

(3) श्री आदू राम मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौहटन की अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित बाखासर के रण क्षेत्र में नमक उद्योग स्थापित किये जाने के संबंध में।

(4) श्री हंसराज मीना, सदस्य की ओर से करौली ज़िले के विधान सभा क्षेत्र सपोटरा स्थित माता कैलादेवी एवं बीजासनी मंदिर क्षेत्र का कॉरिडोर बनाये जाने के संबंध में।

(5) श्री छगनसिंह राजपुरोहित, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर में क्षतिग्रस्त सड़कों तथा पुलों का नवीनीकरण करवाये जाने के संबंध में।

(6) डॉ. प्रियंका चौधरी, सदस्य की ओर से बाड़मेर ज़िले की पेयजल समस्या का शीघ्र समाधान किये जाने के संबंध में।

(7) श्री डूंगरराम गेदर, सदस्य की ओर से सूरतगढ़ को जिला बनाये जाने के संबंध में।

(8) श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र करणपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑफलाईन आवेदन भी स्वीकार किए जाने के संबंध में।

(9) श्री कालूराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग में चिकित्सालयों का क्रमोन्नयन किये जाने के संबंध में।

(10) श्री संजीव कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भादरा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोगीवाला का समन्वयन निरस्त किये जाने के संबंध में।

(11) श्री महेन्द्र पाल मीना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के ग्राम मूंडला स्थित अम्बेडकर पीठ की गवर्निंग काउंसिल का गठन कर शैक्षिक पदों की स्वीकृति दिलाये जाने के संबंध में।

(12) श्री उमेश मीणा, सदस्य की ओर से डूंगरपुर जिले के सोम कमला अंबा बांध में डिसिल्टिंग की निविदा प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं की जांच करवाये जाने के संबंध में।

(13) श्री रफीक खान, सदस्य की ओर से जयपुर शहर में यातायात पुलिस के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के संबंध में।

(14) श्री उदयलाल भडाणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र माण्डल में उद्योगों हेतु आवंटित की गई भूमि का अन्य उपयोग किये जाने के संबंध में।

(15) श्री गोपाल लाल शर्मा, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा डिपो द्वारा कोरोना काल में बन्द की गई रोडवेज सेवाओं को बहाल किये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 06.02.2025 को शून्यकाल में बोलने हेतु 37 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गई, जो निम्नानुसार हैं:-

क्रम संख्या	पर्ची संख्या	मा.सदस्य का नाम	विषय
1.	12	श्रीरामस्वरूप लाम्बा	नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र के ग्राम दातडा में स्थित ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड दातडा में व्यवस्थापक द्वारा वेशकों/काश्तकारों के सावधी जमा योजना (एफडीआर) की राशि का गबन किए जाने के संबंध में।
2.	13	श्री बाबूसिंह राठौड़	जनता जल योजना में कार्यरत सहायक पम्प चालकों की विभिन्न लम्बित मांगों का निराकरण करने के सम्बन्ध में।
3.	10	श्री शंकर सिंह रावत	ब्यावर विधानस भा क्षेत्र के दो बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अन्य विद्यालय में मर्ज / समन्वय करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
4.	4	श्री राजेन्द्र	महवा विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे सर्वे में पात्र व्यक्तियों को लाभ देने के संबंध में।

अब बोलिये, माननीय संसदीय मंत्री जी। माननीय संसदीय मंत्री जी। हो गया, चलिए ठीक है। अब श्री हरिमोहन शर्मा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में टाइगर्स की संदिग्ध मृत्यु

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करूं कि आप मेरे अधिकारों की रक्षा करने में रुचि रखते हैं और मुझे अवसर देते हैं।

श्री अध्यक्ष: आपका ही नहीं, सभी के अधिकारों की रक्षा करता हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ अभयारण्य के लिए 2022-23 व 2023-24 के लिए राज्य सरकार ने उस अभयारण्य के लिए लगभग 09 करोड़ रूपये खर्च

किए लेकिन इसके पश्चात वहां ऐसी व्यवस्था हो गई..

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, खड़े-खड़े नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): जिसके कारण वहां आज से दो महीने पहले, जो बाघिन थी उसकी मौत हो गयी और कंकाल का पता भी विभाग को 12 दिन बाद लगा। उसके दो बच्चे हैं जो अभी जीवित है। उसमें भी एक बात है, उसने तीन बच्चे दिए थे, फॉरेस्ट विभाग ने तीनों का प्रदर्शन किया था लेकिन उसमें से एक बच्चा गायब है, जिसका अपने को आज तक पता नहीं है। तो 12 दिन तक उस कंकाल का, बाघिन का पता नहीं लगना अपनी इन्एफिशिएंसी है, अधिकारियों की लापरवाही कि टाइगर प्रोजेक्ट में 12 दिन तक कोई टाइगर गायब हो और अधिकारियों को पता नहीं लगे। आपने यहां से जांच अधिकारी भेजे, मुझे इस बात का अफसोस कि जांच अधिकारी जिस दिन पहले टाइम जांच करने गये तो वहां गये ही नहीं जहां बाघिन मरी थी, रास्ते से ही वापस आ गये कि जंगल में कौन जाएगा। बाघिन मर गई और बाघिन के साथ उसका बच्चा लापता है, जिसका पता नहीं है। इसके बाद आर वी टी-4 की डैथ हो गई। अभी कुछ दिनों पहले ही आर वी टी-4 जंगल में मारा गया। विभाग का यह कहना है कि दो टाइगर के बीच फ्री फाइट हो गई, वह फ्री फाइट के कारण मर गया। आर वी टी-4 के जब ताला लगा हुआ था, विभाग को पता था कि अकेला है, कहां पर है, दोनों टाइगर की क्या पोजिशन है, यह कैसे लड़ेगे, तो टाइगर का आपस में जब एक दूसरे से कंस्लटेशन होने का था उस समय विभाग को यह पता था लेकिन विभाग ने कोई प्रिक्योशन नहीं लिया।

VPS-RTM-06.02.2025-12.10-1h

टाइगर मरने के बाद जो उन्होंने जांच करके यह बताया कि दो टाइगरों के बीच में फ्री-फाइट है। सर, अगर फी-फाइट है तो दूसरे टाइगर को भी चोटें आयी होंगी। फ्री-फाइट होने का मतलब यह है कि दूसरे टाइगर को भी चोट आयी है, तो उस टाइगर का आज तक पता नहीं है कि उसके बदन पर कहां चोट आयी? इन दोनों का पोस्टमार्टम होने के बाद भी, टाइग्रेस का भी और टाइगर का भी, आज तक किसी भी प्रकार की जांच रिपोर्ट न तो विभाग ने किसी को प्रकाशित की है और न ही जानकारी दी है।

इन सब बातों के पीछे मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि हमारी लाइफ लाइन है वह टाइगर प्रोजेक्ट बूंदी की, टूरिज्म के पाइंट ऑफ व्यू से, विकास के पाइंट ऑफ व्यू से जिस पकार से सवाईमाधोपुर में टाइगरों के लिए आपने पर्याप्त खाद्य व्यवस्था कर रखी है जंगली जानवरों की लेकिन रामगढ़ अभयारण्य में मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रोपर व्यवस्था दूसरे अन्य जंगली जानवरों की वहां नहीं होने के कारण यह परिस्थिति पैदा होती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तीन दिन पहले चार लेपर्ड दो महीने के अंतराल पर सड़क पर मर गये।

श्री अध्यक्षः डॉ. सुभाष गर्ग।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): नैनवा वाली सड़क पर मर गये और बूंदी वाली सड़क पर मर गये।

श्री अध्यक्ष: आपको दो की जगह पर तीन मिनट हो गये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): दो साल में दस चीता वहां पर मर गये, तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है कि मेहरबानी करके इस टाइगर प्रोजेक्ट को ठीक ढंग से चलाये, दोषी अधिकारी जिनको आप मानते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप विराजये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): उनके लिए प्रोपर खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करें और एक टाइग्रेस जरूर भेजें। दो टाइगरों के बीच में एक टाइग्रेस का रहना, यह भी एक चिंता का विषय है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। सदन के टाइगर टाइगरों की चिंता कर रहे हैं, यह अच्छी बात है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप लापरवाही करने वालों के खिलाफ काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। डॉ. सुभाष गर्ग, आप शुरू करिये। आप शुरू करिये। आपका अंकित।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

भरतपुर के शहरी क्षेत्र में जल भराव एवं सी.एफ.सी.डी. परियोजना का अपूर्ण कार्य

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मुझे भरतपुर शहर की वर्षों से चली आ रही जल भराव की समस्या और ड्रेनेज सिस्टम पर बोलने पर समय दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भरतपुर शहर की सबसे बड़ी जल भराव की समस्या जो वर्षों से, पिछले पचास वर्षों से भरतपुर के नागरिक सहन करते आ रहे थे, मैं माननीय पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी को धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ ही इस यू.डी.एच. डिपार्टमेंट को भी कि बड़ी मुश्किल से एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करके जिसमें आई.आई.टी. की एक एक्सपर्ट्स टीम, अभियंताओं की एक एक्सपर्ट्स टीम ने एक योजना बनाई जो लगभग 374 करोड़ रुपये की थी और जो योजना दो फेज में पूरी होनी थी। पहला फेज था 282 करोड़ का और दूसरा फेज था 92 करोड़ का। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि इस फर्स्ट फेज में 4.8 किलोमीटर की पक्की ड्रेन बननी थी और सेकण्ड फेज में 2.78 किलोमीटर की एक पक्की ड्रेन बननी थी जिसमें लगभग फर्स्ट फेज में 90 किलोमीटर पक्की नालियों का निर्माण होना था और सेकण्ड फेज में 190 किलोमीटर की लम्बी लाइनों का निर्माण होना था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की

मिलीभगत से और कुछ भू-माफिया मिलकर इस ड्रेनेज प्रोजेक्ट को रोकना चाह रहे हैं। आज भी काम जो कि 23 महीनों में ही पूरा हो जाना चाहिए था, आज भी उसको बढ़ाकर जुलाई, 2025 कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि आप इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच करायें। आई.आई.टी. के माध्यम से और दुबारा अभी एक लास्ट मीटिंग और करवाइये एम.एन.आई.टी. से और यह कहा गया एम.एन.आई.टी. की टीम के समक्ष कि हमको ऊपर से यह निर्देश हैं इसलिए उस ड्रेन को ओपन रखा जाये।

महोदय, वहां पर पूरी डेन्स पापुलेशन रहती है। ओपन रखने से आये दिन सुसाइड पाइंट बनेगा। सुजान गंगा हमारी नहर है, उसमें ऑलरेडी सुसाइड पाइंट बना हुआ है, तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि जिस तरह से यह प्रोजेक्ट तकनीकी अभियंताओं ने स्वीकृत किया, आई.आई.टी. की टीम ने स्वीकृत करके किया है तो ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से इस ड्रेनेज प्रोजेक्ट के साथ छेड़-छाड़ की जा रही है?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। हो गया।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): वहां का जिला प्रशासन उसको ओपन रखने के लिए आमादा है जबकि वहां के स्थानीय नागरिकों द्वारा आंदोलन भी किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि आप बड़े ईमानदार, बहुत ही मजबूत आदमी हैं, आप इस पूरे प्रकरण की जांच करायें और किन जिला प्रशासन के अधिकारियों की, भू-माफियाओं की, अतिक्रमण करने वालों की मिलीभगत है, उसकी जांच करायें।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। मैं अगला नाम पुकार रहा हूं।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मैं अगला नाम पुकार रहा हूं, उस पर कल मैंने जो व्यवस्था दी थी कि दो माननीय सदस्य जिनके नाम मैंने लिये हैं, श्री सुरेश मोदी और श्री रामकेश, वे दो-दो मिनट में अपने विचार रखेंगे और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री इसका जवाब देंगे। श्री सुरेश मोदी।

प्रदेश के नवगठित तीन सम्भागों एवं नौ जिलों की निरस्ती

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने सम्भाग और जिलों का दर्जा समाप्त करके वहां की जनता के साथ अन्याय और अत्याचार किया है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और क्षेत्र के विकास को खतम करने का काम किया है। आपने मापदंडों पर नहीं, आपने राजनीतिक दुर्भावना से फैसले लिये हैं। शेखावाटी क्षेत्र में तीनों सांसद आपके बी.जे.पी. के हारे, 21 में से 14 आपके विधायक हारे और यह हार आप पचा नहीं पाये इसीलिए आपने सम्भाग और जिले को खतम करने का फैसला किया।

नीम का थाना को जिला बनाने की मांग 1955 से चलती आ रही है। कई आंदोलन हुए, भूख हड़ताल हुई, पैदल यात्रा हुई और इसके बाद पिछली रामलुभाया कमेटी ने बहुत बारीकी

से उसका अध्ययन करके उसको सम्भाग और जिले का दर्जा दिया। जिला बनने के बाद और हटाये जाने तक चारों विधान सभा क्षेत्र में किसी तरह का कोई विरोध जनता का नहीं था बल्कि आपके खंडेला से आने वाले माननीय सदस्य जो कि आपकी ही पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने पिछले सत्र में अपनी 12 पंचायतें और नीम का थाना जिले में शामिल करने की मांग की थी।

आप कहीं पर तो जनसंख्या का आधार लेते हैं, कहीं पर आप क्षेत्रफल का आधार लेते हो, कहीं पर आप दूरी का आधार लेते हो। कहीं पर आप दूसरे राज्य की सीमा का आधार लेते हो और कहीं पर आप राष्ट्रीय औसत की बात करने लग जाते हो, वह सारे मापदंड आप भूल जाते हो। आपने जो-जो फैसले किये हटाने के वे अपने पिक एंड चूज के बेसिस पर किये। डीग की बात करते वक्त तो आप यह कहते हो कि, साहब, दूसरे राज्य की सीमा लगती है तो नीम का थाना की बात करते वक्त आप यह कैसे भूल जाते हो कि हरियाणा राज्य की 60 से 70 किलोमीटर की सीमा नीम का थाना जिले के साथ में लगती है। उसका आप जिक्र नहीं करते हो। हकीकत यह है कि पंवार कमेटी ने सभी जो नये जिले बने थे, उनका दौरा किया था लेकिन नीम का थाना जिले का दौरा उन्होंने नहीं किया क्योंकि वे पूर्वाग्रह से ग्रसित थे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सरकार की तरफ से उनको यह आदेश था कि नीम का थाना जिले को हटाया जाये। आप राष्ट्रीय औसत की बात करते हो। मध्य प्रदेश राजस्थान से छोटा प्रदेश है, वहां की जनसंख्या कम है, वहां का क्षेत्रफल कम है और वहां पर 53 जिले हैं। हरियाणा की बात करें तो आठवां हिस्सा जमीन है राजस्थान से, एक तिहाई यहां से जनसंख्या है और वहां पर आपके 22 जिले हैं।

श्री अध्यक्षः श्री रामकेश। आप बैठिये।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): वहां पर 22 जिले हैं और एक कमेटी का गठन किया गया है नये जिले बनाने के लिए। पांच और नये जिले बनाने की तैयारी चल रही है।

श्री अध्यक्षः आप बैठये। हो गया। विराजिये।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि यह जो आपने गलत काम किया है इस काम को आप वापस ले और जो जिले आपने हटाये हैं, जो सम्भाग हटाये हैं, उनको वापस घोषित करें और वहां की जनता को राहत दें।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः हो गया। विराजिये। हो गया, आपका विषय आ गया। श्री रामकेश।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने 17 नये जिलों का गठन किया था, उसमें से नौ जिले और तीन सम्भागों को भाजपा की सरकार ने राजनीतिक द्वेषता से निरस्त कर दिया।

श्री अध्यक्षः बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री रामकेश (गंगापुर): जैसा कि अभी सुरेशजी मोदी साहब यह कह रहे थे कि भाजपा की

सरकार ने इन जिलों को खतम करते समय जो मापदंड देखने चाहिए थे उन मापदंडों का कोई परीक्षण नहीं किया, उसके लिए कोई कमेटी गठित नहीं की और केवल ऐसे राजनीतिक व्यक्तियों की कमेटी गठित की है जो पहले से बिलकुल यह तय कर रखा था कि इन जिलों को खतम करना है और जिनकी अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की, वे भी भाजपा के सदस्य माननीय पंवार साहब रहे हैं और उन्होंने राजनीतिक द्वेषता से यह कार्यवाही की है।

जैसा कि अभी मोदीजी ने कहा है कि कहीं पर आप दूरी का मापदंड लेते हैं, कहीं पर आप जनसंख्या का मापदंड बताते हैं और अखबारों के माध्यम से हमें जो जानकारी मिल रही है, उसमें आपने कहीं दूरी के लिए तो मैं आपको दूरी के लिए कहना चाहता हूं कि डीग की दूरी भरतपुर से मात्र 38 किलोमीटर ही है और हमारे सांचोर में 140 किलोमीटर की दूरी है। आपने सांचोर को निरस्त कर दिया और डीग को रख लिया। अनूपगढ़, इसी तरीके से नीम का थाना, केकड़ी, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, गंगापुर सिटी, दूदू, शाहपुरा, इन सारे जिलों में आपने अलग-अलग मापदंड तय किये हैं।

ssy/rtm/06.02.2025/12.20/1j

यह मापदंड किसी भी रूप में ठीक नहीं कहे जा सकते। इन मापदंडों के पीछे आपकी राजनीतिक दुर्भावना है। उसके कारण यह जिले खत्म किये हैं। मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं। राजस्थान में 7 जिले बने और सातों जिलों में बारां, धौलपुर, हनुमानगढ़, दौसा, राजसमंद, करौली और प्रतापगढ़ थे। उस समय जब करौली को जिला बनाया था, उस समय यह आपत्तियां उठी थी। कुम्भट कमेटी का गठन हुआ। कुम्भट कमेटी ने यह तय किया था कि जिले की जो जनसंख्या है वह कम से कम 10 लाख होनी चाहिए। उस 10 लाख का मापदंड यह सारे के सारे जिले पूरे कर रहे हैं। फिर भी आपने पिक एंड चूज करके इन जिलों को खत्म किया है। गंगापुर जिला जो पूरे मापदंड तय करता था, आपने जान-बूझ करके उसको खत्म किया। गंगापुर के लोग बहुत पहले से गंगापुर को जिला बनाने की मांग करते हुए आ रहे थे, आपने उसको अनसुनी किया। गंगापुर के लोगों के साथ जो ज्यादती की है, कुठाराघात किया है, समय आने पर इसका जरूर आपको जवाब मिलेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। बैठिये, आपके मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों माननीय सदस्यों ने राजनीतिक दुर्भावना से जिले रखने या खत्म करने की बात कही है। यह भी कहा है कि पैरामीटर्स नहीं लागू हो रहे तो क्या हो गया, जिलों को तो रखना चाहिए था।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): पैरामीटर्स नहीं लागू हो रहे, यह नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष: सुनिये। आपका नंबर आये तब आप भी बोलना।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यूं मान लो, कोई बात नहीं। हां, पैरामीटर्स लागू होते हैं फिर भी कर दिया।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): यह नहीं कहा है हमने।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कोई बात नहीं। जो आपने कहा है, मैं मेरिट पर इसकी बात तथ्यात्मक रूप से कहूं उससे पहले दोनों माननीय विधायक जो बोल रहे हैं, दोनों की रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लगी। उस रिट याचिका में स्वयं सुरेश मोदी जी पार्टी हैं, जिन्होंने खुद ने लगाई। उसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो प्रारंभिक कमेंट्स किये हैं वह आपके सामने रखना चाहता हूं, "after going through the petition we find that the petitioner/s have not sought any information from the authority concerned under the Right to Information Act 2005, or otherwise to seek whether the decision to do abolish 9 districts was based on any matter or not…" यह रिमार्क्स हैं आपकी पिटीशन पर, मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी है हाई कोर्ट की, "straightaway, the petition has been filed before this Hon'ble Court making a serious allegation. In this petition, Learned Advocate General is directed to file a reply."

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): जवाब दो ना आप अपना।

श्री अध्यक्ष: सुन लीजिये। यह बाद में बताना। आप सुन लीजिये। आपने जो बोला वह सही था कि गलत था, उत्तर तो आपको मंत्री जी का सुनना होगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सुरेश मोदी जी, अब आप सुनना नहीं चाहते हैं। मैं तो फिर भी नहीं खोलना चाहता था, अब सुरेश मोदी जी की रिट याचिका, "in view of the submission of the Learned Counsel for the party that another Public Interest Litigation (PIL) involving identical case; notices have been issued. The reply also filed by the respondent so an so…."आपके केस में इसी को बेस बनाया है।

अब दूसरा विषय, पहला पाइंट अब दूसरा, मैं आपसे बहुत पिनपाइंट निवेदन करुंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): सीधी बात करो ना।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कानून क्या है? कोई भी जिला बनाने और नहीं बनाने का कानून क्या है?

श्री अध्यक्ष: सुनिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी बार टोकने के बावजूद भी माननीय सदस्य अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं तो कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष: आप अपनी बात रखिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का सैक्शन 15 और 16 है, उसमें जिले बनाने या नहीं बनाने के सम्बन्ध में है। कृपया ध्यान लगाकर सुन लीजिये। क्षेत्रों, डिविजनों आदि के निर्माण, समाप्ति अथवा परिवर्तन करने की शक्ति, राज्य सरकार नये जिले, उपखंड, तहसीलें, उप तहसीलों और गांवों का निर्माण कर सकती है अथवा वर्तमान जिले, उपखंडों, तहसीलों और उप तहसीलों को समाप्त कर सकेगी। यह absolutely right है गवर्नमेंट को, पहला।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): यह क्या बात हुई …(व्यवधान)…

श्री अध्यक्षः सुनने के बाद बोलना। एक बार सुन लीजिये। माननीय सदस्य, आपका भाषण भी सुना गया है। इनका भी सुनिये ...(व्यवधान)... आप कंटीन्यू रखिये।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): गला काटोगे आप ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरा निवेदन है कि हमारा गला काटा, किसने काटा, इधर आकर बैठे, पता लगा कि नहीं लगा? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः बैठिये। बिना अनुमति के जो बोल रहा है वह अंकित नहीं होगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): पहला, सरकार को पूर्ण अधिकार है कि किसी जिले को बनाये या किसी जिले को समाप्त करे।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): 000

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): दूसरा, यह आरोप लगाया गया कि राजनीतिक क्षेत्र से प्रभावित किसी व्यक्ति की कमेटी बना दी गई। ध्यान से सुनें, मैं सदन को ध्यान दिलाना चाहता हूं, कहने से पहले विचार करना पड़ता है, बोलने से पहले पढ़ना पड़ता है, बोलने से पहले रिकार्ड देखना पड़ता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1956 से लगाकर जब हमारा राजस्थान बना तो 25 जिले थे। सबसे पहला जिला 1982 में धौलपुर बना इनके कार्यकाल के दौरान। उसके बाद में 10 अप्रैल, 1991 को बारां बना। 10 अप्रैल, 1991 को दौसा बना। 10 अप्रैल, 1991 को राजसमंद बना। 12 जुलाई, 1994 को हनुमानगढ़ बना। 19 जुलाई, 1997 को करौली बना। 26 जनवरी, 2008 को प्रतापगढ़ बना। यह सारे के सारे जो जिले बने हैं वह सारे ही भाजपा के कार्यकाल में बने हैं। अपने कार्यकाल में एक भी जिला आपने नहीं बनाया।

तीसरा, जिलों के सम्बन्ध में 3 कमेटियां आज तक बनी हैं।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): 000

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री अध्यक्षः आप बोलिये मत, उत्तर आने दीजिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): पहली कमेटी बनी कुम्भट कमेटी 1997 में। जिसकी सिफारिश करौली जिले की हुई। दूसरी कमेटी डॉ. परमेशचन्द्र, सीनियर आईएएस ऑफिसर की और तीसरी कमेटी बनी रामलुभाया जी की और चौथी कमेटी अभी बनी, जिसका आप आरोप लगा रहे हैं। यह जो डॉ. परमेशचन्द्र जी की कमेटी बनी थी और अभी जो कमेटी बनी थी, दोनों की हूबहू एक ही रिपोर्ट है। सरकार ने ना केवल इस कमेटी को आधार बनाया, डॉ. परमेशचन्द्र जी की कमेटी जो उस समय बनी थी, उस कमेटी को भी आधार बनाया है। उसके खिलाफ आपका एलिगेशन नहीं है। उस कमेटी को as it is adapt किया गया है। यह मैं इन जिलों के बारे में कहना चाहता हूं। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र की बात है वह पूर्ण रूप से गलत है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वह कमेटी कब बनी थी, यह बता दीजिये? यह

कमेटी कब बनी थी?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नाम बताया है ना सभी का ही। परमेशचन्द्र कमेटी, रामलुभाया कमेटी और कुम्भट कमेटी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह कमेटी कब बनी थी? कौनसे सन् में बनी थी? वह बता दें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सब बता रहा हूं। सुनोगे तो पता लगेगा। जमीन खिसक रही है नीचे से। बीच में बोल रहे हो।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिये, आप बोलिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जिलों के गठन हेतु निर्धारित ...(व्यवधान)...

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, एक बार मंत्री जी का पूरा स्टेटमेंट हो जाये उसके बाद प्रश्न पूछिये। बीच में कैसे कूद रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, बैठो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नये जिलों के गठन हेतु निर्धारित मापदंड मुख्य-मुख्य रूप से, भौगोलिक परिस्थितियां, भौगोलिक सीमाएं, भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, प्रशासनिक संरचना, जन भावनाएं, सांस्कृतिक सामंजस्य, यथा संभव पूरी पंचायत समिति या तहसील का हस्तांतरण, क्षेत्र का पिछड़ापन, वर्तमान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं, जिला मुख्यालयों से दूरी, तहसील से दूरी, प्रभावी कानून व्यवस्था और त्वरित अभिप्रयोग, यह मोटे-मोटे तौर पर आधारभूत संरचनाएं हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप राष्ट्रीय स्तर का औसत देखेंगे और फिर राजस्थान का या पड़ोसी जिलों का जैसा इन्होंने कहा मध्य प्रदेश का, एक-एक का जवाब दूंगा। राष्ट्रीय स्तर का जो औसत है।

श्री अध्यक्ष: इनको संक्षेप में दीजिये जवाब।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): राष्ट्रीय स्तर का जो औसत है वह 781 जिले हैं। औसत जनसंख्या 23 लाख है। औसत क्षेत्रफल 4212 है। औसत तहसील 7.2 हैं। उपखंड 9.2 हैं और गांवों की संख्या औसत 900 है। हमारे यहां इन औसत जिलों के अनुसार जिन-जिन की संख्या पाई गयी है उसका विस्तृत विवरण, चूंकि समय आपने कम दिया है, पूरी रिपोर्ट मेरे पास है।

तीसरा जो मैं सबसे महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं वह यह है कि इन जिलों के गठन में और इन जिलों के ...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): 000

श्री अध्यक्ष: उत्तर तो सुनना पड़ेगा ना। आप संक्षेप में दीजिये ...(व्यवधान)... 2 मिनट नहीं, 4-4 मिनट बोले हैं। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी ...(व्यवधान)...

spp/rtm/06.02.2025/12:30/1k

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपको सुनना ही पड़ेगा। सोते सांप को छेड़ा ही क्यों? सुनना ही पड़ेगा। ...(व्यवधान)..

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सवाल पूछते हैं तो उत्तर सुनने की भी हिम्मत रखो हरिमोहन जी। ..(व्यवधान)..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास किया गया। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: आप संक्षेप में दीजिये। ..(व्यवधान)..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरा निवेदन यह है कि जिलों के गठन में अगर मेरे साथी इतने ही सही हैं तो पूरे कार्यकाल में, 50 साल हुए होंगे या 47 साल हुए होंगे, जो भी कार्यकाल रहा, एक के सिवाय दूसरा जिला नहीं बनाया। जिले नहीं बनाने वाले हमको शिक्षा दे रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप इसको पॉलिटिकल ले जा रहे हो। ..(व्यवधान)..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा।

श्री अध्यक्ष: अब आप दो मिनट में कंक्लूड करें। ..(व्यवधान).. यह दो मिनट में पूरा कर रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सर्वप्रथम कांग्रेस की नीयत को जानना बहुत जरूरी होगा। जाते-जाते चुनावी दांव खेला। यह दांव ऐसा उल्टा पड़ गया। इनको जनता ने हराकर उधर बैठा दिया।..(व्यवधान).. नवम्बर, 1956 में जैसा मैंने अभी बताया तीन तो नोटिफाइड थे और बाकी 20 जिले थे, क्यों नहीं वह जानना जरूरी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जानना जरूरी है एक तहसील खोलते हैं, एक हॉस्पिटल खोलते हैं या स्कूल भी खोलते हैं तो उसमें भी पूरी व्यवस्था देखते हैं। व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? एक विचार करो, एक जिले को बनाने में 800 से 1000 करोड़ रुपये का खर्चा होता है। प्रशासनिक, पुलिस, न्याय, समग्र विकास, विभागों की भूमि, संसाधन, मजरे, गांवों तक करना पड़ता है। इसकी कोई व्यवस्था नहीं की।

इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इनको पता होता, एक उदाहरण मध्य प्रदेश का दिया, जिसका जवाब देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश का मैं बताना चाहूंगा क्योंकि भारत में राज्यों के पुनर्गठन के बाद एक साथ सबसे ज्यादा जिलों का पुनर्गठन आठ बार मध्य प्रदेश ने 1998 में किया, जिससे कांग्रेस सरकार रिपीट हो गयी। उसकी नकल की और नकल ....(भारी व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: आपने ही कहा उत्तर दो। उत्तर मिल रहा है न। ..(व्यवधान)..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मध्य प्रदेश की सरकार थी और इनका घाटा...

..(व्यवधान)..

सदन कूप में

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

श्री अध्यक्षः इधर नहीं आयें। ..(व्यवधान)..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): परंतु राजस्थान ने 2023 की न तो कोई पृष्ठभूमि थी, न कोई नीयत थी। ..(व्यवधान)..

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा अपनी सीटों पर खड़े होकर नारे।)

श्री अध्यक्षः बैठिए, आपके मंत्री बोल रहे हैं। ..(व्यवधान).. आपके मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): पुनर्गठन की आवश्यकता थी। ..(व्यवधान)..हमारी सरकार रिपीट हो जाए, ऐसी अपेक्षा से की गयी। वह अब जनता ने जवाब दे दिया। ..(व्यवधान)..

और आखिर में सुनो, जिलों को रखा गया, उसका ठोस आधार भी उल्लेख नहीं है। राजस्थान भौगोलिक, क्षेत्रफल, परिस्थिति, जनसंख्या, मात्रा, गुणवत्ता आदि को आधार बनायें। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः अब समाप्त करिए। ..(व्यवधान)..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जहां तक नये संभागों के गठन की समाप्ति की बात है, दुर्गति से.. ..(व्यवधान).. इन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार ने पूर्ण रूप से पारदर्शिता से एवं निष्पक्षता से सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर किया है। ..(व्यवधान).. यह समझना पड़ेगा आपको। ..(व्यवधान)..

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

श्री अध्यक्षः आप सब अपनी-अपनी सीटों पर जाइए। ..(व्यवधान).. मोदीजी, आप अपनी सीट पर जाइए। ..(व्यवधान).. माननीय सुरेश जी मोदी, अपनी सीट पर जाइए। You go to your seat. यह बोलेंगे, आप अपनी सीट पर जाइए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जिलों का यह बहुत गम्भीर विषय है। दोनों माननीय सदस्यों ने तथ्यों के साथ बताया। सरकार जवाब दे रही है। आप विधि मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं। आपने एक भी रिकार्ड बताया क्या कि कौनसे जिले को किस बेस पर रखा और कौनसे जिले को किस बेस पर निरस्त किया? हम यह भाषण सुनने के लिये नहीं आए हैं। यह भाषण तो सारे आप प्रेस में देना। एक-एक तथ्य बता दीजिए। ..(व्यवधान).. तथ्यों के साथ बताइए न। आप तथ्यों के साथ बात रखिए।

श्री अध्यक्षः चर्चा समाप्त हुई। ..(व्यवधान)..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपने जिनको निरस्त किया, वह बताइए।

श्री अध्यक्षः स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त। ..(व्यवधान).. प्रक्रिया के नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाएं। श्री विद्याधर सिंह।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

अपनी-अपनी सीटों पर जाइए। ..(व्यवधान).. सब माननीय सदस्य अपनी सीटों पर जाइए।

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाएं। श्री विद्याधर सिंह। (बोलने के लिये खड़े नहीं हुए।) ..(व्यवधान).. सदन की कार्यवाही तो चलाएं।

(कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा 10 लाख का एवरेज है। एक जिले में 10 लाख की जनसंख्या का एवरेज है। ..(व्यवधान).. 10 लाख जनसंख्या एवरेज है।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य दिस साइड, अपने वेल में रहिए। इधर नहीं आयें। ..(व्यवधान)..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कुछ नहीं है, ठन-ठन गोपाल है। आपके खिलाफ यह रहा हाई कोर्ट का। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इधर नहीं आयें। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, इधर नहीं।

सदन की कार्यवाही 2.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.36 बजे 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

jyg/rtm/06.02.25/14.00/2c

(समय: 14.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष,पदासीन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय विपक्ष के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे अपनी सीटों पर जायें ताकि सदन की कार्यवाही हो सके। पधारो। ...(व्यवधान)... आपका आ गया, आपके दो-दो लोग बोल लिये। आपकी बात दोनों की आ गयी, अब किसी को कोई अनुमति नहीं है। श्री विद्याधर सिंह। ...(व्यवधान)... आप बैठिये। विद्याधर सिंह हैं? नहीं हैं। ...(व्यवधान)...

(माननीय सदस्य के सदन कूप में होने के कारण नहीं बोला गया।)

श्रीमती शोभा चौहान। बोलिये। ...(व्यवधान)...

जब कह दिया, आपके कहने से दोनों लोगों को मैंने बोलने की अनुमति दी। मंत्री का जवाब हो गया, अब क्या बचा है? नो। ...(व्यवधान)... ये तानाशाही जो है, वो किसकी है? मैं दबाव में नहीं आऊंगा। मैं दबाव में नहीं आऊंगा। आप अपनी सीटों पर जायें। मैं आपसे पुन: आग्रह कर रहा हूं। निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं। नेता प्रतिपक्ष बाद में, पहले कार्यवाही शुरू हो। ...(व्यवधान)... कार्यवाही शुरू हो, नो। नो, इस मुद्दे पर नहीं। इस मुद्दे पर

कुछ नहीं होगा। ...(व्यवधान)...

श्रीमती शोभा चौहान। बोलिये।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सोजत राजकीय महाविद्यालय की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करना

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने विधान सभा के नियम 295 के तहत सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आज कार्यवाही में कोई भाग नहीं ले पायेगा। इधर के लोग भी बोलेंगे। ...(व्यवधान)... पहले सब सीटों पर जाओ। ...(व्यवधान)... पहले सीटों पर जाओ। वैल में खड़े होकर बोलने की किसी को अनुमति नहीं है। ...(व्यवधान)... यह जीरो ऑवर पूरा करवा लूं। ...(व्यवधान)... अब शुरू हो गया। आपको बोलने की अनुमति दूंगा, एक बार बैठिये। ...(व्यवधान)... एक बार बैठिये। मैं इसको पूर्ण करके आपको बुलवाऊंगा। मैं आपको दो मिनट बुलवाऊंगा। ...(व्यवधान)... पहले इसको पूरा कर लें, दस लोग हैं।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, गत विधान सभा सत्र में भी मेरे द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था कि राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी, जिला-पाली वर्ष 2006-07 में स्वीकृत हुआ था। यह भवन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सोजत शहर के खेल मैदान की भूमि पर बनाया गया है और विद्यालय को इतनी ही जमीन खेल मैदान हेतु श्री शांतिलाल मेहता, चैरिटेबल ट्रस्ट, सोजत द्वारा दान में दे दी गई थी। लेकिन उक्त भूमि महाविद्यालय के नाम से दर्ज नहीं होने के कारण महाविद्यालय को यूजीसी एवं अन्य उच्चतर शिक्षा योजना के तहत प्राप्त होने वाले अनुदानों का लाभ नहीं मिल पा रहा है जिससे महाविद्यालय का विकास अवरूद्ध हो रहा है।

वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ग्राम सोजत चक 1 के खसरा नं. 4480 रकबा 8. 3940 है. किस्म गैर. मुमकिन मैदान शिक्षा विभाग के नाम दर्ज है। इसी खसरे में राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी का परिसर एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोजत का परिसर स्थित है। राजस्थान भू-राजस्व नियम (विद्यालयों, महाविद्यालयों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपभोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के खण्ड-2 (ग) के अनुसार उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन, छात्रावास, खेल मैदान आदि को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 7 एकड़ अर्थात 2.80 हैक्टेयर भूमि आवंटन किया जाने का प्रावधान है। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हम अपनी बात रख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: किस मुद्दे पर?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपसे अनुमति लेकर आज जिस प्रकार से सारा वाकया हुआ। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बोल भी रहे हैं और मैंने नाम भी पुकार लिया है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इनके बाद बोल लेंगे। इनके बाद बाद आप अनुमति दे दो।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, अतः महाविद्यालय द्वारा मौका काबिज भूमि (4.63 हैक्टेयर) राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी के नाम दर्ज हो सके इस हेतु अविलम्ब ही राजस्व विभाग को आदेशित करवाया जाये ताकि महाविद्यालय को यूजीसी एवं अन्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं के तहत प्राप्त होने वाला अनुदान मिल सके जिससे महाविद्यालय एवं उसमें अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का सर्वांगींण विकास हो सके। बस यही कहकर मैं अपनी बात को विराम देती हूं, पुनः धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं तो सिर्फ आपने जो व्यवस्था दी। आपकी व्यवस्था देने के बाद हमारे सदस्यों ने अपनी बात रखी जिलों के लिये, संसदीय मंत्रीजी ने भी अपनी बात रखी। सिर्फ और सिर्फ आग्रह इतना-सा है कि संसदीय मंत्रीजी के द्वारा एक भी बात जो माननीय सदस्यों ने रखी उसका जवाब नहीं दिया। पहली बात तो आप का ही निर्देश था यह, उसको कल रोकने की कोशिश की, आज आपने समय दिया, स्थगन प्रस्ताव पर समय था, सरकार ने कहा कि हम उस पर जवाब देंगे, हमने उसको भी मान लिया, आप दस मिनट का भाषण दे रहे हो, जो बात हमारे सदस्यों ने रखी है उसका तो जवाब ही नहीं है। उसके बाद हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारे सदस्यों को उधर से संसदीय मंत्री की तरफ से धमकाया जा रहा है। उनको धमका रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपके लोग आज यहां तक आ गये। मैं नाम नहीं पुकारना चाहता। पक्ष की ओर जाने की आपके सदस्यों की हिम्मत कैसे हुई? यहां पर बोर्डर है। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्षजी, बोर्डर से उधर नहीं जा रहे हैं। बोर्डर से उधर नहीं गये। वो तो खुद संसदीय मंत्री हमको ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: इस पर चर्चा समाप्त।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इस पर सरकार का जवाब तो पूरा आने दो।

श्री अध्यक्ष: श्री आदू राम मेघवाल।

बहिर्गमन

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप इस पर नहीं कराना चाहते हैं तो हम बहिर्गमन कर रहे हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: हां, बोलो, नहीं बोलो।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है। सदन में विपक्ष के द्वारा प्रदर्शन करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन पिछली सरकार में जब मदन दिलावर एक बार यहां तक बढ़ गये थे तो उनको सत्र काल तक के लिये निलम्बित किया गया था। आज भी बामनवास से आने वाले माननीय

सदस्य ने बिलकुल वही कृत्य किया है। उनके खिलाफ भी आपको कार्यवाही करनी चाहिये।

बाखासर (चौहटन) में नयी नमक इकाई की स्थापना

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान प्रदेश समृद्ध विरासत, कला, संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों की भूमि है। पश्चिमी राजस्थान की थार नगरी बाड़मेर जिले के चौहटन विधान सभा क्षेत्र में भारत-पाक सीमा पर स्थित बाखासर के रण कच्छ क्षेत्र में करीब 10 हजार बीघा जमीन लवणीय तथा बंजर पड़ी है, जो नमक उत्पादन के लिए उद्योग विभाग को आरक्षित भी कर रखी है।

वर्ष 2014-15 में उद्योग विभाग द्वारा इस जमीन पर पत्थरगढी का कार्य कर भूमि आवंटन हेतु आवेदन भी आमंत्रित किए गए थे। जिला उद्योग केंद्र द्वारा ब्लॉकवार ड्राइंग रिपोर्ट भी तैयार कर दी गई थी, परंतु विगत 10 वर्षो से इस लवणीय व बंजर भूमि आवंटन का मामला विभाग में अटका पड़ा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल ही में प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट- 2024 के तहत एक बेहतरीन विजन एवं रोडमैप तैयार किया गया है।

इसी समृद्ध, सशक्त व विकसित राजस्थान की दिशा-दशा में प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा व उद्योग मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि प्रदेश स्तरीय एक विशेष कमेटी गठित कर सीमावर्ती चौहटन विधान सभा क्षेत्र के बाखासर रण क्षेत्र में करीब 10 हजार लवणीय व बंजर जमीन पर नमक उद्योग की स्थापना कर नमक उत्पादन की नवीन इकाइयां प्रारंभ की जावें, तो निश्चित रूप से सीमावर्ती क्षेत्र का चहुंमुखी विकास एवं स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार आसानी से कृत्य प्राप्त होंगे। साथ ही प्रदेश का बुनियादी व आर्थिक ढाँचा भी समृद्ध व विकसित होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हंसराज मीना।

कैलादेवी एवं बीजासनी मन्दिर क्षेत्र में कॉरिडोर का निर्माण

श्री हंसराज मीना (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र- सपोटरा के करौली उपखण्ड की ग्राम पंचायत कैलादेवी में कालीसिल नदी के किनारे पर स्थित माता कैलादेवी मन्दिर देश-प्रदेश के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केन्द्र है। यहां प्रतिवर्ष चैत्र माह में नवरात्रि पर लक्खीमेला भरता है जो लगभग एक माह तक चलता है। मेले में राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों के लाखों श्रद्धालु पैदल एवं वाहनों से माता कैलादेवी के दर्शनों को आते है। इसी के नजदीक ग्राम पंचायत खोहरी में स्थित बीजासनी माता का मन्दिर है। माता बीजासनी यहां के क्षेत्रीय जन मानस में कुलदेवी के रूप में पूजनीय है। स्थानीय जन मानस में माता कैलादेवी के दर्शनों से पहले माता बीजासनी के दर्शन किये जाने की मान्यता है। जिससे माता बीजासनी के दर्शनों के

लिए भी वर्ष भर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है।

परन्तु यहां की बेतरतीब बसावट एवं आवश्यक जन सुविधाओं (जैसे होटल, धर्मशाला, भोजनालय, वाहन पार्किंग, सुलभ शौचालयों) की अत्यधिक कमी होने के कारण देश-प्रदेश के दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी होती है। जिससे हमारी सरकार एवं जिला प्रशासन की छवि भी खराब होती है।

मैं सदन के माध्यम से लोकहित के मुद्दे की ओर सरकार का आकर्षित करना चाहूंगा कि कैलादेवी आस्था धाम को टाउन प्लान के द्वारा सुव्यवस्थित किया जाकर आवश्यक जन सुविधाएँ विकसित की जाती है तो यहां धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकास की विपुल संभावनाएँ है। अतः जनहित में माता कैलादेवी एवं माता बीजासनी मंदिर क्षेत्र को कोरिडोर बनाया जाकर क्षेत्र को विकसित किया जावे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री छगनसिंह राजपुरोहित। छगन सिंह राजपुरोहित। (अनुपस्थित)।

बाड़मेर की पेयजल समस्या का निराकरण

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहती हूं कि सीमावर्ती एवं मरूस्थलीय जिला बाडमेर में वर्षों से पेयजल की गंभीर समस्या है। वर्तमान में वर्ष 2019 में केन्द्र सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन योजना से इस मरूस्थलीय इलाके को मीठा पानी उपलब्ध होने की आस बंधी थी, परंतु विगत राज्य सरकार द्वारा इस पर ध्यान नहीं देने के कारण उक्त योजना धरातल पर पूर्ण रूप से नहीं उतर पाई। विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में जल जीवन मिशन योजना का कार्य तीन भागों में बांटा गया था - पार्ट A में कुल 46 गांव तथा पार्ट B में 84 गांव एवं पार्ट C में 156 गांवों को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में आज दिनांक तक विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के सबसे बड़े भाग, जिसमें 156 गांव शामिल हैं (पार्ट C), के जल जीवन मिशन योजना की निविदा तक नहीं खोली गई है, जबकि इस योजना का लक्ष्य मार्च, 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचाने का था।

इस अति महत्वपूर्ण योजना के समय पर पूर्ण नहीं होने से क्षेत्रवासियों व पशुपालकों को पेयजल संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग पानी के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं। इनका अधिकांश समय पानी की व्यवस्था करने में ही बीत जाता है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में 32 नलकूप एवं 82 हैण्डपंप नाकारा एवं बंद पड़े हैं। पुराने समय में भाडखा एवं नागाणा में स्थित भूजल स्रोत से बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र को पेयजल की आपूर्ति होती थी, वो भी आज बिलकुल नाकारा एवं बंद पड़ी है।

अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री महोदय से करबद्ध आग्रह है कि बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की इस गंभीर समस्या को देखते हुए नागाणा जैसी महत्वपूर्ण पेयजल परियोजना को

पुनः सुचारू किया जाये, साथ ही बंद पड़े 32 नलकूप एवं 82 हैण्डपंप को पुनः प्रारंभ करवाने का कष्ट कराएं, जिससे पानी की समस्या से लंबे समय से त्रस्त बाड़मेर की आम जनता को राहत मिल सके।

MLS/RTM/06.02.2025/14:10/2d

श्री अध्यक्षः श्री डूंगरराम।

सूरतगढ़ को जिला बनाया जाना

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। सूरतगढ़ को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत मैं एक महत्त्वपूर्ण मसले पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सूरतगढ़ कस्बा जिला बनाने की सम्पूर्ण पात्रता रखता है। सूरतगढ़ में एयरपोर्ट है, मिलिट्री स्टेशन है, सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन है, श्रीसीमेंट की बड़ी फैक्ट्री है। सामरिक दृष्टि से भी सूरतगढ़ अति महत्त्वपूर्ण शहर है। साथ ही, सूरतगढ़ में शिक्षा का बहुत बड़ा हब है और 50 हजार से अधिक छात्र दूसरे कस्बों, शहरों, राज्यों से आकर यहां पर शिक्षा लेते हैं। इसके अलावा सूरतगढ़ में एडीएम कार्यालय, डिप्टी एस.पी. कार्यालय, तहसील कार्यालय, एडीजे कोर्ट, कॉलेज सहित अधिकतर कार्यालय भी संचालित हैं।

महोदय, सूरतगढ़ को जिला बनाने की वर्षों से मांग चली आ रही है और इस सम्बन्ध में सरकार के स्तर पर भी कई बार बात पहुचायी गयी है, परन्तु जिला नहीं बनाये जाने से जनता में आक्रोश है।

महोदय, वर्तमान सरकार द्वारा पूर्व में गत सरकार द्वारा बनाये गये जिलों की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है, जो इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी। मेरा यह निवेदन है कि सूरतगढ़ समस्त मापदण्ड पूरे करता है तथा सूरतगढ़ तहसील के कई गांव श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ से 150 किलोमीटर की दूरी पर है, जिनकी जनता का जिला मुख्यालय पर आने में काफी समय तथा धन खर्च होता है और उन्हें असुविधा का भी सामना करना पड़ता है।

अतः प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत यह विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि सूरतगढ़ को जिला बनाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, हमारी भलमनसाहत तो देखो। यानी ये जिले तोड़ रहे हैं, फिर भी हम जिले बनाने की मांग कर रहे हैं। उम्मीद तो देखो।

श्री अध्यक्षः श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर। श्री कालूराम।

डग में चिकित्सालयों का क्रमोन्नयन

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र डग में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवानी मण्डी वर्तमान में

75 बेडेड है। यह उपखण्ड का सबसे बड़ा चिकित्सालय है। यह विधान सभा क्षेत्र का सबसे बड़ा चिकित्सालय है। यह मध्य प्रदेश सीमा से जुड़ा हुआ है। यहां पर मध्य प्रदेश के रोगी भी उपचार कराने आते हैं। यहां की एवरेज ओपीडी 800-900 व आईपीडी 40-50 प्रतिदिन होती है। यहां पर सीजेरियन प्रसव की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां रंगीन सोनोग्राफी की सुविधा भी उपलब्ध है। यह फर्स्ट रेफरल यूनिट भी है। इस सीएचसी में एफआरयू पर डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। यह झालावाड़ क्षेत्र का सबसे बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है। यहां की आबादी लगभग 70-80 हजार है। अतः इस चिकित्सालय संस्थान को सैटेलाइट चिकित्सालय भवानी मण्डी सब डिविजनल चिकित्सालय बनाया जाये तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र, उमरिया को क्रमोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाये। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चोमेला को 30 बेडेड से बढाकर 75 बेडेड किया जाये तथा शहरी क्षेत्र भवानी मण्डी में शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति प्रदान करवायी जाये तथा आवर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की अनुमति दी जाने का श्रम कराएं।

श्री अध्यक्षः श्री संजीव कुमार।

जोगीवाला (भादरा) के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के समन्वयन का निरस्तीकरण

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोगीवाला जिला हनुमानगढ़ का समन्वयन निरस्त करवाने बाबत् नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि दिनांक 08.01.2025 को शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक प.14(4)शिक्षा-1/School merge-Demerge/2024-25311 एवं कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश से शून्य/कम नामांकन व एक ही परिसर में अथवा अत्यधिक नजदीक संचालित विद्यालयों का समन्वयन किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं, जिसमें तहसील भादरा के गांव जोगीवाला का राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का समन्वयन कम नामांकन वाले हिन्दी माध्यम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोगीवाला में किया गया है जो कि विद्यालय में अध्ययनरत् बालिकाओं व अभिभावकों के लिए काफी कष्टदायक व अनुचित है। उपरोक्त बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 123 बालिकाएं अध्यनरत् हैं, जबकि प्रदेश में इससे कम नामांकन होने के बावजूद भी उच्च माध्यमिक विद्यालय का समन्वयन नही किया गया है। महोदय, बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोगीवाला में बच्चियों के लिए समस्त कक्षाएं संचालित करने के लिए पर्याप्त कमरे, प्रधानाचार्य कक्ष, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था सहित समस्त सुविधाएं विद्यमान हैं।

उक्त विद्यालय में ग्राम जोगीवाला के अलावा पड़ोसी गांव लाखन वास, पटवा, अमरपुरा, भोलावास गांव की बालिकाएं भी अध्ययन करने आती हैं। अतः निवेदन है कि अध्ययनरत् बालिकाओं एवं अभिभावकों की मांग को देखते हुए अतिशीघ्र शिक्षा विभाग के उक्त आदेश को

निरस्त कर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोगीवाला का संचालन पूर्व की भांति यथावत रखा जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री महेन्द्र पाल मीना।

मूंडला (जमवारामगढ़) स्थित अम्बेडकर पीठ में शैक्षिक पदों की स्वीकृति

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के मूंडला गांव में संविधान शिल्पी व भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के नाम पर भाजपा सरकार ने वर्ष 14 अप्रैल 2007 को तत्कालीन मुख्य मंत्री श्रीमती वसुधरा राजे ने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर फाउंडेशन (अम्बेडकर पीठ) की नींव रखी थी। पीठ को 75.3 बीघा जमीन आवण्टित है। अम्बेडकर पीठ को शोध केन्द्र के रूप में विकसित करके 'सैंटर ऑफ एक्सीलेंस' में विकसित करना था। अम्बेडकर पीठ परिसर में प्रशासनिक भवन, सेमिनार हॉल, लाइब्रेरी, कम्प्यूटर लैब व छात्रावास बने हुए हैं। अम्बेडकर पीठ में वित्त विभाग से 16 पद स्वीकृत हैं। इनमें से एक पद अकादमिक शोध निदेशक का स्वीकृत है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा जारी नियमों में यह प्रावधान है कि शोध केन्द्र की स्थापना के लिए प्रत्येक विषय में दो-दो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व अस्सिटेंट प्रोफेसर का पदस्थापन आवश्यक है। शैक्षिक पदों के सृजन के अभाव में उक्त अम्बेडकर पीठ शोध केन्द्र के रूप में प्रारम्भ नहीं हो पा रही है। वित्त विभाग को शैक्षिक पदों की स्वीकृति के लिए पत्रावली भेजी गयी थी। विभाग ने शासी परिषद से अनुमोदन के अभाव में प्रस्ताव पीठ को वापस लौटा दिया है। महोदय उक्त पीठ में अन्तिम बार शासी परिषद की बैठक 21 अप्रैल 2012 को आयोजित हुयी थी।

अतः आप से अनुरोध है कि अम्बेडकर पीठ की गवर्निंग कांउसिल का तुरन्त गठन करके वित्त विभाग से शोध के लिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व सहायक प्रोफेसरों एवं अकादमिक स्टाफ के पदों की मंजूरी दिलायी जाये तथा पीठ के नियमों के अनुसार एसटी वर्ग के विद्यार्थियों को भी पीठ की छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ दिलवाया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री उमेश मीणा।

सोम कमला आम्बा बांध में डिसिल्टिंग की निविदा प्रक्रिया में अनियमितताएं

श्री उमेश मीणा (आसपुर): प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत सोम कमला आंबा बांध में डिसिल्टिंग टैंडर में गड़बड़ी की जांच के लिए प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन इस प्रकार है कि डूंगरपुर जिले में सोम कमला आंबा बांध और उसके कैचमेंट एरिया में डिसिल्टिंग के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, बीकानेर द्वारा 78 करोड़ का टैंडर जारी किया गया है। यह टैंडर कई अनियमितताओं और गड़बड़ियों के कारण विवाद का विषय बन गया है। डूंगरपुर जिला पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अधीन नहीं आता, फिर भी इस परियोजना द्वारा टैंडर जारी किया गया, जो क्षेत्राधिकार की अनदेखी को दर्शाता है।

टैंडर की शर्तों में विशेष उपकरणों, जैसे कि कटर सेक्शन मशीन और ग्रेव बेखो टाइप ब्रेजर मशीन के उपयोग की शर्तें जोड़ी गईं, जिससे केवल एक विशेष फर्म को लाभ मिला। इसके अलावा, टैंडर में केवल "डिसिल्टिंग" का उल्लेख है, लेकिन वर्तमान में बजरी निकालकर बेची जा रही है। बजरी को "मिनरल" के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसके लिए अलग टैंडर होना चाहिए। सम्बन्धित विभागों, जैसे खनिज विभाग, जिला कलक्टर और पर्यावरण विभाग से एनओसी नहीं ली गयी, जो स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन है।

अतः निवेदन है कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि भविष्य में ऐसे टैंडर पारदर्शिता के साथ जारी हों।

mkd/rtm/06.02.2025/14:20/2e

श्री अध्यक्ष: श्री रफीक खान।

जयपुर में यातायात पुलिस के रिक्त पदों पर भर्ती

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव कर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जयपुर में जाम की समस्या अब आम हो गई है। यहां लगातार जाम की स्थिति पनप रही है। पूरे जयपुर में मुख्य सर्किलों और चौराहों के 403 पॉइंट बने हुए हैं, जिनमें से 341 पॉइंट पर 1498 जवान तैनात हैं। वहीं स्वीकृत 2935 पदों की कमी हैं। जितने पद स्वीकृत हैं, उस हिसाब से यहां यातायात पुलिस पदस्थापित नहीं हैं, जिसके चलते परेशानी हो रही है। जयपुर सिटी के अंदर से बाहर आने-जाने के लिए 5 नेशनल हाइवे हैं, जहां से लाखों लोग रोजाना काम-काज के सिलसिले में आते जाते हैं. जिनमें टोंक रोड, आगरा रोड, दिल्ली रोड, अजमेर रोड, सीकर रोड मुख्य हैं।

प्रमुख सडकों से रोजाना शहर में हजारों की संख्या में वाहन जयपुर आते जाते हैं. जिसमें कभी-कभार वीवीआईपी मूवमेंट के चलते घंटों का जाम लगता है। जिसमें शहर के अंदर सबसे ज्यादा जाम की स्थिति टोंक रोड और जेएलएन मार्ग पर लगता है, बड़े चौराहे पर तो ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात हैं, पर छोटे छोटे रास्तों में बने कट में सबसे ज्यादा जाम की स्थिति बनी रहती है।

अतः मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जयपुर शहर में ट्रैफिक पुलिस के रिक्त पदों को भरें, ताकि जयपुर शहर की प्रत्येक सड़क पर जाम नहीं लगे और यहां कि जनता को हर वक्त लगे जाम से राहत प्रदान हो सके, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री उदयलाल भड़ाणा।

माण्डल में उद्योगों हेतु आवंटित भूमि का अन्य उपयोग

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): अध्यक्ष महोदय, आपने विशेष उल्लेख नियम 295 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार-धन्यवाद।

मेरे विधान सभा क्षेत्र माण्डल में पूर्व सरकार द्वारा 500 बीघा जमीन शहर के पेरीफेरी

एरिया में इंडस्ट्री हेतु आवंटित की गयी।

उक्त जमीन का उपयोग नाम बदलकर जमीनें बेच दी गईं। यह कि उक्त जमीनों का उद्योग के लिए उपयोग नहीं किया जाकर बाहर तो फैक्ट्री के बोर्ड लगे हुए हैं, परंतु अंदर रिसोर्ट/बार/होटलें व शराब के ठेके संचालित हैं। जांच में सामने आया कि हरणी कलां, गठीला खेड़ा, आटून, बिलिया खुर्द, भदाली खेड़ा, ईरास, मंडपिया में उद्योग के नाम पर दूसरी गतिविधियों संचालित होती पाई गईं। इन जमीनों को नियमों के विपरीत जाकर मूल आवंटी के नाम हटाकर नए डायरेक्टर भी बना दिए। इसमें कई राजनेता व अधिकारी शामिल हैं। हरणी कलां मैसर्स समता सिंटेक्स उद्योग के लिए जमीन दी थी। जिसमें समता रिसोर्ट संचालित है। यह रिसोर्ट प्रदेश के पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री चला रहे हैं।

उक्त सारी जमीन को लीपापोती कर बेच दी गई और आसपास की चरागाह भूमि पर भी कब्जाधारियों ने कब्जे कर लिए हैं। जमीन की करोड़ों की कीमत होने के बावजूद भी लीज रेंट लिया जा रहा है, यह नियमों के विरुद्ध है। मेरी यह मांग रहेगी कि उक्त प्रकरण में जो भी तात्कालिक अधिकारी व प्रभावशाली जनप्रतिनिधि लिप्त पाये जाते हैं तो उन पर नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही करने का श्रम करें, साथ ही जो राजकोषीय घाटा हुआ है। उसकी पूर्ति कर दोषियों के खिलाफ ठोस कार्यवाही करवायें।

मैं अखबारों की कटिंग और जो उद्योगों की लिस्ट है, दो-दो रुपये महीने में लीज पर दी हुई है, वह मैं टेबल करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः इसमें जो लिखा है, वही पढ़ना है। श्री गोपाल लाल शर्मा।

भीलवाड़ा डिपो द्वारा बन्द बसों का पुनः संचालन

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं संचालन नियमों का नियम 295 विशेष उल्लेख प्रस्ताव कर निम्न अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

भीलवाडा डिपो में कोरोनाकाल से पूर्व आगार कि 117 रोडवेज बसों का संचालन किया जा रहा था। कोरोना के समय 37 बसों का राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर द्वारा संचालन बंद कर दिया गया। वर्तमान में भीलवाडा डिपो पर मात्र 80 रोडवेज बसों का ही संचालन किया जा रहा है। रोडवेज बसों की कमी को देखते हुए, जिन-जिन मुख्य रेवेन्यू वाले रूटों पर रोडवेज बसों का संचालन किया जाना चाहिए था। वहां संचालन नहीं किया जाकर छोटे-छोटे रूटों पर रोडवेज बसों का संचालन किया जा रहा है। जिससे यात्रियों को तो परेशानी हो ही रही है, साथ ही निगम को भी घाटा हो रहा है। वर्तमान में निगम द्वारा पूरे प्रदेश में एक हजार नई बसों का संचालन किया गया है, जिसमें से भीलवाडा आगार को मात्र 3 रोडवेज बसें देकर इतिश्री कर ली है। जो कि ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के आमजन कि मांग को ध्यान में रखते हुए, पूर्व में बंद किए गए रूटों पर निम्न रोडवेज बसों का पुनः संचालन किया जाकर राहत प्रदान करावें।

1. भीलवाडा से जोगणियां माता वाया सिंगोली सुबह 6.00 बजे

2. भीलवाडा से कोटा वाया मांडलगढ़-बिजौलियां रात्रि 11.30 बजे

3. भीलवाडा से कोटा वाया महुआ-श्यामपुरा सुबह 6.15 बजे

4. भीलवाडा से रावतभाटा वाया सवाईपुर आकोला बडलियास बरूंदनी सिंगोली, बिछोर बेगूं

5. भीलवाड़ा से कोटडी, मन्शा, ककरोलिया घाटी, राजगढ़, कछोला, सरथला तक

अतः मेरा सरकार से यह निवेदन हैं कि लोकहित को देखते हुए विधानसभा क्षेत्र में मांडलगढ़ में पूर्व में बंद की गई रोडवेज बसों का पुन संचालन करवाकर आमजन को राहत प्रदान करवाई जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री विद्याधर सिंह।

सूण्डो का बास (फुलेरा) के पंचायत भवन में कार्य संचालन

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत मुझे विशेष उल्लेख पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की ग्राम पंचायत सूण्डो का बास पंचायत समिति, किशनगढ़ रेनवाल में दिनांक 04-02-2021 को पंचायत भवन निर्माण हेतु दान की गयी भूमि में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी गयी थी। जिस पर भवन का दिनांक 14-04-2023 को निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया लगभग निर्माण कार्य पूर्ण होते ही ग्राम सभा की कोरम बैठक व्यवस्था चालू कर दी गयी थी, तत्पश्चात उक्त पंचायत भवन पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ताले लगवा दिये गये। जबकि पंचायत भवन की कई बार जांचें हुईं, जिसमें पंचायत भवन निर्माण कार्य नियमानुसार सही पाया गया। वर्तमान में ग्राम पंचायत के पास अन्य कोई सार्वजनिक भवन नहीं है, जहां पर पंचायत भवन संचालित हो सके। इस संबंध में उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन भी चाहा, लेकिन उच्च अधिकारियो द्वारा अनदेखा किया गया।

अतः माननीय पंचायती राज विभाग मंत्री महोदय से निवेदन है कि ग्राम पंचायत सूण्डो का बास के पंचायत भवन में कार्य संचालन कराने की अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: जो लिखा है, वहीं पढ़ना है। श्री बाबूसिंह राठौड़, पर्ची।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जनता जल योजना में कार्यरत सहायक पम्प चालकों की मांगों का निराकरण

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, जनता जल योजना को लेकर मेरी आज पर्ची खुली है। सन 1994 में ग्रामीण पेयजल योजनाओं को सरकारीकरण से मुक्त करके उपभोक्ताओं की उसमें भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जनता जल योजनाएं शुरू की गईं। इन योजनाओं का संचालन, संधारण जो था, वह जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से हो रहा था और पंचायतों को अंशकालीन श्रमिक लगाने का इसमें प्रावधान किया गया है।

Bhs/Rtm/06.02.25/14.30/2f

और पी.एच.ई.डी. ही इसमें मेंटीनेंस के लिए चार सौ रुपये हार्स पॉवर के हिसाब से पैसा

दे रहा था और श्रमिकों को मानदेय भी उससे मिल रहा था। उसके पश्चात सन् 2011 में फिर से सरकार ने यह फैसला किया कि पंचायती राज विभाग इसको अपने अण्डर में लेकर के मानदेय का पैसा वह दे तो मानदेय का पैसा दे रहे थे, मेंटीनेंस का पैसा दे रहे थे और यह चल रहा था। उसी दौरान न्यायालय में एक रिट याचिका हुई और रिट याचिका में यहां के सारे श्रमिकों ने कहा कि हमें न्यूनतम मजदूरी दी जाये तो 6.9.2017 को जो अंशकालिक श्रमिक थे उनके लिए न्यायालय ने फैसला किया कि अंशकालिक श्रमिक का जो पद है इसको हटा करके सहायक पम्प चालक किया जाये तो न्यायालय के आदेश से सहायक पम्प चालक हो गये और उसके बाद में इनको सहायक पम्प चालक के नाम से पुकारा जाने लगा और ये सारे जनता जल योजनाओं को चला रहे थे। उस दौरान वापस फिर से 1.5.2022 को सरकार ने निर्णय लिया कि ये ग्राम पंचायतें चलाने में असक्षम हैं इसलिये पी.एच.ई.डी. इसको अपने अधीन ले ले तो पी.एच.ई.डी. ने अधीन ले लिया लेकिन हुआ यह कि कांग्रेस शासन के समय में आनन-फानन में इन सारी योजनाओं को लिया गया। उस समय राजनीतिक बदले की भावना से और राजनीतिक द्वेष भावना से उसमें सर्वे कराया गया कि जो ये सहायक पम्प चालक लगे हुए हैं और हमारी विचाराधारा के हैं उन सबको ले लिया गया और दूसरी विचाराधारा के थे या उनके विरुद्ध विचाराधारा के थे उन सबको छोड़ दिया गया। जोधपुर जिले में ऐसी सात सौ योजनाएं जिनमें ओपन वैल हैं, नलकूप हैं उन सात सौ स्कीमों को छोड़ दिया गया जिससे आज भी इतने वर्षों से वो जो वहां पर पम्प चालक लगे हुए हैं, चार सौ योजनाएं तो चल रही हैं उनको भी बिलकुल भी मानदेय नहीं मिल रहा है और उसके बाद में भी तीन सौ योजनाएं तो मानदेय नहीं मिल रहा था इसलिये वो योजनाएं बन्द हो गयी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का भी और मंत्री महोदय का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जोधपुर जिले की तो सात सौ हैं और राजस्थान में पता नहीं कितनी योजनाएं होंगी जो उस समय पी.एच.ई.डी. के अधीन नहीं आई। अब ये दोहरा भेदभाव है। आधी योजनाओं को तो पी.एच.ई.डी. में ले लिया गया और आधी योजनाएं छोड़ दी गई। अब उनको अगर मेंटीनेंस का पैसा नहीं मिलेगा, उनको मानदेय का पैसा नहीं मिलेगा तो वो जो पम्प चालक हैं वो भी छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद में यह पेयजल का भयंकर संकट व्याप्त हो जायेगा। इसलिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाह रहा हूं कि यह लम्बे अर्से से 1994 से लगे हुए हैं तो क्यों नहीं आपके यहां पी.एच.ई.डी. में इतने पद खाली हो गये हैं आप नयी भर्तियां करें और नयी भर्तियों में इनको अगर बोनस के माध्यम से लें या अनुभव के आधार पर इनको नियमित भी कर सकते हैं। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक मिनट। नियमित भी कर सकते हैं और इनकी जो मांगें हैं वो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जनता जल योजना में कार्यरत पम्प चालकों को विभाग में रिक्त पदों पर समायोजित करते हुए नियमित घोषित किया जाये। सहायक पम्प चालक आदेश 2023 के अनुसार पदनाम सृजित कर एवं अनुभव के आधार पर ग्रेड प्रथम, द्वितीय, तृतीय तय कर

सेवा नियम निर्धारित किये जायें।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह रावत।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): बस दो पाइंट हैं।

श्री अध्यक्ष: बस, दो मिनट बोलते हैं, चार मिनट हो गये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सहायक पम्प चालक कर्मचारी बीमा भविष्य निधि स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति एवं अन्य सेवा नियम का लाभ दिया जाये। वंचित बन्द पड़ी नलकूप इकाइयों को पुन: चालू कराया जाये एवं वंचित नलकूपों को अतिशीघ्र पी.एच.ई.डी. में समायोजित कर बकाया पम्प चालकों के मानदेय का भुगतान किया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह रावत।

ब्यावर के दो बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों का अन्य विद्यालय समन्वयन

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका आभार। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ब्यावर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, देलवाड़ा और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, डिग्गी मोहल्ला इन दोनों विद्यालयों के बीच में लगभग सात किलोमीटर की दूरी है और इसमें देलवाड़ा के अन्दर 284 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। उसकी बिल्डिंग के लिए पांच करोड़ रुपये अभी और स्वीकृत हुए हैं वह भी तैयार हो रही है और यह बीस वर्ष से यह बालिका विद्यालय संचालित है और इसी प्रकार डिग्गी मोहल्ला, ब्यावर में 352 बच्चियां आज भी अध्ययनरत हैं और भवन व सब कुछ अलग-अलग है चालीस वर्षों से यह विद्यालय चल रहा है और अभी मेरा निवेदन है कि डाइरेक्टर ने आदेश क्रमांक 19200 दिनांक 16 जनवरी, 2025 द्वारा इसका शून्य और कम नामांकन आंक कर और एक ही परिसर मान करके इसको निरस्त कर दिया गया है। यह हमारे लिए बहुत ही दुखदायी है। कांग्रेस सरकार गयी है लेकिन नमूनों को छोड़ कर गयी है इस प्रकार के कोई आदेश अगर निकाले हैं तो माननीय दयालु मंत्री महोदय हैं जो ऐसी दया करके इस प्रकार के जो अधिकारी हैं उनको आप कहीं आगे-पीछे करें और आप उनको नसीहत दें कि इस प्रकार का जो आदेश निकाला है उसको निरस्त करके आप उन बच्चियों को लाभ दिलायें। यही आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट, मंत्री जी कुछ जवाब दे रहे हैं। धन्यवाद, साहब।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र।

महवा में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत पात्र व्यक्तियों को लाभ

श्री राजेन्द्र (महवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि देश में प्रधान मंत्री आवास योजना पिछले लम्बे समय से चल रही है और वर्तमान में भी पी.एम. आवास योजना का सर्वे पूरे प्रदेश, पूरे देश में चल रहा है लेकिन जब हम गांवों में जब इसका वास्तविक और धरातल पर अध्ययन करते हैं तो पता लगता है कि आज भी बहुत से आवास विहीन परिवार पिछले काफी वर्षों से आवास विहीन मिलते हैं

जबकि इनकी शिकायतें होती रहती हैं। उक्त व्यक्ति का पक्का आवास होने के बावजूद भी पी.एम. आवास आवंटन हो जाता है और गड़बड़ियों की शिकायतें भी मिलती रहती हैं। मेरे अनुभव के आधार पर इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा उचित सर्वे नहीं किया जाना और अपने चहेते लोगों को नाम जुड़वा दिया जाता है इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए सर्वे लिस्ट फाइनल होने के उपरान्त एक गोपनीय कमेटी पारदर्शिता हेतु कलेक्टर के स्तर पर इसकी जांच करें और दोषी अधिकारी और कर्मचारियों को दंड की कार्यवाही करें। प्रावधान कुछ भी बने हों लेकिन इनकी सख्ती से पालना और अमल भी होना चाहिये जिससे भ्रष्टाचार मुक्त हमारी सरकार द्वारा गरीब पात्र और वंचितों को इस योजना का उचित लाभ मिल सके।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचना। श्री हेमन्त मीणा।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

राजस्व विभाग

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की निम्न 6 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1. अधिसूचना संख्या:प.9(26)राज-6/2024/16 दिनांक 26.7.2024 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (सोलर, अक्षय, ऊर्जा) आवंटन नियम, 2007 के नियम 2, 2ए, 3, 4, 6, 7, 8 और प्रारूप-ए तथा प्रारूप-बी में पॉवर प्लान्ट/पॉवर पार्क हेतु संशोधन किया गया है;

2. अधिसूचना संख्या:प.9(48)राज-6/2024/21 दिनांक 17.10.2024 जिसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम, 7 में ग्रिड सब स्टेशन (जी.एस.एस) हेतु चरागाह भूमि वर्गीकरण परिवर्तन के प्रावधान किये गये हैं;

3. अधिसूचना संख्या:प.4(16)राज-6/2024/24 दिनांक 21.11.2024 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व सेवा नियम, 1971 के नियम 4सी में राजस्व मण्डल में सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु योग्यता के संबंध में संशोधन कर प्रावधान किये गये हैं;

4. अधिसूचना संख्या:प.1(4)राज-6/2020/25 दिनांक 22.11.2024 जिसके द्वारा संपरिवर्तन हेतु ऑनलाईन आवेदनों के संबंध में राजस्थान भू राजस्व संपरिवर्तन नियम, 2007 नियम 9 के उप नियम 1 में संशोधन कर "ऑनलाईन आवेदन की प्रति को सात दिवस के भीतर प्राधिकृत प्राधिकारी को भेजा जायेगा" प्रतिस्थापित किया गया है;

5. अधिसूचना संख्या:प.9(72)राज-6/2024/28 दिनांक 29.11.2024 जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन (संशोधन) नियम, 2024 के नियम 9 के खण्ड-ए में आवंटित की जाने वाली भूमि की दर के संबंध में संशोधन कर नया प्रावधान प्रतिस्थापित

किया गया है; एवं

6. अधिसूचना संख्या:प.9(35)राज-6/2024/30 दिनांक 04.12.2024 जिसके द्वारा राजस्थान भू राजस्व संपरिवर्तन नियम, 2007 के नियम 6 बी, 8, 9 में संशोधन कर एस.सी/एस.टी. के खातेदारों की भूमि पर सोलर परियोजनाओं हेतु रियायत दिये जाने के संबंध में नये प्रावधान प्रतिस्थापित किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन व लेखे। डॉ. प्रेम चन्द बैरवा।

प्रतिवेदन एवं लेखे

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

का वार्षिक/प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष (2024-25)

1. महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2003 की धारा-43 के अन्तर्गत महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक/प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2024-25;

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष (2024-25)

2. पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम, 2012 की धारा-42 के अन्तर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25;

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर

का वार्षिक/प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष (2024-25)

3. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1999 की धारा 25(2) के अन्तर्गत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक/प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2024-25;

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर

का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2024-25)

4. डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा-42 के अन्तर्गत डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2024-25;

एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2024-25)

5. एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2021 की धारा-43 के अन्तर्गत एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25;

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2024-25)

6. राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अधिनियम, 2012 की धारा-42 के अन्तर्गत राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-

25;

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2024-25)

7. कोटा विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2003 की धारा-43 के अन्तर्गत कोटा विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25;

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2024)

8. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 1962 की धारा 39 के अन्तर्गत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024;

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2024-25)

9. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर अधिनियम, 1987 की धारा-38 के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25; एवं

गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2024-25)

10. गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा अधिनियम, 2012 की धारा-41 के अन्तर्गत गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25

श्री अध्यक्षः श्री गजेन्द्र सिंह।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2024)

1. मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2023 की धारा-45 के अन्तर्गत मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2024।

Kas/rtm/06.02.2025/14.40/2g

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2024)

2. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा-44 के अन्तर्गत राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024

श्री अध्यक्षः श्री के.के. विश्नोई।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखें सदन की मेज पर रखता हूं:-

जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (रीको) का प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं आय-व्यय लेखा (वर्ष 2022-23)

1. राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम (RSIR), 2016 की धारा 66 के अन्तर्गत जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (रीको) का प्रशासनिक

प्रतिवेदन एवं आय-व्यय लेखा वर्ष 2022-23;

खुशखेड़ा भिवाड़ी-नीमराना विनिधान क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (रीको) का प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं आय-व्यय लेखा (वर्ष 2022-23)

2. राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम (RSIR), 2016 की धारा 66 के अन्तर्गत खुशखेड़ा भिवाड़ी-नीमराना विनिधान क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (रीको) का प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं आय-व्यय लेखा वर्ष 2022-23;

विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2024-25

3. विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 की धारा-37 के अन्तर्गत विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2024-25

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

राजस्थान लोक सेवा आयोग का 74वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24) एवं विभिन्न सेवा नियमों में संशोधनों के प्रस्ताव पर राजस्थान लोक सेवा आयोग की सलाह से असहमति के कारणा का विवरण

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 74वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 एवं विभिन्न सेवा नियमों में संशोधनों के प्रस्ताव पर राजस्थान लोक सेवा आयोग की सलाह से असहमति के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री कन्हैयालाल।

राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड के मेमोरेन्डम ऑफ आर्टिकल के नियम-114 के अन्तर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री सुमित गोदारा।

राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट (वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25)

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2001 की धारा 14 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री झाबर सिंह खर्रा।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखें सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान आवासन मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे (वर्ष 2023-24)

1. राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा-47 के अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वर्ष 2023-24

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे (वर्ष 2023-24)

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा-60 के अन्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वर्ष 2023-24

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

3. अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा-60 के अन्तर्गत अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

श्री अध्यक्ष: पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन। श्री रफीक खान। आधे मिनट में अपनी इन्फोरमेशन दें।

सूचना

जयपुर स्थित भावना नगर में जेडीए की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पाइंट ऑफ इन्फोरमेशन पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरी कांस्टीट्यूएंसी में आगरा रोड पर भावना नगर नाम से एक कॉलोनी बसी हुई है और उस भावना नगर में कल जेडीए की कार्यवाही की गई। यह कॉलोनी पिछले दस सालों से बसी हुई है। मेरे पास इसके पट्टों की कॉपियां हैं, रजिस्टर्ड डाकूमेंट की कॉपियां हैं जो 2015 में रजिस्टर्ड हैं, 2010 में रजिस्टर्ड हैं, 2018 में रजिस्टर्ड हैं और उसके बावजूद कॉलोनी में जाकर जेडीए द्वारा ध्वस्त किया गया, वह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: इन्फॉर्मेशन देनी है, भाषण नहीं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): बल्कि गवर्नमेंट लैंड पर जो नाजायज कॉलोनियां आज कट रही हैं, उनको रोके, पुरानी बस्ती उजाड़ना ठीक नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें कार्यवाही हो और यह कार्यवाही रुके।

श्री अध्यक्ष: राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस शुरू हो, उसके पहले एक व्यवस्था है, आज चूंकि अपना लगभग डेढ़ घंटा एक्स्ट्रा हुआ है, तो इसके कारण से और बोलने वाले सदस्यों की संख्या भी आज ज्यादा है। मैंने दोनों सचेतकों से आग्रह किया है, उन्होंने कुछ माना है। इसलिए पहला वक्ता 20 मिनट बोलेगा, उसके बाद सारे के सारे 10 मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे, तब भी जाकर दस-साढ़े दस तो आज फिर भी बजने वाले हैं। इसलिए कोई भी सदस्य ज्यादा समय का आग्रह न करें, अपने समय पर अपनी बात पूरी कर दें। श्रीमती अनिता भदेल।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, अभी यह जो माननीय उप मुख्य मंत्री साहब ने वर्ष 2024-25 के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं, मैं यह जानकारी चाह रहा हूं कुछ

विश्वविद्यालय में वर्ष 2024 लिखा हुआ है, कुछ में 2024-25 लिखा हुआ है, क्या यह करेक्ट है, इतनी सी जानकारी चाह रहा हूं, क्योंकि 2024-25 तो अभी 31 मार्च को खतम होगा, इसको थोड़ा देख लें।

श्री अध्यक्ष: मैं इसको देखकर आपको जानकारी कराता हूं। शुरू करें।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के प्रिएम्बल को पढ़कर मैं अपनी बात की शुरूआत करना चाहूंगी। प्रिएम्बल में लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिये तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिये दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संविधान की प्रस्तावना में लिखा है और संविधान को हमने 26 जनवरी, 1949 को लागू किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता जब सेवा बन जाये तो राष्ट्र का निर्माण होता है और जब सत्ता विरासत बन जाये तब लोकतंत्र खतम हो जाता है। हमारे इस प्रिएम्बल में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख आया है, लोकतांत्रिक गणराज्य का उल्लेख आया है और यह लोकतांत्रिक गणराज्य जनता के लिये, जनता के द्वारा और जनता को समर्पित होकर इस गणतंत्र की स्थापना की गई। कांग्रेस के लंबे कालखण्ड में, 55 सालों के नेतृत्व में पंथ निरपेक्षता को तुष्टिकरण बना दिया, लोकतंत्र को परिवारवाद में कन्वर्ट कर दिया और जन कल्याणकारी राज्य को भ्रष्टाचारी राज्य बना दिया। जिस तरह से पिछले पांच वर्ष हमने राज्य में देखे और 2014 से पहले केन्द्र में देखे, कांग्रेस की सरकारों ने किस तरह से परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम किया और न केवल परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम किया, बल्कि संविधान की मूल भावना को तोड़-मरोड़ कर बहुत निर्लज तरीके से इसका दुरुपयोग करने की कोशिश की। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से पिछले पांच सालों में कांग्रेस की सरकार चली, पूरी सरकार में जितने सरकार के पक्ष के विधायक थे, वो सब मुख्य मंत्री बन कर घूम रहे थे। वो सारे के सारे भ्रष्टाचार में डूबे थे। मैं तुष्टिकरण का एक उदाहरण दूं, अल्प संख्यक वर्ग से आने वाली एक महिला मंत्री ने आर्डर जारी किया कि रमजान का महीना है, इसलिए रमजान के क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था माकूल होनी चाहिये। यह शर्मसार करने वाला आदेश था। आज से पहले कभी किसी सरकार के मंत्री ने इस प्रकार का आर्डर नहीं निकाला। किस तरह से

सरकार चलाई जाती है, किस तरीके से तुष्टिकरण की पराकाष्ठा की जाती है, यदि देखना है तो कांग्रेस के शासन को उठाकर देख लें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत मेहनत और दूर दृष्टि रख कर देश के सभी राज्यों का एकीकरण किया, लेकिन डाक्टर अंबेडकर जी के संविधान को तोड़ा-मरोड़ा ही नहीं, आज अंबेडकर जी इसलिए याद आ रहे हैं क्योंकि दलित वर्ग के वोटों की संख्या बढ़ गई है और दलित वर्ग का वोटर भी न केवल विवेक से, बल्कि समझ से अब कांग्रेस से शिफ्ट होने लगा है। इसलिए दलित वर्ग की याद आने लगी है।

(समय: बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कांग्रेस के एक 56 साल के युवा नेता पूरे देश में घूम-घूम कर यह बात कर रहे हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीटें ले आयेगी तो संविधान बदल देगी, आरक्षण छीन लेगी।

Msk/rtm/06.02.25/1450/2h

मैं यहां उसी पार्टी के सदस्यों और सदन को भी बताना चाहूंगी कि संविधान के अनुच्छेद 368 में स्वयंभू यह प्रावधान है कि आप समय की गति को देखते हुए, वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, पर उसकी मंशा और प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान परिवर्तन करो, लेकिन उसकी मंशा अच्छी होनी चाहिए, उसकी प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए।

अब मैं बताना चाहूंगी कि कांग्रेस के 55 सालों में संविधान में 77 परिवर्तन हुए और भारतीय जनता पार्टी के 16 साल, जिसमें छह साल अटल बिहारी वाजपेयी जी के हैं और दस साल नरेन्द्र मोदी जी के हैं। इन 16 सालों में 22 बार संविधान में संशोधन किये गये, लेकिन प्रक्रिया और नीयत की बात देखिये। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के समय पहला संशोधन, मैंने यह प्रिएंबल पढ़कर सुनाया और इसमें तारीख का भी उल्लेख किया, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसको अंगीकृत किया, लेकिन पहला संविधान संशोधन जो कांग्रेस के शासन में हुआ, 18 जून, 1951, माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत तथ्यात्मक रूप से प्रमाणिकता के साथ में अपनी बात इस सदन में कह रही हूं। किसी माननीय सदस्य को आपत्ति हो तो केन्द्र में लोक सभा और राज्य सभा का दस्तावेज उठाकर देखें। 18 जून, 1951 में पहला संविधान संशोधन 19(ए) का जोड़ा गया और उस समय न तो लोकसभा का गठन हुआ था, न राज्य सभा का गठन हुआ था, न आम चुनाव हुए थे। पहला आम चुनाव भी नहीं हुआ, उसके पहले कांग्रेस कुछ संशोधन लेकर आयी, वह संशोधन था कि आम नागरिक की अभिव्यक्ति की आजादी को कम कैसे किया जाए, यह 19(ए) का संशोधन है, यह इतिहास बना है। इसको आप उठाकर देखिये।

दूसरा संविधान संशोधन जो कांग्रेस लेकर आयी, 24वां संविधान संशोधन,

05.11.1971 को। यह संविधान संशोधन क्या था, जो इन्दिरा जी लेकर आयी थीं। इन्दिरा जी क्या संशोधन लेकर आयीं कि लोगों के मौलिक अधिकारों को कम कैसे किया जाये? यह संविधान संशोधन था। मुझे संविधान पर इसलिए बोलना है, क्योंकि मैं भी दलित वर्ग से आती हूं, महिला हूं। संविधान की बात जिस तरह से कांग्रेस के लोग कर रहे हैं तो उनको आईना दिखाना बहुत जरूरी है। नागरिक के मौलिक अधिकारों को कम किया है, यह 24वां संविधान संशोधन है, जिसको आप और मैं बदल नहीं सकते हैं। अब वह इतिहास बन चुका है। 39वां संविधान संशोधन जो कांग्रेस लेकर आयी और इन्दिरा जी के समय का है, वह 39वां संविधान संशोधन क्या था, कि कोई भी प्रधान मंत्री के चयन पर न्यायिक समीक्षा नहीं होनी। माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात थी कि यह रेट्रोस्पेक्टिव आदेश था। इसका सीधा-सीधा मीनिंग है कि यदि इन्दिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाइकोर्ट ने कैंसिल कर दिया, चुनौती दे दी तो उस पर न्यायिक जांच नहीं होनी चाहिए। इसलिए यह संविधान संशोधन लाया गया। संविधान संशोधन लाकर इसको रोका गया। यह संविधान संशोधन 39वां संविधान संशोधन था, जिसको इन्दिरा गांधी जी लेकर आयीं। माननीय सभापति महोदय, 42वां संविधान संशोधन क्या था? 42वां संविधान संशोधन यह था कि कोई राज्य सरकार या केन्द्र सरकार का कार्यकाल जो कि संविधान में लिखा हुआ है, पांच वर्ष का है। जब इन्दिरा गांधी जी इमरजेंसी लेकर आयीं तो इमरजेंसी के बाद चुनाव कराना है। ...(व्यवधान)... हां, संविधान पर बोलना है। संविधान पर क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यह देश संविधान से चलता है। यह राज्य सरकार संविधान से चलती है। केन्द्र सरकार संविधान से चलती है। इसलिए संविधान पर बोलना बहुत जरूरी है। ...(व्यवधान)... तो वह 42वां संविधान संशोधन क्या था? यह था कि इमरजेंसी आने के बाद चुनाव होने थे तो राज्य सरकारों के कार्यकाल को छह साल बढ़ाया गया और लोकसभा के कार्यकाल को छह साल बढ़ाया गया। यह 42वां संविधान संशोधन करके उन्होंने एक-एक साल के कार्यकाल को बढ़ाया ताकि चुनाव आने पर हम हार न जायें। वन राज्य- वन नेशन-वन इलेक्शन की बात जब हम करते हैं तो वन-स्टेट वन इलेक्शन, वन-नेशन कैसे हो सकता है? तो आपने 42वें संविधान संशोधन में कैसे किया था? अपने इतिहास में झांको, आप इतिहास में जाकर आओ। माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ा आश्चर्य तो मुझे तब होता है जब कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने इन चीजों का विरोध करना शुरू करना किया तो इन्होंने कांग्रेस की मीटिंगों में आना छोड़ दिया। कांग्रेस की बैठकों में जाना छोड़ दिया। लोकसभा की बैठकों में, राज्य सभा की बैठकों में जाना छोड़ दिया तो लोगों का कोरम पूरा नहीं होता था, तो एक संविधान संशोधन और साथ में किया गया। वह संविधान संशोधन क्या था कि पांच सांसद भी यदि लोक सभा में पहुंचते हैं या राज्य सभा में पहुंचते हैं तो कोरम पूरा हो जायेगा और उनकी बात मानी जायेगी। इससे बड़ी निर्लज्जता तो कोई हो ही नहीं सकती है। इससे बड़ी निर्लज्जता और क्या हो सकती है? और फिर संविधान की बात करते हैं। संविधान की बात करते हैं, इतनी बड़ी निर्लज्जता करके। ...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): Please sit down. महत्वपूर्ण बात हो रही है।

श्री सभापति: विराजिये। आप नंबर आये तब बोल देना।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के लोगों को इससे बुरा लगना वाजिब है, लेकिन कांग्रेस के लोग अपने नेताओं को समझाएं कि इस प्रकार की करतूत न करें। ये चीजें इतिहास से मिट नहीं सकतीं। अब तो इतिहास में दर्ज है और आप उसको मिटा नहीं सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपति शासन की अवधि भी छह माह बढ़ायी गयी और यह देखकर बढ़ायी। ये हैं, कांग्रेस के कुछ संविधान संशोधन, जिनका उल्लेख मैंने यहां पर किया है।

आप कांग्रेस के लोग कहते हैं कि संविधान बदल देंगे, मोदी जी 400 पार हो जायेंगे तो संविधान बदल देंगे, पर मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन के कुछ उदाहरण बताना चाहूंगी। माननीय सभापति महोदय, मोदी जी जब 2014 में पहली बार प्रधान मंत्री बने तो मोदी जी कौनसा संविधान संशोधन लेकर आये? मोदी जी ने कौनसे अनुच्छेद में संविधान संशोधन किया, कुछ उदाहरण मेरे पास हैं। ...(व्यवधान)... हां, ये अभिभाषण से ही जुड़ा हुआ है। आपको सुनना चाहिए। आपके नेताओं की बातों को सुनना चाहिए।

श्री सभापति: प्लीज बैठे बैठे नहीं बोलें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मोदी जी ने 101 अनुच्छेद में परिवर्तन किया है, 101वां संविधान संशोधन। यह 101वां संविधान संशोधन 2014 के बाद 2017 में किया गया और वह क्या था? देश को अर्थ तंत्र में मजबूत करने के लिए, पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और द्वारिका से हमारे कश्मीर तक, कामाख्या से द्वारका तक, ये देश की चारों सीमाओं में हमारा अर्थतंत्र कैसे मजबूत होगा, इसलिए जीएसटी को लेकर आये। यह 101वां संविधान संशोधन माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया।

सबसे बड़ी बात हमारे कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हर बात में ओबीसी की बात को बीच में घुसा देते हैं। ओबीसी के कितने अधिकारी हैं? ओबीसी की जनगणना नहीं करा रहे, जातिगत जनगणना नहीं करा रहे हैं तो ओबीसी से आपका कितना प्रेम है? यह भी मैं बताना चाहूंगी। माननीय सभापति महोदय, आप देखिये, ओबीसी को लेकर 102वां संविधान संशोधन हुआ। यह ओबीसी को लेकर 102वां संविधान संशोधन मोदी जी के शासन में किया। नेशनल कमीशन आफ बैकवर्ड (ओबीसी) को संवैधानिक दर्जा दिया गया। न केवल संवैधानिक दर्जा दिया। माननीय सभापति महोदय, यह संवैधानिक दर्जा 1980 में मिल जाना चाहिए था, जब कालेलकर जी की रिपोर्ट आयी थी, लेकिन कांग्रेस ने 1980 में लागू नहीं किया। फिर कमीशन बना। 1955 में कालेलकर जी रिपोर्ट आ गयी, उस रिपोर्ट को न तो राज्य सभा में प्रस्तुत किया, न लोक सभा में प्रस्तुत किया, उसको लाइब्रेरी में डंप कर दिया। लाइब्रेरी में डंप करके, जब बहुत मांग उठी तो 1980 में कमीशन बना। 1980 में कमीशन बनने के बाद फिर कमीशन ने रिपोर्ट दी, लेकिन उसको लागू नहीं किया। उसको लागू कब किया? उसको

1990 में लागू किया। वह भी कांग्रेस की सरकार जा रही थी, जब कमीशन की रिपोर्ट लागू की, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। उसको संवैधानिक दर्जा कब मिला, जब 102वां संविधान संशोधन मोदी जी के शासन हुआ और यह ओबीसी को संवैधानिक दर्जा मिला।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से मैं उदाहरण देना चाहूंगी 103वां संविधान संशोधन। वह 103वां संविधान संशोधन क्या था? वे जातियां, जिनको आरक्षण नहीं मिलता है, वे आरक्षण से बाहर हैं। उन जातियों के गरीब लोगों को ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया जाये और 10 प्रतिशत आरक्षण मिले।

mdp/rtm/06.02.2025/15:00/2j

वे जातियां भी एक समान मुख्य धारा में आकर खड़ी हों, यह है 103वां संविधान संशोधन। यह भावना की बात है। यह नीयत की बात है कि आपकी नीयत कितनी खोटी है कि आपने अपने शासन को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी हार को स्वीकार करने के लिए संविधान में संशोधन किए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, मोदी जी के शासनकाल में उन जाति-वर्गों को ऊँचा उठाने के लिए संवैधानिक संशोधन हुए जिनको आज तक कांग्रेस के शासन में नहीं मिल पाया।

सभापति महोदय, इसी प्रकार 105वां संशोधन हुआ। 105वां संविधान संशोधन क्या है? 105वां संविधान संशोधन यह है कि ओबीसी जिसे सिर्फ केटेगेराइज या परिभाषित केन्द्र सरकार या लोक सभा या राज्य सभा सरकारें ही कर सकती हैं। राज्य सरकारों को वह अधिकार प्राप्त नहीं था। मोदी जी की सरकार में ये 105वां संविधान संशोधन हुआ कि इतने बड़े देश में 140 करोड़ आबादी जिस देश की है, 140 करोड़ आबादी में बहुत सारी जातियां ऐसी हैं, जिनको केन्द्र स्टडी नहीं कर पाता, नहीं जान पाता, इसलिए राज्य को भी उन ओबीसी जातियों को परिभाषित करने का अवसर मिलना चाहिए। ये 105वां संविधान संशोधन उस समय लाया गया।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से 33 प्रतिशत आरक्षण, मैं माननीय नरेन्द्र मोदी जी को इस मंच से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं। कांग्रेस की यूपीए सरकार की चैयरपर्सन सोनिया गांधी रहीं और बार-बार यह मांग करती थीं, जब दूसरी सरकारें होती थी कि 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए, परंतु उन्होंने किया नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शासन जब आया तो 106वां संविधान संशोधन हुआ 28/09/23 को, नारी शक्ति वंदन विधेयक के माध्यम से लोक सभा और राज्य सभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया। मैं हमारी भजन लाल जी की सरकार को भी धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने राज्य में शिक्षा में 50 प्रतिशत आरक्षण और सरकारी सेवाओं में, पुलिस में 30 से 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को किया है, महिलाओं की सुरक्षा की बात की है, काली बाई भील कोर की स्थापना की है।

माननीय सभापति महोदय, इस तरह से नियति का कितना फर्क है। ..(व्यवधान).. अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी।

श्री सभापतिः प्लीज। प्लीज।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी कि कोई संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन वह अच्छा नहीं बन सकता जब तक कि उसको चलाने वाले सकारात्मक और अच्छे नहीं हैं। कोई संविधान कितना भी बुरा हो, लेकिन उसको चलाने वाले सकारात्मक हैं, उनकी भावना अच्छी हैं तो वह बुरा संविधान भी अच्छा संविधान साबित हो सकता है। यह अम्बेडकर जी ने कहा था। 55 सालों के शासन में कांग्रेस के हाथों में इस संविधान को कठपुतली की जैसे घुमाया गया, तोड़ा-मरोड़ा गया और उस कारण से देश की यह हालत हुई। अपमान हुआ। माननीय अम्बेडकर जी को चुनाव में हराने की कोशिश की गयी। हराया गया। उनको इस्तीफा देना पडा, मजबूर होकर के और आज ये अम्बेडकर जी की बात करते हैं। किस दिल से करते हैं? उनके सीने पर हाथ रखकर बोलें कि वह अम्बेडकर जी की बात किस मुंह से करते हैं। उन्होंने न केवल अम्बेडकर जी को हराया, जब अम्बेडकर जी ने इस्तीफा दिया तो पंडित जवाहर लाल नेहरु जी के ये वक्तव्य थे कि अम्बेडकर जी के इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस सरकार पर। यह वक्तव्य लिखा हुआ है लोक सभा में और उनके पत्र के जवाब में। इसलिए आप कितना ही गुमराह कीजिए दलित वर्ग के लोगों को, दलित समुदाय को, इस देश को, लेकिन अब वह आपके झांसे में आने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से पिछली राज्य सरकार ने इस राज्य को कर्ज में डूबोया, खजाना खाली रखा, उसके बावजूद भी भजन लाल जी की सरकार ने अथक परिश्रम करके पुनः ..(व्यवधान)... इस सरकार के खजाने को न केवल भरा है, बल्कि पहला बजट भूतो न भविष्यति, हर विधायक की डिमांड पर उन्होंने कुछ न कुछ देने की कोशिश की। ...(व्यवधान)... आज फिर अपमान कर रहे हैं, क्योंकि दलितों को सुनना इनकी फितरत में नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय भजन लाल जी की सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने सरकारी भर्तियों में चार लाख तक की भर्ती की घोषणा की। न केवल घोषणा की 69000 भर्तियां उन्होंने पूरी कीं और 1 लाख 72 हजार भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। राजस्थान का युवा सपना देखता है सरकारी नौकरी में जाने का। सरकारी नौकरी में जाने के बाद उसका सामाजिक परिवेश, उसका आर्थिक परिवेश बदल जाता है। जितनी मेहनत आज एक युवा जयपुर में आकर, कोटा में आकर कोचिंग क्लासेज करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार के कारण से, पेपर लीक के कारण से ये भर्तियां गलत हाथों में चली जाती है तो मेरा आपसे निवेदन है और माननीय भजन लाल जी की सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने न केवल एस.आई.टी. का गठन किया, बल्कि सरकारी भर्तियों में आगे बढ़ाया।

इसी प्रकार से उन्होंने आंगनबाड़ी वर्कर्स को दस प्रतिशत वृद्धि, मुख्य मंत्री अमृत आहार, लाडो प्रोत्साहन योजना और लखपति दीदी के नाते से इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात की।

श्री सभापतिः प्लीज, समाप्त कीजिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, दो-तीन पाइंट हैं।

श्री सभापतिः समय हो गया।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, महिला सशक्तिकरण में यह सरकार हमेशा याद रखी जाएगी। मैं पिछली बीस वर्षों से इस सदन में आती हूं। मैंने हर सरकार में कभी इन्वेस्टमेंट समिट के नाम से, कभी किसी और नाम से इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश प्रोत्साहन के लिए सरकारों को काम करते देखा है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि भजन लाल जी की सरकार ने इन पांच सालों के प्रथम कार्यकाल में राइजिंग राजस्थान समिट आयोजित करके 35 लाख करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट यहां आमंत्रित किये। यदि ये 35 लाख करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट यहां आते हैं तो युवाओं को न केवल रोजगार मिलता है, राजस्थान प्रगति के पथ पर और आगे बढ़ता है।

इसी प्रकार से पेंशन योजना और सामाजिक, माननीय सभापति महोदय, चूंकि एक आम आदमी का सपना होता है कि वह किसी तरह से अपने जीवन-यापन को बहुत सुखदायी तरीके से, बहुत आरामदायक तरीके से व्यतीत करे। उसके हाथों को रोजगार चाहिए, उसके बच्चों को शिक्षा चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था हो जाए और रोजगार की व्यवस्था हो जाए तो आम आदमी स्वयं खुद-ब-खुद चल पड़ता है। इसलिए आम आदमी को राहत देने का काम भजन लाल जी की सरकार ने किया है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात पूरी करती हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री हरीश चौधरी जी।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): सबसे पहले तो आज हमारे थार के आराध्य देवता श्री खेमा बाबा की जयंती है। आप सबको बहुत-बहुत बधाई। राज्यपाल के अभिभाषण, जो कैबिनेट से अनुमोदित होकर राज्यपाल महोदय ने इस सदन के समक्ष बोला, उसके सन्दर्भ में मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं तहेदिल से धन्यवाद देता हूं।

मेरे से पूर्व स्पीकर महोदय की सबसे चहेती विधायिका ने संविधान के सन्दर्भ में बात की और संविधान के विपरीत ही उन्होंने बात की। संविधान के अन्दर इस तरह की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है कि किसी एक व्यक्ति की सरकार होगी। संविधान के अन्दर कैबिनेट की सरकार होती है। वह अलग बात है कि आज के समय में इस देश में कैबिनेट मंत्री भी यह महसूस नहीं करते हैं कि हम सरकार का हिस्सा है। एक व्यक्ति की महिमा मंडन करने के लिए, उससे कुछ प्राप्त करने के लिए जो कोई भी मुख्य मंत्री होता है, उसकी महिमा मंडन के अन्दर उस संविधान के प्रावधानों के विपरीत उसका नाम लेकर सरकार की बात करता है। जब संविधान की आप बात कर रहे हैं और उसके विपरीत ही आप उसी भाषण के अन्दर संविधान के मूल जो उद्देश्य हैं, उनके खिलाफ ही आप बात कर रहे हैं तो कितना संविधान के

सन्दर्भ में आपकी मंशा है।

सभापति महोदय, पहला संविधान संशोधन 12 मई, 1951 के अन्दर हुआ था और वह हुआ किसलिए? वह आरक्षण के सन्दर्भ में हुआ। सीनियर विधायिका जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस चर्चा के अन्दर, उस समय के तत्कालीन लोक सभा के सदस्य श्याम प्रसाद मुखर्जी ने क्या उस बिल के सन्दर्भ में, संविधान संशोधन के सन्दर्भ में बोला, वह प्रति मैं आपको जरूर दूंगा। वह आप पढ़कर सदन को साझा करें। सभापति महोदय, ओबीसी की भी बात की। ओबीसी के सन्दर्भ में मंडल कमीशन के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था हुई। उस मंडल कमीशन के सन्दर्भ में आर.एस.एस. की क्या राय थी, उस वक्त तत्कालीन, वह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ओबीसी की चिंता रखने वाली, वह भी मैं इनको साझा करूंगा।

Ans/rtm 15.10 2k 06.02.2025

सभापति महोदय, चुनाव से पहले तीन मुख्य बातें भारतीय जनता पार्टी ने कीं। दो दफा राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, दोनों के अन्दर उसका उल्लेख नहीं हुआ। पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान भारत के प्रधान मंत्री जी ने भी उसका उल्लेख अपने भाषणों में किया, राजस्थान की जनता के बीच में इसकी चर्चा की परन्तु राज्यपाल के दोनों अभिभाषणों के अन्दर उसकी चर्चा नहीं हुई।

सभापति महोदय, बहुत लाल डायरी, लाल डायरी बोला गया। राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है कि वह लाल डायरी है कहां। या तो अपनी असक्षमता को स्वीकार करते इस अभिभाषण के मार्फत कि जो कुछ भी हमने बोला, राजस्थान की जनता के सामने हमने जो बात की थी वह गलत थी। अगर वह स्वीकार्यता नहीं है तो शायद इस लोकतंत्र के अन्दर जो अधिकार आपको मिला है सरकार के तौर पर, वह गलत है।

सभापति महोदय, लाल डायरी के अलावा जेजेएम के भ्रष्टाचार के संदर्भ में बात की। अगर जेजेएम के अन्दर भ्रष्टाचार हुआ है तो एक वर्ष में इनको किसने रोका? आज राजस्थान के अन्दर आज जो पेयजल की उपलब्धता है वह बहुत कम है। जमीन के अनुपात में हम लोगों को बहुत कम जल मिल रहा है, पूरे हिन्दुस्तान में सबसे कम है। पेयजल हम लोगों की सबसे पहली प्राथमिकता है। जेजेएम योजना बनी, जेजेएम योजना के अन्तर्गत जो व्यवस्थाएं हुईं उसमें कहां कमियां रह गईं, क्या यह हम लोगों की सामुहिक जिम्मेदारी नहीं बनती। यह राजस्थान सरकार है, कोई कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की व्यवस्था संविधान ने नहीं दे रखी। यह आपके समझ की कमी है कि अपने आपको आप सीमित कर जाओ कि नहीं पहले कांग्रेस की सरकार थी, पहले भी कांग्रेस सरकार नहीं थी वह राजस्थान सरकार थी और आज भी कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, राजस्थान सरकार है। जेजएम के अन्तर्गत जो कुछ भी कमियां रही उसके बारे में हम लोगों ने कभी भी यहां चर्चा नहीं की, और कौन करेगा। जेजेएम का पहला कदम, सर्वे के मार्फत उस इलाक़े के सन्दर्भ में योजना

बनानी है उसके अन्दर कमी रह गई, उसमें कमी रहने के कारण यह जेजेएम की परिस्थितियां बनीं। मेरे से पूर्व बाड़मेर से आने वाली विधायिका ने बात करी कि जेजेएम के अन्दर स्वीकृतियां नहीं हुई। मेरे बायतू विधान सभा में 100 प्रतिशत राजस्व गांव में जेजेएम की स्वीकृति हुई। परन्तु उसमें हम लोगों के पास जो चुनौतियां आ रही है, वेरिएशन का प्रावधान नहीं है। अगर गुणवत्ता में किसी ने भी कमी रखी, कोई भी ठेकेदार हो, अधिकारी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करो। आप लोगों ने की भी है, शिक्षक ने कुकृत्य किया, आप लोगों ने उसके खिलाफ कार्यवाही की, मैं सदन के मार्फत राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने अच्छा काम किया। कोई भी सरकारी अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, अगर वह कुकृत्य करता है तो उसको अधिकार नहीं है। हम लोगों को कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं है। एक सामान्य नागरिक से भी हम लोगों के अधिकारों की कटौती होती है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है। सरकार में कोई भी चाहे वह कितने ही बड़े पद पर हो अगर उसका संरक्षण करता है तो वह गलत है, गलत है, गलत है। जेजेएम में 2023-24 में 06 हजार 803 करोड़ खर्च हुए थे। इस वर्ष 2024-25 के अन्दर सिर्फ 34 सौ 44 करोड़ ही हुए हैं। यह खर्च और कैसे बढ़े। अगर यह योजना हम लोग सफल नहीं कर पाए तो भविष्य में हम लोगों को कोई भी दूसरी योजना इस तरह की नहीं मिलेगी। छोटूसिंह जी ने निवेदन किया था कि सिर्फ पेयजल के ऊपर हम लोगों का जीवन नहीं है, पशुपालन भी है। इसके अन्दर प्रावधान है कि 50 लीटर का 80 लीटर कैसे हो सके। मेरा निवेदन है कि एक दिन का एक सत्र हम लोग इस विधान सभा में पेयजल के सन्दर्भ में रखें। जो भी कमियां रही हैं, वे कमियां पूरी की पूरी हम लोगों पर ही छोड़ दो, हम लोगों को उसका ओलमा दे दो, क्योंकि एक साल से तो आपने वह कमियां ही कमियां करीं। राजस्थान की जनता ने आपको जो जिम्मेदारी दी, एक साल तक आपने उसके ऊपर कार्य नहीं किया। हर बात में यह कि पिछली सरकार ने यह किया यह नहीं किया, एक साल आप लोगों को दिया।

सभापति महोदय, पेपर लीक के सन्दर्भ में। पेपर लीक क्या है, किसलिए हो रहा है, इसकी जड़ में हम लोगों को जाने की आवश्यकता है। आज की हमारी शैक्षणिक व्यवस्था है, आज स्कूली विद्यालय व्यवस्था के अन्दर हम हमारे बच्चों को किस दिशा में भेज रहे हैं। कुछ चंद संस्थाओं के एंट्रेस के लिए, उस एंट्रेस टेस्ट में कैसे सफल हो सके, उस सन्दर्भ में हम अपने स्कूली बच्चों की प्रतिभा कैसे आगे बढ़ाएं, उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे। इस सदन में भी नहीं कर रहे। इस सदन में भी तेरे-मेरे की बात कर रहे हैं। आज बच्चा स्कूल से कोचिंग संस्थाओं की ओर जा रहा है। कोचिंग संस्था के अन्दर क्या माहौल बना हुआ है, कोटा के अन्दर सुसाइड हो रहे हैं, वह सुसाइड गलत है, उन बच्चों को तनाव क्यों है। आज हम लोग चर्चा करके व्यवस्था में परिवर्तन व सुधार नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इस सन्दर्भ में बात हो रही है कि कोटा सेफ है, सुरक्षित है, और तो और संवैधानिक पद पर बैठे हमारे लोकसभा अध्यक्ष को भी यह कहने की जरूरत पड़ गई कि कोटा सुरक्षित है क्योंकि उनका गृह जिला है। जो मूल कारण है, कॉलेज के अन्दर बच्चे आते हैं उन बच्चों के लिए हम क्या

करते हैं, उनको हम सब मिलकर धकेलते हैं कि कॉलेज की शैक्षणिक व्यवस्था के माध्यम से वे योग्य नहीं बनें, किसी भी तरह से चंद नौकरियां, हमारे राजस्थान की जनसंख्या साढ़े आठ करोड़ है और आपने चार लाख का लक्ष्य रखा, कितना होगा वह भविष्य में पता चलेगा। चार लाख नौकरियां। नौकरी क्यों चाहते हैं कि हम लोगों को सुरक्षा मिलती है सरकारी नौकरी के मार्फत। हमारी अर्थव्यवस्था के अन्दर हम लोगों को बहुत कम स्थान मिल रहा है, उसके लिए प्रयास हो रहे हैं, कुछ और भी बढ़ोतरी हो जाए, उसके लिए हम कोचिंग संस्थाओं की तरफ धकेल रहे हैं कि चंद परीक्षा कैसे पास कर ले, उस परीक्षा को पास करने से उनको सुरक्षा मिल जाए।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि यह सदन इस बारे में गंभीरता से चर्चा करें कि यह दोनों के दोनों संस्थाओं के एंट्रेस और सरकारी नौकरियों के सन्दर्भ में पेपर, इंटरव्यू की व्यवस्था है इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है क्या। दुनिया के अन्दर दूसरी जगह भी वैकल्पिक व्यवस्था हुई है। अगर हम चर्चा नहीं करेंगे, आरोप-प्रत्यारोप, बड़े लफबाजी, आरपीएससी गलत है, आरपीएससी को भंग कर दो, यह सब बातें हम लोगों में से ही कही, कभी आप लोगों ने करी होगी, कभी हम लोगों ने करी होगी। आरपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा की व्यवस्था है उसके अन्दर हम परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या परिवर्तन हो सकता है। समय कम है, 20 मिनट होते ही आप घंटी बजा देंगे, नहीं तो इस सन्दर्भ में मेरी सोच थी वह मैं आप लोगों को बताता।

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार कैबिनेट से मुझे यह आशा नहीं थी। आज जब राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी को आपने याद किया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम भी अटल बिहार वाजपेयी जी को बहुत श्रद्धा से मानते हैं। सैद्धांतिक तौर पर उनसे असहमत हो सकते हैं। आपने पूरे राज्यपाल अभिभाषण में एक दफा भी डॉ. मनमोहन सिंह जी जो अभी हमारे बीच से गए हैं, उनका नाम तक नहीं लिया, मुझे दुख हुआ। इतना छोटा मन नहीं रखना चाहिए। आप राजस्थान का नेतृत्व कर रहे हो, किसी एक विचारधारा, एक दल का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। डा. मनमोहन सिंह जी ने हम लोगों को क्या-क्या नहीं दिया। डॉ. मनमोहन सिंह जी ने नरेगा के माध्यम से राजस्थान को क्या नहीं दिया। आज यश लेने के लिए हम लोग बहुत बातें करते हैं कि रिफाइनरी हमने बनाई, हम लोगों के अन्दर भी यश की बड़ी प्रतिस्पर्धा है, आप लोग भी हो, आप लोग भी जाकर वहां करते हो। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, पूरे के पूरे घटनाक्रम को मैंने नजदीकी से देखा, किसी एक व्यक्ति ने राजस्थान रिफाइनरी के अन्दर फैसला किया तो उनका नाम स्व. डॉ. मनमोहन सिंह जी है। बाकी सबके सब उसके श्रेय के लिए, उसके अवरोधक के लिए था। इस समय मैं आज उनको भी याद करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, हम लोग आज विकास की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, उसके साथ-साथ कुछ और बातें भी हम लोगों के बीच आती है। सोलर की बात हुई उस सोलर से हम लोगों को, आने वाले समय में जो कठिनाईयां हैं, आने वाला समय क्या है, मेरा

निवेदन है कि इस सदन को इसके सन्दर्भ में, हम सब लोगों को करना है। आज हिन्दुस्तान और राजस्थान के पास जो युवाओं की ताकत है, क्या यह युवाओं की ताकत आगे भी रहेगी, नहीं रहेगी। आज युवा प्रदेश है, युवा देश है। भविष्य में हम युवा देश, युवा प्रदेश नहीं रहेंगे। अगर हम यह आंकड़ा देखें, टोटल फर्टिलिटी रेट प्रजनन दर की बात करें तो 2.19 रहनी चाहिए जो हमारी जनसंख्या है वह रहने के लिए, वैसे की वैसे रहने के लिए। 1950 के अन्दर वह 6.18 थी और 2021 में वह 1.9 रह गई।

VPS-RTM-06.02.2025-15.20-2l

हम लोगों की जनसंख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। भारत के अन्दर, राजस्थान के अन्दर उसमें कमी हो रही है, और तो और इन संस्थाओं ने 21 हजार के अन्दर 1.24 का प्रीडिक्शन किया है कि दो के अनुपात के अन्दर एक ही जनसंख्या भारत में और राजस्थान में रहेगी तो आज हम लोगों को यह युवा भारत, युवा राजस्थान का अवसर मिला हुआ है, उसका फायदा हम लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं? कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, कई उद्योगपतियों ने भी ऐसे उदाहरण दिये हैं। आप किशनगढ़ के अन्दर देख लो, किसी सरकार ने नहीं किया, किशनगढ़ के अन्दर जो आज एशिया की सबसे बड़ी मार्बल की या स्टोन की मंडी बनाई तो हमारे यहां के राजस्थान के उद्योगपतियों ने और व्यवसाइयों ने बनाई है। क्या हम लोगों की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस तरह से हम लोग आगे बढ़ें?

आज सिर्फ उद्योग के अन्दर ही नहीं लिटरेसी के अन्दर भी पिछले दिनों जयपुर लिटरेसी फेस्टिवल हुआ, इस तरह की और कई चीजें हों, भविष्य के अन्दर हम कैसे आगे बढ़ सकें, किस दिशा में बढ़ सकते हैं? टेक्सटाइल के अन्दर हम लोगों के पास बहुत अवसर है। लगातार आज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करते हैं तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मंत्रीजी के हाथ में नहीं है। मेरी सरकार के वक्त भी मैंने यह बोला कि यह बोर्ड और कॉर्पोरेशन की यह जो माया है यह बिलकुल ही अलग है। हमारे समय में शान्ती धारीवालजी को हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया, वह इकलोता पद था, उसके अलावा इन सब बोर्ड और कॉर्पोरेशन के अन्दर आई.ए.एस. अधिकारी ही रहते हैं। उसके कारण इस समस्या के समाधान के अन्दर हम लोगों की कहीं भी भागीदारी नहीं रहती है इसके सन्दर्भ में भी हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए।

जो अधिकार संविधान ने हम लोगों को दिया है उस अधिकार को हम लोग और कहीं पर सौंप रहे हैं यह बात मैं आज की सरकार में ही नहीं कह रहा हूं यह पहले भी मैं बोल चुका हूं। जो यह विकास हो रहा है उस विकास के अन्दर माननीय सभापति महोदय, हम लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। बहुत बड़ी चुनौतियां क्या-क्या हैं? आज जो सोलर पावर से हम लोगों को ऊर्जा मिल रही है उस सोलर पावर से ऊर्जा के अन्दर हम लोगों के सामने आने वाले समय के अन्दर जो भी ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन, जो बिजली ले जाने के लिए जो व्यवस्था बना रखी है उसके अन्दर लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, गांव दर गांव यह

समस्या होती जा रही है। केन्द्र सरकार की 05 नवम्बर, 2024 से पहले इसमें कोई पॉलिसी नहीं थी। 05 नवम्बर, 2024 को यह पॉलिसी बनाई है। हम लगातार यह मांग करते आ रहे हैं, पिछले कम से कम पांच-दस सालों से, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिस किसी ने भी यह पॉलिसी बनाई, कम से कम पॉलिसी तो बनाई। आप नहीं हो, यह गलतफहमी छोड़ दो, यह राजस्थान सरकार है। यह अपने व्यक्तिगत तौर के ऊपर अपनी आइडेंटिटी के कारण इस राजस्थान को और पीछे नहीं धकेलें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): बी.जे.पी. की सरकार थी।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): बी.जे.पी. सरकार भी संविधान के अन्दर कोई व्यवस्था नहीं है इसीलिए तो आपको संविधान के सन्दर्भ में बारबार हम लोग चेता रहे हैं तो उसके अन्दर जो पहले से व्यवस्था थी, वह अलग बात है कि अब कुछ मुआवजा इसमें बढ़ रहा है तो मेरे जैसे जन-प्रतिनिधि जाकर उसका श्रेय लेने की बात कर लेते हैं कि जो भी अब हो रहा है, पांच मीटर तक वहां पर जो खंभे लगे हुए हैं, उसके अन्दर दो टाइम डी.एल.सी. रेट से मिल रही है और लाइन के नीचे डी.एल.सी. रेट से 30 प्रतिशत मिल रही है पर, माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही कम है। हमारे सदन और राजस्थान सरकार की तरफ से यह बात जानी चाहिए कि इस पॉलिसी के अन्दर और कैसे हम लोग उनको आगे बढ़ा सकते हैं?

माननीय सभापति महोदय, आज के समय के अन्दर जो ये तार लेकर जा रहे हैं, उन तारों के ऊपर 27 मीटर से लेकर 54 मीटर तक उन तारों के नीचे कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान है और यह बड़ा सख्त कानून है। यह सख्त कानून किसके अंतर्गत है? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अन्दर जो शक्तियां दे रखी हैं ऊर्जा विभाग को उसके तहत कोई भी उसके काम की खिलाफत नहीं कर सकता है अगर खिलाफत करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो जाती है तो मेरा यह निवेदन है कि यह जो ट्रांसमिशन की लाइनें हैं, यह ज्यादातर 400 के.वी. की और 765 के.वी. की ट्रांसमिशन लाइनें ज्यादा जा रही हैं तो जो नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, पहले ट्विन मेगा के नाम से जो व्यवस्था चल रही है, उसको क्या एच.पी.डी.एस. की जो नई टेक्नोलॉजी आयी है, उसके माध्यम से हम करेंगे तो यह तार, पोल और खंभे हम लोगों को कम लगाने पड़ेंगे। पूरा का पूरा ट्रांसमिशन कॉरिडोर की आवश्यकता है। कहीं दस-पन्द्रह किलोमीटर में ट्रांसमिशन कॉरिडोर हम लोग बना दें और वहां से ही नेशनल ग्रिड के अन्दर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर से जो सोलर ऊर्जा जा रही है और आज एच.पी.डी.एस. हिंदुस्तान में लग चुकी है। आगरा से दिसपुर, असम के अन्दर 3200 किलोमीटर वह प्रणाली लग चुकी है तो हम लोगों के यहां राजस्थान के अन्दर भी वह होनी चाहिए। राजस्थान सरकार नहीं कर सकती, वह केन्द्र सरकार कर सकती है तो ऊर्जा मंत्रीजी मेरा यह निवेदन है और सरकार से मेरा यह निवेदन है कि उस सन्दर्भ के अन्दर आप करें।

ओरण भूमि के सन्दर्भ में निवेदन है कि हमारी ओरण भी डिस्टर्ब हो रही है, इको सिस्टम भी हम लोगों का डिस्टर्ब हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम

से यह बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार के अन्दर 29 हजार बीघा जो सरकारी जमीन थी उसको ओरण में दर्ज किया गया। कितना? 29 हजार बीघा को। कहीं पर भी उस पर विवाद नहीं हुआ। कहीं भी उस पर चर्चा नहीं हुई। कहीं भी उसका विरोध नहीं करने की जरूरत पड़ी। जहां फैसला हो रहा था, उस फैसले के अन्दर यह हुआ। पिछले दिनों के अन्दर कुछ कम्पनियां हम लोगों की ओरण, जो मुंह बोली ओरण है, यह तमाम ओरण जो 29 हजार 500 बीघा की थी, वह सब हम लोगों की मुंह बोली ही थी। पिछले दिनों के अन्दर वे कम्पनियां हम लोगों के यहां इस तरह के ओरण के ऊपर काम करना चाह रही थी और मगरा और बयां के अन्दर 1038 बीघा सिर्फ छोड़ी है। ओरण के अन्दर दर्ज नहीं की गयी तो मेरा यह निवेदन है राजस्थान सरकार को कि जो भी मुंह बोली हम लोगों की ओरण है जो उसके अन्दर पिछली सरकार ने की, उसी तरह से इस सरकार के अन्दर भी वह करे। यह ओरण की बात अभी नहीं चल रही है, कोई साल भर से ही नहीं चल रही है, ओरण की बात सदियों से चल रही है और पिछली सरकार जो हम लोगों की सरकार थी, कैबिनेट की सरकार थी, उसने इस तरह का फैसला लिया है तो मेरा कैबिनेट के तमाम सदस्यों से निवेदन है कि आप भी इस तरह का फैसला लो।

तालाब के लिए और गोचर के सन्दर्भ में भी यह बात करी गयी। मेरा यह निवेदन है कि इस तालाब के लिए पोकरण के विधायक महोदय ने भी बात करी है तो आओ, चलो, बाड़मेर के अन्दर जो तालाब के अन्दर या आदू रामजी चौहटन के तालाब के ऊपर जो अतिक्रमण है, अपन सब लोग मिलकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अभी तत्काल अपन वहां जाकर उस तालाब से अतिक्रमण हटाने की शुरूआत करें। उसके ऊपर किसी प्रकार की राजनीति, सियासत नहीं करें। हमें पता है और आपको भी पता है कि उन तालाबों के ऊपर किसी न किसी तरह का अतिक्रमण हुआ है। तालाब, ओरण और गोचर को मुक्त करें।

अंत में, माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने तामलोर का जिक्र किया। उसके अन्दर पेयजल की योजना के सन्दर्भ में जिक्र किया। तामलोर की योजना का मैं इतिहास बताना चाहता हूं। यह आई.जी.एन.पी. के माध्यम से डी.एन.पी. से यह इलाका जुड़ा हुआ था पर डी.एन.पी. के अन्दर प्रतिबंध होने के कारण यहां पर योजना की स्वीकृति नहीं हो पायी और उस योजना के अंतर्गत जब स्वीकृति नहीं हुई तो उस समय के तत्कालीन विधायक 2009 से 2014 के बीच में रामसर में भील समाज के कार्यक्रम में उन्होंने यह बोला कि यहां पर यह योजना नहीं आ सकती, आपके यहां टांकों के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

श्री सभापति: प्लीज, समाप्त कीजिए।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): उस समय मैं लोक सभा का सदस्य था और उसको नर्मदा से जोड़ा, आज उसी योजना से यहां पर पानी आया है।

अंत में, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने, थार के लोगों ने एक कार्यक्रम की शुरूआत की है, थार की बात, उसमें आने वाले समय में थार के टांकों के सन्दर्भ में हम

लोग बात करेंगे। राज्यपाल महोदय, आपसे यह निवेदन है कि थार के टांके क्या हैं और टांकों के माध्यम से हमको गुणवत्तायुक्त पानी मिले। मनमोहन सिंहजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए टांकों के अन्दर नरेगा का प्रावधान किया, उसके माध्यम से आप लोगों को वे टांके गलत चीज लग रहे थे, प्रधान मंत्रीजी को भी गलत लग रहे थे, एक लाख से ज्यादा टांके हैं।

अंत में, मेरा निवेदन यही है, समय कम है।

श्री सभापति: आप समाप्त कीजिए।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): जिनको आजादी ही 2014 में नजर आयी, वे लोग सरदार पटेल और अम्बेडकर जी की बातें कर रहे हैं। क्योंकि उनसे पहले उनका आजादी के अन्दर योगदान था।

श्री सभापति: श्री देवी सिंहजी शेखावत।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): मुझे दु:ख होता है कि उन लोगों के मुंह से आजादी और संविधान की बात हो रही है तो मेरा यह निवेदन है कि या तो वे सही हैं या ये सही हैं। ..व्यवधान.. आप बैठो मंत्रीजी, आप बड़े सीनियर मंत्री हो। एक जोगारामजी भी हम लोगों के यहां, जोगारामजी, जो हमारे मारवाड़ के सबसे सज्जन परिवार से आते हैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय, अंकित नहीं होगा।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): 000

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, राज्यपालजी के अभिभाषण पर आपने मुझे इस सदन में, राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं सभापति महोदय का आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही जिन लोगों ने, मेरे बानसूर विधान सभा क्षेत्र की 36 कौम के लोगों ने मुझे यहां इस विधान सभा में भेजा, जिसके कारण मुझे यह मौका मिला है, उनका भी मैं अभिवादन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लालजी जो ग्रामीण परिवेश और किसान परिवार से आते हैं, उन्होंने एक साल के कार्यकाल में जो कार्य करके दिखाया, मैं यह कहता हूं कि यह अभूतपूर्व है और आज तक के इतिहास में किसी भी मुख्य मंत्री के कार्यकाल में एक साल में इतना काम नहीं हुआ जितना भजन लालजी ने किया।

ssy/rtm/06.02.2025/15.30/2m

माननीय सभापति महोदय, जल जीवन है और कहा जाता है कि हमारी जो देह है यह पंच महाभूतों आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल से बनी हुई है, जिसमें जल भी मुख्य है।

अभी मेरे से पूर्व वक्ता हरीश जी कह रहे थे कि हमारे यहां पानी की कमी है। हमारे हिन्दुस्तान में सतही भू जल 4 प्रतिशत है और राजस्थान में उसकी मात्रा केवल 1 प्रतिशत है। हमारे पूर्वी राजस्थान में ज्यादातर जो पब्लिक है, जनता है वह खेती पर या पशुपालन पर निर्भर है। 17 जिलों के 3 करोड़ लोगों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, गांवों का अस्तित्व बना रहे, किसानों का अस्तित्व बना रहे, वे खुशहाल हो सकें, समृद्ध हो सकें इसके लिए

भजन लाल जी ने एक भागीरथ के रूप में काम किया। ईआरसीपी की योजना, पीकेसी जिसे राम सेतु परियोजना नाम दिया गया है, उसको लाने का काम किया।

मैं यहां सदन में बैठे हुए रोज यह सुन रहा हूं कि ईआरसीपी का मेमोरेंडम नहीं देखा। क्या एमओयू हुआ हमने नहीं देखा। लेकिन आप सबको यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें प्रथम चरण के 12 हजार करोड़ रुपयों के कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है और बहुत जल्दी ही उस पर काम होने वाला है। ईआरसीपी के अलावा भी चाहे इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो, चाहे नर्मदा नहर परियोजना हो, चाहे सीकर, झुंझुनूं, चूरू के लिए यमुना जल समझौता किया उससे भी करोड़ों लोगों और हमारे किसान भाइयों को फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, जिसकी वसुन्धरा राजे जी की सरकार ने परिकल्पना की थी, उसे मूर्त रूप भजन लाल जी ने दिया। देश के प्रधान मंत्री जी ने सरकार का एक साल पूर्ण होने पर इस योजना को प्रारंभ कर दिया है। माननीय भजन लाल जी के मुख्य मंत्री बनते ही यहां राजस्थान में ऊर्जा का यह हाल था कि उन्हें दूसरे ही दिन दिल्ली जाकर छत्तीसगढ़ के मंत्रियों से मिलना पड़ा, जो हमारी कोयले की आपूर्ति बंद हो गई थी, उसको उन्होंने पुनः चालू करवाया। इसी की बदौलत आज किसानों को 6 घंटे बिजली थर्मल पावर प्लांटों के माध्यम से मिल सकी। कांग्रेस का ऐसा कोई विजन नहीं था। कांग्रेस की ऐसी कोई सोच नहीं थी। जब आपकी बारी आये तो आप अवश्य बतायें कि पिछले 5 सालों में पानी को लेकर आपने क्या किया? ऊर्जा के क्षेत्र में एक यूनिट बिजली के उत्पादन के लिए कोई सकारात्मक कार्य पिछली सरकार ने किया हो तो वह आप सदन के माध्यम से अवश्य बतायें।

माननीय सभापति महोदय, प्रधान मंत्री सौर ऊर्जा के माध्यम से घर-घर में बिजली जा रही है। हमारे जो किसान भाई हैं, उनको समृद्ध करने के लिए, वह ना केवल अन्नदाता रहें बल्कि बिजली के दाता भी बनें, इसमें किसानों को भी अलग से कुसुम योजना में कवर किया गया है ताकि वे समृद्ध हो सकें। उनकी जो अनुपयोगी, बंजर, बगैर पानी की जो जमीन है उससे भी उनको आय हो सके। इस प्रकार की दूरदृष्टि हमारे मुख्य मंत्री जी की रही है। राजस्थान निरंतर आगे बढ़ रहा है।

रिसर्जेंट राजस्थान के माध्यम से जो 35 लाख करोड़ रुपये एमओयू हुए हैं, उनमें से 24 हजार करोड़ के कार्य धरातल पर उतर चुके हैं। 350 बिलियन डालर की जो हमारे बजट की सोच है, उसकी तरफ यह महत्वपूर्ण कदम है। आज औद्योगिक विकास चारों तरफ हो रहा है। सड़कों का जाल फैल रहा है। पिछले साल जितनी घोषणाएं बजट में मुख्य मंत्री जी के द्वारा, हमारी वित्त मंत्री जी के द्वारा यहां हुईं, मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि मेरे भी विधान सभा क्षेत्र में वे सारी योजनाएं धरातल पर आ चुकी हैं। जो जमीन अलॉट की थी, उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। जो करोड़ों रुपयों की सड़कें स्वीकृत हुई, उन सबके काम चल रहे हैं। शायद पूरे राजस्थान में वे चल रहे होंगे।

किसानों को दिन में बिजली इस साल भी खूब मिली है। हमारे मुख्य मंत्री जी की नीयत अच्छी है तो ईश्वर भी मेहरबान है। इस बार मावठ से हमारे जो किसान भाई हैं, वे बहुत खुश

हैं। बहुत अच्छी सभी के फसल होगी, ऐसी उम्मीद है। राजस्थान की 76 प्रतिशत जनता जो गांव में रहती है, उनके हाथ में पैसा आयेगा और हमारा राज्य समृद्ध होगा।

पिछली बार सरकार इतनी कमजोर थी कि होटलों में बैठी थी। अपने किये हुए वादे उन्होंने कभी नहीं निभाये। बजट में बानसूर विधान सभा क्षेत्र के, मेरे क्षेत्र के किले पर सौंदर्य करण की घोषणा हुई। वहां भी उन्होंने करोड़ों का बजट जारी किया। तालवृक्ष के लिये उन्होंने करोड़ों का बजट जारी किया। बानसूर से नारायणपुर रोड पर जो बोर्ड लगे हैं, वह तो बड़ी ही हास्यास्पद स्थिति है क्योंकि जो उद्योग मंत्री थीं, वे वहीं की थीं। उन्होंने बड़े-बड़े उद्योग लगाने के वादे किये और बोर्ड लगाये। लेकिन धरातल पर कोई भी कार्य नहीं हुआ। मैंने यह सदन के माध्यम से भी जाना है कि वहां पर कभी कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं रहा कि बानसूर में उद्योग खुलें।

हमारे युवा जिनकी सारी की सारी परीक्षाओं के पेपर कांग्रेस सरकार में आउट हुए। यह लगता है कि नकल गिरोह ही असल गिरोह हो गया था क्योंकि वह चाहता जिसको नौकरी दिलाता था। ऐसे-ऐसे लोग नौकरी में आ जाते थे कि भाई, क्या करता है, यह शराब के ठेके पर बैठता है और अचानक लोगों को पता लगता कि वह टीचर बन गया। इतनी नकल उनमें हुई। इसके उलट हमारे मुख्य मंत्री जी की दृढ़ संकल्प शक्ति से आज जितने पेपर हुए हैं, उनमें एक में भी नकल नहीं हुई है।

साथ ही, आज तक एक साल के लगभग कार्यकाल में 59236 नौकरियां दे दी गई हैं। जूली साहब बहुत खुश हो रहे हैं। इस साल 2025 में 81 हजार नौकरियों का कैलेंडर जारी हो चुका है। 172990 सर्विस प्रोसेस में हैं, पाइप लाइन में चल रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे चुनावी एजेंडे में जो वादे किये थे, ये 5 साल नहीं, केवल 3 साल में पूरे हो जायेंगे और राजस्थान विकास में बहुत तेज दौड़ेगा।

पिछले 5 सालों में सरकार होटलों में व्यस्त रही। जनता पर भार पटका। पूरे देश में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल अगर कहीं बेचा तो कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में बेचा। हमारे मुख्य मंत्री जी ने आते ही राजस्थान में जो वैट था, उसमें 2 प्रतिशत की कटौती की, जिससे डीजल और पेट्रोल के भावों में डेढ़ रुपये से लेकर 6 रुपये तक का राजस्थान की आम जनता को फायदा हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं और सदन में ना पक्ष का भी समर्थन चाहूंगा कि जिस तरह और वर्गों का पंचायत और निकायों में रिजर्वेशन है, इसी तरह ईडब्ल्युएस में जो पात्र हैं, उनका भी नगरपालिका और पंचायत में कोटा किया जाये। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री अमित चाचाण।

श्री अमित चाचाण (नोहर): सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। 2014 से, जब से केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक जोड़ी की जो सरकार सत्ता में बैठी है 2014 के बाद पूरे

देश के अन्दर उन्होंने राजनैतिक स्तर को गिराने का काम किया। जहां-जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उन सदनों की गरिमा को गिराने का काम देश में और राज्य में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं।

आज सत्ता पक्ष के लोग जब भी भाषण की शुरूआत करते हैं, जैसे हम शुभ कार्य के लिए गणेश जी की वंदना करते हैं वैसे ही यह देश के प्रधान मंत्री जी की करते हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब 2014 से पहले प्रधान मंत्री गुजरात के मुख्य मंत्री थे तब एक भाषण दिया था कि मैं प्रदेश का मुख्य मंत्री हूं, मुझे पता है कि रुपया जैसे-जैसे गिरता है देश के प्रधान मंत्री की गरिमा भी उसी अनुपात में गिरती है।

spp/rtm/06.02.2025/15:40/2n

मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि उस समय तो डॉलर का भाव 58 रुपये था, आज 88 रुपये पहुंच गये तो गरिमा हमें ढूंढनी चाहिये कि पाताल में कहां वो देश के प्रधान मंत्री की गरिमा पहुंच चुकी है। 10 वर्षों के अंतराल में महंगाई आसमान को छू रही है। आज गरीब का चूल्हा नहीं जल पा रहा है। यह देश के हालात हैं।

आज हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग, जो 71वें स्थान पर थी, आज वह 90वें स्थान पर पहुंच चुकी है। आज देश के अन्दर साढ़े छह लाख करोड़ रुपये का कर्ज हो चुका है और देश का प्रधान मंत्री, जिनको देशवासियों के मन में आत्मविश्वास भरना चाहिये, आज हमारा प्रधान सेवक क्या भाषण दे रहा है। एक प्रत्येक भारतीय के अन्दर डर और भय पैदा कर रहा है कि आपकी भैंस चोरी कर लेंगे, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। यह देश का प्रधान मंत्री इस तरह के वक्तव्य दे रहा है। आज हमें शर्म आती है। बहुत-सी हमारी वेशभूषाएं थीं, बहुत-से हमारे धर्म थे, बहुत-सी हमारी जातियां थीं, एक साथ बैठकर उनके अन्दर सौहार्द का वातावरण था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने निजी स्वार्थों की वजह से पूरे देश के अन्दर भाईचारे को खत्म कर दिया। पूरे देश के अन्दर जहर घोलने का काम किया। आज भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। परिवार को परिवार से लड़ाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिये पूरे देश के अन्दर माहौल को खत्म करने का काम इस देश में बैठी केन्द्र की तानाशाह सरकार कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, आज जो बात कर रहे हैं, इन्होंने राज्यपाल महोदय से अभिभाषण पढ़ाया। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि एक वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं का ही शिलान्यास किया या उद्घाटन किया। एक वर्ष के कार्यकाल में अपने पास से एक पैसे का भी काम इस राजस्थान की सरकार ने नहीं दिया। यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। यह नहीं चाहती कि गरीब का चूल्हा जले, यह नहीं चाहती कि गरीब को अंग्रेजी शिक्षा मिले, यह नहीं चाहती कि किसान आगे बढ़े। तभी तो किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है। कांग्रेस के हमारे नेताओं ने एक समाज सेवा के रूप में काम

किया था कि राजनीति के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति को हम न्याय दिलाएं। गरीब का हम चूल्हा जलाने का काम करें और अंतिम छोर तक विकास की गंगा को पहुंचाने का काम करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ड्राफ्टिंग चन्द पूंजीपति घरानों के आफिसों से चलती है और उन्हीं के लिये ये नियम और कायदे कानून बनाये जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे पूर्व मुख्य मंत्रीजी अशोक जी गहलोत ने देखा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार महंगाई बढ़ रही है, गरीब का चूल्हा नहीं जल रहा, गरीब के बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनको मुख्य मंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना देने का काम किया जिससे कि गरीब के घर में भी चूल्हा जले। लेकिन वह भी इनको रेवड़ी नजर आयी और मुख्य मंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना को भी बन्द करने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर दो-दो नियम लागू हैं। एक तो वह जिसने पूर्व में कनेक्शन किया, उसके परिवार को 200 यूनिट बिजली निःशुल्क मिल रही है, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अगर किसी ने बिजली का कनेक्शन लिया, उस गरीब आदमी को 200 यूनिट बिजली नहीं मिल रही है। माननीय सभापति महोदय, मात्र 500 रुपये का जब बिल आता है तो उस गरीब की जेब में पैसे नहीं होते। इस कारण से उनका कनेक्शन काट दिया जाता है और उनके बच्चे अंधेरे में रहते हैं। हमारे पूर्व मुख्य मंत्रीजी, गहलोत जी ने उनका दर्द समझा था, तब जाकर 200 यूनिट बिजली निःशुल्क की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये तो रेवड़ियां बांट रहे थे। गरीब का दुःख-दर्द दूर करना रेवड़ियां बांटना नहीं होती।

माननीय सभापति महोदय, जोगाराम जी कह रहे थे कि हमारी सरकार के पास अधिकार है कि हम किसी भी जिले और संभाग को खत्म कर सकते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि संविधान के अनुसार जिसको जितने अधिकार दिये गये हैं, उतने ही ज्यादा उनके कर्तव्य भी उनको दिये गये हैं। आप सिर्फ अधिकारों की बात करते है पर आप कर्तव्यों की बात नहीं करते। आपका कर्तव्य यह भी है कि जनभावना के अनुरूप जनता की मांग को देखते हुए विपक्ष का मत रहता है कि जनता की भावना को सदन में रखे और सत्ता पक्ष का यह अधिकार होता है कि उनकी बातों को सुना जाये, लेकिन आपने सदैव जनता की मांग को अनसुना किया। जनता की मांग को आपने सुना नहीं, तब ही जाकर आपने 9 जिलों और संभागों को खत्म करने का काम किया।

आज आप मुख्य मंत्रीजी को भागीरथ-भागीरथ कहते हैं। एक कहावत है कि गांव बसा नहीं, मंगते पहले आ गये। एक बूंद पानी तो आप लेकर आये नहीं। अगर पानी की बात करते हो तो मेरे नोहर और भादरा की बात कीजिए। अशोक गहलोत जी ने नोहर फीडर की लाइन की घोषणा की थी और 28 गांवों को सिंचित करने के लिये 100 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किये थे। कहां चली गयी वह योजना? चुनाव से पूर्व आपके ही नेता दिल्ली में जाकर फोटो खिंचाते थे कि हमारी सरकार बनने के बाद हम पानी लेकर आयेंगे। आज तो कई इंजनों की सरकार है। हरियाणा में आपकी सरकार है, दिल्ली की, केन्द्र में आपकी सरकार

है, राजस्थान में आपकी सरकार है। फिर नोहर और भादरा को हमारे हिस्से का पानी क्यों नहीं मिल पा रहा? क्यों नहीं नोहर फीडर की रिलाइनिंग का काम हो रहा है? क्यों नहीं उन 28 गांवों को सिंचित किया जा रहा है? आपके कार्यकाल में जो सुई ब्रांच का निर्माण बंद कर दिया गया था, उस सुई ब्रांच का निर्माण कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं वहां निर्माण कार्य पूर्ण हो रहा? आपने बजट में तो पढ़वा दिया कि हमने हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों के लिये 108 करोड़ रुपये के खाळे बनवाये। मैं आपको कहना चाहता हूं कि नोहर और भादरा के लिये ही 200 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी हुई थी, उसको आपने रोकने का काम किया, क्योंकि आप नहीं चाहते कि किसान के खेत तक पानी पहुंचे और किसान के हाथ मजबूत हों।

आज आप बिजली की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम दिन में किसानों को बिजली दे रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले में देखिए, आपके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। सर्दी के मौसम में किसानों को बिजली नहीं मिल रही और किसानों की फसल आपकी वजह से बर्बाद हो रही है। उनको डिमांड जमा करवाये हुए बारह-बारह महीने हो गये पर उनको कृषि कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं आपकी वजह से। किसानों के जले हुए ट्रांसफार्मर नहीं मिले आपकी वजह से। किसानों के मीटर नहीं बदले जा रहे हैं आपकी वजह से। उनके जले हुए तार नहीं बदले जा रहे हैं आपकी वजह से। इंदिरा गांधी नहर में आपने फरमान जारी कर दिया कि 01 फरवरी से पानी नहीं मिलेगा। पूरे हनुमानगढ़ जिले के किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। आज वहां पर गेहूं की फसल पकाव पर है, लेकिन पानी नहीं मिलने की वजह से वह फसलें बर्बाद हो रही हैं और आप प्रदेश की जनता को एक असत्य सपना दिखाने जा रहे हैं। प्रदेश की जनता को मुंगेरीलाल के हसीन सपने दिखाने जा रहे हैं कि राजस्थान में पानी आयेगा। जहां व्यवस्था मौजूद है, वहां तो आप पानी पहुंचाकर दिखाइए।

आप भ्रष्टाचार के आरोप-प्रत्यारोप की बात करते हैं। एक भी मंत्री दावे के साथ कह दे कि मेरे डिपार्टमेंट में ब्लॉक से लेकर जयपुर तक भ्रष्टाचार नहीं होता। ....(व्यवधान)...

श्री सभापति: बिराजिए, बिराजिए। ..(व्यवधान)..

श्री अमित चाचाण (नोहर): हम एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के असली जन्मदाता जो हमारे अधिकारी हैं, आज भी 10 से 20 प्रतिशत का कमीशन, चाहे वह किसी भी डिपार्टमेंट में हो, निर्माण कार्य के लिये जाता है और वह कमीशन ईमानदारी का मानते हुए आफिसों में अधिकारी और कर्मचारी ले रहे हैं। वह लगाम हम क्यों नहीं लगा रहे हैं? चाहे हमारी सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो, सदियों से यह चलता आ रहा है। राज्य सरकार का गरीब जनता का 20 प्रतिशत का पैसा कमीशन के रुप में अधिकारियों की जेबों में जा रहा है। आप नियम बनाइए और आय से अधिक सम्पत्ति की जांच करवाइए। अधिकारियों की भी जांच करवाइए। आपको सब पता चल जाएगा। सब मंत्रियों की आंखों के नीचे यह काला धंधा हो रहा है। 20-20 प्रतिशत कमीशन उन अधिकारियों और कर्मचारियों की जेबों में जा रहा है। उसके बारे में किसी ने भी आज तक सोचने की बात नहीं कही। हम

तो आरोप-प्रत्यारोप लगाते रह जाएंगे, लेकिन जनता का पैसा कहां जा रहा है, यह भी हमें सोचना होगा।

माननीय सभापति महोदय, आज हम बात किसी भी किसान की कर लें, किसानों को यूरिया नहीं मिला। यूरिया के लिये लाइन में लगना पडा। बात हम बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया। आज गरीब के धरातल पर जाकर देखिए, गांव में जाकर देखिए, किसान की हालत देखिए, मजदूर के हालात देखिए। भारतीय जनता पार्टी को यह सब चुनाव में याद आते हैं गरीब, किसान, मजदूर, महिला, दलित, मध्यमवर्गीय, लेकिन सत्ता में आने के बाद वह इन सब नामों को भूल जाती है और दो ही शब्द याद रहते हैं 'हम दो हमारे दो' और उन्हीं के लिये यह देश में बैठी तानाशाह सरकार यह काम कर रही है। देश की तानाशाह सरकार ने चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया तो हमारे प्रदेश में बैठी हुई सरकार, जो हमारे चुने हुए जन-प्रतिनिधि थे, चाहे चेयरमैन हों, चाहे प्रधान हों, उनको गिराने का, उनको निलम्बित करने का काम किया और आज तक उन पर कोई दोष साबित नहीं कर पाये हैं। जिन्होंने अपने चहेते को पालिका का अध्यक्ष बनाया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, झाबरसिंह जी खर्रा बैठे हैं, आप एक उच्च कमेटी बनाकर उनकी जांच करा लीजिए, आप तो नोहर में ही जांच करा लीजिए।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री अमित चाचाण (नोहर): पिछले छह महीनों में जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, पूरे प्रदेश में थानों की बोलियां लग रही हैं और पोपाबाई का राज आ चुका है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है और कोई भी मंत्री-अधिकारी बोलने के लिये तैयार नहीं है। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री रामसहाय वर्माजी। ...(व्यवधान)..

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): कांग्रेस के राज में थाना बिक जाता था, तहसील बिक जाती थी और सारे कांग्रेस के लोग लूटते रहते थे। वह याद आ रहा है। .(व्यवधान)..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, या तो संसदीय मंत्री बोलें या सचेतक बोलें। आप खड़े हो जाते हो बार-बार।

श्री रमेश खींची (कठूमर): माननीय सभापति महोदय, इसको कार्यवाही से निकाला जाए। इन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग भूखे मर रहे हैं। इसको कार्यवाही से निकाला जाए। यह गलत बोल रहे हैं, बिलकुल अशुद्ध बोल रहे हैं।

श्री सभापतिः आप बिराजिए। बिराजिए। ..(व्यवधान)..

श्री रमेश खींची (कठूमर): आप एक भी नाम बताइए, कौन भूखा मर रहा है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपका नंबर आये तब पूछ लेना। ..(व्यवधान)..

श्री रमेश खींची (कठूमर): यह कोई तरीका है बोलने का। ..(व्यवधान)..

jyg/rtm/06.02.25/15.50/2o

श्री सभापतिः ...(व्यवधान)... विराजिये, विराजिये, विराजिये। ...(व्यवधान)... अंकित नहीं होगा।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आपणो अग्रणी राजस्थान शब्द से जो महक आ रही है उससे समूचा राजस्थान महक रहा है। माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण में जहां एक ओर सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियां दिखायी दे रही थी तो दूसरी ओर विकसित भारत, विकसित राजस्थान को लेकर दूरगामी सोच स्पष्ट हो रही थी।

माननीय सभापति महोदय, विपक्ष में बैठे मेरे साथी, जिनमें कई बुजुर्ग भी शामिल हैं, वो मात्र राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए असत्य पर असत्य बोले जा रहे हैं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी भजन लाल जी शर्मा ने कोई कार्य नहीं किया। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य को लेकर चल रही हमारी सरकार ने पहली बार राज सखी राष्ट्रीय मेले का आयोजन जयपुर में करवाया जिसमें 24 राज्यों के स्वयं सहायता समूहों ने भाग लिया। माननीय प्रधान मंत्रीजी की लोकल फोर वोकल थीम को ध्यान में रखते हुए 400 से अधिक स्टॉल लगाये गये जिनमें राजस्थान के 20 जीआई टैग के उत्पाद सम्पूर्ण भारत के 200 से अधिक जीआई टैग उत्पाद में बिक्री हेतु उपलब्ध रहे हैं। इस मेले में 650 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हुई जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विपक्ष का काम केवल बोलने का है, उनको केवल भर दिया जाता है कि आप तो पक्ष का विरोध कीजिये। कभी आप भी यहां पर बैठे थे, उस समय हम लोग विरोध नहीं करते थे, अच्छे काम करो आपको कोई कहने वाला नहीं है यह था हमारा विजन। अच्छे काम हुए उनके लिए बोलो तो सही कि काम हो रहा है लेकिन आपको केवल विरोध करना है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने राजीविका हेतु राज सखी मोबाइल एप जारी किया है जिसके माध्यम से राजीविका की कैडर बहिनों का मानदेय, राजकीय कर्मियों की भांति प्रत्येक 1 तारीख को उसके बैंक खाते में सीधा पैसा जमा होने लगा है। राजीविका कैडर का मानदेय ऑनलाइन सीधा खाते में भुगतान करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि राजस्थान देश में पहला राज्य बना है। ऑफलाइन मानदेय में लगने वाले समय और आंशिक भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलने से महिलाओं को अपार प्रसन्नता है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राजीविका परियोजना में 48 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभांवित किया जा रहा है। इस हेतु राजीविका परियोजना निदेशक का कार्य सराहनीय रहा है। अब मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि केवल विरोध ही मत करो, जो काम हो रहा है उसकी हों तो भर लो जो काम हो रहा है। आप लोगों को ताली बजानी चाहिए कि मुख्य मंत्रीजी ने ऐसा काम किया है। ...(व्यवधान)...

मैं अभी बताऊंगा, अभी आदर्श नगर का भी बताऊंगा। आदरणीय आपको आदर्श नगर के लोगों ने इसलिए नहीं चुना कि आप यहां आकर नारे लगाओ, आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा, पांच साल बाद में कि आपने सदन में यहां आकर केवल विरोध किया और नारे लगाये। चार दिन से सदन में देखा जा रहा है कि केवल आप विरोध करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। हाथ खड़े करके विरोध करने से काम नहीं होगा। आप अपने विधान सभा क्षेत्र में जाकर काम करो तब जाकर आपको पता पड़ेगा कि वहां काम क्या हो रहा है। इसलिए मैं माननीय सदस्य रफीक खान जी से विशेष निवेदन करूंगा कि नारे लगवाने के लिए लोगों को इकट्ठा नहीं करें और यहां पर आकर अपना काम करें। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आप अपनी बात रखिये।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): माननीय सभापति महोदय, एक ओर आँगन बाड़ी कार्मिक बहनों के मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है तो दूसरी ओर नौनिहालों के समुचित विकास के दृष्टिकोण से मुख्य मंत्री अमृत आहार प्रारम्भ कर बच्चों के लिए गर्म दूध की व्यवस्था की है।

माननीय सभापति महोदय, सबने देखा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिन-रात एक करके सम्पूर्ण राजस्थान के जिलों में तथा राज्य स्तरीय राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करवाया है। इस पर हमारे विपक्ष के सार्थियों को आपत्ति हो रही है। जो काम अच्छा हो रहा है कम से कम उसकी बड़ाई तो कर दिया करो। हम तो अभी नये हैं, आप लोग तो बहुत पुराने बैठे हुए हैं, आप लोग भी तो इस चीज को देखा करो।

माननीय सभापति महोदय, मानने से काम नहीं चलता है, महसूस करने से पता चलता है। ...(व्यवधान)... माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से आदरणीय डोटासराजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारी सरकार का पूर्ण भरोसा एवं विश्वास विगत 9 दिसम्बर को डोटासराजी ने राइजिंग राजस्थान को लेकर 'एक्स' पर टिप्पणी की थी कि उम्मीद है कि सरकार सिर्फ एमओयू नहीं करेगी, निवेश लायेगी और जनता को निवेश की सच्चाई बतायेगी। आपने सरकार से यह भी अपेक्षा की थी कि निवेश के साथ ही वो प्रदेश में पुख्ता कानून और व्यवस्था, भय मुक्त माहौल और निवेशकों को अपराधियों से सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी। आपकी इस टिप्पणी से यह तो साबित हो गया है कि विगत सरकार में बिगड़ी कानून व्यवस्था एवं भय पूर्ण माहौल से निवेश लाने में आप विफल रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से आदरणीय डोटासराजी को और अवगत करवाना चाहता हूं कि राइजिंग राजस्थान समिट की अभिनव पहल से हमारी सरकार के पहले ही साल में 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश की बुनियाद रखी गयी जो माननीय मुख्य मंत्रीजी के कुशल नेतृत्व तथा सरकार के प्रति निवेशकर्ताओं के विश्वास को प्रदर्शित करता है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी उप मुख्य मंत्री महोदया, आदरणीय दिया कुमारीजी ने आम जन को बेहतर आवागमन की सुविधा देने हेतु बिना भेदभाव किये राजस्थान के सभी 200 विधान सभा क्षेत्रों में 5-5 करोड़ रुपये तक की लिंक सड़कें बनायी और उन्होंने कोई

भेदभाव नहीं किया। उन्होंने यह नहीं देखा कि यह कांग्रेस का विधायक है या बीजेपी का विधायक है। उन्होंने सबको दिया है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज, सदस्य प्लीज। आपका नम्बर आये तो बोल लेना।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से विगत 5 वर्षों में हाशिये पर खड़े हमारे विद्यालयों में कक्षा कक्ष एवं शौचालयों के निर्माण हेतु शिक्षा मंत्रीजी ने 3-3 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। उन्होंने भी यह नहीं देखा कि कांग्रेस का विधायक है या बीजेपी का विधायक है। उन्होंने पूरे राजस्थान के लिए काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, आदरणीय भजन लाल जी की सरकार के मंत्रिमण्डल ने दिव्यांग तथा अल्प वेतन भोगी कर्मियों को जो अपने घरों से 500-600 किलोमीटर दूर रहकर नौकरी कर रहे थे उनको घर पर लाने का कार्य भी किया है। यह सरकार का एक सराहनीय कार्य है। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि विगत दिवसों में माननीय डोटासराजी ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, लाइन मैन भर्ती पर यह कहकर उपहास किया था कि उन खम्भे पर चढ़ने वाले कर्मचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्तियां ज्यादा हैं और द्वितीय श्रेणी के पद कम हैं। यह कोई भर्तियां क्या हैं? माननीय डोटासराजी से कहना चाहूंगा कि कोई कार्य छोटा नहीं होता है, ये लाइन मैन ही हैं जिनके कारण आपके और हमारे घरों में निर्बाध बिजली आपूर्ति होती है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का महत्व उन बच्चों से पूछो जिनके घर में रोजी-रोटी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन आपको इससे क्या सरोकार है, आपको तो सिर्फ लच्छेदार भाषण और परिवारवाद का ख्याल रखना है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह वो सरकार है जो कार्य स्वीकृत कर शिलान्यास से लेकर लोकार्पण तक का कार्य स्वयं करती है, जैसा कि हमारे मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ था। विगत पांच वर्षों में जिस तरह से संस्कृत शिक्षा को हाशिये पर खड़ा किया गया था, इस संस्कृत शिक्षा के महाविद्यालय के भवन निर्माण की घोषणा की जिसके परिणामस्वरूप मेरे विधान सभा क्षेत्र में गहलोद में महाविद्यालय के भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। आपने देववाणी संस्कृत शिक्षा का मान बढ़ाया उसके लिए मेरा आपका हृदय से आभार।

माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने जैसा बताया कि हमारी सरकार वादों पर काम करने में विश्वास करती है, ईआरसीपी प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो कई सालों से अटका था, यह आप लोग भी कर सकते थे पर आप लोग तो केवल और केवल होटलों में रहने और सरकार को बचाये रखने में रहे।

माननीय सभापति महोदय, आज अभी चाचाण साहब बोल रहे थे, उससे पहले हरीश जी बोल रहे थे, आप दोनों की भाषा हमने देख ली। हरीश जी कम से कम सकारात्मक तो बात कर रहे थे, इनको तो केवल नेगेटिविटी के अलावा कोई काम ही नहीं है। ऐसी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, उससे क्या होगा कि जो भी नये आये हैं वो क्या सीख कर जायेंगे?

...(व्यवधान)...

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने देश की सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर चुके अमर शहीदों के नाम पर 51 राजकीय विद्यालयों का नामकरण करने का कार्य इस वर्ष किया है, जिसे विगत सरकार ने कई वर्षों से बंद बस्ते में डाल रखा था। माननीय सभापति महोदय, विगत वर्षों में सरकारी भवनों की मरम्मत के नाम पर बस खानापूर्ति हुई जिसका परिणाम यह हुआ कि आज अधिकांश राजकीय कार्यालयों में एवं विद्यालयों में भवन जर्जर अवस्था में पहुंच गये हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार है कि आपने बाढ़ प्रभावित जिलों में क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों की मरम्मत के लिये इस वर्ष 373 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की। माननीय मुख्य मंत्रीजी से विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि विगत सरकारों की अनदेखी के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी पहले जिनकी हालत खराब है, आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि पीपलू और निवाई के नवीन भवनों की स्वीकृति जारी करायें ताकि आम जन का कार्य निर्बाध रूप से चल सके।

माननीय सभापति महोदय, समाज की धारा से अलग जीवन यापन करने वाले घुमंतू परिवारों को, यह बहुत बड़ा का बता दूं आपको, विपक्ष को, घुमंतू परिवारों को भूखण्ड उपलब्ध करवाकर मुख्य मंत्रीजी ने इतना काम किया है कि उन दलित और पिछड़े और वंचित परिवारों को, जिनके लिए बार-बार कहते हैं, अभिभाषण में अनुसूचित जाति के लिए लिखा है, घुमंतू परिवार, अनुसूचित जाति से ही आते हैं, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं।

श्री सभापति: प्लीज आप समाप्त करें।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): आप वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना को समझो।

माननीय सभापति महोदय, सुबह का भूला शाम को घर लौट आये तो उसको घर वापसी कहते हैं लेकिन जिसको जबरन घर से बाहर ले जाया जाये वो विधि विरुद्ध अंतरण कहते हैं। चूंकि मैंने पहले भी सदन में बोला है कि कई शक्तियां हमारे भोले-भाले लोगों को बहला फुसला कर, प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाती है, इसे कानून बनाकर रोकना चाहिये। सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस प्रकार का बिल लाने जा रहे हैं, जिससे विधि विरुद्ध धर्मांतरण पर रोक लगायी जा सके। धन्यवाद। जय भारत, जय हिन्द।

MLS/RTM/06.02.2025/16:00/2p

श्री सभापति: श्री मुकेश भाकर।

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे जो सामने सत्तापक्ष के माननीय सदस्य बैठे हैं, वे इस बात पर खुश हैं कि 6 महीने का सस्पेंशन हुआ। ...(व्यवधान)... वापस तो 6 महीने होने के बाद ही आया हूं मैं इस सदन में। उसमें आपकी कोई बहादुरी नहीं है।

सभापति महोदय, हम वे लोग हैं जिन्होंने संविधान और इस चेयर का हमेशा सम्मान

किया है। हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के उस संविधान को मानते हैं, जिसमें यह चेयर इस सदन ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान के लोगों की उम्मीद और आकांक्षा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्यों घटी, यह सारा गतिरोध क्यों हुआ, क्योंकि मेरे सामने जो सत्तापक्ष के लोग बैठे हैं, ये न तो जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पा रहे और न इनके मंत्री इस सदन में जवाब दे पा रहे। इनके बचाव में स्पीकर साहब को आना पडा और उसकी वजह से मेरा सस्पेंशन हुआ। सभापति महोदय, यह तो शहादत है, जो जिन्दा लोगों के हिस्से में आती है। अगर जनता की आवाज उठाने के लिए मेरा ऐसा सस्पेंशन बार-बार हुआ तो भी मैं उस आवाज को उठाता रहूंगा, इस बात को इस सदन में रखना चाहता हूं।

आज इस राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, यह किताब मेरे हाथ में है और मुझे अफसोस है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिनकी छवि यह बनी हुई है कि असत्य भाषण दो, असत्य वादे करो, बार-बार करो ताकि जनता उनके बहकावे में आ सके, मुझे अफसोस है कि यह किताब हाथ में देकर राज्यपाल महोदय से इन लोगों ने दो घंटे में इतना असत्य बुलवाया, राजस्थान की जनता के धरातल पर जिसका कोई लेना-देना नहीं है।

पहला जो इनका बजट आया, उसका जमीन पर एक भी क्रियान्वयन नहीं हुआ। दूसरा बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आ रही है और राज्यपाल महोदय को, हमने देखा कि यह संवैधानिक पद है और यहां बैठा व्यक्ति राजस्थान की जनता की, दोनों पार्टियों की, पक्ष-विपक्ष की बात यहां करता है, लेकिन राज्यपाल महोदय से ऐसे भाषण दिलाया जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर वे यहां बोल रहे हों।

आदरणीय सभापति महोदय, अभी थोड़े दिन पहले केन्द्र का दूसरा बजट आया और हमने देखा कि फिर से बजट में राजस्थान का नाम कहीं भी नहीं था। राजस्थान के लोगों के लिए केन्द्र के उस बजट में कहीं भी कोई घोषणा नहीं हुई। मैंने एक अख़बार में पढ़ा कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, वे जिस स्टेट की, जिस राज्य की साड़ी पहनकर बजट पढ़ती हैं, उस राज्य के लिए सबसे ज्यादा घोषणाएं होती हैं। पहले उन्होंने आंध्र की पहनी, कभी बिहार की पहनी और इस तरीके से बंगाल की साड़ी पहनी और उसी राज्य को वह बजट दे दिया गया। हमारी वित्त मंत्री सम्माननीय दिया कुमारी जी भी महिला हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि एक-दो साड़ी आप उन्हें देकर आएं ताकि बजट पढ़ते समय उन्हें राजस्थान की याद रहे और एकाध घोषणा राजस्थान की जनता के लिए हो सके।

माननीय सभापति महोदय, आज मुझ से पूर्व वक्ता कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय सदस्य हैं वे बोले कि हमने काम किया, उसकी तो आप प्रशंसा करें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब हम छोटे थे तब से सुनते थे कि इस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को सींचने वाले लोग किरोड़ी लाल मीणा जी, वसुन्धरा राजे जी, देवी सिंह भाटी जी, ये इस भारतीय जनता पार्टी को सींचने वाले लोग हैं। ये हमारे मुंह से प्रशंसा करवाना चाह रहे हैं, लेकिन वे दिग्गज इन लोगों की खिलाफत कर रहे हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं। इसका जवाब इन्हें देना चाहिये।

श्री सभापतिः अपनी बात रखें, समय जा रहा है।

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): समय में ही बात कर रहा हूं, दस मिनट ही बोलूंगा। बस यही दिक्कत है, इनको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में यह सब गतिरोध बढ़ रहा है। ये सारे लोग आप लोगों की बुराई कर रहे हैं, हमारे मुंह से आप लोग क्यों बड़ाई करवाना चाह रहे हैं और क्यों हम करेंगे, राजस्थान की जनता देख रही है।

सभापति महोदय, किसी भी राज्य सरकार या पुराने टाइम में शासक होते थे या केन्द्र की सरकार है, वह अपने लोगों को ग्राउंड पर भेजती है कि आप जाकर देखें कि हमारे प्रति लोगों की क्या राय है, क्या परसेप्शन बन रहा है। यहां कुछ मंत्री बैठे हैं, मुख्य मंत्री जी के प्रति जिनका विशेष लगाव है, उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि आप जाकर ग्राउंड पर देखें। लोगों ने बहुत उम्मीद की थी, जब सरकार बनी तो पूरे राजस्थान में पेपर लीक, ईआरसीपी, एसओजी, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, इस तरीके के वादे भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा किये गये।

आज जब इन्होंने कहा, हम मगरमच्छ पकड़ेंगे, पेपर लीक हो गया, हम राजस्थान के युवा को उसका न्याय देंगे। अभिभाषण में लिखा है कि हमने 100 मुकदमे दर्ज किये और 207 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन अब तक जो लोग मगरमच्छ पकड़ने की बात कर रहे थे, जो मछलियां पकड़ीं, वे भी इनके जाल से बाहर निकल गईं। सारे सब-इंस्पेक्टरों की जमानत हो गयी। एसआई भर्ती, परीक्षा रद्द करने को लेकर कभी क्या बयान आता है, कभी क्या बयान आता है। आज भी राजस्थान का युवा कह रहा है कि इन भजन लाल जी से पार पड़ने वाली नहीं है, ये तो सिर्फ भाषण दे सकते हैं। आपके मुख्य मंत्री और आप लोगों की छवि लोगों में बच सके, उसके लिए आप लोग कम से कम ऐसे कठोर कदम उठाएं, जिनसे राजस्थान की जनता कहे, युवा कहे कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी लोगों से करके आयी थी, उन पर कुछ काम कर रही है।

आदरणीय सभापति महोदय, बजट में बात हुई, इस अभिभाषण में बात हुई कि पूर्ववर्ती सरकार ने राजस्थान की बिजली व्यवस्था खराब कर दी। अब आप लोगों की सरकार है, छत्तीसगढ़ में आप लोगों की सरकार है, केन्द्र में आप लोगों की सरकार है, कोयला आप कहीं से भी ला सकते हैं। सभापति महोदय, जो सौर ऊर्जा की बार-बार आप बात कर रहे हैं, जाकर धरातल पर देखें, यह स्थिति है सर्दी के समय भी किसानों को गांवों में, और मुझे लगता है कि आपकी डिक्शनरी में सिर्फ शहर और उद्योग हैं जिन्हें बिजली दे सकते हैं, तो बात अलग है, बाकी गांवों में किसानों की, लोगों की यह स्थिति हैकि समय पर बिजली नहीं आ रही, वोल्टेज नहीं आ रहे और बचे हुए में जो कर्मचारी-अधिकारी हैं, वे लोग उनकी कटौती करके किसानों को परेशान कर रहे हैं।

आज सौर ऊर्जा की आप लोग बड़ी लाइनें बिछा रहे हैं, हमारे समय भी चालू हुईं। कोई भी तरीके की उनके लिए आप लोगों ने मुआवजे की व्यवस्था नहीं की। एक किसान है, जिसका एक बीघा का खेत है, दो बीघा का खेत है और वहां से बड़ी लाइन जा रही है, उनके लिए मुआवजे की प्रॉपर व्यवस्था आप लोग इस सदन से करवाएं, यह मांग आप लोगों से मैं

करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैंने जैसा कहा और मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, सरकार की स्थिति और मुख्य मंत्री जी की जो छवि लोगों में बन रही है, उसे अगर आप लोग बचाना चाहते हैं, आप लोगों ने सबसे पहले मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया, फिर एससी समुदाय को टारगेट किया और मैं इस सदन में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से जाट समाज को शेखावाटी और मारवाड़ में टारगेट किया है, उसका जवाब जनता आपको देगी।

जिस तरीके से जाट समाज के कर्मचारियों को आप लोग जाति और धर्म नाम देखकर ट्रांसफर कर रहे हैं, अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि हम घर के पास लाये, कितने लोग हर विधान सभा क्षेत्र में 100 से 200 लोगों को आप लोगों ने ट्रांसफर किया है और उसकी कोई वजह नहीं थी। सभापति महोदय, पहले ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती थीं 2, 3, 5, 7, जो विदाई का नजदीक है, जो पार्टी की विचारधारा से ज्यादा अलग हैं, उनके ट्रांसफर कर दो। एक सन्देश होता था, लेकिन आपने तो बाबू, लाइनमैन, चपरासी और जिन लोगों का प्रोबेशन कम्प्लीट नहीं हुआ, उन लोगों के भी ट्रांसफर कर दिये। अभी जो मंत्री यहां बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोगों को यहां मंत्री इसलिए बनाया है कि आप उस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप यह बात कहिये मुख्य मंत्री जी को कि आप किसी के प्रति दुर्भावना से ट्रांसफर न करें। यह बात आप लोगों को पहुंचानी होगी। ...(व्यवधान)... माननीय, आप जाकर लिस्टें देखिये। माननीय मंत्री, आप मेरे जिले के प्रभारी मंत्री हैं, आप जाकर स्थिति देखिये। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में किस तरीके से आप लोग दुर्भावना से उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। कौन कर्मचारी-अधिकारी चुनाव जिता देगा, लेकिन आप लोग उन पर अपनी दुर्भावना निकालने का काम कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं, यह सही भी हो सकता है।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आज नागौर में सबसे ज्यादा अधिकारी जितने लगे हैं, जाट लगे हैं।

mkd/rtm/06.02.2025/16:10/2q

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): आप जाकर देखिये, आपने विधान सभाएं, थाने, तहसील, कचहरी सब लोग ठेके पर दे दिये। आप जाकर देखिये आप लोगों की छवि, गांवों में जनता घुसने नहीं देगी। जिस तरह से लोक सभा में आप लोगों हश्र हुआ, वही आप लोगों का दुबारा हश्र होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): छवि की चिन्ता नहीं करें, अभी खींवसर और झुंझुंनू में लोगों ने आशीर्वाद दिया है।

एक माननीय सदस्य: माननीय सभापति महोदय, ये मुख्य मंत्री जी का नाम किसलिए इंगित कर रहे है, ये माननीय मुख्य मंत्री का नाम गलत इंगित कर रहे हैं, ये जातिगत जहर घोलने का काम बता रहे हैं।

श्री सभापतिः ताराचन्द जी जैन साहब। अंकित नहीं होगा। समय समाप्त हो गया। विराजिये।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): 000

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): 000

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा, समय समाप्त हो गया। विराजिये, विराजिये।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, ये मुकेश भाकर जी का कसूर नहीं है, यह कांग्रेस की फितरत रही है कि राजस्थान में जातिवाद का जहर, जो कांग्रेस ने घोला है, कांग्रेस के संस्कारों में है, इस प्रकार जातिगत बात सदन में शोभा नहीं देता है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति जी, ये बार-बार ऐसे, संसदीय मंत्री जी बैठे हैं, वे बोल देंगे। ये बार-बार खड़े हो जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं है।

श्री सभापतिः विराजिये। ताराचन्द जी साहब, चालू करिये।

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): माननीय सभापति, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): रुकिये।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): सरकार इस बात की जांच करा ले, यह बात सही है या गलत है। ये इस प्रकार के स्थानान्तरण हुए हैं, तभी दुःख बोल रहा है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ऐसा दुःख तो होता रहेगा, आपकी संस्कृति बोल रही है। यहां संस्कृति वह नहीं है। आप बैठ जाइये, प्लीज। मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, यह राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस हो रही है, यह ट्रांसफर पर बहस नहीं हो रही है और क्या स्तर गिरा दिया है विधान सभा का, यह क्या स्तर गिरा दिया है, यह क्या हो रहा है? माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा आपसे अनुरोध है कि यह आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम किसकी बात करें, किसकी बात नहीं करें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति जी, ऐसा है, आपके लोग नहीं लगा रहे आरोप, आपके लोग नहीं बोल रहे हैं। बात यह नहीं है, यानी दूसरे की थाली में आपको गलत नजर आता है। मैं यह कह रहा हूं, माननीय सदस्य ने अभिभाषण पर अपनी कोई बात रखी है, आपको ऐतराज है तो संसदीय मंत्री उस पर जवाब दे दें। आपको ऐतराज है, आप लिस्टों की जांच करवाकर बात कर लें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): किस की जांच करा लें?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): लिस्टों की जांच करा लो आप कि जाति के नाम पर टारगेट करके आपने ट्रांसफर किये हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कोई जाति के नाम पर टारगेट नहीं है। यह कांग्रेस की फितरत है।

श्री सभापतिः विराजिये, आपके नेता, प्रतिपक्ष बोल रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपको अगर ऐतराज है तो जांच करवा लें। बाकी यह इतना वाद-विवाद का विषय नहीं है। माननीय सदस्य ने अपनी बात कह दी, आप बोलो जब अपने आंकड़े पेश कर देना।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद से ऊपर काम करती है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): विश्नोई जी, आप बढ़िया आदमी हैं, आप क्यों चक्करों में पड़ते हों?

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार।

राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में माननीय प्रधान मंत्री मोदी के 2047 के विकसित भारत बनाने और विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को साकार करने का संकल्प है यह बजट।

राज्यपाल महोदय द्वारा जो धर्म परिवर्तन प्रतिबंध विधेयक, 2025 पेश किया, उसका मैं समर्थन करता हूं। साथ ही, सरकार का आभार और धन्यवाद प्रदान करता हूं कि इस बिल से प्रदेश की हजारों युवतियां और बालिकाएं लव जिहाद से बचेंगी और लव जिहाद की आड़ में धर्मान्तरण के कुकृत्य पर लगाम लगेगी।

मैं केन्द्र सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उदयपुर विश्व का मुख्य पर्यटन क्षेत्र है एवं चारों ओर झीलें हैं, दूसरी ओर पहाडियां हैं, उन झीलों और पहाड़ियों के संरक्षण हेतु केन्द्र सरकार ने 24 जनवरी, 2025 को इन झीलों के संरक्षण हेतु सरकार के प्रयासों से विश्व के 31 शहरों में उदयपुर एवं इंदौर पहले दो शहरों का नाम आया, जिन शहरों को वैट लैंड सिटी का वैश्विक दर्जा प्राप्त हुआ है। इससे उदयपुर को वैश्विक दर्जा प्राप्त हुआ है। मैं इस सदन के अन्दर यह पत्र रखना चाहता हूं, राजस्थान पत्रिका ने जिस तरह से एक पेज का पृष्ठ छापकर इसका महत्व बताया है, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आप इस ओर चिन्तन करें। उदयपुर की झीलें, पहाड़ियां संरक्षित होंगी। पिछले सत्र में मैंने उदयपुर के पहाड़ों को लेकर 295 के तहत प्रश्न पूछा। विभाग ने 43 में से 15-16 पहाड़ियों को नियम विरुद्ध छलनी होना स्वीकार किया, लेकिन उसमें खानापूर्ति कर कार्यवाही की इतिश्री कर दी। अतः यह चिन्ता का विषय है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि पहाड़ियों की खातेदारी के बदले जमीन देकर, कानून बदलकर इसे फॉरेस्ट लैंड घोषित किया जाये। पूर्ववर्ती सरकार ने, 1962-63 में कांग्रेस सरकार ने, स्वर्गीय प्रधान मंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कहा गया था कि देश एक ओर सूखे की मार झेल रहा है तो दूसरी ओर बाढ़ की आपदा झेल रहा है और सुझाव दिया कि देश की नदियों को आपस में एक दूसरे से जोड़कर दोनों विपदाओं से निपटा जा सकता है। उस समय के कांग्रेस सरकार के सदस्यों ने उस बात का मखौल बनाया कि प्रकृति

को कैसे चैंज कर सकते हैं। आज यह सत्य प्रतीत होता नजर आ रहा है ।

माननीय भजन लाल सरकार द्वारा इस सपने को साकार करने हेतु यमुना जल समझौता, उसके साथ-साथ उदयपुर जिले का देवास थर्ड और फोर्थ। माननीय सुखाड़िया जी ने 1965 के अन्दर सोचा था, उसका सर्वे भी करवाया, लेकिन उनके राजनीति में कमजोर होते ही उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। देवास थर्ड और फर्स्ट माननीय वसुन्धरा जी के शासन में माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया जी ने स्वीकृत कराया और पूरा किया। साथ ही, कांग्रेस ने थर्ड और फोर्थ, जाते-जाते अन्तिम बजट में घोषणा की, लेकिन बजट का प्रावधान नहीं किया।

वर्तमान माननीय भजन लाल जी, मुख्य मंत्री जी ने सरकार की क्रियान्विति में 1600 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है और कार्य का वन क्षेत्र एवं भूमि का डायवर्जन कर टनल का सर्वे पूरा कर लिया गया और अप्रैल माह तक यह चालू हो जायेगा, इससे समग्र राजस्थान की इन तीनों योजनाओं से तीन-चार वर्षों में आपूर्ति निश्चित हो जायेगी।

साथ-साथ में, माही और जाखम का पानी ठेठ अपने जयसमन्द तक पहुंचायेंगे तो पूरे राजस्थान में खुशहाली का वातावरण बनेगा। निश्चित रूप से भजन लाल सरकार का मैं आभार व्यक्त करूंगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुर शहर महत्वपूर्ण पर्यटन नगरी होने के कारण पर्यटकों का वर्ष भर आवागमन रहता है। बड़ी-बड़ी परीक्षाओं में शहर में पचास हजार विद्यार्थी आने से शहर के एक कोने से दूसरे कोने में जाने में घंटे लगते हैं। भजन लाल सरकार ने शहर के रेलवे स्टेशन से कलेक्टर निवास तक पौने तीन किलोमीटर का एलिवेटेड रोड, जिसकी लागत डेढ़ सौ करोड़ रुपये है, उसके बनने का कार्य 14 दिसम्बर को चालू हो गया है। उससे पूर्व कांग्रेस सरकार ने बजट के अन्दर अन्तिम समय में दो हवा-हवाई एलिवेटेड बनाये, जिसका न तो बजट में प्रावधान किया, न आज तक मौके पर देखने को मिला है। इस कार्य के पूर्ण होने के पश्चात शहरवासियों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी।

शहर के आवागमन के द्वार पर गुजरात से आने वाले पर्यटकों के लिए प्रवेश द्वार पारस चौराहे पर 37 करोड़ की लागत से ओवर ब्रिज बन रहा है, जिसे 14 दिसम्बर को यूआईटी द्वारा चालू कर दिया गया है। इससे शहर में काफी राहत होगी। शहर के सभी चौराहे जो चौड़े किये जा सकते हैं, इससे निश्चित रूप से पर्यटकों को बहुत राहत मिलेगी। पेयजल हेतु 215 करोड़ का बजट आवंटित किया है, स्वच्छ पेयजल हेतु चार परिशोधन यंत्र, 10 पानी की टंकी और शहर की 40 वर्ष पुरानी विभिन्न पाइप लाइन, जो 2 लाख 14 हजार 533 मीटर डालने से क्षेत्रवासियों को शुद्ध पेयजल मिलेगा।

वर्षों से स्वीकृत 400 केवी का ग्रिड स्टेशन भूमि आवंटित होने के बाद, पिछले 12 वर्षों से वह लम्बित था, वर्तमान सरकार ने उसे स्वीकृत किया और मुझे विश्वास है नई भूमि भी आवंटित कर दी गई है।

Bhs/Rtm/06.02.25/16.20/3a

और अप्रैल में चालू हो जायेगा उससे उदयपुर सम्भाग चित्तौड से लेकर बांसवाड़ा, सागवाड़ा और इन सभी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति ठीक हो जायेगी। महाराणा भूपाल चिकित्सालय में भवन जो पिछली कांग्रेस सरकार के समय में बना था, दो मंजिला इमारत धंस गई। फिर उसकी जांच की तो जांच में भी लीपापोती हो गई, उसके लिए सरकार ने फिर बजट आवंटित किया है। मैं सरकार से मांग करूंगा, चिकित्सा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि डी.एम.एफ.टी. और यू.आई.टी. द्वारा यह पैसा आवंटित करा कर इस राशि को तुरन्त दिया जाये।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि 2022 में जिस तरह से कन्हैया लाल हत्याकांड एवं देवराज हत्याकांड जो उदयपुर नगरी में हुए थे, वो दोनों हत्याकांड सारे देश और समाज को हिलाने वाले थे और जिसके अन्दर पिछली सरकार की पैरवी के अभाव में कन्हैया लाल के हत्यारों को जमानत मिल गई थी। मैं चाहूंगा कि कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उदयपुर शहर में दो पुलिस चौकियां हैं एक तो आयर वह बहुत बड़ा सेंसेटिव जोन है, दूसरा खाजीपेह वह क्षेत्र भी सेंसेटिव है, इन दोनों पुलिस चौकियों को पुलिस थाने का दर्जा दें ताकि कानून-व्यवस्था मजबूत हो सके। ऐसा मेरा सरकार से आग्रह है।

सभापति महोदय, इसी तरह से हम देख रहे हैं प्रताप नगर और अहमदाबाद मुख्य मार्ग पर आवाजाही बहुत रहती है। फोर लेन का कार्य प्रगति पर है। बलीचा रोड को 4 लेन के बजट में सम्मिलित करा कर पचास बीघा भूमि आवंटित कर दी गई है। हाई कोर्ट बैंच के लिए राशि आवंटित करने का मैंने आग्रह किया है वह दिलाने का कष्ट करें।

सभापति महोदय, पिछली सरकार के समय 272 करोड़ का एक प्लॉट घोटाला हुआ था। मैं यू.डी.एच. मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सदन में यह घोषणा की थी कि इसकी 31 दिसम्बर तक जांच पूरी करके दोषियों को दण्डित करेंगे, उसमें निश्चित रूप से कार्यवाही हुई है लेकिन पर्याप्त नहीं हुई है। आठ मुल्जिम पिछले कई महीनों से जेल में हैं लेकिन मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि अभी तक एक भी कर्मचारी गिरफ्तार नहीं हुआ है, एक भी अधिकारी गिरफ्तार नहीं हुआ है। यह चिन्ता का विषय है। 49 भूखण्ड निरस्त कर दिये हैं, उनके कब्जे ले लिये लेकिन आज तक उसमें एक भी कर्मचारी को, नोटिस जरूर दिये हैं, लेकिन गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा कि निश्चित रूप से अपराधियों तक, क्योंकि यह चिन्ता का विषय है कि जिस तरह से इन 272 प्लॉटों में घपले किये गये थे इससे सरकार और कानून का भय समाप्त हो गया था और इससे निश्चित रूप से अगर कानून के शिकंजे में आयेंगे तो सरकार की छवि भी सुधरेगी और पिछले घोटालों का खुलासा भी होगा और कानून का राज कायम होगा।

मैं पुन: एक बार सरकार से आग्रह करूंगा कि यह बजट निश्चित रूप से 2047 के अन्दर नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है उस संकल्प को पूरा करने की नींव का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री सभापतिः कुमारी रीटा जी चौधरी।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): धन्यवाद, सभापति महोदय। हम लोगों ने विष्णु पुराण में पढ़ा समुद्र मन्थन के बारे में। जब समुद्र मन्थन हुआ तो उसमें बहुत सारे रत्न निकले, उसमें विष भी निकला। हमारी जो यह विधान सभा है इसमें भी विचारों का मन्थन होता है। मैं आज से नहीं अपने पिताजी के टाइम से भी विधान सभा के अन्दर आयी, ऊपर दर्शक दीर्घा में बैठ करके भी मैंने कार्यवाही देखी लेकिन जिस तरीके की अमर्यादित स्थिति चाहे वह पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, वह देखने को इस बार इस सदन में मिल रही है वह इससे पहले कभी नहीं हुई।

सभापति महोदय, विचारों का आदान-प्रदान होता है, सब अपने विचार यहां पर रखते हैं। विचारों में कहीं त्रुटि भी हो जाती है लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष अपना आपा खो देती है मंत्री सारे एक साथ उठ जाते हैं विपक्ष को दबाने की कोशिश करते हैं आसन को दबाने की कोशिश करते हैं यह आज से पहले कभी नहीं देखा। यहां पर महामहिम राज्यपाल गुलाब चन्द जी कटारिया भी विपक्ष के नेता रहे हैं। राम नारायण जी चौधरी मेरे पिताजी भी विपक्ष के नेता रहे हैं। राजेन्द्र जी राठौड़ भी यहां विपक्ष के नेता रहे हैं लेकिन जो मान और सम्मान इन विपक्ष के नेताओं का सदन में होता था, सदन के नेता करते थे, सत्ता पक्ष करते थे वो आज यहां दिखायी नहीं देता है। एक बार मेरे पिताजी विपक्ष के नेता थे, उनको वसुन्धरा जी से मिलना था, सदन की नेता थीं, प्रदेश की मुख्य मंत्री थीं, उनका ड्राईवर नहीं आया, उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे सी.एम. हाउस तक ले चल, मुझे मुख्य मंत्री जी से चर्चा करनी है। मैं उनको लेकर गई। खुद गाड़ी चला कर उनको वहां पर लेकर गई तो मैंने देखा कि वसुन्धरा राजे जी पूरे सम्मान के साथ गेट पर पिताजी को लेने आई, नेता, प्रतिपक्ष को लेने आई और आदर के साथ उनको अन्दर लेकर गई, उनकी बात सुनी, उनके काम किये।

सभापति महोदय, यहां पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मैं सुन रही हूं। कैलाश जी ने अपनी बात शुरू की अभिभाषण पर और जो अमर्यादित भाषा का यहां पर आप लोग प्रयोग कर रहे हैं, आपने कोरोना काल को मजाक बना दिया। कोरोना काल में राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने जो काम किया वह देश के प्रधान मंत्री ने माना और उसकी वाहवाही की और यहां पर आप प्रधान मंत्री को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हो।

सभापति महोदय, जब ये लोग अपने अभिभाषण पर चर्चा कर रहे थे तो मुजफ्फर वारसी की एक दो लाइन याद आ गई, 'औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता है।' एक राज्य का धर्म होता है वह अपनी जनता को अच्छी शिक्षा दे, अच्छी चिकित्सा दे, पानी की व्यवस्था करे, बिजली की व्यवस्था करे, आधारभूत संरचनाओं की व्यवस्था करे, सड़कें बनाये। मैं दो-तीन बिन्दुओं पर अपनी बात रखूंगी। अंग्रेजी शिक्षा, आपको जानकारी नहीं है, राजस्थान में सबसे पहले 2014-15 में तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने बड़ी तादाद में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे विवेकानन्द मॉडल स्कूल के नाम से और तकरीबन 135 स्कूल उन्होंने खोली, उन्होंने जो विवेकानन्द मॉडल स्कूल खोली अंग्रेजी

माध्यम की तो उन्होंने क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक खोली।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहती हूं पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी को जिन्होंने गरीबों की पीड़ा समझी, किसानों की पीड़ा समझी और वंचित लोगों की पीड़ा समझी। उन्होंने इंग्लिश मीडियम की स्कूल खोली लेकिन उससे भी बड़ा धन्यवाद मैं अपने पूर्व मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत को देना चाहती हूं कि उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर विवेकानन्द मॉडल स्कूल को डेढ़ करोड़ रुपये दिये। 1 से 5वीं तक उसको चालू किया और उसी साल में उसको चालू करने का काम किया। यह होता है लोकतंत्र। एक सरकार नींव रखती है तो दूसरी सरकार जब आती है तो वह उसके ऊपर एक इमारत खड़ी करती है लेकिन यहां पर अमर्यादित टिप्पणी हमारे शिक्षा मंत्री करते हैं। वे शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूलों को रिव्यू करने की बात वो करते हैं, उनको यह ध्यान रहता है कि शिक्षिका ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। भरी सभा में वो शिक्षिका के कपड़ों पर आलोचना करते हैं लेकिन उनको यह ध्यान नहीं है कि आज की जरूरत है अंग्रेजी माध्यम। किसानों के गरीब बच्चे, वंचित जो समाज है उसके लिए वो जरूरी है।

सभापति महोदय, ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम का मुद्दा क्यों उठा, यह इसलिये उठा कि एक रिव्यु कमेटी बना दी डॉ. प्रेम चन्द जी बैरवा की अध्यक्षता में और उस कमेटी ने यह कहा कि आधारभूत जो सुविधाएं हैं वो उस स्कूल में उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि साढ़े तीन हजार से ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले और साढ़े सात लाख से ज्यादा बच्चे उनके अन्दर अध्ययनरत हैं। आज उनकी स्थिति यह हो गई शिक्षा मंत्री के बयान से असमंजस की स्थिति है। गांवों के अन्दर ग्रामीणों ने चन्दा इकट्ठा किया, बीस-बीस, तीस-तीस लाख रुपये उन्होंने इकट्ठे किये और उन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में उन्होंने कमरे बनवाये, उसका रंग-रोगन किया और बच्चों को लाने ले जाने के लिए भी व्यवस्था उन लोगों ने की। आज वहां पर बच्चे एडमिशन लेने के लिए कतरा रहे हैं पता नहीं स्कूल बन्द हो जायेगी। यह तो आपकी शिक्षा नीति है।

सभापति महोदय, दूसरी बात आती है गुड गवर्नेंस की। अभी 25 दिसम्बर को पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस के रूप में सम्पूर्ण भारत में मनाया गया लेकिन राजस्थान में यह सरकार आयी, लोगों से वोट लिये सुशासन के नाम पर।

Kas/rtm/06.02.2025/16.30/3b

पिछली सरकार ने राम लुभाया कमेटी के आधार पर बहुत सारे जिले और संभाग बनाये। आपकी सरकार ने 13 महीने निकाल दिये। 21 महीने नये जिले व संभाग बने हुए हो गये, वहां पर एस.पी. कलेक्टर बैठ गये, बहुत सारे अधिकारी-कर्मचारी वहां चले गये, नये दफ्तर बन गये। होता तो यह कि जो जिले व संभाग आपने खतम किये, वहां के लोगों की राय लेते, वह आपने नहीं ली। आप वहां के नेताओं से चर्चा करते, आपने नहीं की। आनन-फानन

में आपने मंत्रिमंडल में 9 जिले और 3 संभागों को खतम करने का फैसला ले लिया। मेरा सीधा-सीधा आरोप है कि आपने उस समय का फायदा उठाया, उस समय हमारे पूर्व प्रधान मंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह जी का देहांत हो गया, पूरा देश शोक में था, कांग्रेस पार्टी शोक में थी और आपने ऐसे समय में मंत्रिमंडल में फैसला लिया ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता सड़कों पर इसके विरोध में नहीं आ सके, आपने समय उचित चुना। आपने इसलिए भी यह समय चुना कि उस समय न्यायालय की शीत कालीन छुट्टियां थीं, ताकि हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकें।

सभापति महोदय, 28 जनवरी को न्यायालय में जो जवाब पेश किया, वह और भी हास्यास्पद है। इन्होंने कहा कि विकास के लिये सरकार को प्रशासनिक निर्णय लेने का अधिकार है। यह कैसा विकास है? 150-150, 200-200 किलोमीटर की दूरी पर लोग चलकर आते हैं, काम करावाने के लिये अपने जिले के हैडक्वार्टर पर आते हैं, इसको विकास नहीं कहते। अच्छा होता आप उसको रिव्यू करते और अपनी बात जनता के बीच में ले जाते और उचित होता तो आप उनको समाप्त करते, लेकिन आपने वाह-वाही लूटने के लिये यह काम किया।

सभापति महोदय, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। जिस तरीके से जनवरी में आपने स्थानांतरण खोले, मैं तो अपनी सरकार में भी बोलती थी कि स्थानांतरण नीति बनाओ, लेकिन नहीं बनी, कोई बात नहीं, लेकिन आपने जिस तरीके से स्थानांतरण खोले, राजनीतिक द्वेषता के चलते आप लोगों ने स्थानांतरण किये। एक व्यक्ति के 5-5 बार आपने स्थानांतरण कर दिये। आप झुंझुनूं जिले के जिला परिषद की लिस्ट उठाकर देख लो, एक चपरासी को, एक अपाहिज व्यक्ति, जिसके दोनों पैर नहीं हैं, उसको उठाकर आपने खेतड़ी भेज दिया। आप लोगों ने जिस तरीके से राजनीतिक द्वेषता से काम किया, और तो और यह हमारे झुंझुनूं जिले का दुर्भाग्य है कि जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं...

श्री सभापतिः प्लीज, अपनी बात समाप्त कीजिए।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): उनका जो आचरण है, वो अच्छी तरीके से जानते हैं, एक एचएस को लेकर वह घूमते हैं, उसके कहने से थाने में फोन करते हैं, उसके कहने से एस.पी. को फोन करते हैं और यह झुंझुनूं जिले का दुर्भाग्य है कि ऐसा एस.पी. हमारे जिले में बैठा है जो एक एचएस के लिये थाने में जाकर फोन करता है कि इसके लिये पास की व्यवस्था करना और इसके घर पर पास देकर आना। प्रभारी मंत्री जी, हाथ जोड़ने से नहीं होता, आपका जो अमर्यादित व्यवहार रहा है, ऐसा काम क्यों करते हो कि किसी को सर्किट हाउस के पीछे वाले गेट से बाहर निकालना पड़े।

श्री सभापतिः श्री बालमुकुन्दाचार्य।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): आपने मेरे झुंझुनूं के मंडावा विधान सभा क्षेत्र में वृद्धा पेंशन बंद कर दी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): प्रकरण मेरे समझ में

नहीं आया, क्या है रीटा जी?

श्री सभापति: आप अपनी बात समाप्त कीजिए, अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): 000

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): बहुत-बहुत धन्यवाद बहन जी, विराजें आप। धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। सदन में विराजमान पक्ष और विपक्ष के हमारे सम्माननीय सभी सदस्यों ने अपनी-अपनी बात रखी। मैं सदन में पहली बार जरूर आया हूं, लेकिन टीवी चैनल के माध्यम से और दर्शक दीर्घा में मैंने यही देखा है कि विपक्ष को अच्छा काम हुआ है तो भी उसकी बुराई ही करना है, लेकिन जनता बाहर सब देख रही है। महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि आप अल्प मत में हो गये हैं। उप चुनाव में भी आप पराजित हो गये हैं और जहां एक सीट आई है वह भी कितने अंतर से आई है, यह आप लोगों को पता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार में जो अच्छा काम हो रहा है उसकी तारीफ करें, धन्यवाद करें और सहयोगी बने। जनता की सेवा का जो पुण्य हम सबको मिल रहा है, उसका लाभ लें।

माननीय सभापति महोदय, लंबे अंतराल के बाद महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अपना पूरा अभिभाषण पढ़ा गया, जो हमारी सरकार की उपलब्धियों के बारे में था। इसके लिये हमारी सरकार द्वारा गत एक वर्ष में जो ऐतिहासिक काम किये गये, ऐतिहासिक कदम उठाये गये, उनकी चर्चाएं थीं और जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। जिस तरह से एक वर्ष में ऐतिहासिक काम किये गये, हमने जो वादा किया था, लगभग तीन वर्ष में वह पूरा हो जायेगा । माननीय सभापति महोदय, जनता के हित में अनेक फैसले लिये गये हैं, कार्य किये गये हैं। प्रतिपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, कुछ कहने को बचा नहीं, इसलिए अनर्गल बातें करके और व्यर्थ की चर्चा करके सदन का समय जाया किया जा रहा है।

मैंने पिछले दिनों इधर से और उधर से भी काफी कुछ सुना, लेकिन मैंने जो उधर से सुना, उसमें कुछ तथ्य पाया नहीं, क्योंकि जो बातें की गईं, उन बातों के कई प्रमाण मेरे पास उपलब्ध हैं। जैसे पिछली सरकार में मैं मानता हूं कि प्राकृतिक आपदा थी, भले ही कोरोना काल था, लम्पी था, प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन आपदा में जिम्मेदारी सरकार की थी, जनता ने जिनको चुन कर भेजा था उन प्रतिनिधियों की थी। उस कोरोना काल एवं लम्पी के वायरस में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और उससे सम्बन्धित विचार परिवार के कार्यकर्ता रोड पर थे और जहां सेवा की जरूरत थी वहां हम सब मिलकर सेवा कर रहे थे। मेरे भी परिचय में बहुत सारे मंत्री थे, लेकिन मैं अनुभव करता था कि रिटर्न जवाब नहीं आता था। फोन अटेंड होता तो था कि कहां से अस्पताल की व्यवस्था होगी, कहां इंजेक्शन की होगी, कहां दवा की होगी, कहां सिलेंडर मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस के किसी भी नेता ने, मैं खुद इस बात का गवाह हूं हमने उस काल में कई लोगों को गंवाया है, वहां से कोई रिटर्न जवाब नहीं आया, कोई मदद नहीं की गई, भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया था। ठीक है, गहलोत साहब के मैनेजमेंट की तारीफ की, हम भी तारीफ करते हैं जो अच्छा होता है, लेकिन उसका

रिजल्ट क्या आया? आप लोग भी तारीफ करें, जिस प्रकार से 2014 के बाद ऐतिहासिक फैसले आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में लिये गये। देश में जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ, आज देश में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा और जय-जयकार होने लगी है और उसी क्रम में आज पूरे भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को लार्जेस्ट पार्टी बनाया है और हम सबको यहां जनता की सेवा के लिये चुनकर भेजा है। यह आदरणीय मोदी जी के फैसले, उनके किये हुए कार्यों की ही जय-जय है और उन्हीं की वजह से हम लोग यहां काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार की कितनी ही अनगिनत योजनाएं थीं, बार-बार हम लोग जल जीवन मिशन की भी बात करते हैं और केन्द्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के लिये अरबों रुपये का बजट आया, उसकी भी बात करते हैं, लेकिन उस बजट का उपयोग क्या हुआ, किस तरीके से हुआ? उन सबकी जांच की मैंने खुद ने भी मांग की है कि पिछली सरकार में जिस प्रकार के काम हुए, वो जो केन्द्र सरकार से बजट आया था, उस बजट के द्वारा जो काम हुए, उनकी जांच होनी चाहिये। पिछले एक वर्ष में जो ऐतिहासिक काम हुए हैं उसी की बदौलत जनता ने आशीर्वाद दिया और उप चुनाव में हम जीते। जैसा कि अभी हमारे सदन के पिछले वक्ताओं ने कहा कि हमारे पास खोने को था क्या, हमको तो मिला ही है। आप लोग पिछली बार सदन में बार-बार कह रहे थे कि आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे।

Msk/rtm/06.02.25/1640/3c

कोई गमछे वाले भाई साहब, कोई ठुमके वाले भाई साहब। तरह-तरह के काम करके आप लोग यहां बता रहे थे। कोई कह रहा था कि यह भजन मण्डली आ गयी। आप लोगों को भजन से, सत्संग से, सनातन से, तीर्थ से और महाकुंभ से तकलीफ है, बात मानते हैं, लेकिन हमारी भावनाओं को समझें, उनका आदर करें, न कि इस प्रकार की बातें करके, आप लोग भजन मण्डली, भजन, सत्संग और तप से जो काम किया जा सकता है। आज आप, हम लोग कहीं न कहीं राम को मानते हैं। राम को जानते हैं और राम की मर्यादा को भी मानते हैं, लेकिन आप लोगों के अन्दर कहीं कोई जीजी-जीजा जी, मम्मी-बेटा और इटली, कोई प्रभाव है या उन्होंने कुछ कह रखा है कि जो राम की बात करे, उसके विरोध में रहो, जो सनातन की बात करे, उसके विरोध में रहो। मैंने राम-राम कर लिया, जय श्री राम कर लिया, मेरा स्वभाव है तो उसमें बहन जी को आपत्ति हो गयी। संविधान की जो पुस्तक आप लिये घूमते हैं, मेरी प्रार्थना है, मेरा आपसे निवेदन है कि संविधान की पुस्तक को पढ़ लो, उसके पन्नों पर जो फोटो छपे हैं, शिवाजी महाराज के, राजा रामचन्द्र भगवान के, भगवान बुद्ध के, जरा उनके भी दर्शन करके उनका भी मनन-चिन्तन कर लिया करो।

श्रीमती वसुन्धरा राजे सिंधिया जी के समय हमारे प्रदेश की क्या स्थितियां थीं, चमचमाते शहर थे, गांव, ढाणी सब क्षेत्रों में अच्छा विकास था। फिर आपकी सरकार आयी। सरकार को ढूंढने लगे तो पता चला कि फाइव स्टार होटल के अन्दर है। दो मुख्य मंत्रियों की लड़ाई के

अन्दर चारों ओर भ्रष्टाचार मचा पड़ा है। अधिकारी और सरकार दोनों ही नदारद थे और जनता अपने हाल पर थी, भगवान के भरोसे थे। उसके जीते-जागते प्रमाण हैं। ...(व्यवधान)... कोरोना तो आपदा थी, चलो मान लिया, लेकिन उस समय सरकार कहां थी, सरकार होटल में थी। आप लोग एक वर्ष के काम में कोई कमी निकाल दो। मैं मानता हूं, आपका तो धर्म बनता है हर बात का विरोध करना, लेकिन आप विरोध किस बात का करें। क्या काम नहीं हुआ, क्या विकास नहीं हुआ। आपदा पार्टी ने पंजाब को पहले नंबर कर्जे पर छोड़ा और कांग्रेस ने दूसरे नंबर पर छोड़ा था, पूरे भारत में। उस कर्जे के बाद भी सड़कें ढूंढने पर भी नहीं थीं, गड्ढे-गड्ढे ही थे। कहीं कोई सीमेंट नहीं था, कहीं डामर नहीं था। आज जिस तरीके से सड़कों का जाल भी बिछा है और केन्द्र सरकार के द्वारा अनगिनत योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा घर ढाणी तक आज योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है।

आप लोग किसान की बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को थोड़ा-सा स्मरण कर लिया करो। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो गांव-ढाणी के लिए, गांव से शहर को जोड़ने के लिए सड़कों की योजना बनायी। नदी-नालों को जीवित करने की योजना बनायी। बाढ़ क्षेत्रों का पानी, जिन क्षेत्रों में जल की समस्या है, वहां तक पहुंचे, उसके लिए योजनाएं बनायीं। उन पर काम होना शुरू हुआ और उसी सपने को साकार करने लिए आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने संकल्प लिया और सबके आशीर्वाद के साथ सबका साथ, सबका विश्वास जीतकर सबके प्रयास के साथ उस पर काम किया और उसी का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। आप गिरेबां में झांका तो करें। सिर्फ मम्मी-बेटा, जीजी-जीजा जी, चार को खुश करने के लिए आप दिन भर हम लोगों को कोसते रहें, कमियां निकालने का काम करें, जो हैं नहीं। आप सिर्फ इस पर ध्यान दे रहे हैं। आप अपने आपको सोचें, आप संविधान की बात करते हैं। अंबेडकर साहब को किसने रोका, जवाहरलाल नेहरू जी ने रोका, सदन में आने से किसने रोका? अंबेडकर साहब को आप प्रतिष्ठा दिला पाये? वह मान-सम्मान, नाम दिला पाये? वह मान-सम्मान मिला 2014 के बाद। पंचतीर्थ किसने बनाये? राहुल गांधी जी ने जो पिछले दिनों कहा है, जो 56 साल के युवा बनते हैं, उन्होंने पिछले दिनों कहा है कि हमारे हाथ से वह वोट बैंक छिन गया है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) हमारे हाथ से दलितों का वोट बैंक जा रहा है, हमारे हाथ से आदिवासियों का जा रहा है। यह उन्होंने खुद ने अपना दुख बताया, क्योंकि हमने इनके लिए कभी कुछ किया नहीं है। उस दुख और पीड़ा को बताया। उसके बाद आपको संविधान की याद आने लगी। बाबा साहेब की याद आने लगी है।

राज्यपाल महोदय ने एक वर्ष के ऐतिहासक कार्य, आदरणीय मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने जो किये, उनकी चर्चा और चर्चा राज्यपाल ने ही नहीं, पूरे राजस्थान में हो रही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): सभापति महोदय, नया हूं, थोड़ा-सा। पिछले दिनों मैं महाराष्ट्र भी गया, गुजरात भी गया और गुजरात एवं महाराष्ट्र में लोगों से हमने तारीफ सुनी कि आपने मुख्य मंत्री ने तो पहली बॉल पर छक्का मार दिया। कैसे? बोले लोग तो सरकारें जाती हैं तब सोचते हैं, ऐसी प्लानिंग, ऐसी योजनाएं। जो राजनीति के जानकार थे, वे तारीफ कर रहे थे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): आपके मुख्य मंत्री महोदय ने आने के साथ ऐतिहासिक कदम उठाया, ईआरसीपी का मामला हो, जनकल्याणकारी योजनाओं की बात हो या आपके राइजिंग राजस्थान हो, बहुत अच्छे-अच्छे कार्य शुरू में ही प्रारंभ किये, इसका मतलब आपके राजस्थान में एक वर्ष में जो ऐतिहासिक काम हो रहा है, आपकी उप चुनाव में भी जीत होगी और वही हुआ, जो वहां हम लोग सुने थे। वही हुआ कि उप चुनावों में हमारी ऐतिहासिक जीत हुई।

श्री सभापति: माननीय रविन्द्र सिंह भाटी।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): सभापति महोदय, दो मिनट का समय दीजिये। बहुत अच्छे कार्य एक वर्ष में हो रहे हैं। मैं मेरे क्षेत्र के लिए और थोड़ा-सा निवेदन करना चाहूंगा।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): सभापति महोदय, मेरे पास पांच मिनट हैं। आपका आशीर्वाद मिला तो बड़ी शानदार तरीके से बोलेंगे और आपकी बात भी रख लेंगे। सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं शिव की जनता का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक अध्यापक के बेटे पर विश्वास जताया और प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में सबसे युवा सदस्य बनने का मौका दिया। शिव की देवतुल्य जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ, मैं वर्तमान सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि वह यूथ पॉलिसी ले आये। घुमन्तू और अर्द्ध घुमन्तुओं के लिए आपने पट्टे की व्यवस्था की। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था, इस सदन में मांग उठायी थी, उस पर काम हुआ, मैं उसकी बधाई देता हूं।

साथ ही साथ, राइजिंग राजस्थान एक सफल आयोजन रहा। मैं उसकी भी आपको खूब-खूब बधाई देता हूं। साथ ही साथ, राइजिंग राजस्थान में हम सभी को जाने का मौका मिला, उसके एमओयू के बारे में पढ़ने का मौका मिला। रोज अखबारों में बहुत बड़ी-बड़ी बातें उसको लेकर लिखी जाती थीं। 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। बहुत बढ़िया है, होना चाहिए, स्टेट आगे बढ़ना चाहिए, विकास होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब उसके अन्दर देखा कि 35 लाख करोड़ के एमओयूज में और क्या-क्या है, तब पता चला कि, साहब, 28 लाख करोड़ तो हमारे अक्षय ऊर्जा के हैं। बहुत अच्छी चीज है। स्टेट में ऊर्जा तो होनी ही चाहिए। अगर आप वेस्टर्न राजस्थान से ऊर्जा उत्पादित कर रहे हो तो यह वाकई बहुत बड़ी चीज है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। पर, साहब, इसकी कीमत कौन चुका रहा है? इसकी कीमत आज के समय में वे सीमान्त के लोग चुका रहे हैं। उस अक्षय ऊर्जा के नाम पर आज भी

जितनी भी बिजली जनरेट कर रहे हैं, आप बतायें कि उसके बदले इस स्टेट को क्या मिल रहा है? पॉवर ग्रिड से हम आंध्रा को, तेलंगाना को बाहर, देश के अलग-अलग राज्यों को बिजली दे रहे हैं? क्या हमारे किसानों को आज हम पूरी बिजली दे पा रहे हैं? जिस चीज की घर में जरूरत है, उसकी पूर्ति तो आप करायें। आज के समय में हमारे किसानों को कहीं बिजली नहीं मिल पा रही है। जो जमीन थोड़ी-बहुत बची थी, ओरण एवं गोचर, उसको भी आपने पूरी तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज के चरणों में रख दिया। आज पूरे किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं, पर उनकी बात कोई नहीं कर रहा है।

विकास की बात आयी, हमने सोचा कि, साहब, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहां लगेंगी, खूब सारे युवाओं को यहां रोजगार मिलेगा। कई सारे लोगों ने कहा कि विकास तो आपके वेस्टर्न राजस्थान में बरस जायेगा, आप देखो क्या होता है। वही सपने हमें दिखाये गये, जो रिफाइनरी आयी, उस समय हमें दिखाये थे। हमें कहा गया कि यह आने वाले समय में दुबई बनेगा। जैसे शेखों के पास में रॉल्स रॉयस की गाड़ी है, वैसी आपके पास भी होगी। यहां पर अपार संभावनाएं हैं। बदले में क्या हुआ? आज भी वह पश्चिमी राजस्थान और वे सीमान्त के लोग वहीं खड़े हैं। आज पुनः वैसे सपने उन भोलेभाले लोगों को दिखाये जा रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि, साहब, आपके यहां रेवेन्यू जनरेट होगा, विकास होगा। साहब, सौर ऊर्जा का जो एक प्लांट लगता है, लगने के बाद दो गार्ड के अलावा वहां तीसरा आदमी नहीं लगता। रही बात दूसरी। पहले प्लेट साफ करने के लिए एकाध आदमी लगाया करते थे, आज कल तो उसका भी रोबोट आ गया है। वहां पर पूरे तरीके से वन्य सम्पदा थी, उसको पूरे तरीके से खतम कर दिया गया।

अभी महाराज जी लम्पी की बात कह रहे थे। पिछले लम्पी के दौर में हमने भी खूब सारा प्रयास किया। गाय हम सभी के लिए पवित्र है, भगवान रूपी है। पर साहब आप बतायें कि जब यह ओरण और गोचर खतम हो जायेगा तो वह गऊ माता कहां जायेगी? आज उसकी बात कौन कर रहा है? पिछले दिनों भियांड गांव में ओरण पर अनैतिक तरीके से, अवैध तरीके से अलॉटमेंट हो रहे थे। हमने मांग उठायी, वह लड़ाई लड़ी। बदले में क्या, मुकदमे। क्या मुकदमों से डरा देंगे? क्या मुकदमों से दबा देंगे? मैं आपको कहना चाहूंगा कि वाकई अगर आप चाहते हैं, वाकई अगर आप युवाओं के साथ हो, वाकई अगर आप किसानों के साथ हो।

mdp/rtm/06.02.2025/16:50/3d

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 70 परसेंट अन-स्किल्ड और सेमी स्किल्ड में प्राइवेट जॉब्स में रिजर्वेशन लाएं और बोलें कि साहब, जहां पर यह काम हो रहा है वहां के युवाओं को वरीयता देंगे। आप लाएं, आप नहीं ला पाएंगे, मैं चैलेन्ज करता हूं। अगर आप ला पाएं तो आप जहां कहेंगे वहां खड़े रहने के लिए हम तैयार है। आज इस तरीके से ये जो काम कर रहे हैं, वाकई बहुत दुखद है। लाखों की संख्या में खेज़ड़िया कट रही हैं, वन सम्पदा

खतम हो रही है। आप याद कीजिए तेजा जी महाराज, पाबू जी को, हड़बू जी को, अमृता देवी जी को, जम्भेश्वर भगवान को, पर्यावरण के लिए उन्होंने क्या-क्या नहीं किया।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): आज बदले में क्या-क्या हो रहा है? हम एक तरफ 'एक पेड़ मां के नाम' लगा रहे हैं और दूसरी तरफ सौ-सौ पेड़ किसके नाम पर काट रहे हैं। जवाब मांगती है ये जनता, स्टेट देख रहा है। पश्चिमी राजस्थान के उन तमाम हमारे 47 माननीय सदस्यों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर समय रहते आपने उस क्षेत्र की आवाज को नहीं रखा तो जनता तैयार बैठी है। ये एक साल निकल गया, चार साल निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। साहब, उन लोगों के लिए, उन सीमांत के लोगों के लिए अगर कुछ भला कर सको तो कर लो। इससे बड़ा कोई मौका नहीं आना है।

श्री सभापतिः श्री अर्जुन लाल जी जीनगर।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): आप जिस सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, आप जिस विंड की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि वह विंड जहां लगता है, आसपास की 500 मीटर उस परिधि में कोई भी इंसान और आने वाली पीढ़ी सुन नहीं पाएगी। यह स्थितियां उस क्षेत्र में पैदा होने वाली है। बात करनी होगी।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): 000

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय श्री हरिभाऊ जी बागडे के इस अभिभाषण की प्रशंसा भी करता हूं और समर्थन भी करता हूं एवं कुछ तथ्यों के साथ अपनी बात भी रखना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं महामहिम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वह महाराष्ट्र की धरती, शिवाजी वीर सपूत की धरती से आए हैं और हमारी इस राजस्थान की धरती पर महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की धरती पर आकर उन्होंने हमारी माटी को नमन किया और हमारे 8 करोड़ प्रदेशवासियों को सुख और समृद्धि की कामना भी उन्होंने की। राजस्थान की माटी के कण-कण में शौर्य, त्याग और बलिदान की गाथाएं रची बसी हैं। यहां के किले, महल बावड़ियां हमेशा अपने गौरवशाली इतिहास को याद रखते हैं। हमारे वीर और वीरांगनाएं, हमारी आन-बान-शान के आधार पर प्राणों की आहुति देने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। ऐसी वीर प्रसूता भूमि पर बागडे जी ने आकर अभिभाषण पढ़ा, इसलिए भी हम उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं।

महामहिम ने अपने अभिभाषण में स्पष्ट कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में अपने पहले ही बजट में राजस्थान की जनता का भरोसा जीत लिया और उन्होंने अपने पहले ही बजट में राजस्थान के आगामी पांच वर्षों की विकास की पटकथा लिख दी। हर वर्ग के विकास को उन्होंने गति देने के लिए समावेशी बजट पेश किया। इसका नतीजा यह रहा कि जनता में भारतीय जनता पार्टी की, भजन लाल

जी की सरकार की पैठ बनी और उसका सबूत भी राजस्थान प्रदेश के उप चुनावों में पता चल गया। 7 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालकर कांग्रेस को आईना दिखा दिया कि उन्होंने पिछले इनके कार्यकाल में प्रदेश में जो चहुंमुखी विकास होना था, वह नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने पिछले शासन में सिर्फ और सिर्फ खराब कानून व्यवस्था, पेपर लीक, चोरी, डकैती, लूट माफिया और भ्रष्टाचार के तोहफे देने का काम किया।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के नौजवानों के साथ, बेरोजगार नौजवानों के साथ इन्होंने छलावा किया। पेपर लीक करने का काम इन्होंने किया। आर.पी.एस.सी. जैसी विश्वसनीय संस्था के ऊपर भी इन्होंने अपना आंचल डालकर भ्रष्ट करने का काम किया। 17-17 बार पेपर लीक का काम कांग्रेस के राज में हुआ। जब परीक्षार्थी परीक्षा देने जाता था, अन्दर ही पता चल जाता कि पेपर आउट हो गया। इस प्रकार से परीक्षार्थियों के लिए छलावा करने का काम किया और हमारे नौजवानों को छलने का काम इन्होंने किया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे तो उस दिन ताज्जुब हुआ जब पेपर लीक की घटनाएं सामने आयी और एक बिल्डिंग को दूसरे दिन धराशायी कर दिया। वह बिल्डिंग किसकी थी? बिल्डिंग किसी अन्य व्यक्ति की थी, चलाने वाला कोई भ्रष्टाचारी था। उस भ्रष्टाचारी पर कोई कार्यवाही नहीं की और उस बिल्डिंग को धराशायी करके खुंदस निकालने का काम कांग्रेस राज में हुआ। आज हमारी सरकार में पेपर माफिया, ऐसे भ्रष्ट लोगों को, 260 बदमाशों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भजन लाल जी की सरकार ने किया है। कांग्रेस के राज में कानून व्यवस्था कहीं नजर नहीं आती थी। चोरी, डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार, महिला अत्याचार, अपहरण की न्यूज से हमेशा अख़बार भरे पड़े रहते थे।

सभापति महोदय, प्रदेश में जिस समय कोरोना था, कांग्रेस का शासन था। दो व्यक्ति एक कुर्सी पर बैठने के लिए लड़ाई-झगड़ा कर रहे थे। उस समय कोरोना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, संघ के कार्यकर्ताओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस प्रदेश को संभालने का काम किया और इनकी सरकार ने फाइव स्टार होटलों में बैठकर आराम करने का काम किया। कांग्रेस के राज में बिजली का अता-पता नहीं था। वीसीआर भरे जाते थे 50-50 हजार रुपये के। यदि ट्रांसफार्मर जल गया तो 20-25 हजार रुपये देने के बाद ही ट्रांसफार्मर लगते थे, लेकिन आज दिन में बिजली किसानों को मिलती है। 24 घंटे बिजली मिलती है। निर्विवाद रूप से बिजली मिलती है।

कांग्रेस के राज में जल जीवन मिशन योजना प्रारम्भ की थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी को कि उन्होंने जिस प्रकार से जल जीवन मिशन राजस्थान में लागू किया, लेकिन कांग्रेस के राज में इन्होंने लागू नहीं किया और अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम किया। कहीं छोटा-मोटा काम भी प्रारम्भ किया था जल जीवन मिशन में, उसमें भी भारी मात्रा में बड़ा घोटाला किया। सचिवालय के बाहर ढ़ाई-ढ़ाई करोड़ रुपया एक कार्यालय में मिलना और एक-एक किलो सोना मिलना, ये भ्रष्टाचार के सबसे

बड़े उदाहरण है। नदी, नाले, वन क्षेत्रों में, चरागाह भूमि पर अवैध कब्जा करके अवैध खनन करने का काम इन्होंने किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी को उन्होंने सबसे पहले हमारी अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डालर तक ले जाने का लक्ष्य रखा। इसे साकार करने के उद्देश्य से राइजिंग राजस्थान इंवेस्टमेंट समिट, सरकार की दूरदर्शी सोच का एक उदाहरण है। इसी के माध्यम से राजस्थान के अन्दर लगभग 35 लाख करोड़ के समिट में निवेश का लक्ष्य रखा और यह लक्ष्य प्राप्त होगा। राजस्थान के अन्दर औद्योगिक क्रांति के प्रेरणा स्रोत हमारे यशस्वी, विजनरी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी से राजस्थान को यह प्रेरणा मिलती है कि हम भी औद्योगिक क्रांति लाकर राजस्थान को औद्योगिक दृष्टि से मजबूत करें।

हमारी सरकार के मुखिया माननीय भजन लाल जी ने पूरे राजस्थान के अन्दर किसानों को खेती के लिए अच्छा पानी मिल सके और पीने के लिए हर घर को मीठे जल का शुद्ध नल का पानी मिल सके, इसके लिए उन्होंने जल जीवन मिशन को प्रारम्भ करने के लिए और 17 जिलों के लिए पार्वती-कालीसिंध-चम्बल (केपीसी योजना) का नया नाम दिया। हमारे मोदी जी यहां आए थे और उन्होंने राम जल सेतु लिंक परियोजना को स्वीकृति देकर काम किया। राम जल सेतु परियोजना का नाम ही अपने आप में एक अद्भूत नाम है। इसकी पहचान कैसे बनी? यह राम का नाम आया कैसे? राजस्थान का पहला अक्षर है 'रा' और मध्य प्रदेश का पहला अक्षर है 'म' इन दोनों अक्षरों को मिलाकर उसका नाम हो जाएगा 'राम' और जिस योजना का दोनों अक्षरों को मिलाने से यदि राम बनता है, जिस परियोजना का नाम ही राम हो जाए, वह परियोजना सबके लिए सुखदायी, आनन्ददायी और अन्नपूर्णा जैसी योजना बनकर हमारे सामने आती है। राम का नाम लेने से ही यदि सुख मिलता है तो ये राम जल सेतु योजना हमारे सबके लिए सुखदायी होगी। रामायण में चौपाई लिखी हुई है कि 'सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा' इस प्रकार से राम के नाम की महिमा है।

Ans/rtm 17.00 3e 06.02.2025

हमारी सरकार ने पिछले बजट में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल पहुंचाने का संकल्प लिया, उसके तहत कई परियोजनाएं राणा प्रताप सागर बांध, ज्वार सागर बांध, माही कोटा जाखम बांध, माही सोम बांध इस प्रकार से कई योजनाएं हैं। 17 ज़िले उधर से आ जाएंगे, 10 ज़िले इधर से आ जाएंगे यानी 27 ज़िले, इस प्रकार से काम हो जाएगा। मैं सोचता हूं कि राजस्थान के अन्दर सारा काम ठीक होगा।

मेरे कपासन विधान सभा क्षेत्र में जिस प्रकार से मुख्य मंत्री जी ने छप्पर फाडकर विकास के काम दिये, उनके लिए तीन मिनट में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, सड़क के क्षेत्र में लगभग 450 करोड़ रूपये से ज्यादा का कपासन विधान सभा क्षेत्र

को तोहफा दिया। कारल से कपासन, हमीर गेट से राशमी, कांकावास से बांसवाड़ा, रोल्या से रेलमगरा, ईटाली से बांसवाड़ा, कोटडी से कपासन बाई पास, हाई लेवल ब्रिज, पांच करोड़ की सड़कें। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसी तरह प्रकार से बिजली के क्षेत्र में बांसवाड़ा में 132 केवी का जीएसएस। चिकित्सा सुविधा के अन्दर भीमगढ़, आक्या, रूद के अन्दर पीएचसी। पशु चिकित्सालय में भी मोन पशु, उसके लिए भी पशु वैन प्रारम्भ करने के लिए हमारे मंत्री महोदय ने बड़ा काम किया और टोल फ्री नम्बर देकर, प्रदेश में लगभग 536 वैन प्रारम्भ करके शुभ काम किया। गो-माता आपको खूब देगी, खूब आगे बढ़ाएगी। आपने मुख्य मंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारम्भ की।

श्री सभापतिः प्लीज, समाप्त कीजिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): दो मिनट और लूंगा। मेरे क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या थी, तो मुख्य मंत्री जी ने डीके फीडर के नाम से 25 करोड़ रूपये स्वीकृत किए। कपासन, जासमा, दमाना, भोपासागर को पानी मिलेगा। डिंडोली फीडर के लिए 6.5 करोड रूपये सैंक्शन किए, उससे डिंडोली, सिंगपुर, तूमड्या सरोवर तालाबों को भरने का काम होगा। इस प्रकार से जायका योजना के अन्दर भी लगभग 50 करोड़ रूपये हमको मिले हैं। उच्च शिक्षा के लिए भी कॉलेज हुआ।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए। श्री विद्याधर सिंह जी।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): इस प्रकार हर क्षेत्र में पैसा मिलने का काम हुआ। अंत में एक लाइन पूरी करुंगा।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का वक्त दिया उसके लिए धन्यवाद। मैंने राज्यपाल महोदय को अभिभाषण को पढ़ा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): हमारी सरकार राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश बनाकर, चहुमुखी विकास करने का काम करेगी। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): मैं भगवान से आशा करता था कि इस अभिभाषण में जो पढ़ा वह सच साबित होगा परन्तु यह सरकार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के विपरीत दिशा में काम कर रही है। इसकी मैं तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करुंगा, एक-एक विषय पर बताऊंगा।

पैरा संख्या 23 में उल्लेख किया है कि नल से जल उपलब्ध कराने के लिए 6 हजार 91 करोड़ रूपये का व्यय कर लगभग 11 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया है, लेकिन धरातल पर यह बात साकार नहीं हो रही है। हकीकत कुछ और है। ना तो नल लगा है, ना जल आया है, ना ही पाइप लाइन बिछाई गई है। अगर पाइप लाइन बिछाई गई है तो केवल काग़ज़ों में बिछाई गई है जिससे चारों ओर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में हकीकत यह है कि सप्ताह में एक दिन पानी आ रहा है। मैंने

पिछली बार यह मुद्दा उठाया था। मंत्री जी यहीं बैठे हैं, इन्होंने खुद कहा कि फुलेरा में 18 एमएलडी पानी अलॉट है, लेकिन हम 09 ही दे पा रहे हैं क्योंकि हमारी पाइप लाइन दुरुस्त नहीं है। मंत्री जी यहीं बैठे हैं, मैं इनके सामने बात रख रहा हूं। अब बताइये कि आप कह रहे हैं कि सबको जल मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा, आधा पानी मिल रहा है, फुलेरा प्यासा बैठा है और यहां राज्यपाल जी कह रहे हैं इतने करोड़ को पानी पिला दिया, इतने नल लगा दिये, यह है सरकार की हकीकत।

पैरा संख्या 25 में अमृत योजना की बात कर ले। इस योजना के पूर्व में चिह्नित किए गये, पूर्ववर्ती सरकार के स्थानों की जगह अब मनमर्जी से अपने नये स्थानों को चिह्नित किया जा रहा है। क्या जल लाने की जगह अपने चहेतों को टेंडर देकर उनके द्वारा काम कराना चाह रहे हैं? जरूरतमंद लोगों को जल से दूर रखने की पूरी प्रक्रिया ही बदली जा रही है, इसमें चारों ओर लूटपाट मची हुई है। अपर्याप्त जल, साफ-सफाई, स्वच्छता के कारण प्रतिवर्ष लाखों लोग मर रहे हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है, 2013 तक लगभग 21 प्रमुख शहरों में भूजल स्तर खतम हो जाएगा, जिसका प्रभाव प्रदेश के कई शहरों में पड़ने वाला है, इसको भी ध्यान में रखकर सरकार काम करें।

पैरा संख्या 28 में सरकार ने कहा कि 2027 तक किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली देने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि एक साल में हमारी सरकार ने बिजली का उत्पादन भी बढ़ा दिया है। विडम्बना वही है, उत्पादन बढ़ गया तो बिजली की खपत कहां हो रही है, क्या सरकार किसानों को बिजली नहीं देकर बेचने का काम कर रही है? सभापति महोदय, प्रदेश को छोडिये, मेरे विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में 27 नवम्बर से 30 नवम्बर तक, अभी बिजली मंत्री चले गये वरना मैं यह बात उनके सामने ही कहना चाहता था। कांग्रेस के वार्ड में, बिजली कहीं भी जाए, सड़क कहीं भी जाए, सब लोग चलते हैं, सब लोग उसका उपयोग करते हैं चाहे किसी पार्टी या किसी भी धर्म का हो, लेकिन चिह्नित वार्डों में बिजली कटौती की गई। मैंने अधिकारियों से पूछा तो यह कहा कि दबाव है। दबाव किसका है। मंत्री जी चले गये हैं। मैंने मंत्री जी से बात की कि मंत्री जी फुलेरा के 5-6 वार्डों को क्यों काटा गया है तो कहते हैं कि बिजली के बिल जमा नहीं है। मैंने पूछा क्या फुलेरा में ही जमा नहीं है या और भी जगह जमा नहीं है, तो बोले कि नहीं सभी नगरपालिकाओं में एक ही हाल है। तो फिर फुलेरा को चिह्नित क्यों किया गया, यह है भेदभाव की नीति, यह सरकार की नीति है। मैं ऊर्जा मंत्री को कहना चाहूंगा कि इस नीयत से काम करोंगे तो आम गरीब जनता कभी माफ नहीं करेगी।

गोशाला पर आ जाइये। बालमुकुन्द जी धर्म की बात करते हैं। आप क्या धर्म की बात कर रहे हैं, आप तो एक ही धर्म मानते हैं, हिन्दू धर्म ही। हम तो हिन्दू धर्म भी मानते हैं, ईसाई का भी मानते हैं, पंजाब का भी मानते हैं, बालाजी, भैरूंजी, जो हमारे सामने आता है उसको ही नमस्कार करते हैं। आप हमें धर्म का पाठ पढ़ा रहे हो। धार्मिक भावना को उकसा रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है। गोशाला की बात करते हैं।

पैरा संख्या 76 में कहा है कि पंजीकृत गोशालाओं को देय अनुदान में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। आपने बढ़ोतरी की, मैं अच्छा मानता हूं, आप बधाई के पात्र है। लेकिन वहां हो क्या रहा है? वह पैसा आप उन गोशालाओं को दे रहे हो? मेरे विधान सभा किशनगढ़ रेनवाल में बालाजी गोशाला में रोज कई गायें मर रही है। मेरे आमजन द्वारा सरकार को अवगत कराया गया, आमजन ने मुझे कराया। सरकार ने एसडीएम किशनगढ रेनवाल से एक कमेटी बिठाई। उस कमेटी ने उसके अगेन्स्ट रिपोर्ट दी कि इन्होंने अनियमितता की है, उसके बाद उनको 05 लाख का अनुदान और दिया गया है यानी उनको आशीर्वाद के रूप में कि खाये जाओ और यह 05 लाख और लो। जबकि वही कमेटी कार्य कर रही है, मेरे पास रिपोर्ट है। मंत्री जी चाहेंगे तो रिपोर्ट है, आपकी सरकार के एसडीएम की, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, यदि किसी को शंका हो तो ले सकता है।

अब शिक्षा पर आइये। अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि युवाओं की शक्ति को यदि उचित दिशा दी जाए तो चुनौतियों का सामना करने के लिए मानवता में बदलाव और शांति, समृद्धि में वृद्धि होगी। सभापति महोदय, लेकिन यह सरकार युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है।

मैं पेपर लीक की बात करूँ। जो युवा नौकरियों में है उनको भी जगह-जगह इधर से उधर कर रहे हैं। अभी सदस्य मुकेश जी भाकर ने एक बात रखी। सदन है, शांति से बात को सुनना, उसको विरोध के रूप में नहीं। यह तय है कि अभी आपने 4-4,5-5 बार ट्रांसफर किए हैं उसमें मेरा फुलेरा जीता जागता उदाहरण है। मेरे फुलेरा में कोई अधिकारी जाट नहीं है, जो थे सब बदले गये। एक लड़की एसडीएम थी उसको भी अभी 10 दिन पहले ही बदला गया है। क्यों भई, जाटों ने क्या किया है। जाट होना कोई गलत नहीं है। फुलेरा में ऐसा एक अधिकारी नहीं है जो जाट है, यह भावना गलत है। जातीय भेदभाव, अभी आप कह रहे थे जाट की बात।

VPS-RTM-06.02.2025-17.10-3f

आप तो धर्म की बात करते हो, हम जाट की बात नहीं करें? हम जाट की बात करते हैं तो कहते हैं कि जाट है तो क्या गुनाह कर दिया हमने? जाति में जहां जन्म हुआ है, अब लोग कहते हैं पार्टी, पार्टी ही माई-बाप है पर मैं कहता हूं इस सदन में कि पार्टी को माई-बाप कहने वाले असत्य लोग हैं। मैं यह कहता हूं कि पहली पार्टी है मां-बाप और उसके बाद में है समाज और तीसरी पार्टी जो आप ज्वाइन करो वह पार्टी है। मैं खुले में कहता हूं।

दूसरी बात है, हम सच्चाई की बात कहते हैं और मंत्री लोग, हम विपक्ष के लोगों को सत्ता पक्ष के लोग डराने के लिए हावी हो जाते हैं। हम किसान के बेटे हैं, हमने बहुत धाराएं देखी हैं, हमने बहुत मौसम देखा है। छह महीने किसान फसल के लिए खड़ा रहता है और छह महीने में फसल अगर खराब होती है तो वह दुबारा बोने की तैयारी करता है और उसके लिए पश्चाताप नहीं करता है तो हम तो वे लोग हैं जो छह-छह महीने का देखते हैं।

अब दूसरी बात, आप पेपर लीक की बात कह रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि हमारे पेपर लीक नहीं हो रहे हैं। आप क्या पेपर लीक की बात करोगे, आप मगरमच्छों को क्यों नहीं पकड़ते? मैं तो खुद यह कह रहा हूं कि आप ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो? यह विपक्ष वालों को सिर्फ ब्लैकमेल, डर दिखा रहे हो कि हम पकड़ लेंगे, हम पकड़ लेंगे,आप कुछ तो पकड़कर बताओ। कुछ को तो जेल में डालो, हमें भी पता लगे कि ये हमारे भाई थे, यह हमारे भाई थे।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): 134 लोगों को बर्खास्त किया गया है। ...(व्यवधान)...

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): आप पकड़कर दिखाओ। ऐसा नहीं, ब्लैकमेल मत करो। मंत्रीजी, आप ब्लैकमेल मत करो, आप पकड़कर साबित करो। बड़ी-बड़ी मछलियां बच गयी हैं, उनको भी आप पकड़ें। ...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): 134 लोगों को बर्खास्त किया है, पकड़ कर नौकरी से निकाला है। वे आपके भर्ती किये हुए थे। आपने नकल करवायी थी, पेपर आऊट किये थे। 134 लोगों को निकाला है और जो जांच में और आएंगे उनको और निकालेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): अभी रीटा बहिनजी ने यह कहा था कि एक समय था, जिसमें हम यहां पर अपनी बात रखते थे और उस बात को सब सुनते थे।

श्री सभापति: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): आज यह हालात है, आप यह कह रहे हो कि हम देश का नाम ऊँचा करेंगे। मोदीजी, हिंदुस्तान का नाम ऊँचा करेंगे पर अभी देखा नहीं कि अमेरिका ने 300 लोगों के हथकड़ी लगाकर नीचे उतारा है और उनको यहां पर भेजा है इंडिया में। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: श्री अर्जुन लालजी।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): सरकार से नहीं हो रहा कोई काम, ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): 000

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री भजन लालजी शर्मा एक वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में नये आयाम स्थापित कर रहे हैं तथा मजबूत हाथों में कमान होने से राजस्थान की खुशहाली के लिए बहुत बेहतर काम चल रहा है और भविष्य की चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार करके केन्द्र व राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय से प्रदेश के समग्र विकास के लिए निर्णय लेते हुए हमारे गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला, श्रमिक, दलित, वंचित, शोषित के लिए तथा समाज के हर वर्ग का जीवन बेहतर करने के लिए और उसे सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

विकसित भारत और विकसित राजस्थान के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी ज्ञान शब्द दिया है जो G से गरीब, Y से युवा-नौजवान, A से अन्नदाता किसान और N से नारी, महिलाओं के उत्थान के लिए व विकास का एक मूल मंत्र दिया है जिसको हमारे सरकार के मुख्य मंत्री श्री भजन लालजी शर्मा साहब के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को बखूबी निभा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं राइजिंग राजस्थान, ई.आर.सी.पी., परसा कोल माइन्स, एनर्जी, पेपर लीक, नकल मामलों में, जे.जे.एम. में घोटाले, भ्रष्टाचार एवं गरीब, युवा, किसान, महिलाओं पर बाद में बात करूंगा लेकिन इससे पहले मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा पर कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूं-

केसर की क्यारी सा गुंजित मारवाड़ का आई माता का धाम सुनो,
राजस्थान की रतन धरा पर क्षेत्र बिलाड़ा नाम सुनो।
सेवा और समर्पण का प्रण ले, उन्नति का नया स्वप्न बुना,
21वीं सदी की नव बेला में जब धन्य जनों ने मुझे चुना।
जन-जन के सपनों को लेकर मैं राजधानी की ओर चला,
वर्षों से लंबित मुद्दों को हल करने का फिर एक नूतन दौर चला।

जिसमें गत बजट में हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लालजी ने बिलाड़ा के लिए जो दिया है, वह भी एक पद्य के रूप में निवेदन करना चाहता हूं-

उप जिला अस्पताल, उपखंड कार्यालय, उप जिला परिवहन ऑफिस मिले,
उप अधीक्षक भवन के संग में अटल पथ भी खूब मिले।

उसके पहले हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्री वसुन्धराजी राजे ने भी बिलाड़ा के लिए दिये हैं-

कॉलेज, ट्रोमा, कोर्ट ए.डी.जे., आई.टी.आई. और मॉडल स्कूल,
बिलाड़ा की बगिया में महके प्रगति के सारे फूल।
सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा में भी प्रगति के प्रतिमान बढ़े,
कदम से कदम मिलाकर सबको साथ लेकर आगे बढ़े।
भजन लालजी ने वापस क्या दृढ़ता से संकल्प लिया है,
प्रदेश की पेयजल समस्या को हल करना है,
मेरी शपथ का सार यही है, जसवन्त सागर बांध को पुनः भरना है।

नरेन्द्र भाई मोदी ने कहा है-

उन्नति की इस महा दौड़ का सफर अभी भी जारी है,
सच्ची समर्पित सेवा का जयघोष सभी पर भारी है।

मुख्य मंत्रीजी ने कहा है-

आने वाले और दिनों में अभी बहुत कुछ करना है,
बिलाड़ा के मानचित्र में शेष रहे सब रंग भरना है।

औद्योगिक विकास के लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट

समिट का आयोजन कर एक ही साल में, पहले साल में ही 300 बिलियन डालर की प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ले जाने का एक लक्ष्य रखा था और उस लक्ष्य को अर्जित करने की एक दूर-दृष्टि सोच रखी थी। इससे राजस्थान का तो भाग्योदय होगा ही होगा साथही साथ राजस्थान के जो बेरोजगार नौजवान हैं उन युवाओं को भी रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और साथ ही साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।

इसमें राइजिंग राजस्थान के साथ ही साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए भी मैं मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करता हूं कि बिलाड़ा में 15 वर्षों से अटका कर लटकाया कापरड़ा सेज, वह सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो 15 वर्षों से लटका हुआ है और उसके साथ रीको क्षेत्र कापरड़ा और झाग को प्रारंभ करवाने की भी मैं आवश्यकता समझता हूं।

हमारी सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है जिसका जीता जागता उदाहरण ई.आर.सी.पी. ने सिद्ध कर दिया है। पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धराजी राजे ने इस परियोजना की पहली बार प्रस्तावित डी.पी.आर. बनवाई थी लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार बदलती रही और उसे अटका कर लटका दिया। मैं धन्यवाद देता हूं देश के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदीजी को और प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री भजन लालजी शर्मा के साथ ही साथ मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री मोहनजी यादव को भी जिन्होंने इस संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल योजना का जो वर्तमान में नाम अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा था राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने की पहल की है तो मैं मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करता हूं कि इसी तर्ज पर हमारे पश्चिमी राजस्थान के लिए डब्ल्यू. आर.सी.पी. को साकार रूप देकर पश्चिमी राजस्थान को भी सरसब्ज बनाने की कार्यवाही करें।

राजस्थान वह प्रदेश है जो पानी की एक-एक बूंद का महत्व जानता है और जहां पर सदियों से जल संचयन और जल संरक्षण की परम्परा रही है। गत कांग्रेस सरकार को गांव-ढाणी में बसे लोगों को स्वच्छ पेयजल सुलभ करवाने के लिए हमारी केंद्रीय सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से हर घर नल से जल पहुंचाने का एक बहुत अच्छा अवसर दिया था।

ssy/rtm/06.02.2025/17.20/3g

लेकिन यह सोचकर कि इस कार्य की वाहवाही देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी को मिल जायेगी, उनका नाम हो जायेगा तो उन्होंने इस योजना को मूर्त रूप नहीं देकर लटका करके रखा। जहां भी काम किया वहां पर घोटाले और भ्रष्टाचार के उदाहरण मिलते गये। इससे देश के अन्दर अपने प्रदेश की बदनामी हुई। अब हमारी सरकार ने जेजेएम योजना को पुनः शुरू करने और सुधारने का काम शुरू किया है। इसके साथ ही यमुना जल लाने, आईजीएनपी, चंबल की नहरों के दुरुस्तीकरण का कार्य कर रही है।

मेरे विधान सभा बिलाड़ा क्षेत्र के लिये जोधपुर जिले का जो सबसे बड़ा बांध जसवंत सागर है, मंत्री महोदय, जोधपुर के अन्दर जो 2 मीटर व्यास की पाइप लाइन से पेयजल के

लिए पानी आता है, जोधपुर शहर खुद पानी के ऊपर तैर रहा है, अंडर ग्राउंड में पानी आ चुका है कायलाना, सूरपुरा आदि से, मैं चाहता हूं कि इस योजना को थोड़ा एक्सटेंड करके करीब 60 किलोमीटर आगे इस पाइप लाइन को बढ़ा देते हैं तो जसवंत सागर बांध पुनः भर जायेगा। उससे पूरे मारवाड़ को बिना पंपिंग बाई ग्रेविटी पानी मिलेगा। इसके साथ ही माणिकलाव दांतिवाड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें देवलिया से गोयदाना के लिए 16 गांवों के लिए पानी की जो व्यवस्था है, वह भी आपको करनी है।

ऊर्जा के क्षेत्र में परसा कोल माइंस के लिए मेरे से पहले सारे लोगों ने भी बताया है। इसके साथ ही सुजानगढ़, बूंदी और लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्यों ने अपने वक्तव्य में यह बात उठाई थी कि अभिभाषण के 44 पेज के 168 बिन्दुओं में कहीं पर भी अनुसूचित जाति का उल्लेख नहीं है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी जी ने जो मूल मंत्र दिया है ज्ञान का, या तो वह ज्ञान आपके ध्यान में नहीं आ रहा है और इनको आयेगा भी नहीं।

श्री सभापतिः प्लीज, बात समाप्त कीजिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): उस ज्ञान में जो गरीब, युवा, किसान और महिला है, क्या इसमें अनुसूचित जाति के लोग नहीं आते हैं?

श्री सभापतिः प्लीज, क्लोज करें। प्लीज, समाप्त कीजिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): यह आपकी मानसिकता का द्योतक है। जो वोटों की राजनीति करते हुए जाति, वर्गो और धर्मों में जनता को बांटने का काम कर रही है। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री सुभाष गर्ग।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि राज्यपाल जी के अभिभाषण की एक पंक्ति है जिसमें उन्होंने कहा है कि 'अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का कल्याण हो और न्याय मिले'। इसी तरह से वर्तमान सरकार का जो बजट आया था, उसके 10 संकल्प हैं। उन 10 संकल्पों में से 01 संकल्प जिसमें सारे 09 संकल्प पूरे हो जाते हैं, सुशासन, गुड गवर्नेंस की बात करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं पूरे सदन का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि प्रत्येक सरकार का, चाहे सरकार पूर्ववर्ती हो, चाहे वर्तमान हो और प्रत्येक सदस्य का जो इस सदन में बैठा हुआ है, उसका उद्देश्य होता है कि जनता ने जिस भावना और जिस आंकाक्षा को लेकर भेजा है वह है कि अंतिम छोर के व्यक्ति को कैसे लाभ मिले। कैसे सुशासन मिले।

हर सरकार यह चाहती है कि कोई भी पीछे ना छूटे। कोई भी गरीब ना रहे। कोई भी भूखा ना सोये। कोई भी अनपढ़ ना रहे। कोई भी दम ना तोड़े। कोई भी भय या डर में ना जीये अर्थात जीओ और जीने दो। इस भावना के साथ जब हम चुनकर के आते हैं तो मैं देखता हूं, यह अनुभव है और हम सभी का अनुभव है, जब हम इस पक्ष में होते हैं तो आलोचना करते हैं, जब सामने वाले इधर आते हैं तो वह आलोचना करते हैं। लेकिन सरकार का पूरा मकसद क्या है? सरकार का मकसद तो गुड गवर्नेंस है।

मैं इसमें बताना चाहूंगा, महामहिम राज्यपाल महोदय को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने जो गांधी जी का वाक्य कहा कि अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ कैसे मिले। हमारी यह ड्युटी बनती है। हम अपने ही हाथों से विधायिका के रोल को कमजोर करते चले जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मैं भी मंत्री रहा हूं और मैंने भी फेस किया है, आप भी फेस कर रहे हैं, हम स्वयं ही अपनी कलम से विधायिका की जो स्ट्रेंथ है उसको कमजोर कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय को अनुरोध करना चाहूंगा कि हम देखते हैं कि जितने भी कॉरपोरेशंस बनते हैं, हरीश चौधरी जी ने कहा था, मैं भी उससे जूझा हूं, माननीय जल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो प्राधिकरण का बिल लेकर आये थे उसको प्रवर समिति को सौंपा और विचार कर रहे हैं।

आप सोचिये कि कार्यपालिका का जो रोल हो रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता और जिस चर्चा की हम आलोचना करते हैं उसको व्यक्तिगत ले लिया जाता है। चाहे सरकार अपने ऊपर ले लेती है, चाहे हम लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, चाहे कोई और भी ले लेता है। उसको जज नहीं करना चाहते कि कार्यपालिका जो खेल कर रही है, उसको समझने की जरूरत है। चाहे वह पूर्ववर्ती सरकार में हो, चाहे उससे पहले सरकार हो और चाहे वर्तमान सरकार हो, जब तक एकजुट होकर के पूरी विधायिका इस रोल को आइडेंटिफाई नहीं करेगी तो निश्चित रूप से मानिये कि 5 साल बाद वही तस्वीर रहेगी। इसको सोचने की जरूरत है।

सभापति महोदय, मैं बोर्ड और कॉरपोरेशंस के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, मैंने भी एक बिल रोका था, क्या कारण है कि एक एग्जिक्यूटिव ऑफिसर को 3-3 चार्ज दे दिये जाते हैं। सीएमडी वह, एमडी वह और सेक्रेटरी वह, एक ही व्यक्ति, तो कैसे पावर्स का बैलेंस होगा? आप बताओ। इसको खुले विचार से पूरी विधायिका को डिसकस करने की जरूरत है। इस तरह के नियम लाने चाहिए कि सीएमडी, मैं तो कहता हूं कि पॉलिटिकल आदमी डेमोक्रेट्स ही है, गणतंत्र और जनतंत्र की व्यवस्था किसलिए की थी? जनतंत्र को सुरक्षित करने के लिए गणतंत्र की व्यवस्था की थी। उस गणतंत्र को हम कमजोर करते चले जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस पर सोचने की जरूरत है। विधायिका का रोल हम कमजोर करते चले जा रहे हैं। कार्यपालिका का रोल बढ़ता चला जा रहा है। इसी सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि क्या कारण है, अभी 2 विधेयक आ रहे हैं बीकानेर विकास प्राधिकरण बिल आया है। भरतपुर का भी आ रहा है। उससे पहले भी कोटा, बीकानेर, अजमेर, बहुत सारे हैं। जेडीए में जब मंत्री चेयरमैन हो सकता है तो भरतपुर विकास प्राधिकरण, बीकानेर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण या जोधपुर विकास प्राधिकरण में चेयरमैन क्यों नहीं हो सकता?

यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यदि आप सीएजी की रिपोर्ट्स को पढ़ लें, बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं, उसमें सीधा आयेगा कि इस कार्यपालिका के द्वारा किस तरह के घोटाले किये जाते हैं। वह रिपोर्ट्स 4-4, 5-5 साल तक आती नहीं हैं। आप सीएजी को पढ़िये। खुद

विभाग के मंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप उनको पढ़ लेंगे तो आपको मालूम पड़ जायेगा कि कार्यपालिका क्या करती है। लेकिन अफसोस कि इस पर काम नहीं हो पाता है। इस पर काम करने की जरूरत है।

दूसरा मुद्दा मैं उच्च शिक्षा का लेना चाहूंगा। मैं उच्च शिक्षा में रहा हूं। तकनीकी शिक्षा में भी रहा हूं। शिक्षक रहा हूं और मंत्री बनने का मौका मिला। आप देखिये कि क्या स्थिति हो रही है। यह यूनिवर्सिटीज व्हाइट ऐलिफेंट हो गई हैं।

श्री सभापतिः प्लीज, समाप्त कीजिये।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): आप देखिये, वाइस चांसलर्स को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। बाहर के व्यक्ति कुलपति आ रहे हैं। हमारे समय में भी हुआ और अभी भी हो रहा है। वह कुलपति नियुक्त कर दिये गये हैं जिनको दूसरे राज्यों में बर्खास्त किया गया, जिन पर आरोप लगे। इसको भी देखने की जरूरत है। इसमें संशोधन करना चाहिए।

कुलपति से आपने कुलगुरु किया, बहुत बढ़िया किया। लेकिन कुलगुरु की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? इसको भी डिफाइन करने की जरूरत है कि कुलगुरु जैसी क्वालिटी वाइस चांसलर्स में, कुलपतियों में होनी चाहिए। इसको देखना चाहिए।

सभापति महोदय, एक मैं जल की बात करना चाहूंगा। मेरा किसी की आलोचना का मत नहीं है। मैं केवल सिस्टम की बात कर रहा हूं। ईआरसीपी एवं यमुना जल समझौता, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से, सिंचाई मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि यह जो यमुना जल समझौता 1994 में हुआ है, भरतपुर आज भी उससे पीड़ित है। पूरा 400 एमसीएफटी पानी नहीं मिल रहा है। उसमें मैं कहना चाहूंगा कि बाण गंगा, गंभीर नदी को पांचणा बांध से जोड़ते हुए उसको भी लिया जाये।

श्री सभापतिः कृपया समाप्त करें। श्री राजेन्द्र जी।

(समयः बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): सभापति महोदय, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं अल्पसंख्यक हूं। बहुत कम समय मिलता है। 5 मिनट मिलते हैं। जब तक वह भूमिका बनती है तब तक समय हो जाता है। लेकिन मैं पुनः कहना चाहूंगा पूरे सदन को कि इसे सोचने की जरूरत है। विधायिका के रोल को, मंत्रियों के रोल को हम लोग कम करते चले जा रहे हैं और कार्यपालिका का रोल बढ़ता चला जा रहा है।

श्री अध्यक्षः श्री राजेन्द्र जी, बोलो।

श्री राजेन्द्र (महवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। 3-4 दिनों से लगातार पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपने विचार रखे जा रहे हैं। विपक्ष का धर्म है कि वह सरकार को ध्यान दिलाये और सरकार का कर्तव्य यह है कि जो वादे हमने चुनाव से पहले किये उन वादों को हम पूरी ईमानदारी के साथ धरातल पर उतारें।

spp/rtm/06.02.2025/17:30/3h

मैं आपसे कहना चाहूंगा एक साल के अन्दर आदरणीय भजनलाल जी ने जिस प्रकार का बजट राजस्थान की जनता को दिया, उसकी विपक्ष ने भी सराहना की है और पूरे प्रदेश के अन्दर निश्चित रूप से बहुत तेजी से जो काम हो रहे हैं, क्योंकि मैं भी राजनीतिक परिवार से हूं। मैंने राजनीति के अन्दर सब कुछ देखा है। चाहे वसुन्धरा जी का राज हो, चाहे आदरणीय भैरोंसिंहजी का राज हो या वर्तमान में आदरणीय भजनलाल जी का राज है। जिस प्रकार से दीन-हीन-गरीब की सेवा का मकसद लेकर जो हमारी सरकार बनी है, उसको हम पूरी ईमानदारी के साथ पूरा कर रहे हैं।

हमारे देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदीजी के कुशल नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों से लगातार प्रगति की है। आप देख सकते हैं कितनी मजबूती के साथ भारत के प्रधान मंत्री ने अन्य देशों में जाकर अपने देश का नाम रोशन करने का जो काम किया है, हमको तो पहले यह ही पता नहीं लगता था कि हमारे देश का प्रधान मंत्री विदेश में जा रहा है। अख़बार में दो-तीन लाइनों के खबर पढ़ा करते थे। लेकिन आज जब हमारे देश के प्रधान मंत्री किसी भी देश में जाते हैं तो निश्चित रूप से वहां पर रहने वाले हमारे भारतीय, उनका जिस प्रकार से मान-सम्मान करते हैं, यह हमको गौरवान्वित महसूस होता है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री आज किस दिशा में जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे प्रधान मंत्रीजी की सबसे महत्वपूर्ण योजना थी जल जीवन मिशन, उनका एक ही मकसद था कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर घर में पानी मिलने का काम हो ताकि मेरे पूर्वी राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान में पानी की विकट समस्या हमेशा से रहती आयी है, ताकि महिलाओं को पांच-पांच, छह-छह किलोमीटर सिर पर मटकी रखकर कुओं पर नहीं जाना पड़े। इसके लिये यह योजना लागू की गयी थी, लेकिन आपने देखा है कि योजना में पूर्ववर्ती सरकार ने कितना जबर्दस्त भ्रष्टाचार किया और इतना जबर्दस्त भ्रष्टाचार हुआ कि ईमानदारी से अगर पांच साल सामने वाले काम करते तो निश्चित रूप से जनता को पानी मिलता और यह जिस जगह बैठे हैं, उस जगह पर नहीं होते।

आदरणीय किरोड़ीलाल जी ने इस मामले को राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार को कठघरे में खड़ा किया था और पूरे राजस्थान में करीब 20 हजार करोड़ रुपये का घोटाला इसमें हुआ था। अकेले मेरे महवा विधान सभा क्षेत्र में, यहां विपक्ष के नेता बैठे हैं, करीब 40 करोड़ रुपये का मेरे यहां घोटाला हुआ था। आज जनता जिस प्रकार से पानी के लिये तरस रही है, मात्र इनकी रीतियों और नीतियों के कारण, अन्यथा आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, आज हर व्यक्ति के घर पर नल से पानी मिलने का काम हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जे.जे.एम. का घोटाला जबर्दस्त हुआ। सबको पता है, सरकार की क्या स्थिति रही? आज आदरणीय भजनलाल जी ने जिस

प्रकार का बजट हमको दिया है, निश्चित रूप से आप कहीं भी जाकर देख सकते हैं और मैं सामने बैठे हुए विपक्ष के भाइयों से कहना चाहूंगा कि आपने साल भर में हमारी सरकार के खिलाफ कितने जन-आंदोलन खड़े किये हैं? आप जन-आंदोलन इसलिए खड़े नहीं कर पा रहे क्योंकि सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। बाकी तो आप देख सकते हो, जब आपका पांच साल जो कार्यकाल था, सड़कों पर किस प्रकार से आम जनता दीन-हीन-गरीब दिन भर सरकार के खिलाफ जन-आंदोलन करने का काम करती थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्य मंत्रीजी को, कि उन्होंने इस एक साल के पीरियड में जनहित के इतने मामले हमारी आम जनता को देने का काम किया है और हम तो पूरी ईमानदारी के साथ, हमारे सत्ता पक्ष के सारे विधायक अपने अपने क्षेत्रों में दीन-हीन-गरीब, जो अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके लिये सरकार ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने में लग रहे हैं। मैं तो विपक्ष के सारे भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि हमसे आपको सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला समय आप सबको पता है। दिल्ली की भी स्थिति आपने देख ली है। कल टी.वी. पर आपने एग्जिट पोल देखे हैं और अब परिणाम भी आने वाला है। पूरे देश के अन्दर भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से शासन सभी जगह बनने जा रहा है और आने वाले समय में एग्जिट पोल में तो मुझे लगता है दिल्ली में कांग्रेस की एक भी सीट आने की उम्मीद नहीं है। इसलिए सारे जितने भी एग्जिट पोल के जितने भी एडिटर वगैरह हैं, उन्होंने जीरो गोले लगाए हैं। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप विपक्ष का धर्म ईमानदारी से निभाएं और भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता, एक-एक विधायक से यह सीख लें कि जिस प्रकार से जनता ने हमको चुनकर इस राजस्थान की विधान सभा में भेजा है, ऐसा काम आप भी करें ताकि आप अच्छे तरीके से विपक्ष की भूमिका निभा सकें। नहीं तो आपको हमेशा हमारे सामने ही बैठना पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री रतन देवासी।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने जो अभिभाषण दिया है, हम सब जानते हैं, जो इस सदन में बैठे हैं, जो चुनकर आते हैं और जो राजनीति में रूचि रखते हैं कि माननीय राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण होता है, सरकार का गठन होने के, कार्यकाल में आने के प्रथम अभिभाषण और उस कार्यकाल का एक वर्ष बीतने के बाद में जो दूसरा अभिभाषण होता है, उन दोनों अभिभाषणों में प्रदेश की जो जनता है, जो माननीय सदस्य हैं, राजनीतिक दल के जो लोग हैं, वह सब यह आशा करते हैं कि प्रथम अभिभाषण में जो दर्शाया गया है, जो बताया गया है, जो पढ़ा गया है, उसके बाद में जब दूसरा अभिभाषण आता है तो उस अभिभाषण में हमने क्या किया है। एक रोडमैप की तरह सरकार में और जो 14 महीने बीते हैं, उसमें हमारा क्या योगदान रहा है, क्या कीर्तिमान स्थापित किया है, उसके बारे में उल्लेख होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति, हर माननीय सदस्य अपनी बात

कहता है। हमने अक्सर यह देखा है कि हम हां और ना में ही बंट जाते हैं। हां पक्ष और ना पक्ष में बंट जाते हैं और उसमें मान लिया गया है कि हां पक्ष को हां ही कहना है और ना पक्ष को ना ही कहना है। मगर मेरा यह मानना है कि जो हम लोग चुनकर आते हैं, हमारी बात वर्षों तक लोग याद रखते हैं और आज तो सोशल मीडिया का टैक्निकल रूप में बहुत बड़ा जमाना आ गया है। उन बातों को लोग भविष्य में याद करते हैं और अच्छी बात का स्मरण कराते हैं। मेरा मानना है कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ। इस अभिभाषण के बाद में बजट आएगा। इसमें जो कमियां हैं, जो यह अभिभाषण पढ़ा गया है, इसको सिर्फ आलोचना के रूप में न देखें बल्कि में कोई सुझाव हों, कोई सुधार हो, कोई गलतियां रह गयी हैं, जिन अधिकारियों ने या व्यक्तियों ने इस अभिभाषण को मिलकर तैयार किया है, उन्होंने पिछले राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़कर उसी पैरा को रिपीट किया है या नहीं किया? उसमें कमियां छोड़ी हैं या आपने पीछे कुछ कहा है 2024 में और 2025 में कुछ कहा है। इसका अध्ययन और विश्लेषण आप जरूर करना, इससे आपकी सरकार की साख रहेगी।

मेरा यह मानना है कि इसके बाद बजट आएगा तो जो अभिभाषण में हम बिन्दु पढ़ रहे हैं, उसका ताल्लुक बजट से नहीं होता है। आप न केवल इस अभिभाषण को बल्कि जो बजट आने वाला है, उसके सुझाव के रूप में भी आप लेंगे। इसलिए मैं सिर्फ उस बिन्दु को ही बताना चाहता हूं। बाकी सारे लोगों ने अपनी अपनी बात कही है। आप लोगों ने पिछले अभिभाषण में यह कहा था कि चुनाव में आपने जो वादे किये, चुनावी सभाओं में जो वादे किये थे, जो विभिन्न यात्राओं में आपने वादे किये थे, वह संकल्प-पत्र के रुप में भरा गया है। जो संकल्प पत्र बनाया है, वह संकल्प पत्र ही, उस अभिभाषण में भी आपने कहा कि राजस्थान में अराजकता में है, अंधकार में है और उसमें इसको लाया गया है, उसको प्रकाश की ओर, और जो परिकल्पना जो प्रदेश की जनता करती है, उसकी ओर आप ले जाओगे। मगर आपने इसको रिपीट नहीं किया।

आपने उस अभिभाषण में स्व.भैरोंसिंहजी को याद किया और अंत्योदय स्कीम के बारे में आपने बताया। स्व.भैरोंसिंहजी हम सबके नेता थे। इस सदन के सदस्य के रुप में सब उनका सम्मान करते हैं। मगर उसको आपने आगे बढ़ाया? इस अभिभाषण में वापस उल्लेख करते हुए उस पैरा में जन्म शताब्दी मनाने की बात हमने की थी उस समय और आपने आज उसको आगे नहीं बढ़ाया। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने जिस संकल्प पत्र को आधार बनाया है, कोई भी पार्टी मेनिफेस्टो को आधार बनाती है और यह कहती है कि यह हमारा घोषणा पत्र है, हमारा मेनिफेस्टो है, हम चुनाव में इसको लेकर जाएंगे और सारे वादे पूरे करेंगे। आपने एक कदम आगे बढ़कर संकल्प-पत्र को उसका आधार बनाया था। मगर संकल्प-पत्र को आधार बनाने के बाद में उसमें कितने पैरा पूरे हुए, क्या हुआ, आप उसका विश्लेषण जरूर कर लेना।

मैं आपको सीधे तौर पर तीन-चार सुझाव दूंगा। उसको आप आलोचना के रूप में नहीं

लेते हुए इसको सुझाव के रूप में लें ताकि बजट में भी वह चीजें आ सकें और अगर कोई इस अभिभाषण में कमियां रही हैं, जो राज्यपाल महोदय से सरकार ने पढ़ाया है, उन कमियों को भी आप दूर कर सको।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने एक बात कही थी। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में एक बात कही थी कि इस पवित्र मन्दिर में बैठे प्रत्येक माननीय सदस्य के मन, मस्तिष्क में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की सेवा करने का लक्ष्य होना चाहिए और उसकी भावना होगी।

jyg/rtm/06.02.25/17.40/3j

अब जो आपने अभिभाषण किया है, इसमें यह करेंगे, कर रहे हैं, अभी भी सुधार कर रहे हैं, पर अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है उसका पूर्ण रूप से कल्याण कैसे होगा, उसका उल्लेख बहुत स्पष्ट तौर पर किसी ने नहीं कहा। मैं आपको वीकर सेक्शन के लोग जो वंचित हैं, जिनको सुविधाएं अभी तक नहीं मिली है, अभाव है जिनको सुविधाओं का, मैं उनके बारे में दो-चार चीजें बताना चाहता हूं क्योंकि अभिभाषण बहुत लम्बा है और समय का अभाव है।

जल जीवन मिशन की आपने बात की, आपने पिछले अभिभाषण 2024 में कह दिया कि भ्रष्टाचार हुआ है, काम नहीं हुआ है, इसका सुधार करेंगे, मान लेते हैं आपकी बात को, अभी आपने क्या कहा, इस अभिभाषण में आपने वापस कहा कि भ्रष्टाचार हुआ, काम नहीं हुआ, हम उसको सुधार करेंगे, 14 महीने में आप सुधार नहीं कर पाये। क्या स्थिति है, पानी की स्थिति आगे गर्मी का मौसम आयेगा, सबको भुगतनी है, आपको, मेरे को, जितने माननीय सदस्य यहां हैं, जिनके ड्राई एरिया है, वाटर सप्लाई के अभाव में जिन लोगों को तकलीफ आती है उन सबको भुगतना है। मेरे क्षेत्र में जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, आपने कहा था उसको ठीक करेंगे। राजस्थान में 14 महीने बीते हैं, एक जगह डीपीआर के अगेंस्ट काम हुआ, पाइप के साइज में फर्क हो गया, ढाणियों में पाइप डाल दिये, एक पाइप में एक बूंद पानी नहीं आ रहा है, 200 करोड़ रुपये खर्च हो गये, 35 करोड़ रुपये सरकार से और मांगे जिस पर हमने आपत्ति दर्ज की है। माननीय मंत्रीजी या तो उस पर कमेटी बना दे, खुद आये या खुद आये नहीं तो आगे लोगों को तकलीफ आयेगी। हम कह रहे हैं कि आप कार्यवाही करो, किसी की भी सरकार में वो योजना स्वीकृत हुई हो, किसी की सरकार में गलती रही हो, मगर 14 महीने आपको मिल गये, आपने वादा किया था अभिभाषण में, कम से कम आपको उनको सज़ा देनी चाहिये थी, पर एक जगह भी पानी नहीं आया है, फेस आपको और आपके प्रशासन को करना पड़ेगा। हमने हमारी बात यहां पर भी कही है और वहां पर भी कह देंगे।

माननीय सभापति महोदय, गोपालन मंत्रीजी बैठे हुए हैं, आप भी उस क्षेत्र से आते हैं, गोसेवा, गायों को सब्सिडी दे रहे हैं हम लोग, गोशालाओं के बारे में मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था, बजट अभी आया है, बजट में निवेदन किया था, नया बजट आ रहा है और आपके

माननीय हां पक्ष के सदस्य बैठे हैं, कई सदस्यों ने मेरी बात को दोहराया था और मैं वापस आपको निवेदन कर रहा हूं कि गाय बचानी है, गायों का काम करना है और वास्तव में गोसेवा का, गोमाता जिंदाबाद का नारा अगर मन से हमको देना है, मुख से नहीं देना है तो आप मेहरबानी करके जो पशुपालक गायें लेकर इधर-उधर जाता है, झुण्ड में सैकड़ों गायें रखता है, हजारों गायें रखता है, जो सच्चे रूप में सेवा कर रहा है, आप उसको सच्चे रूप में सब्सिडी देना शुरू कर दो। अगर आप देंगे तो आपको बहुत अच्छा पुण्य भी मिलेगा और वो गायें भी बच जायेगी, यह मैं आपको निवेदन कर रहा हूं क्योंकि उसके बारे में किसी ने नहीं कहा। राज्यपालजी ने कहा है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के बारे में सुनो और सोचो, वो अंतिम छोर का व्यक्ति है, गोशालाओं में सब्सिडी दे रहे हो, कई जगह बहुत अच्छा काम हो रहा है और कई जगह कैसा काम हो रहा है, आप खुद जाकर देख लो। मगर उस पशु पालक को अगर सब्सिडी मिलेगी तो उसकी गायें बच जायेंगी।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बातें मेरी थीं। पट्टे की जो बात आयी है, घुमंतू, अर्द्ध घुमंतू, पशु पालक, डीएनटी के लोग उनको आपने देने की बात की है। दिये भी हैं कई लोगों को मगर वो आपका सपना साकार नहीं हो सकता है, हमारा भी नहीं हो सकता है। क्योंकि पूर्व में वो गांव के बाहर होते थे, बाड़े गांव के बाहर होते थे, वो गोचर में जाकर बस गये, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में निर्देश है कि आप गोचर को एक-दो कामों के अलावा कंवर्ट नहीं कर सकते मगर आप कैबिनेट में ऐसा बिल लाओ और विशेष अनुमति लो ताकि दूसरी जमीनें आपकी आरक्षित हो जाये और उन जमीनों पर बाड़े लेकर जो छोटे-छोटे लोग बैठे हैं, उनका नियमन करके पट्टे मिल जायें।

सारे माननीय सदस्य, मैं आपको अंत में बता रहा हूं कि दो बातें और है। एक तो जो मिसिंग लिंक की सड़कें हैं उनको लेकर और दूसरी सड़कें बन भी जायेंगी और रिन्युअल भी हो जायेगी, मगर हमारे समय में 10 करोड़ की मिसिंग लिंक की सड़कें दी थीं, आप हिम्मत करके 15 करोड़ की करो, हर एमएलए की बात पूरी हो जायेगी, एक-दो-चार किलोमीटर की जो सड़कें बची हुई हैं, जो डिमांड आती है गांवों को कनेक्ट करने की, वो सड़कें पूरी हो जायेगी। आपने उनका उल्लेख इस अभिभाषण में नहीं किया है।

अंत में राज्यपालजी ने अपना समापन करते हुए भाषण में सरदार वल्लभ भाई पटेलजी को याद किया और अम्बेडकरजी को याद किया। मेरा इतना ही निवेदन माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि एमएलए लैड की जो गाइडलाइंस बनी हुई हैं वो बहुत पुरानी है, उसमें चेंजेज आने चाहिए और अम्बेडकरजी को आपने याद किया है तो आपको अम्बेडकरजी को, सरदार पटेल को और स्कूलों में मां सरस्वती की मूर्तियां जो लोग लगाना चाहते हैं उनको पूर्ण रूप से हण्डरेड परसेंट एमएलए कोटे से आप लोग स्वीकृति प्रदान कराओ ताकि हिम्मत करके हम लोग उनको दे भी सकें और यह काम भी पूरा हो सके। यही मैं निवेदन आपको करता हूं, आप सबका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री आदू राम मेघवाल।

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चार पंक्तियों के साथ में अपनी बात रखूंगा।

मोदीजी की गारंटी के सुख परिणाम आ गये,
कांग्रेस के कुशासन पर विराम आ गये,
भय और भ्रष्टाचार से प्रदेश अब हो जायेगा मुक्त,
क्योंकि अब भारत राष्ट्र विश्व पटल पर रहेगा,
शांति, सुरक्षा और मार्गदर्शक का अग्रज।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 16वीं राजस्थान विधान सभा के तृतीय सत्र में लोकतंत्र के पवित्र मन्दिर इस सदन में महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सर्वप्रथम मैं सदन के माननीय अध्यक्ष एवं सभी ज्येष्ठ व श्रेष्ठ सदस्यगण का आशीर्वाद लेना चाहूंगा और साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय का सहृदय आभार प्रक्ट करना चाहूंगा कि आपने मुझे सदन में बोलने का सुअवसर प्रदान किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं सदस्य चुनकर आया हूं, पश्चिमी राजस्थान की थार नगरी, कला, साहित्य और संस्कृति का अनोखा त्रिवेणी संगम, भक्ति और शक्ति के वीर भोग्या वसुन्धरा, चौहटन विधान सभा क्षेत्र से वहां की देव तुल्य जनता के प्रतिनिधि के रूप में अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मैं उसी पश्चिमी राजस्थान के भारत-पाक सीमा के सरहदी गांव ताम्र और थार नगरी बाड़मेर से आता हूं जिनका महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अपने अमृतमय अभिभाषण में जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। जहां आज भी हमारी ऐतिहासिक, पौराणिक संस्कृति जीवित है। जी हां, इसीलिए वीर वसुन्धरा के लिए कहा जाता है कि

सोने री धरती अठै, चाँदी रो अनोखो आसमान,
रंग-रंगीलो रस भरियो,
सतरंगी संस्कृति है इस धरती की पहचान।
आपणो राजस्थान, आपणो राजस्थान।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा विकसित भारत, विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने वाली विकासपूर्ण नीतियों को 16वीं राजस्थान विधान सभा के तृतीय सदन में प्रस्तुत किया गया, जो कि प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। इसकी मैं सम्पूर्ण प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी रानीवाड़ा से हमारे सदस्य महोदय कह रहे थे कि ऐसे राजस्थान के पहले मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने घुमंतू, अर्द्ध घुमंतू और विमुक्त जातियां हैं, जो डगर-डगर, गांव-गांव घूमने वाली जातियां हैं, उनको भी यदि बसाने का काम किया है तो हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने किया है। आदरणीय, माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय संविधान के महान शिल्पकार, भारत रत्न, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकरजी को भी याद करता हूं। मैं पूर्व प्रधान मंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयीजी को भी स्मरण करता हूं जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापित किया है। प्रधान मंत्री सड़क योजना हो जिसमें लाखों गांवों को विकास की मुख्य धारा में शामिल किया गया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जिसमें राष्ट्र के चारों कोनों को सड़कों से जोड़ने का कार्य किया है। मैं मां भारती के अनन्य साधक आदरणीय नरेन्द्र मोदीजी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन और प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा जी की दूरदृष्टि, सोच और कुशल कार्य शैली से सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास अवधारणा से हमारी सरकार के एक वर्ष का स्वर्णिम कार्यकाल निश्चित रूप से प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कारगर साबित हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी भाजपा सरकार के एक वर्ष के स्वर्णिम कार्यकाल में सीमावर्ती चौहटन विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री ने 2024-25 का जो अपना पहला बजट पेश किया, उस बजट के अन्दर जो उन्होंने घोषणाएं कीं, वो पहले मुख्य मंत्री हैं राजस्थान के जिन्होंने धरातल पर उन घोषणाओं को उतारा है।

MLS/RTM/06.02.2025/17:50/3k

हमने यह देखा है, मेरे चौहटन विधान सभा क्षेत्र में जिला मुख्यालय के ऊपर जिला अस्पताल है, उसी के मार्फत् चौहटन विधान सभा क्षेत्र में जिला अस्पताल की जो घोषणा की गयी, आज वह धरातल पर हमारे चौहटन से बाइपास जाने वाले रास्ते पर, हमारे भामाशाहों के सहयोग से अस्पताल के लिए जमीन देकर आज धरातल पर काम शुरू हो रहा है।

एशिया के सबसे क्वॉलिटी वाले जीरे का यदि कहीं उत्पादन होता है तो वह सेड़वा की धरती पर होता है। वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में है। जहां राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने कृषि मण्डी के रूप में घोषणा की थी, आज मैं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने 2024 के बजट में जो घोषणाएं की थीं, उन्हें धरातल पर उतारने के लिए राजस्थान की कैबिनेट के सभी मंत्री, जिनके पास जिलों का प्रभार है, उन्हें अपने-अपने जिलों में भेजकर उसी समय हमारे अधिकारियों के साथ बैठकर उन योजनाओं को, चाहे जमीन के अलॉटमेंट का काम हो, चाहे वित्तीय स्वीकृति हो, इन सब मामलों को लेकर आज जो उन्होंने घोषणाएं धरातल पर उतारी हैं, मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री जी को और उनकी पूरी कैबिनेट को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।

अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित चौहटन विधान सभा क्षेत्र के लोगों ने सदियों से पानी की कमी और पेयजल को लेकर संघर्ष देखा है। पूर्ववर्ती सरकार को जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने का अवसर मिला था, परन्तु उसका दुर्भाग्य यह रहा कि कार्य प्रारम्भ करने में ही घोटालों से सम्पूर्ण देश में बदनामी हुई है। मैं राजस्थान पत्रिका का, अखबारों में जो उन्होंने दिया है, जहां राजस्थान के यशस्वी राज्यपाल जी ने अपने

अभिभाषण में जहां तामलोर की चर्चा की थी, उनका जीवित उदाहरण था, जहां लोग वर्षों से पानी के लिए तरस रहे थे, जल जीवन मिशन के माध्यम से आज हमारी सीमा का पहला गांव है, हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी कहते हैं, उस सीमा के पहले गांव में आज नर्मदा का मीठा पानी पहुंचा है। मैं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री जी को उसके लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने उनकी आंखों में पानी देखा है। पानी के एक लोटे के लिए तरसते थे, जहां घी सस्ता था, हर घर में मिल जाता था, एक पानी का लोटा उस जगह कहीं मिलना बहुत ही मुसीबत का काम था। उस जगह भी जल जीवन मिशन के माध्यम से, हर घर नल के माध्यम से आज नर्मदा का मीठा पानी पहुंचा है।

मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत 1538 करोड़ रुपये की योजना लागू की है। आने वाले समय में हमारे चौहटन विधान सभा क्षेत्र के 438 गांवों में नर्मदा का मीठा पानी पहुंचेगा। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: श्री रामावतार। वाइंड अप करिये, आपका समय हो गया।

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने किसान भाइयों के साथ जिस तरह से छलावा किया था, आज जो 2024 सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा 31 किसानों के बीमा...

श्री अध्यक्ष: बैठिये, हो गया। माननीय, हो गया आपका समय। श्री रामावतार। शुरू करिये।

श्री रामावतार बैरवा (चाकसू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर लोकतंत्र के इस पवित्र मन्दिर में इस सदन ने मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं।

सबका साथ, सबका विकास,

तभी तो है जन-जन को डबल इंजन की सरकार पर विश्वास।।

राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण में राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु किये जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए सशक्त एवं सम्पन्न राजस्थान की संकल्पना के बारे में बताया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में एक वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश ने नये-नये आयाम स्थापित किये। राज्य सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन कर निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लाने व राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक ले जाने के लिए जो प्रयास किये जा रहे हैं, उनसे राज्य को तो नवीन दिशा व दशा मिलेगी ही, साथ ही साथ, हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नवीन अवसर भी प्राप्त होंगे।

राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 जैसी अनेक योजनाएं लाकर निवेशकों को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे राज्य में नित नये निवेश आ रहे हैं एवं राज्य

की अर्थव्यवस्था को नवीन आयाम प्राप्त हो रहे हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घण्टे बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही पूरे होने तक ही बढ़ा दें न। फिर बढ़ाना पड़ेगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक के लिए बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ाया गया।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री रामावतार बैरवा (चाकसू): माननीय अध्यक्ष महोदय,

मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है,
पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी डबल इंजन की सरकार सपने दिखाने में नहीं, उन्हें हकीकत में बदलने में विश्वास करती है। इसी दिशा में राज्य को राम जल सेतु लिंक परियोजना यानी पार्वती कालीसिन्ध चम्बल (पीकेसी) लिंक के माध्यम से सिंचाई एवं पेयजल हेतु हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में इस कार्य को मूर्त रूप देने हेतु 12 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसे पिछली सरकार ने राजनीतिक लाभ के कारण अटकाये रखा।

महोदय, राजस्थान में सदियों से जल संचय एवं संरक्षण की परम्परा रही है। उसी दिशा में माननीय प्रधान मंत्री जी के कथन ''कैच द रेन'' को साकार करते हुए राज्य सरकार ''कर्मभूमि से मातृभूमि'' अभियान चलाकर वर्षा जल संचय का काम कर रही है, जिससे किसानों एवं उद्योगों को जलापूर्ति की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, राज्य सरकार युवाओं के सुनहरे भविष्य को पंख देते हुए खेल सुविधाओं को विकसित करने पर कार्य कर रही है एवं प्रदेश में नवीन खेल स्टेडियम सृजित किये जा रहे हैं, जिनमें से मेरे विधान सभा क्षेत्र चाकसू व राज्य के अन्य क्षेत्रों में स्टेडियम बनाये जाने हैं, जिससे देश-प्रदेश के युवा खेलों में नित नयी उपलब्धियां हासिल करते हुए अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल ही में केन्द्रीय वित्त मंत्री जी द्वारा घोषित बजट में केसीसी लिमिट 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गयी है। प्रधान मंत्री किसान सम्मान

निधि की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा मुख्य मंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू कर प्रदेश के किसानों को 2 हजार रुपये अतिरिक्त दिये जाने का प्रावधान किया है। राज्य सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसानों को कड़ाके की ठण्ड से बचाते हुए उन्हें सिंचाई हेतु दिन में बिजली देने और कृषि उत्पादों की बिक्री हेतु नवीन कृषि मण्डियों का सृजन किया गया है। इसी क्रम में पिछले बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र चाकसू के कोटखावदा में भी एक कृषि मण्डी की घोषणा की गयी है और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में कृषि मण्डी प्रांगण बनाया जाना है। इसी के साथ, किसानों को ऑनलाइन प्लैटफॉर्म के माध्यम से जन कल्याणकारी योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे फार्म पॉन्ड, डिग्गी, तारबन्दी, जैविक खेती जैसी अनेकों योजनाओं का लाभ हमारे किसान साथी घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त कर रहे हैं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, ग्रामीण सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में 1 हजार करोड़ रुपये की लागत से मिसिंग लिंक एवं नॉन-पैचेबल सड़कों के 1631 कार्य प्रारम्भ किये गये एवं 530 किलोमीटर लम्बाई से 309 कार्य पूर्ण हुए। 10 हजार से अधिक आबादी वाले गांव अटल प्रगति पर बनाये जा रहे हैं। प्रथम चरण में 206 करोड़ रुपये की लागत से 52 गांवों में अटल प्रगति पथ का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। अतिवृष्टि क्षतिग्रस्त सड़कों पर भी मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु 964 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गयी है एवं मरम्मत कार्य प्रारम्भ किये गये हैं।

mkd/rtm/06.02.2025/18:00/3l

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम के विजन प्लान को समर्पित करते हुए चार पंक्तियां कहना चाहूंगा, अग्निपथ पर चलते जाना है, विकास में जन-जन को भागीदार बनाना है और सन्देश यही है, संकल्प यही है, हर व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया, जय हिन्द, जय भारत, जय शीतला माता, (..व्यवधान..) राम-राम सा।

श्री अध्यक्ष: श्री भीमराज भाटी।

श्री भीम राज भाटी (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने के लिए मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मेरे पार्टी के नेताओं का भी आभारी हूं। महामहिम राज्यपाल जी द्वारा पेज संख्या 25 पर पेश..।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): ईमानदारी से सही-सही बोलना।

श्री भीम राज भाटी (पाली): मैं तो ईमानदारी से ही बोलता हूं और यहां लिखा हुआ है कि इस सदन में जो भी आयेगा, वह सच बोलेगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहेगा तो यह मेरे लिए ही लागू नहीं होता है, आप सब के लिए भी लागू होता है। मैं इसी बात को ही कहने जा रहा हूं।

माननीय मुख्य मंत्री जी को यशस्वी, आप सब लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन आप वही बात कह रहे हैं, जो मुख्य मंत्री जी सुनना चाहते हैं, you are telling only those things which he wants to listen. जो वो सुनना चाहते हैं, वही बात आप करते हैं। वो तारीफ करने से कोई फायदा नहीं है, अभी एक साल हुआ है, पांच साल खत्म हो जाने दीजिये, फिर आपकी परफोर्मेंस का पता चलेगा, फिर आपके मुख्य मंत्री जी की परफोर्मेंस का पता चलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो कहना चाहता हूं, महामहिम राज्यपाल जी से पेज संख्या 25 पर पैरा नम्बर 81 में भरतपुर एवं बीकानेर विकास प्राधिकरण की घोषणा करवाई गई है, जबकि भरतपुर विकास प्राधिकरण का बिल उस दिन अभिभाषण के बाद पेश किया गया, पहले नहीं पेश किया गया तो यह बात ऐसे, सफेद टोपी ओढ़े हुए हमारे राज्यपाल जी हैं, यह सफेद टोपी त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रतीक है। ऐसे सफेद टोपी ओढ़े हुए त्यागी, तपस्वी और बलिदानी राज्यपाल जी से इस तरह की कई थोथी और गलत घोषणाएं करवाई गई हैं, उसके बारे में..।

श्री अध्यक्षः आप भी सफेद ड्रेस पहनकर आते हैं, टोपी तो नहीं लेकिन ड्रेस तो सफेद ही है।

श्री भीम राज भाटी (पाली): मेरे पिताजी सफेद टोपी पहनते थे, इसलिए मुझे सफेद टोपी से बहुत मुहब्बत है। मुझे खुशी है कि राजस्थान के राज्यपाल महोदय सफेद ने टोपी ओढ़कर इस सदन में भाषण दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में खनन नीति के अभाव में खनन विभाग की ओर से 2 करोड़ 36 लाख रुपये की जिनके ऊपर रिकवरी निकली हुई है, वह रिकवरी अभी तक किसी ने वसूल करने की कोशिश नहीं की है। पिछली सरकार में भी किसी ने नहीं की और इस सरकार में भी किसी ने नहीं की और जिनके खिलाफ 2 करोड़ 36 लाख की रिकवरी है, उनकी एक प्रोपर्टी माइंस डिपार्टमेंट द्वारा नीलाम की गई, उस प्रोपर्टी को किसी अनुसूचित जाति के आदमी ने खरीदा। उस जमीन की रजिस्ट्री हो गई। उसने पूरे पैसे जमा करा दिये, रजिस्ट्री उसके नाम हो गई, लेकिन उसको उस जमीन का कब्जा अभी तक यह सरकार नहीं दिला पाई है। जिसके ऊपर 2 करोड़ 36 लाख की रिकवरी है। वह आदमी पुलिस से मिलकर, पुलिस की पंचायती वह आदमी कर रहा है, पुलिस थाना में वह बैठा रहता है और आज भी अनुसूचित जाति के आदमी को वह जमीन अभी तक कब्जे नहीं दी गई है।

माननीय, यदि ऐसा ही व्यवहार रहा तो, यही हाल रहा तो, ऐसे अवैध खनन करने वाले, माननीय अध्यक्ष जी, मुझे दुःख है कि हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री, गृह मंत्री भी हैं। गृह मंत्रालय से माननीय मंत्री महोदय ऐसे ऑर्डर निकलते हैं, जो पुलिस अधिकारी शराब पीकर थाने में डांस करते हुए, जिसका वीडियो वायरल हुआ है, उस आदमी का सिंगल जीओ ऑर्डर इश्यू होता है, यहां गृह मंत्रालय से, गृह मंत्री माननीय मुख्य मंत्री, यशस्वी मुख्य मंत्री हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है और उनके मंत्रालय से ऐसे पुलिस अधिकारी का थाने में अपॉइंटमेंट

होता है, जिस आदमी का थाने में शराब पीकर डांस करता हुए वीडियो वायरल होता है। उस आदमी का सिंगल जीओ ऑर्डर इश्यू होता है। वह तो मैं धन्यवाद देता हूं, उस पाली के एसपी को, जिसने उस जीओ ऑर्डर को नहीं माना और उसको कहीं दूसरी जगह लगाया तो यह हालत है आपके गृह मंत्रालय की। गृह मंत्री, मुख्य मंत्री हैं। मैं नहीं कहता मुख्य मंत्री जी का इसमें कोई लेना देना है, लेकिन इस तरह के ऑर्डर से सरकार की छवि धूमिल होती है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा मैं आपसे क्या बात कहूं, असामाजिक व्यक्तियों की सैटिंग से जयपुर से इस तरह के जीओ ऑर्डर निकलते हैं, उन जीओ ऑर्डर की कम्प्लाइंस जो आदमी नहीं करता है, उसको तकलीफ देखनी पड़ती है, जो पुलिस अधिकारी नहीं करता है, उसको तकलीफ देखनी पड़ती है।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल जी ने जल जीवन मिशन के बारे में बात की। जल जीवन मिशन बहुत ही शानदार योजना है, उससे घर-घर में नल से लोगों को पानी पीने को मिलेगा, लेकिन मेरे इलाके में आज भी दस-दस दिन तक पानी नहीं आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दस-दस दिन तक पीने का पानी नहीं आता है और इस सर्दी के मौसम में भी एक हजार से कम में कोई टैंकर उस गांव में खाली नहीं होता है। यह हालत इस सर्दी के मौसम में है तो पता नहीं जब गर्मी आयेगी तब क्या हालत होगी।

मैं धन्यवाद देता हूं, मैंने उस दिन भी यहां विधान सभा में मुख्य मंत्री जी को सैल्यूट किया था और माननीय वित्त मंत्री जी को कि उन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए 3 हजार करोड़ रुपये दिये। 2280 करोड़ रुपये उन्होंने दिये थे, जवाई बांध से 194 किलोमीटर जोधपुर की नहर को पक्की करने के लिए, उस काम के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, हमारे माननीय मंत्री महोदय जोराराम जी साहब को, जिनकी मेहरबानी से वह प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ, लेकिन आज दिन तक माननीय मंत्री महोदय उस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई काम नहीं हुआ।

माननीय मंत्री जी, मैं धन्यवाद देता हूं, आपने सोमनाथ मन्दिर के लिए पैसे मंजूर किये, इस सरकार ने पैसे मंजूर किये, लेकिन उस सोमनाथ मन्दिर की जीर्णाद्धार के लिए आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, कुछ भी नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह हाल है, खींवसर के तो वे राजा हैं, गजेन्द्र सिंह जी साहब। मेरे पाली के हास्पिटल की हालत यह है कि कोई भी मरीज जाता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी मरीज जाता है, उसको सीधे जोधपुर रैफर कर दिया जाता है। पाली में कोई योग्य डॉक्टर रहने नहीं दिया जाता है। ब्लड बैंक की हालत यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी को कहना चाहता हूं, ब्लड बैंक की हालत यह है कि ब्लड बैंक में तो यहां फर्जी पर्ची की बात करते हैं, लेकिन मेरे पाली के ब्लड बैंक में भी पर्ची के बिना किसी गरीब को ब्लड नहीं मिलता है और ब्लड मिलता है तो 500-1000 रुपये उसको देने पड़ते हैं। ब्लड बैंक में यह हालत है। जिला मुख्यालय है, सम्भाग मुख्यालय था, सम्भाग तो आपने वापस ले लिया, लेकिन जिला मुख्यालय तो अभी भी है। जिला मुख्यालय के सबसे बड़े हॉस्पिटल में बिना पर्ची के खून

नहीं मिलता है तो यह क्या सरकार की हालत है। मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में जाने को मजबूर कर दिया जाता है। चिकित्सा मंत्री स्वयं राजा हैं, खींवसर के, उनको इस तरह की कार्यवाही पर रोक लगानी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण में पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा Common Effluent Treatment Plant (CETP), इसमें 6 करोड़ 36 लाख रुपये का घोटाला हुआ। दिल्ली से आईएएस ऑफिसर्स आये, दिल्ली से टीम आई, उस दिल्ली की टीम ने 6 करोड़ 36 लाख रुपये के गबन की तीन सौ पेज की रिपोर्ट भेजी। राजस्थान के वित्त मंत्रालय के ओडी डिपार्टमेंट से 2016 से लगातार जिला कलेक्टर को चिट्ठी लिखी जा रही है कि ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ पुलिस में कार्यवाही करो, ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ पुलिस में एफआइआर दर्ज करो, लेकिन आज दिन तक कोई भी एफआइआर दर्ज नहीं की गई। आज दिन तक वह 6 करोड़ 36 लाख का घोटाला एज इट इज दबा हुआ पडा है और उसे दबाया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, इस सदन में 35 लाख करोड़ रुपये का जिक्र किया जा रहा है, राइजिंग राजस्थान में, मुझे खुशी होगी अगर एक भी आदमी 35 लाख करोड़ रुपये में कितने जीरो होते हैं, कितने जीरो 35 लाख करोड़ में, अगर एक भी आदमी यह बता दें कि 35 लाख करोड़ रुपये में इतने जीरो लिखे जाते हैं, 35 लाख करोड़ रुपये, 35 लाख करोड़, 35 लाख करोड़ की चर्चा हो रही है। मुझे खुशी होगी, जिस दिन 35 लाख करोड़ रुपये राजस्थान में इन बाहरी उद्यमियों द्वारा, बाहरी जो उद्योगपति हैं, उन लोगों द्वारा इन्वेस्टमेंट कर दिया जायेगा। मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मैं खुद इंजीनियर हूं, 35 लाख करोड़ इंवेस्टमेंट हो जायेगा, उस दिन मुझे खुशी होगी। उस दिन मैं मुख्य मंत्री को यशस्वी मुख्य मंत्री कहूंगा, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामबिलास।

Bhs/Rtm/06.02.25/18.10/3m

श्री रामबिलास (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की विकसित भारत की संकल्पना अनुसार राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं, आदरणीय श्री भजन लाल शर्मा जी की दूरदर्शी सोच, राइजिंग राजस्थान, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आदि कदम एवं भजन लाल सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल की तस्वीर बदलने वाले प्रथम बजट के महत्वपूर्ण जन आकांक्षाओं के कार्यों एवं ऐतिहासिक निर्णयों का आइना सदन में प्रस्तुत किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पहली बार यह देखा है कि इस सदन में विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। पहले सदन चलने से पहले अखबारों में बड़े-बड़े हमारे विपक्ष के साथियों

की खबर पढ़ते थे छठी का दूध याद दिला देंगे। अब मैं सोचता हूं कि छठी का तो दूर की बात है पहला ही नहीं दिखा रहे। कोई मुद्दा है ही नहीं और मुद्दा है तो सिर्फ असत्य का मुद्दा है। असत्य का मुद्दा है इनके पास में। ये कह रहे हैं कि राजस्थान में किसानों को बिजली नहीं मिलती, मैं चैलेंज करता हूं सदन के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में आप आपका प्रतिनिधिमंडल भेज दो अगर एक भी किसान आपसे यह कह दे कि मेरे तो यहां रात को लाइट आयी है दिन में लाइट नहीं आयी और एक भी किसान यह कह दे कि 6 घंटे की बजाय 5 घंटे लाइट आयी है तो मेरी जिम्मेदारी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भेज दो आपका प्रतिनिधिमंडल। चैलेंज कर रहा हूं मैं इस सदन के माध्यम से, आपको तो दिखेगी ही नहीं लाइट आती हुई। आपको तो दिख ही नहीं रही।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के कार्यकाल में क्या रहा था लाइट आती नहीं थी, अधिकारियों से बात करते थे। हम जैसे भी धरना-प्रदर्शन करते थे, साहब, क्या करें सरकार के पास कोयला नहीं है। आज कोयले की बात कहां गई, आज कहां से कोयला आ गया? पहले बात करते थे ट्रांसफार्मर की कि एक-एक महीना जला हुआ ट्रांसफार्मर नहीं मिलता था। बात करते थे कि साहब, सरकार से ऊपर से आ नहीं रहे। आज 24 घंटे में ट्रांसफार्मर हमारे किसानों के चैंज हो रहे हैं। पिछली सरकार में पूरी असत्यता का काम किया है इन्होंने। बगरू से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि सर्कस मंडली है इन्होंने आठ बार सर्कस किया और उस सर्कस के सबसे बड़े जोकर ने घोषणा की कि साहब, राजस्थान में सरकार बनते ही हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, वो दस दिन पूरे पांच साल में पूरे नहीं हुए। उन्होंने घोषणा की कि साहब, हम युवाओं को सरकारी नौकरियां देंगे। सरकारी नौकरियों की जगह उन्होंने पेपर बेचने का घोटाला किया, पेपर को ऐसे बेचा जैसे अख़बार वाला सुबह साइकिल से अख़बार बेचता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने घोषणा की थी युवाओं को 3,500 रुपये प्रति माह का हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक भी युवा ऐसा बता दो जिसको इन्होंने 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया है। ऐसी असत्य की दुकान लगा कर ये सत्ता में आये और जिस तरीके से इन्होंने कोरोना जैसी महामारी में अपनी सरकार का टाइम पांच सितारा होटलों में बिताया, राजस्थान की जनता ने इनको याद रखा और चुनाव आये तो चुनाव में इनको यहां से विदा करके वहां बैठाया, जो यह उदाहरण है राजस्थान की जनता ने इनको दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में मुख्य मंत्री भजन लाल जी की सरकार पिछले जुलाई माह में बजट लेकर आयी थी। यह कह रहे हैं कि खाली घोषणाएं हैं। इस मामले में मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए आप लोगों को चैलेंज करता हूं, विपक्ष को इस सदन के माध्यम से कि मेरे यहां जो-जो घोषणाएं हुई हैं मैं एक-एक गिना दूं आपको। मेरे वहां पर कृषि उपज मंडी की घोषणा हुई थी, उसकी जमीन अलॉट होकर के कब्जा लेकर के वहां पर काम शुरू कर दिया कृषि उपज मंडी बनाने का। दूसरी घोषणा मेरे वहां की थी लगभग 35 से 40 करोड़ की सड़कों की, बाईपास को लेकर, मिसिंग लिंक को लेकर, नॉन पेचेबल को, जहां

पर टेंडर होकर उनका शिलान्यास होकर उनका काम चालू हो गया। सारों का काम चल रहा है। मेरे लालसोट विधान सभा क्षेत्र में घोषणा की थी नगरपालिका को नगर परिषद बनाने के लिए। आज नगर परिषद के रूप में हमारे वहां पर काम हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां महिला कॉलेज को यू.जी. से पी.जी. बनाने की घोषणा की थी, आज पी.जी. कॉलेज बन करके फर्स्ट ईयर क्लास चल रही है। मेरे वहां घोषणा की थी एनिकट डेम बनाने की, उसका भी टेंडर हो गया, शिलान्यास होना बाकी है और ये कह रहे हैं कि खाली घोषणा है। मेरे वहां बजट घोषणाओं के हण्ड्रेड परसेंट काम हुए हैं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुए हैं, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं। राजस्थान में तो हुए ही हैं मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र का बता रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी रात-दिन एक करके जिस तरीके से इस राजस्थान के विकास में भागीरथ के रूप में लगे हुए हैं, आप लोग पूरे पांच साल सिर्फ इस चीज पर राजनीति करते रहे कि ई.आर.सी.पी., ई.आर.सी.पी., ई.आर.सी.पी.। पांच साल उस ई.आर.सी.पी. का गीत पूरा आपसे नहीं हुआ और माननीय भजन लाल जी की सरकार बने एक साल पूरा नहीं हुआ उससे पहले ही आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा उस ई.आर.सी.पी. का उद्घाटन भी हुआ और राजस्थान की जनता के बीच में पानी आने का एक निश्चय हुआ और मैं समझता हूं कि आने वाले चार साल में राजस्थान में सिंचाई के लिए ई.आर.सी.पी. के माध्यम से पानी आयेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन में आपने घोटाला किया वह जग जाहिर है। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा हर घर को नल से पानी पहुंचाने का सपना था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने सिर्फ अपनी सत्ता बचाने में समय खराब किया और जल जीवन मिशन योजना के नाम पर घोटाला करके अपने चहेतों को लाभ दिया। यह भी जग जाहिर है। पुनः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र में मोदी जी और राजस्थान में भजन लाल देश और राज्य की जनता हो रही है निहाल। इस सदन में मुझे अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह चौहान। (अनुपस्थित)

श्री जाकिर हुसैन गैसावत।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, आपका एवं हमारे विपक्ष के नेता जी का मैं बहुत-बहुत तहेदिल से धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी ने 31 जनवरी को अपना अभिभाषण पढ़ा और हम सबने सुना। 44 पेज 168 पैरा, 1 घंटा 27 मिनट तक राज्यपाल जी ने अभिभाषण जो पढ़ा वह हम सबने सुना। उस भाषण में कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसका काम हो गया। उसमें यही लिखा गया, यही पढ़ाया गया उनसे कि यह कार्य हो रहा है, यह प्रगति पर है या यह है वो है और आज 6 दिनों से अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और सदन में बैठे हां पक्ष

के नेता सब तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा अभिभाषण पेश किया सरकार ने एक साल तक अच्छा काम किया। विपक्ष में बैठे हम लोग कह रहे हैं कोई धरातल पर काम नहीं हुआ। असली सच्चाई तो जब आप लोग जाओगे साढ़े आठ करोड़ जनता के बीच में, तो आप देखो उसकी चर्चा क्या है। साढ़े आठ करोड़ की जनता के बीच में मात्र और मात्र एक ही चर्चा है कि एक साल तक मुख्य मंत्री जी ने सरकार में कोई कार्य नहीं किया है। यह जो राज चल रहा है यह राज ऐसे चल रहा है जिस तरह से कोई पोपा बाई का राज हो। कोई भी धणीधोरी नहीं है। यह राज जब से बना है ब्युरोक्रेसी अधिकारियों के हाथों से यह राज चल रहा है। यह राज मात्र एक वी.सी. के माध्यम से, वी.सी. के माध्यम से मुख्य सचिव सेक्रेटरीज की मीटिंग लेता है वी.सी. के माध्यम से सेक्रेटरी कलेक्टर्स की मीटिंग लेता है और वी.सी. के माध्यम से ही कलेक्टर एस.डी.ओ. की मीटिंग, तहसीलदारों की मीटिंग लेकर, पटवारियों की मीटिंग लेकर खाली खानापूर्ति की जाती है।

Kas/rtm/06.02.2025/18.20/3n

जनप्रतिनिधि का जो अधिकार होता है, चाहे मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे कोई भी हो, वह जवाब नहीं देते हैं। कोई भी विधायक, मंत्री को या अधिकारी को या मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखता है, उसका कोई जवाब नहीं दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं पर भी एससी, एसटी, अल्प संख्यक की किसी योजना का जिक्र नहीं किया गया है। एक साल से राजस्थान की जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। इसमें चाहे महिलाओं के साथ बलात्कार हो, डकैती हो, माफियाओं का खुला आतंक, किसानों पर लाठीचार्ज, गोलीबारी हो रही है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। अभी जायल में एक सरसनी गांव है, वहां पर जेएसडब्ल्यू द्वारा एक सीमेंट प्लांट लगना था, उन लोगों को जमीन के उचित दाम नहीं मिल रहे थे, वहां 135 दिनों से वो लोग धरने पर थे, 6 पुलिस थानों ने मिलकर उन पर लाठीचार्ज किया गया, उनको घसीट-घसीट कर मारा गया, उसको राजस्थान की जनता ने देखा है। रूपनगढ़ में भू-माफियाओं ने डंपरों से गोलियां चलाईं, एक व्यक्ति खतम हो गया और 8-10 व्यक्ति घायल हो गये, इस तरह से जो राज चल रहा है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, भू-माफिया, खनिज माफिया या बजरी माफिया तो आपने सुना होगा, लेकिन देश में पहली बार ब्लड माफिया का काम और चालू हो गया है। मेरे मकराना में अभी 26 जनवरी को हमारे पूर्व एमएलए रूपाराम जी के छोटे भाई के श्रद्धांजलि पर ब्लड डोनेशन कैम्प लगा था। वहां पर बड़ी मात्रा में ब्लड भी आया था, वहां पर सरकार के दो-दो मंत्री जी, अविनाश जी और विजय सिंह जी भी आये थे, दो-तीन एमएलए आये थे, वहां मकराना ब्लड बैंक ने 255 यूनिट ब्लड लिया और उसको वे सवाईमाधोपुर बेचने जा रहे थे। वहां की हैड कांस्टेबल राजकुमारी ने उसकी रेकिंग कर जोबनेर थाने में उसको पकड़ाया। उसमें गाड़ी का ड्राइवर था, उसमें मेन माफिया के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई और जिस राजकुमारी ने इसकी

रेकिंग की, उसको उल्टा लाइन में लगा दिया गया, जबकि उसका प्रमोशन होना चाहिये था। इस तरह से नई-नई चीजें हमको देखने को मिल रही है, इस पर भी कुछ कार्यवाही होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, सभी लोग प्रधान मंत्री जी की और मुख्य मंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं, इसके पैरा नंबर 4 में प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व का जिक्र किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं देश में जो महंगाई के हाल है, वे किसी से छिपे हुए नहीं है। आज भारत के रुपये के भाव कितने गिर गये हैं, रुपया एक डालर के सामने 87 रुपये तक पहुंच गया है, जबकि हमारे पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के समय 2013-14 में एक डालर की कीमत 59 रुपये थी और उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को संभालते हुए देश को बहुत सस्ते भाव में डीजल-पेट्रोल दिया। अभी केन्द्र सरकार का बजट आया, उसमें राजस्थान को मोदी जी ने कुछ भी नहीं दिया। जिस तरह से आज कच्चे तेल की कीमत 72 डालर प्रति बैरल है तो लोगों को उम्मीद थी कि देश में डीजल-पेट्रोल और गैस के दाम कम होंगे, लेकिन मोदी जी ने 90 रुपये डीजल और 105 रुपये लीटर पेट्रोल के भाव कर रखे हैं। जब हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस समय कच्चे तेल की कीमत 130 डालर प्रति बैरल थी, लेकिन उस समय डीजल 60-70 रुपये प्रति लीटर दिया। आज असली महंगाई तो पेट्रोल-डीजल की वजह से हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, इस राज में कभी जिले हटा दिये जाते हैं, कभी संभाग हटा दिया जाता है। वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर पूरे अधिकारियों को उलझा रखा है। यहां हमारे मंत्री जी खर्रा साहब बैठे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने पंचायतों के सरपंचों का समय बढ़ाया है, बहुत सराहनीय बात है, लेकिन नगर पालिकाओं का समय खतम हो गया है, उन पर आपने प्रशासक लगा दिये और आज नगर पालिकाओं की हालत यह हो गई है कि कोई कहने सुनने वाला नहीं है। चाहे मृत्यु प्रमाण-पत्र हो या पट्टे का काम हो या सफाई का काम हो, कोई सुनने वाला नहीं है। परिसीमन का जो आपने बढ़ाने के लिये कहा है, मेरे मकराना विधान सभा क्षेत्र में हुड्डा ग्राम पंचायत जो परबतसर विधान सभा क्षेत्र की आती है, वह सरपंच बार-बार शिकायत कर रहा है कि हमें नगर पालिका में नहीं जाना है, उसको परिसीमन में जोड़ दिया गया है और जो 60 वार्ड बने हैं, उनमें भी इतना भारी भ्रष्टाचार हुआ है।

श्री अध्यक्ष: श्री विरेन्द्र सिंह।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं 60 के 60 वार्डों में समान जनसंख्या भी नहीं दी गई है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, शुरू कीजिए।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): 000

श्री अध्यक्ष: हो गया विरोजो, 10 से 11 मिनट हो गये।

श्री विरेन्द्र सिंह (मसूदा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की तर्ज पर प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल जी ने पूरे प्रदेश की 8 करोड़ जनता का काम किया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि विपक्ष के सम्माननीय विधायकों को वह दिखता नहीं है। जिस प्रकार महाभारत में संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, वो महाभारत का युद्ध देख नहीं पा रहे थे तो उनको श्री कृष्ण भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि विपक्ष के साथियों को भी दिव्य दृष्टि प्रदान करें, ताकि वो जो काम हो रहा है, उसको देखें और महसूस करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी विपक्ष के सम्माननीय विधायक डीजल और पेट्रोल पर बोल रहे थे, विगत पूरे पांच सालों में हम विपक्ष में थे, संगठन में काम करते थे, हम आये दिन वैट कम करने के लिये कलेक्ट्रेट और एसडीओ पर धरना-प्रदर्शन करते थे, लेकिन पिछले पांच साल में आपके मुख्य मंत्री जी ने पेट्रोल-डीजल पर एक पैसा कम नहीं किया। आज आप भी डीजल-पेट्रोल भरवाते हो, आपकी भी बचत हो रही है, आप भी कम पैसे देकर पेट्रोल-डीजल भरवा रहे हो। आज गैस के दामों में कमी हुई है।

अध्यक्ष महोदय, अभी सभी सम्माननीय साथीगण कह रहे थे कि पिछली सरकार ने जल जीवन मिशन में बहुत घोटाला किया। यह घोटाले तो जब देश आजाद हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी, 1947 के बाद लगातार इन्होंने घोटाले किये हैं। इन्होंने न आकाश छोड़ा न पाताल छोड़ा, हर जगह भ्रष्टाचार किया। चाहे कॉमन वेल्थ गेम हो, इनकी इतनी लंबी श्रृंखला है कि अगर मैं उसको पूरा बताऊं तो दो घंटे लगेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिये माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अर्थव्यवस्था को साढ़े तीन सौ बिलियन डालर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। हमारे पहले ही कार्यकाल में 35 लाख करोड़ का निवेश राजस्थान में होगा, उससे पूरे राजस्थान की काया पलट होगी। हमारी सरकार वादों पर विश्वास नहीं करती है, काम में विश्वास करती है। जिस प्रकार ईआरसीपी का काम आपके शासन काल में नहीं हुआ, मैं कोई आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता, लेकिन प्रदेश की 8 करोड़ जनसंख्या को पानी मिले, उस निमित्त ईआरसीपी के माध्यम से पूरे प्रदेश के आधे जिलों में पीने का पानी मिलेगा और इसके साथ ही किसानों को सिंचाई का पानी भी मिलेगा। हमारी सरकार ने राम जल सेतु लिंक परियोजना के रूप में उसका नामकरण किया है। आप चिंता ना करें, इस वर्ष राजस्थान में खूब बारिश हुई है, भूमि का जल स्तर बढ़ा है, अगले वर्ष भी खूब बारिश होगी। अब किसी भी विधान सभा क्षेत्र में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, हमारे मंत्री कन्हैयालाल जी बैठे हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर गांव और ढाणी में नल के माध्यम से शुद्ध जल पहुंचायेंगे।

Msk/rtm/06.02.25/1830/3o

इस प्रदेश में 17 जिलों में चार लाख हेक्टेयर में सिंचाई और तीन करोड़ से अधिक की आबादी को पेयजल मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी का एक संकल्प था, लक्ष्य था कि देश में नदियों को जोड़ा जाए। कहीं अकाल नहीं पड़े, कहीं बाढ़ नहीं आये। उस सपने को साकार किया है, देश के यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल जी ने, जो नदियों को जोड़ने का काम हाथ में लिया है। हर विधान सभा क्षेत्र में, हर गांव जो बड़े बांध, तालाब हैं, उनमें नदियों का पानी आयेगा।

(समय बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

किसानों को साल भर सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, ऐसा राज्य सरकार यह काम कर रही है। हमारी सरकार ने प्रदेश में 2027 तक किसानों को दिन में बिजली मिले, अभी विपक्ष के माननीय सदस्य कह रहे थे कि लाइट नहीं आ रही है। जिस प्रकार अभी रामबिलास जी ने कहा कि विधान सभा क्षेत्र में पूरे छह घंटे दिन में बिजली मिल रही है। मेरी मसूदा विधान सभा क्षेत्र में भी प्रत्येक गांव-ढाणी में आप जाकर पूछ लें, किसानों को लगातार छह घंटे बिजली मिल रही है। आपकी सरकार के समय में किसानों को रात को बिजली मिलती थी। सर्दी में फसल की सिंचाई के समय में बेचारे किसान रात को ठिठुरते हुए अपने खेतों की सिंचाई करते थे। वे दिन आप भूल गये?

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। हमारे राजस्थान प्रदेश में तो सूर्य भगवान की बड़ी मेहरबानी है। इससे पूरे प्रदेश में आने वाले समय में जो बिजली का संकट है, वह संकट मिटेगा। जब प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में भी आपकी कांग्रेस की सरकार थी, कोयले का संकट था। वहां आपकी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जब केंद्रीय मंत्री ने कोयले की खदान आवंटित की। आपकी ही कांग्रेस सरकार थी, उस समय भी आपको कोयला नहीं मिल रहा था। आज कोयला प्रचुर मात्रा में मिल रहा है। पूरे प्रदेश में कहीं बिजली की कोई समस्या नहीं है। हमारी सरकार, माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक वर्ष में पांच नये मेडिकल कॉलेज खोले हैं। राजस्थान की आठ करोड़ की जनता की चिकित्सा की चिंता की है। चिकित्सा के अभाव में किसी को तकलीफ नहीं हो, यह काम किया है। उचित दर पर दवाएं उपलब्ध हों, उसके लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केद्रों में 236 नये औषधि केन्द्र खोले हैं, जिसमें आम गरीब आदमी को सस्ती दर पर दवाएं मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, गोवंश की बात करते हैं। गोशालाओं में जो 10 प्रतिशत अनुदान बढ़ाया है, उससे गोशालाओं की हालत सुधरी है। आज सभी गोशालाओं में जितनी भी गोमाता हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में चारा-पानी और सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। सबसे बड़ी बात तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो किसानों की चिंता की, पशुपालकों की जो चिंता की है। अभी हमारे माननीय पशुपालन मंत्री जी से कह रहे थे कि हमारे गांव में वेटेनरी में डॉक्टर नहीं है, कम्पाउंडर नहीं है, हमारे मुख्य मंत्री जी ने और माननीय मंत्री जी पशुपालकों के लिए

राजस्थान में एक नयी मोबाइल वैन जिसके 1962 नंबर हैं, 1962 पर हम कॉल करते हैं तो वह मोबाइल वैन डॉक्टर और कम्पाउंटर सहित उस पशुपालक के घर पर आकर निःशुल्क उपचार करती है। यह व्यवस्था की है, किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए। हमारी सरकार में, जहां पट्टे वितरण की बात कर रहे हैं। चाहे घुमंतू हो, चाहे अर्द्ध घुमंतू हो, सभी जगह, हर जिला हेडक्वार्टर पर, सभी माननीय विधायकों को ध्यान है कि घुमंतू और अर्द्ध घुमंतुओं को जो पट्टे जारी किये हैं, उनको पिछले 50 सालों से अपने मकान का अधिकार और पट्टा नहीं मिल रहा है, इस सरकार ने वे पट्टे उपलब्ध कराये हैं।

इसके अलावा स्वामित्व योजना, ड्रोन के माध्यम से खेतों के नक्शे तो हमारे राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है, लेकिन आबादी में जिसका भी मकान है, उसका आबादी का नक्शा बना है। ड्रोन के माध्यम से उसका भी एक स्वामित्व प्रमाण-पत्र इस सरकार में सभी को मिले हैं। कहने का मतलब है कि इस प्रदेश में एक साल में जितने काम हुए हैं, महामहिम राज्यपाल ने साल भर में जो काम हुए हैं, विकास के जो कामकाज हुए हैं, उनका ही उल्लेख किया है। लेकिन फिर भी विकास नहीं दिखता है। चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में हो। सभी क्षेत्र में काम हुआ है। यहां शुद्ध जल नल के माध्यम से पहुंचे, इसके लिए सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान की आठ करोड़ जनता को, प्रत्येक गांव-ढाणी को घर में शुद्ध पानी नल के द्वारा पहुंचे, यह काम अभी हमारी सरकार कर रही है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने एक वर्ष में ही 59 हजार 236 पदों पर नियुक्तियां दी हैं और 1 लाख 72 हजार 990 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने जो पिछले पचास सालों में काम नहीं हुए हैं, उसे एक वर्ष में पूरा करने का प्रयास किया है, और काम हुए हैं। आने वाले चार सालों में और विकास के बहुत कामकाज होंगे। बहुत-बहुत, धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापतिः विराजिए। श्री विनोद कुमार।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): रफीक साहब को पानी पीने के लिए जाना है, सब साथ चले गये, इनको इजाजत दें।

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। राज्यपाल जी के अभिभाषण में लोकतंत्र शब्द, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के कल्याण की भावना की गाथा गायेगी, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आयी, लोकतंत्र को खतम करने का काम किया। पूरे राजस्थान के अन्दर जब भी चुनाव कराने की बात आयी, चाहे भादरा का चुनाव ले लो, चाहे मेरे विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में नगर पालिका के चुनाव की बात आयी, जब इन्हें लगा कि हमारे पास बहुमत नहीं है तो इन्होंने हमेशा चुनाव कैंसिल कर दिये। चुनाव कराने की हिम्मत नहीं रखते। नॉमिनेट कर-करके अपने व्यक्तियों को चेयरमैन की सीट पर विराजमान कर दिया।

अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की बात आयी। हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के, सभी मंत्रीगण बैठे हैं। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि इनके कार्यकाल के अन्दर सहायक आचार्य की भर्ती निकलती है। 576 पदों पर भर्ती निकलती है, अगर एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी का जितना भी आरक्षण हमें प्राप्त होना चाहिए, दलित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के लोगों को, अगर उसकी कैलकुलेशन की जाये, इसमें ऑन-रिकॉर्ड सब बातें हैं। 65 पद हैं, एससी, एसटी, ओबीसी के, उनको वंचित कर दिया गया है। सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि नेशनल लॉ विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती निकली। उसमें ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी के वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया। इन सीटों पर NFS (Not Found Suitable) करके उनको Unreserved श्रेणी में डाल दिया गया। क्या पूरे राजस्थान में एससी, एसटी, ओबीसी का कोई बच्चा नहीं है, जो कि इसके सूटेबल नहीं है। इसी तरह की आपकी भाजपा की सरकार आने के बाद आपके द्वारा 2024-25 में भर्ती निकाली गयी थी। मैं कहना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान के अन्दर, जब से हमारी आजादी को 75-76 साल हो गये, लेकिन हम जब किसानों की बात करें, हमारी नहरों की बात करें। चाहे आईजीएनपी में आपने अभी बन्दी दे दी। भांकड़ा क्षेत्र के किसान, जब भी पानी की बात आती है, हमेशा उनको लाठी, डंडे और गोलियां खाकर पानी मिलता है। इस तरीके अपन आज तक व्यवस्था नहीं कर पाये, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो। हमेशा किसानों को लड़-झगड़कर पानी लेना पड़ता है। हमारे यहां खालों की स्थिति क्या है? सेम ग्रस्त इलाका है। खालों की बदतर हालत है। हम किसानों को खातेदारी अधिकार नहीं दे पाये। आज दिनांक तक खातेदारी अधिकार नहीं दे पाये और रही बात, पीलीबंगा के हास्पिटल की जब बात करें तो आज उप खण्ड कार्यालय भी है, सब व्यवस्था है, काफी लंबे समय से 30 बेड का हॉस्पिटल है। हमारी सरकार के काफी मंत्रिगण बैठे हैं। हमारी प्रमुख समस्याएं हैं। मैं आज यूडीएच मंत्री साहब से भी मिला। पीलीबंगा और रावतसर की जब बात आयी तो पानी निकासी के हर क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है।

mdp/rtm/06.02.2025/18:40/3p

उसको लेकर मंत्री जी ने हमें आश्वस्त भी किया है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि शहरों की जब पानी निकासी की बात आती है, पूरे राजस्थान की समस्या है। उस पानी को ट्रीट करके हमें वहां के लोगों को राहत पहुंचाने का काम करना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि जब जे.जे.एम. की बात आयी, बहुत से आरोप-प्रत्यारोप लगे, लेकिन जहां सिस्टम की बात आयी, बहुत अच्छा काम भी हुआ। अब ये जो ढ़ाणियां वंचित रह गयी या कुछ गांव वंचित रह गये। मैं राजस्थान सरकार के नुमाइंदों से कहना चाहूंगा कि जेजेएम में भी अलग से बजट देकर के उन लोगों को जोड़ने का काम कीजिए।

सभापति जी, अभी बिजली की बात आ रही थी, ढाणियों को कनेक्शन देने की बात थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है, राजस्थान सरकार में आप बैठे

हैं। सब ढाणियों को जोड़ने का काम करें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, जो हमारे नौनिहालों की नींव हैं, उन पर हमें ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है क्योंकि जो भी हमारी नींव है, उसको मजबूत करने का काम करें। उनका मानदेय बहुत ही कम रहता है, इसलिए उसमें भी सुधार की आवश्यकता है।

एक-दूसरी विधान सभा में जो सड़कें बनायी जाती हैं, उनमें एक विधान सभा का एमएलए अपनी दो-तीन किलोमीटर सड़क बना लेता है, दूसरी साइड रह जाती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो सड़क के टुकड़े हैं, एक-दूसरी विधान सभा को जोड़ते हैं, जिससे आवागमन में सुविधा हो सके। दुर्घटनाओं पर हम बात कर रहे थे और अभिभाषण के अन्दर भी जिक्र आया तो मैं कहना चाहूंगा कि पीलीबंगा और रावतसर की जो समस्याएं हैं, बाईपास की प्रमुख समस्या है। डेली एक-दो घटनाएं होती हैं। मौत के ग्रास के अन्दर हमारे बहुत-से व्यक्ति चले गये। इसलिए मैं बाईपास की बात भी करना चाहूंगा। स्कूलों में राइजिंग राजस्थान की बात हो रही थी। पूरे राजस्थान के अन्दर, गांव, ढाणी के अन्दर, पूरे स्कूलों के अन्दर हमारे आट्र्स ही पढ़ाई जाती है। हमारे बच्चों को इसके बारे में ज्ञान ही नहीं है। वहां दूसरे जो सब्जेक्ट हैं, आट्र्स की बात हो, चाहे साइंस की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, हमारे बच्चे से आई.टी.आर. की बात करें तो बिजनिस के बारे में हमारे ग्रामीण अंचल के व्यक्तियों को पता ही नहीं है। हमारे बच्चों को पता ही नहीं है, क्योंकि हम उन बच्चों को सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा पाए, जिससे वे भी राजस्थान के अन्दर बिजनिस कर पाए। उनको समझ ही नहीं है। आज आई.टी.आर. की बात करें, इस विधान सभा के अन्दर बैठे हैं, आज आई.टी.आर. के सम्बन्ध में भी हमें पूरा ज्ञान नहीं होता। हमारे बच्चे इन विषय-वस्तु से दूर हो जाते हैं।

सभापति जी, जब कानून व्यवस्था की बात आती है तो मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आपने बजट के माध्यम से 10 हजार की आबादी पर जिम खोलने की बात हो, ग्राउण्ड तैयार करने की बात हो या पुस्तकालय देने की बात हो, मैं कहना चाहूंगा कि दस हजार की आबादी से ऊपर हैं, उनको आपने नगर पालिका बना दिया। इसकी जनसंख्या को कम करके छोटे गांवों को भी शामिल करें तो युवाओं का भला होगा। जो युवा नशे की गर्त में जा रहे हैं, वे नशे की गर्त से बच सकें। मैं एक और बात, हो सकता है कि मेरा भी विपक्ष वाले विरोध करें, लेकिन जिस तरीके से मेडिकेटेड नशा फैल रहा है, क्योंकि पुराने समय के अन्दर पोस्त की खेती हो, अफीम की खेती हो, पूरे राजस्थान के अन्दर होती थी और परमिट दिये जाते थे। डाक्टर के लाइसेंस के द्वारा, अगर कोई व्यक्ति खा रहा है, जिस तरीके से मेडिकेटेड नशा बढ़ रहा है, पहले हमारे जो भी नशा करते थे उनको मेडिकल के हिसाब से परमिट लाइसेंस जारी किये जाते थे। अगर उस तरीके से, सदन को एक दिन इस पर विचार करना चाहिए, जिस तरीके से मेडिकल नशा फैल रहा है, आज मेरी 40-42 साल की एज हो गयी, आस पड़ौस में भी चाहे कोई पोस्त का सेवन करने वाले हो, आज तक कोई गलत

आदतों में चोरी, डकैती में या जो पोस्त खाते थे, उनकी इस तरीके की बात नहीं आयी। जो मेडिकल नशा करते हैं, वह लगभग आपको मिलेंगे कि गलत वे पर जा चुके हैं।

मैं सदन के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि आप इन सब मुद्दों को लेकर पूरे राजस्थान को आगे बढ़ाएं। सार्थक चर्चा करते हुए, पक्ष विपक्ष को मिलकर काम करना होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री उदयलाल भडाणा।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): सभापति महोदय, मुझे आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने नये राजस्थान के निर्माण के लिए, मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा ने 35 लाख करोड़ रुपये के उद्योग-व्यापार राजस्थान में लगे, इसके लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया। नये राजस्थान का निर्माण कैसे हो? मोदी जी की तरह ही, मोदी जी ने 'विकसित भारत संकल्प' लिया है, उसी तर्ज पर राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा ने राजस्थान विकसित कैसे हो? राजस्थान भारत में नंबर वन पर कैसे आये? इसके लिए राइजिंग राजस्थान समिट किया। राजस्थान के अन्दर उद्योग, इकाईयां कैसे लगें, व्यापार कैसे बढ़े? इसीलिए राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा ने 35 लाख करोड़ रुपये के व्यापार, काम-धंधे विदेशों से, देश के दूसरे प्रदेशों से लाने का काम किया।

इसी तर्ज पर हमारे भीलवाड़ा के अन्दर, मैं भीलवाड़ा जिले से आता हूं और भीलवाड़ा जिला औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है, औद्योगिक नगरी के अन्दर मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा ने, सरकार की जो 100 दिन की कार्ययोजना थी, उसी कार्ययोजना में उन्होंने रूपाहेली के अन्दर 1292 बीघा जमीन टैक्सटाइल पार्क के नाम पर अलॉट कर दी। भीलवाड़ा में उद्योग कैसे लगे, व्यापार कैसे बढ़े, वहां के लोगों को रोजगार कैसे मिले? इसको लेकर मुख्य मंत्री जी ने 100 दिन की कार्य योजना में ही 1292 बीघा जमीन का अलॉटमेंट करके टैक्सटाइल पार्क लगाने की घोषणा की। पूर्ववर्ती सरकार के नेताओं ने इसी उद्योग के नाम पर, ये मेर पास 311 लोगों की सूची हैं, उन्होंने केवल और केवल अपने यार-दोस्तों, रिश्तेदारों को, अपने मिलने वालों को, अपने बिजनिस पार्टनरों को जमीन देने का काम किया। लीज डीड कितनी थी? 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और उन्होंने अपने किसी दोस्त के नाम पर समता सिंटेक्स के नाम से अलॉटमेंट कराई फैक्ट्री, वह मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में आती है। भीलवाड़ा शहर के पास पेराफेरी इलाका है, यह अख़बार की बहुत बड़ी-बड़ी कटिंग्स हैं, 500 बीघा जमीन को अपने यार-दोस्तों और अपने मिलने वालों को अलॉटमेंट कर दी। 145 रुपये रोज की लीज डीड के नाम से उन्होंने की और उस दोस्त को डरा-धमकाकर उसको हटा दिया गया। उसकी जगह अपने बेटे को उसका डायरेक्टर बना दिया। शहर के पास में ही इंडस्ट्री, उद्योग के नाम से जमीनें लीं 145 रुपये रोज के नाम पर, ये अखबारों की बड़ी-बड़ी

कटिंग्स हैं, उसी उद्योग के नाम से बाहर समता सिंटेक्स का बोर्ड लगा हुआ है, उसके अन्दर रिसोर्ट चल रहे हैं, बीयर बॉर चल रहे हैं। उसके साथ ही ग्लोरिया-इन नाम की होटल है, वह भी प्रभात सिंथेटिक के नाम से उन्होंने अलॉटमेंट करा रखी है और वहां बड़े-बड़े रिसोर्ट बना रखे हैं। एक दिन का सरकार को पैसा दे रहे हैं 43 रुपया और वह एक दिन का लोगों से वसूल रहे हैं 43 लाख रुपया। एक दिन का दे रहे हैं 145 रुपया लीज के नाम से और 50-50 लाख शादी के नाम पर पैसा ले रहे हैं। सरकार की जमीनों का बंदरबांट करने का काम किया।

हमारी सरकार ने उद्योगों के लिए 1292 बीघा जमीन उद्योगपतियों को दी है। रियायत दर पर उनको फेसिलिटी देने का काम करती है, उनको सुविधाएं देने का काम करती है। पूर्ववर्ती सरकार के जो नेता थे, उन लोगों ने, अधिकारियों ने, अफसरों ने, मैं पेपर्स मुख्य मंत्री जी को भी दूंगा, वर्तमान में जो कर्मचारी हैं, उनके भी होटल हैं, उनके भी रिसोर्ट हैं। केवल उद्योगों के नाम पर जमीनों का अलॉटमेंट करवाकर अपने निजी फायदे के लिए, बाहर लगा हुआ बोर्ड फैक्ट्री के नाम पर और अन्दर दूसरे सब काम चल रहे हैं। उसके साथ-साथ में जो बिला नाम चरागाह भूमि है, उस बिला नाम चरागाह भूमि पर भी अवैध कब्जा कर लिया गया और मैं सरकार से मांग करूंगा कि बहुत जल्दी उसका जो अवैध निर्माण कर रखा है, उसको हटाया जायेगा।

Ans/rtm 18.50 3q 06.02.2025

मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि जो राजस्व की हानि हुई, करोड़ों रुपये की 311 फैक्ट्रियों का अलॉटमेंट किया। उसमें पांच-पांच रुपये में कोई अलाटमेंट होता है? महीने की लीज पांच रुपये, किसी की तीन रुपये और 145 रुपये में बहुत बड़े मंत्री, जो नेता थे हमारे। मैं जिस विधान सभा से चुनकर आता हूं, इस विधान सभा में ज़मीनों का, खानों का, नदियों का जितना घोटाला हुआ आज दिन तक ऐसा घोटाला राजस्थान में शायद किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया होगा।

श्री सभापति: किसी का नाम हो, डिलिट कर देना। नाम डिलिट कर देना।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): राजस्थान में जितना बड़ा जमीनों का घोटाला हुआ, सबसे बड़ा घोटाला मांडल विधान सभा क्षेत्र व करड़ा क्षेत्र में हुआ। करड़ा के अन्दर जो ज़मीनें थी, ग्रेनाइट की जमीनें थी उन सारी ग्रेनाइट की ज़मीनों को वहां के तत्कालीन अधिकारियों ने, तत्कालीन जनप्रतिनिधियों ने, जो जिस गांव का व्यक्ति है, उस गांव में जन्म हुआ, जिस गांव में बड़ा हुआ, जिसका 50-100 साल से कब्जा है, उन लोगों से कब्जा छीनकर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मिलने वालों को जयपुर,दिल्ली से बुलाकर सबको ज़मीनें अलॉटमेंट कर दी। जिसका 50-50 साल से कब्जा था उसको वहां से बेदखल कर दिया गया। मैं सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं, हमारे कडरा क्षेत्र का निवासी है, उस किसान की जमीन अलॉटमेंट की है तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अगर किसान की जमीन का 100

साल से कब्जा था, 91 की रसीद से कार्यवाही कर रहा था, उस जमीन को यदि पूर्ववर्ती सरकार के अधिकारी, जनप्रतिनिधियों ने मिलकर खुर्दबुर्द किया उसकी भी एक सीबीआई जांच होनी चाहिए। कल ही अख़बार में आया, टीवी में आया। टीवी, अखबारों में सीबीआई की जांच चल रही है। एक बहुत बड़ा व्यापारी था उसकी जमीन को खाने का काम किया।

मेरे वहां खारी नदी निकलती है उस खारी नदी के तट पर एनजीटी की पालना नहीं करते हुए, वहां खारी नदी के किनारे ग्रेनाइट की ख़ानें लगा दी और उसका सारा मलबा उस नदी में डाल दिया गया। जितनी भी ग्रेनाइट है, कम से कम हज़ारों बीघा जमीन अलॉटमेंट कर दी, अधिकारियों ने दो-दो लाख रुपये लेकर। सबके सबूत है, दो-दो लाख रुपये लेकर लोगों को जमीन अलॉटमेंट की। जमीन के अन्दर जितना घपला हुआ, घोटाला हुआ, उस घपले की भी मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं। जांच होनी चाहिए।

एक तरफ हमारी सरकार है, राइजिंग राजस्थान के माध्यम से राजस्थान विकसित कैसे बने, राजस्थान नम्बर वन कैसे बने, भजनलाल जी रात-दिन 24 घंटे काम कर रहे हैं। रात को दो-दो बजे तक अपने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं कि राजस्थान नम्बर वन पर कैसे आए। पूर्ववर्ती सरकार के लोगों ने ज़मीनें बेचकर बंदरबाट करने का काम किया।

मैं सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं, मेरा गांव भीलवाड़ा शहर के पास है। नगर विकास न्यास यूआईटी पेराफेरी में मेरी विधान सभा के 56 गांव आते हैं, उन 56 गांवों की जितनी भी जमीनें है सारी यूआईटी व नगर परिषद के माध्यम से आती है। लेकिन उसी नगर विकास न्याय यूआईटी के अन्दर पिछले राज के अन्दर बहुत बड़े-बड़े भू माफिया वहां का टेंडर लेते थे कि मैं फलां अधिकारी को लाऊंगा, वहां की ज़मीनों को लूटूंगा। एक महिला कर्मचारी वहां थी, उसने कम से कम 500-1000 करोड़ रुपये का घपला किया। मैं सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी है उन पर भी सख्त कार्यवाही की जाए। जितने फर्जी रजिस्ट्रेशन हुए, फर्जी आवंटन हुए उन सबको निरस्त किया जाए और आम जनता को फायदा पहुंचाया जाए। राजस्व की जो हानि हुई है उसकी भरपाई की जाए।

बहुत सारी योजनाएं हैं। भजनलाल जी शर्मा ने पिछले बजट में हमारे माण्डल विधान सभा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी योजना दी। एक हरिपुरा चौराहे से लेकर देवगढ़ तक हाईवे का काम पास किया। हाइवे का काम बहुत जल्दी चालू होने वाला है, इसकी डीपीआर बन चुकी है। किशनगढ़ के पास से हाईवे निकल रहा है, एक ब्यावर होकर राजसमंद में जाता है और एक भीलवाड़ा होकर राजसमंद में जाता है, दोनों हाईवे वहां से निकलकर वहां मिल रहे हैं लेकिन बीच में एक लंबे हाईवे से जाकर दवगढ मिलेगा, यह एक हाईवे निकालने का काम कर रहे हैं। दो-चार बड़ी-बड़ी सड़कों का काम भी किया। औद्योगिक क्षेत्र करड़ा में लगाने का काम भी किया।

राजस्थान सरकार के अन्दर बहुत सारी योजनाओं पर काम चल रहा है। ऊंर्जा विभाग की बात करूँ, ऊर्जा विभाग में पूर्ववर्ती सरकार के वक्त किसानों को चार-चार वक्त लाइट दी जाती थी। सुबह 6 बजे से दिन के 12 बजे, 12 बजे से शाम 6 बजे, शाम 6 बजे से रात 12 बजे

और रात 12 बजे से सुबह 6 बजे, किसानों को चार समय लाइट दी जाती थी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उन्हीं किसानों को दो बार लाइट दी गई, सुबह 6 बजे से 12 बजे और 12 बजे से शाम 6 बजे। बहुत सारे किसान ऐसे थे जिनकी सर्दी के समय पाला पड़ने से मौत हो जाती थी। जीव जंतु खा जाते थे, मर जाते थे। भजनलाल जी की सरकार आई और हीरालाल जी ऊर्जा मंत्री बने, इन्होंने कहा कि दो वक्त दिन में ही लाइट देंगे। बहुत जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक समय में सारी लाइट दिन में देने का काम करेगी।

ऊर्जा योजना में कुसुम योजना के माध्यम से सोलर प्लेट की किसानों को, सरकारी भवनों को सब्सिड़ी दी जा रही है, ऊर्जा विभाग के माध्यम से भी काम करेंगे। किसान सम्मान निधि के माध्यम से भारत सरकार की तरफ से 6 हजार रुपये किसानों को मिलते थे। भजनलाल जी ने सोचा कि गरीब किसान का खेती बोने का समय आता है उसको 6 हजार रुपये कम पड़ते हैं, उन्होंने कहा कि मैं हर साल 2 हजार बढाऊंगा और 12 हजार लास्ट तक करने का और 2 हजार बढ़ाकर दिया। हर साल 2 हजार बढाएंगे और किसानों का भला करेंगे। किसान के लिए 12 हजार बहुत होता है। अगर किसान के लिए कोई सोचने वाला है तो वह भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी हैं, उन्होंने 6 हजार रुपये किसान के खाते में डालना स्टार्ट किया। भजनलाल जी भी किसान के बेटे हैं, गांव से निकले हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने भी बढ़ाकर किसानों के लिए सोचने का काम किया। अगर कोई पशुपालक है, उसके पास पैसा नहीं है, काम धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, उन्होंने मंगला योजना के माध्यम से एक लाख रुपये बिना ब्याज किसानों को पशुपालन के लिए देने का काम किया। पशुपालन के माध्यम से बिना ब्याज का होगा तो वह दूध, घी उसके घर आएगा और छोटा-मोटा व्यापार भी करेगा।

हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री भजनलाल जी ने युवाओं को 59 हजार नौकरियां दे दी है और 81 हजार का योजना कलैण्डर जारी कर दिया, बहुत जल्दी देंगे। इसी सदन के माध्यम से परसों हमारे डोटासरा साहब ने कहा था कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नौकरियां दे दी गई। मैं डोटासरा साहब से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे राज में तो 59 हजार दे दी, 81 हजार और देने के लिए सरकार तत्पर है।

श्री सभापतिः समाप्त करे।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल):पिछली सरकार में 19 बार पेपर बेचा गया। हमारी सरकार में एक बार भी पेपर नहीं बेचा गया।

श्री सभापतिः श्री मनीष यादव।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): आपने तो अपने खुद के रिश्तेदारों को 85-85 नम्बर देकर तीन-तीन लोगों को आरएएस आफिसर बनाने का काम किया।

श्री सभापतिः समाप्त करें।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): हमारे भजनलाल जी की सरकार है वह..

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): 000

श्री सभापतिः विराजिये, विराजिये।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): बजट सत्र की शुरूआत में माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में सरकार की बहुत प्रशंसा की, मगर अफसोस की बात है प्रदेश की आठ करोड़ की जनता व्यथा, वेदना व सच्चाई इस अभिभाषण से कोसों दूर रही। प्रदेश की भाजपा सरकार को एक साल पूरा हो गया है, एक साल प्रदेशवासियों के लिए नाउम्मीदी और निराशा से भरा रहा है। जिसमें आम जन को कोई राहत नहीं, तरक्की की कोई आहट नहीं, जनता जानती है कि यह सरकार नहीं पर्ची है, यह कुप्रबंधन व कुशासन की बरगलाने वाले कोरे और थोथे भाषण की साल भर के इस कुराज में बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं का हुआ बंटाधार, बढ़ रहा महिलाओं, दलितों, वंचितों पर अत्याचार, हर वर्ग हुआ लाचार, हजारों युवा मित्र हुए बेरोजगार, ऊपर से असत्य कहते हो कि एक लाख भर्तियां दी। सच बताओ कि कितने फार्म निकाले और परीक्षा करवाकर कितनी ज्वाइनिंग दी या केवल पिछली भर्तियों का क्रेडिट खाकर, असत्य वाह-वाही ली, कितना ही असत्य बोलो मगर ध्यान रखो प्रदेश की जनता आपको पहचानती है, आपकी जनविरोधी नीतियों को जान गई है।

सभापति महोदय, साल भर के अन्दर राजस्थान में भाजपा सरकार के कुशासन व कुप्रबंधन का जो पर्याय राजस्थान की जनता देख रही है, आज किसी क्षेत्र में चले जाओ। आप विकसित राजस्थान की बात करते हो, आप राइजिंग राजस्थान के नाम पर 35 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात करते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे 400 प्रोजेक्ट जो अभी कृषि आधारित है, कृषि नीति 2019 के तहत अभी भी 35 लाख करोड़ निवेश करने के समय अभी भी सब्सिड़ी का इंतजार कर रहे हैं। जिस विकसित राजस्थान की बात आप कर रहे हैं आपको समझना चाहिए कि पिछले दिनों कोटपूतली में एक बच्ची बोरवैल में 10 दिन तक फंसी रही, दौसा में एक बच्चा फंसा रहा, बाड़मेर में घटना हुई, आप जिस विकसित राजस्थान की बात कर रहे हो, जरा देखो कि आज जगह-जगह घटनाएं हो रही हैं। 10-10 दिन तक कोई नलकूप में फंसा हुआ है और विकसित राजस्थान की परिकल्पना हम अपने कोरे भाषणों में कर रहे हैं, अभिभाषण में कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आनन फानन में राजस्थान में जरूर पर्चा निकाल दिया होगा कि हम नलकूप और ऐसे कुओं को बंद करेंगे या ढकेंगे लेकिन मैं कहना चाहता हूं राजस्थान में बहुत सी जगह पर ऐसे नलकूप हैं, जहां टयूबवैल हैं, कुएं हैं जिनको ढकना अभी बाकी है, क्योंकि यह विकसित राजस्थान की और भाजपा सरकार की असल तस्वीर हमको दिखाती है।

सभापति महोदय, आज प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। हर दूसरा नौजवान जो शिक्षित है वह रोजगार के इंतजार में बैठा है। मैं कहना चाहता हूं कि नौजवानों के लिए अगर

राजस्थान में कोई ठोस नीति नहीं बनेगी, ठोस नीतिबनकर उसमें कार्य नहीं होगा तो जिस प्रकार आज के समय बेरोजगारी बढ़ी हुई है, अपराध बढ़ा हुआ है, नौजवान अपराध की तरफ जा रहा है, सरकार को समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में हम प्रयास करें और नौजवानों के लिए कोई ठोस नीति बनायें, जिससे राजस्थान का आने वाले कल का भविष्य तय हो। हमारा शिक्षित नौजावान है उसको रोजगार मिले। कांग्रेस की पिछली सरकार ने 2023-24 के बजट में नेट व सेट पास रिसर्च स्कोलर्स को शोध कार्य में सम्बल देने के लिए हर महीने 20 हजार रुपये की स्कोलरशिप की घोषणा की।

VPS-RTM-06.02.2025-19.00-4a

62 करोड़ रुपये की बजट की मंजूरी भी दी मगर भाजपा सरकार ने लगता है इस स्कीम को ही बंद कर दिया। आपको कांग्रेस राज की स्कीमों का नाम बदलने की आदत है, इस स्कीम का भी नाम बदल दिया लेकिन युवाओं की यह योजना चालू रहनी चाहिए, शुरू रहनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, पिछले दिनों एक वीडियो आया था जिसमें बीकानेर के कुछ बच्चे, दिव्यांग बच्चे जिला हैडक्वार्टर की तरफ जा रहे थे। यह बड़े शर्म की बात है। उन बच्चों का यह कहना था कि हमारे स्कूल को बंद कर दिया गया है। आज राजस्थान में ब्यावर से जोधपुर, कहीं पर भी चले जाओ, 260 से भी ज्यादा विद्यालयों को आपने मर्जर के नाम पर बंद कर दिया है, जिनमें चार सौ से पांच सौ बालिकाएं पढ़ती थीं।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): ये गलत बयानी कर रहे हैं।

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा। विराजिये।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): 000

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): मर्जर के नाम पर यह बंद करना, मर्जर के नाम पर बालिकाओं से शिक्षा का हक छीनना और अंग्रेजी मीडियम के हमारे जो स्कूल बंद करने के नाम पर आपने जिस प्रकार की कमेटी बनाकर गरीब विद्यार्थी को, हमारे ऐसे परिवारों से आने वाले जो कि सामान्य परिवारों से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, उन बच्चों को शिक्षा से रोकना चाहते हो। क्या आपके बच्चे केवल अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ेंगे? आपको यह समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में आप सब लोगों को इस बारे में विचार करना पड़ेगा। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): जिस तरीके से सरकारी विद्यालयों में नामांकन घट रहा है, यह हमको सोचने की जरूरत है। सरकार को ठोस नीति बनाने की जरूरत है। आज बिजली, पानी की व्यवस्था आप कर रहे हो। पिछले उस समय में जब बिजली की स्थिति रही तो पन्द्रह से अठारह घंटे तक बिजली गुल रही और हीटवेव के कारण राजस्थान में मौतें हुईं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह कहा कि हीटवेव में जो लोग मरे हैं उनका आकड़ा जारी करो, उनको मुआवजा दो, आज तक एक व्यक्ति को भी मुआवजा नहीं दिया गया है। सरकार

की यह नीति यह बताती है कि किस तरीके से राजस्थान को चलाना चाहते हैं।

ई.आर.सी.पी. के नाम पर बड़ी-बड़ी बात करने का आपने काम किया है। ई.आर.सी.पी., मैं शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। मेरे पिताजी सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। किसान परिवार से आता हूं। आज पानी का संकट मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिस प्रकार से है, माननीय सभापति महोदय, मैं यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बजट के समय 2024 बजट में जब पैरा 112 कॉलम 2 में यह लिखा गया कि शाहपुरा बांध को ई.आर.सी.पी. में जोड़ा गया है तो मैंने अंतःसत्रकाल में प्रश्न लगाया और उसमें जवाब मांगा कि शाहपुरा बांध कौनसे राजस्व गांव में स्थित है? तो उसमें यह जवाब आया कि शाहपुरा नाम से कोई बांध नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में देवन, शिवसिंहपुरा, धोली, मांटोली में बांध है लेकिन एक भी बांध को नहीं जोड़ा गया है। जल जीवन मिशन में जिस प्रकार से 41 राजस्व ग्रामों की स्कीम हमारे बंद पड़ी है। एक भी गांव में पानी चालू नहीं हुआ और हमारे वहां पर अभी तक जिस प्रकार का काम सरकार को 14 महीनों में करना चाहिए था, वह अभी तक नहीं किया। कोर्ट स्टे की वजह से हमारे लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है।

चिकित्सा व्यवस्था का उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि पाली से दो माननीय मंत्री आते हैं। यहां पर इस दल के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं। पिछले ही दिनों खबर छपी की पाली में प्रसूताएं जिनको बेड नहीं है, बड़े अस्पताल में उनको नीचे लेटना पड़ रहा है। कैसी स्थिति इन्होंने चिकित्सा व्यवस्था की बना दी? आर.जी.एच.एस. में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, जांचें नहीं हो रही हैं। इस सरकार को यह समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में यह राजस्थान को किस ओर ले जाना चाहती है।

भरतपुर की एक दुष्कर्म पीड़िता थाने में अपनी शिकायत लेकर जाती है और जब उसकी शिकायत नहीं सुनी जाती, उसको आत्महत्या करनी पड़ती है, यह राजस्थान का आप लोगों का किया हुआ हाल है। जयपुर में आये दिन लूट की घटनाएं, रेप और अन्य घटनाएं हो रही हैं। जहां राजधानी से मुख्य मंत्री खुद चुने हुए हैं, उनके गृह जिले में क्या स्थिति है? बाड़मेर में दलित को पेड़ से लटका कर मारा जाता है, ये घटनाएं राजस्थान का जो आपका असल चरित्र है, किस प्रकार का राजस्थान? दलित विरोधी, पीड़ित विरोधी, वंचित विरोधी राजस्थान आप चलाना चाहते हो, यह आपकी सोच को परिलक्षित करता है। आने वाले दिनों में जो हाल आपको देखना पड़ेगा, पानी-बिजली से निपटने के लिए आपको ठोस नीति बनानी पड़ेगी जिससे आने वाले समय में राजस्थान में हाल बेहाल नहीं हो।

मेरे विधान सभा क्षेत्र का हाल बेहाल है। मंत्रीजी, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी पानी की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाये और जल्दी से जल्दी हमारे वहां पर जो 41 गांवों की स्कीम है, उसे हाई कोर्ट में सरकार पैरवी करके वह स्टे हटायें ताकि हम लोगों को न्याय मिले, पानी मिले। कुछ दिनों पहले जयपुर में एक कार्यक्रम था। मीडिया के एक कार्यक्रम में मुख्य मंत्रीजी गये तो वहां पर यह कहा गया, मुख्य मंत्रीजी के सामने यह

कहा कि कुछ मंत्री नॉन परफोर्मिंग असेट बन गये हैं और उसका नुकसान जनता को उठाना पड़ रहा है और जब यह कहा गया तो जनता ने खूब तालियां बजाईं। आज एक साल हो गया, पूरा प्रदेश यह जान गया है, मंत्री ही नहीं, पूरी सरकार एन.पी.ए. हो गयी है, जिसका नुकसान राजस्थान को उठाना पड़ रहा है। असत्य वादों से गुमराह करके सत्ता में आयी यह सरकार एक्सपोज हो चुकी है। आप सब लोगों को यह समझना पड़ेगा कि राजस्थान को किस तरफ चलाना है। राजस्थान में अगर सुशासन लाना है तो चिकित्सा, शिक्षा, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं आप सब लोगों को करनी पड़ेगी, एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर राजस्थान को आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक इनवेस्टमेंट समिट के नाम पर जिस प्रकार का एक ऐसा प्रचार करना आप चाहते हो, जब नलकूप में बच्ची फंसी रही, इस प्रकार की घटनाओं के प्रति आपको गम्भीर होना पड़ेगा।

अंत में, दो पंक्तियों से, अदम गोंडवीजी की पंक्ति से मैं इस बात को खतम करना चाहूंगा कि-

'तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है,
मगर यह आंकड़े झूठे हैं, यह दावे किताबी है।'

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री हंसराज मीना।

श्री हंसराज मीना (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिए मुझे अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी के सानिध्य में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने राजस्थान को औद्योगिक राजधानी बनाने के लिए अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान जैसा बड़ा कार्यक्रम सफलतापूर्वक किया है, उसके लिए मैं पूरे सदन की ओर से हमारे मुखिया को, माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने प्रदेश के युवाओं के हक के लिए यह अति महत्वाकांक्षी कदम उठाया है।

माननीय सभापति महोदय, राइजिंग राजस्थान का होना और प्रदेश के लिए 35 लाख करोड़ रुपये के एम.ओ.यू. साइन होना यह बड़ी बात नहीं है इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस तरह का माहौल हमारी सरकार को मिला, जिस तरह की नकारात्मकता पूर्ववर्ती सरकार के प्रति थी और उस नकारात्मकता को दूर करते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री ने इस प्रदेश में जिस तरह का वातावरण बनाया, इस प्रदेश की जिस तरह की छवि बनाई कि देश और विदेश के कंट्री पार्टनर बने और उन्होंने इस प्रदेश पर यह विश्वास किया और उनके विश्वास से ही यह 35 लाख करोड़ रुपये का एम.ओ.यू. साइन हुआ, यह हम सबके के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है।

माननीय सभापति महोदय, ऐसा नहीं है कि पूर्ववर्ती सरकार ने निवेश के लिए काम नहीं किया लेकिन निवेश के लिए उन्होंने जो भी कार्यक्रम किये, इनकी नीयत में खोट था और

उसी खोट के चलते राजस्थान की जगह पर ये स्वयं नेता फले-फूले न कि राजस्थान फला-फूला।

माननीय सभापति महोदय, मैं पूर्वी राजस्थान से आता हूं और पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धराजी राजे ने जिस तरह से ई.आर.सी.पी. का विजन एक राजस्थान के सामने रखा और पूर्ववर्ती सरकार ने उस विजन को राजनीतिक टूल बनाया और राजनीतिक टूल के चक्कर में पूरे पांच साल तक ई.आर.सी.पी. लटका रहा, उस ई.आर.सी.पी. को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने सशक्त नेतृत्व से, जिन्होंने अपने भागीरथी प्रयासों से ई.आर.सी.पी. जैसे अब राम जल सेतु लिंक परियोजना के नाम से जाना जायेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस राम जल सेतु लिंक परियोजना के माध्यम से प्रदेश के 17 जिलों जिनमें 4 लाख हैक्टेयर भूमि को सर-सब्ज करने के साथ ही 3 करोड़ से अधिक आबादी के प्यासे कंठ को शीतलता मिलेगी, जैसा एक महत्वपूर्ण काम किया है, यह निश्चित रूप से हम सबके लिए गौरवान्वित करने वाला पल है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने अपने वादे के अनुरूप एक वर्ष में 59500 सरकारी नियुक्तियां प्रदान की हैं, वही इस वर्ष 85000 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का कलैंडर जारी करना और पिछली सरकार में जिस तरह से न तो भर्तियां निकलती थीं और यदि भर्तियां निकल जाती थीं तो उनके पेपर लीक हो जाते थे और पेपर लीक से बच जाते तो कोर्ट में जाकर वह भर्तियां अटक जाती थीं। जिस तरह का एक युवाओं के अन्दर, एक हमारे प्रतिभावान युवाओं के अन्दर जिस तरह का एक निराशा का और हताशा का भाव बना, उस निराशा और हताशा के भंवर से निकालकर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस प्रदेश के युवाओं के अन्दर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया है और उसी के कारण यह 85000 पदों की जो भर्तियां निकाली हैं, यह यू.पी.एस.सी. की तर्ज पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसका एक पूरा कलैंडर जारी किया है।

ssy/rtm/06.02.2025/19.10/4b

उस कैलेंडर के अन्दर भर्तियां कब होनी हैं, इनकी परीक्षाएं कब होनी हैं, इनका रिजल्ट कब आना है और कब नियुक्ति मिलेगी, यह सारा है। यह पूरा कैलेंडर जारी करना अपने आपमें एक सशक्त नेतृत्व को परिलक्षित करता है।

सभापति महोदय, अभी सदन के अन्दर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों के बारे में चर्चा चल रही थी। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने 3741 हिन्दी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में तबदील किया।

मेरी ही विधान सभा के 2 महात्मा गांधी स्कूल हैं जिनका उदाहरण मैं आपके सामने एक नमूने के तौर पर रखना चाहूंगा। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नारौली डांग जब हिन्दी माध्यम में संचालित था उस समय इसमें नामांकन 681 था, आज स्थिति यह है कि 209

नामांकन ही इस स्कूल का रह गया है। दूसरा, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय डाबरा है, जिसका नामांकन 400 था और अंग्रेजी माध्यम में तबदील करने के बाद में नामांकन केवल 200 रह गया है। यह 2 स्कूल ऐसे हैं जो मेरी विधान सभा के अन्दर हैं। कल हमारे बीच में ही बयाना से सम्माननीय सदस्या अपने क्षेत्र के विद्यालय की मांग को बता रहीं थी। मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के अन्दर ऐसे तमाम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक कलेक्टर को, डीईओ साहब को और जन प्रतिनिधियों को ज्ञापन दे चुके हैं इन विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम से हिन्दी माध्यम में कनवर्ट करने के लिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं महात्मा गांधी जी का एक कोटेशन सदन को स्मरण कराना चाहूंगा। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा पश्चिमी विचारों और संस्कृति की ओर खुलने वाली एक खिड़की मात्र है। जिस तरह से देश के राष्ट्रपिता ने अंग्रेजी शिक्षा के विषय में यह बातें कहीं, मैं अंग्रेजी शिक्षा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो बात कही कि अंग्रेजी शिक्षा पश्चिमी संस्कृति और विचारों की ओर खुलने वाली एक खिड़की मात्र है। पूरे महात्मा गांधी विद्यालय जो इन्होंने तबदील किये यह इस बात को परिलक्षित करता है कि इनका जो आलाकमान है वह पश्चिमी संस्कृति और पश्चिमी विचारों से ताल्लुक़ात रखता है। उस आलाकमान को खुश करने के लिए इन्होंने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों को अंग्रेजी में तबदील किया।

माननीय सभापति महोदय, आपके बीच में निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के अन्दर ऐसे अनेकों स्कूल हैं, इन तमाम स्कूलों की समीक्षा होना जरूरी है। जो वास्तव में जरूरतमंद हैं, उन्हीं स्कूलों को रखा जाये अन्यथा इन स्कूलों को हिन्दी माध्यम में बदला जाये क्योंकि इससे हमारे क्षेत्र में, मैं मेरी विधान सभा की बात कर रहा हूं, उसमें नामांकन पहले की तुलना में आधा रह गया है।

माननीय सभापति महोदय, सभी विपक्ष के सम्मानित सदस्य एक साल के बारे में बातें कर रहे थे कि इस एक वर्ष में हमारी सरकार ने क्या किया है। मैं आपके बीच में इस सदन के माध्यम से अवगत करवाना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार का वह अंतिम साल जब यह पूरे प्रदेश में जिस तरह से रेवड़ियां बांट रहे थे, जगह-जगह घोषणाएं कर रहे थे, उस एक साल की तुलना हमारे इस एक वर्ष से कुछ आंकड़ों के साथ में करना चाहूंगा। काली बाई भील मेधावी छात्रा योजनान्तर्गत स्कूटी वितरण 1 जनवरी, 2023 से हमारी सरकार आने तक इन्होंने 4232 स्कूटियों का वितरण किया है और हमारी इस सरकार ने एक साल के अन्दर 24517 स्कूटियों का वितरण किया है। स्कूली छात्राओं को साइकिल वितरण इनका एक साल के अन्दर अंतिम में जीरो था और हमारी सरकार ने 8.51 लाख साइकिलों का वितरण इस एक साल के अन्दर किया है।

माननीय सभापति महोदय, विद्यार्थियों को टेबलेट वितरण इनका जीरो था, हमने 88800 टेबलेट वितरण किये हैं। इन्होंने 21 राजकीय महाविद्यालयों में भवन निर्माण करवाया और हमने 70 महाविद्यालयों का इस एक साल के अन्दर निर्माण कराया है। सोलर पंप सैट की

स्थापना इन्होंने 1200 की और हमने 28884 सोलर पंप सैटों की स्थापना की है। गेहूं की खरीद, जिसके लिए कहा गया है, वह इन्होंने अपने अंतिम साल में 4.38 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीद की थी। वह हमारी सरकार ने एक साल के अन्दर 12.05 लाख मेट्रिक टन की खरीद की है।

माननीय सभापति महोदय, कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के लिए इन्होंने अपने अंतिम वर्ष में 21.53 करोड़ रुपये दिये थे और हमारी सरकार ने एक साल में 60 करोड़ रुपये दिये हैं। नहरी तंत्र के माध्यम से सृजित सिंचाई सुविधा इन्होंने 12492 हेक्टेयर और हमारा 22648 हेक्टेयर है। नये ग्रिड सब स्टेशन इन्होंने एक साल में 14 किये और हमने 21 किये। सहकारी समितियों में नये गोदामों का निर्माण इनका लास्ट में जीरो था और हमारा 62 है। पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड जो इन्होंने 1.11 लाख दिया उसके मुकाबले में हमने 1.86 लाख दिये।

माननीय सभापति महोदय, गौ शालाओं को सहायता, इन्होंने 733 करोड़ दी और वह हमने 1148 करोड़ दी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में लाभान्वित महिलाएं इनके 1.94 थी जो हमारी 4.86 लाख हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक वर्ष उत्कर्ष परिणाम का यह आपको कुछ नमूना हमने प्रस्तुत किया है। साथ में ही आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहूंगा कि पिछले 3-4 दिनों के अन्दर जिस तरह से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद चल रहा है, उससे एक बात तो यह स्पष्ट होती है कि विपक्ष के पास में ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है जो सरकार के किसी मंत्री को या सरकार के मुखिया को घेर सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी परेशानी माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी नहीं हैं, इनकी परेशानी भजन लाल जी का जिस तरह से सशक्त नेतृत्व है, सबल नेतृत्व है, उसके कारण इस प्रदेश के 7 उप चुनावों में से भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीतकर आई है, उसके कारण इनके अन्दर मरोड़े चल रहे हैं।

श्री सभापतिः विराजें। श्री समरजीत सिंह।

श्री हंसराज मीना (सपोटरा): यह कहीं दिखाई नहीं दिये। इनकी 4-4 जगह जमानत जब्त हो गई। यहां पर हमारे नेताओं का नाम लेकर यह केवल मुद्दा बनाना चाहते हैं।

श्री सभापतिः विराजें, विराजें।

श्री हंसराज मीना (सपोटरा): इनके बीच में, नेता प्रतिपक्ष यहां नहीं बैठे हैं।

श्री सभापतिः अंकित नहीं हो। अंकित नहीं होगा।

श्री हंसराज मीना (सपोटरा): 000

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): सभापति महोदय, आपने आज जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए मुझे समय दिया है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय, पिछले 3 दिन से हम सभी राजस्थान विधान सभा में बैठकर राज्यपाल के अभिभाषण के जरिये सरकार के पिछले एक साल का लेखा-जोखा जो कैबिनेट ने तैयार

करके राज्यपाल के श्रीमुख से कहलाया है, उस पर वाद-विवाद कर रहे हैं। यही प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि सरकार जो काम करती है या जो करने जा रही है, उसकी व्याख्या पर हम लोग मिल-बैठ करके कर रहे हैं, उस पर वाद-विवाद करते हैं और पूरे राजस्थान में इस सोशल मीडिया के जमाने में हर व्यक्ति तक बात पहुंचती है। यह इतराने की जरूरत नहीं है कि आप सच बोल रहे हो कि हम सच बोल रहे हैं। दुनिया अपने आप फैसला करेगी।

सभापति महोदय, सरकारी पक्ष हरदम यह कहता है कि हम ही सब सही काम करते हैं। यह तो वह वाली बात हो गई कि ड्राइविंग सीट पर जो बैठा है वह व्यक्ति कहता है कि गाड़ी तो मैं सही चला रहा हूं। पास वाला कहता है, टकरा जायेंगे, ध्यान रख भाई। पर फिर भी वह मुगालते में ही रहता है कि सही तो मैं ही चला रहा हूं। चलिये, अभी आपका समय है। आप चलाइये।

मेरी मान्यता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह चलती रहेगी। सरकारें आयेंगी, जायेंगी, हर सरकार आती है तो यह तो नहीं होता है कि पिछली सरकार के कामकाज को आप बिलकुल ही बंद कर दोगे। उन सरकारों के कामकाज में जो आपको उचित लगेंगे, उनको आप आगे बढ़ायेंगे और उसके अन्दर कुछ संशोधन भी होते हैं। अभी पिछले समय में कई उद्घाटन हुए। यहां पर बातें भी होती है। राज्य सरकार की बजाय केन्द्र सरकार की बातें आती हैं। राजस्थान का बजट तो अब आयेगा, उससे पहले हम बखान केन्द्रीय बजट का कर रहे थे।

मैं कई बार देखता हूं, मैंने जैसा कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास में प्रधान मंत्री आयेंगे, जायेंगे, मुख्य मंत्री आयेंगे, जायेंगे। एक मुख्य मंत्री नींव रखता है, अगला मुख्य मंत्री उसका उद्घाटन करता है। गवर्नमेंट इन गवर्निंग जो भी करेगा वही उद्घाटन करेगा ना। नींव तो एक रखेगा। आज कश्मीर में बड़ी-बड़ी टनल्स बनी हैं, कोई एक दिन में तो नहीं बनी।

(समय: बजे)

(श्री अर्जुन लाल जीनगर, सभापति, पदासीन)

मनमोहन सिंह जी ने उनकी नींव रखी। मोदी जी ने उनका उद्घाटन किया। एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हमें हैल्दी रुप में लेना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। एक दूसरे की कमियां निकालना, यह तो यही बात हुई कि हर पुत्र कहता है, एक इंग्लिश में कहावत है, "every Son says his father was wrong, by the time he realizes that his father was right, his Son says he was wrong."

spp/rtm/06.02.2025/19:20/4c

हर पुत्र कहता है कि उसका पिता गलत है। जब तक उसको समझ में आता है कि उसका पिता सही था, उसका पुत्र बड़ा हो जाता है, वह कहता है कि मेरा पिता गलत है। यह बड़ी गलतफहमी है जिसमें हम सब जीते जा रहे हैं। हर व्यक्ति काम करता है और विकास चलता

रहता है। अभी आप लोगों ने, जो हमारे काम किये हुए हैं, उन कामों को परिवर्तित नहीं किया। जैसे अभी हमने 17 जिले बनाये, अगर इतने ही खराब जिले थे तो आप सबको खत्म कर देते।..(व्यवधान).. सारे ही खत्म कर देते पोपराम जी। परंतु मेरा यही कहना है कि सारे खत्म करते तो मैं कहता कि गलत बनाये हैं। कोई कार्य होता है उसमें कमियां-खामियां सब रहती हैं, उसमें सुधार भी होते हैं और सुधार की गुंजाइश भी होती है। आपको उनको रिस्ट्रक्चर करने चाहिए थे। जैसे हमारे यहां सांचौर जिला था, उस जिले को आपने रातों-रात खत्म कर दिया। अब 250 किलोमीटर रण ऑफ कच्छ, अगर कोई सांचौर की स्थिति देखें, हमारे मंत्रीजी बैठे हैं के.के.विश्नोई जी, जो वहां के जंवाई हैं, इनको पता होना चाहिए कि 250 किलोमीटर जालौर तक कब पहुंचेगा व्यक्ति? आपको चाहिए था इसको रिस्ट्रक्चर करते। उस निर्णय को आप सही करते, परंतु आप लोगों ने तो एक झटके से खत्म कर दिये। जंवाई कमजोर निकल गये होंगे मेरे ख्याल से। स्थितियां इस तरह से होनी चाहिए थीं। सलूम्बर जैसे छोटे जिले के लिये तर्क देते हैं। अभी कानून मंत्रीजी खड़े होकर तर्क दे रहे थे कि हमें सीमाएं देखनी पड़ती है, यह देखना पडता है। परंतु आपने निर्णय तो लिये हैं न। हर तरह के निर्णय देखकर लेने चाहिए।

इसी तरह से, बजट इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है। आप लोगों ने सालभर की बातें कीं कि हमने साल भर में यह कर दिया। सालभर में आप लोग किस बूते पर करेंगे, बजट के ऊपर ही आप लोगों ने काम किये होंगे न? मुझे यह बताइए कि जो सड़कें आपने डिक्लेयर की थीं, वह सारी पूरी हो गयीं या वहां पर सबका काम शुरू हो गया? काम अभी तक शुरू नहीं हुए और सुधार करने की जहां आवश्यकता थीं, वहां सुधार हुआ नहीं। दुर्भाग्य से भांकरोटा जैसी घटनाएं हुईं क्योंकि हम उसको देख नहीं पाए। हम सब वहां से आते-जाते इस चीज को महसूस भी करते थे, सहन भी करते थे, परंतु उस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। घटना होने के दस दिन के बाद ही वहां पर सड़कें चौड़ी हो गयीं। अगर सरकार की मंशा हो तो क्या उन कामों को सही तरीके से नहीं किया जा सकता। सही समय पर बजट इम्प्लीमेंटेशन, बजट का फॉलो-अप होना चाहिए तब आप लोगों की जिम्मेवारी पूरी होगी।

वी.आई.पी.मूवमेंट्स, मैं इस बारे में भी सोचता हूं कि पहले शासक होते थे, सी.एम. वगैरह रोड से जाते थे। अब 50 किलोमीटर जाने के लिये भी आजकल मुख्य मंत्री हैलिकॉप्टर ही इस्तेमाल करेंगे तो जनता से जुड़ाव इतना ही रह जाएगा। मेरी तो सलाह है आप मंत्रियों को, मुख्य मंत्रीजी को, कि जितना जनता के बीच सड़क पर रहोगे, उतनी जानकारी आपको ज्यादा मिलेगी और जनता के लिये सुधार होने की संभावना ज्यादा रहेगी, जनता से आपको फीडबैक मिलेगा।

बजट में घोषणाएं कीं। आप कहते हैं कि बजट की घोषणाएं हमने पूरी कर दीं। मैं तो एक उदाहरण देना चाहता हूं कि भीनमाल में उप-जिला अस्पताल डिक्लेयर हुआ मेरे विधान सभा क्षेत्र में, अभी तक एक भी डॉक्टर नहीं लगा उप जिला अस्पताल के अनुसार। सिर्फ जमीन अलॉट हुई है। जब अस्पताल है तो डॉक्टर्स तो लग सकते हैं न। वह बरसों पुराना

सेठों का बनाया हुआ है। परंतु अभी तक डॉक्टर नहीं आये हैं वहां पर।

अब एक महत्वपूर्ण बात ई.आर.सी.पी. की कहना चाहता हूं। आप उसके लिये बड़ी-बड़ी शाबाशी लेने में लगे हुए हैं। यहां कई मंत्री बिराजे हुए हैं, इनमें कई पश्चिमी राजस्थान से भी आते हैं। पश्चिमी राजस्थान के लिये भी आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। माही डैम के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि माही डैम का सारा पानी गुजरात इस्तेमाल करता है और खंभात की खाड़ी में जा रहा है। सारा कल्याण गुजरात के लोगों का हो रहा है तो क्यों नहीं हम उस माही के प्रोजेक्ट को बढ़ावा दें ताकि इस पश्चिमी राजस्थान में उसका फायदा मिल सके।

इसी तरह से नर्मदा नहर में गुजरात ने किस तरह से सुजलाम्-सुफलाम् करके कच्ची नहरें बनाकर पूरे गुजरात का कल्याण किया है। अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार है। बड़ी बातें होती हैं, तो लाइए, चार साल बाद हम भी शाबाशी देंगे अगर इस तरह की योजनाएं आप लोग लेकर आएंगे।

पानी की, जल जीवन की बातें आती हैं। मैं तो आपको कहना चाहूंगा कि जल जीवन में भीनमाल विधान सभा क्षेत्र में 2013 में पानी की जो घोषणा हुई, आज 2024 चल रहा है। आपकी सरकार आयी-गयी, हमारी भी सरकार आयी-गयी और वापस आपकी सरकार आ गयी, अभी तक उस पानी का कोई पता नहीं। अब पता नहीं घर-घर मीठे पानी का जल तो कब पहुंचेगा?

इसी तरह से हमारे वहां एक डैम है, वह डैम 2003 में बना था और आज दिन तक उस पानी से सिंचाई नहीं हुई है। वहां पानी भरा पडा रहता है। डाउन स्ट्रीम की नालियां सूख गयीं। मंत्रीजी, वहां पर पानी काम नहीं आ रहा है और उस पानी का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, फिर हम शाबाशी लेने की बातें करें।

राजस्थान में राइजिंग राजस्थान की बहुत बातें हुईं। चलो, उम्मीद करते हैं आपके पास चार साल हैं। जैसाकि भाटी साहब ने आंकड़ों की बातें कीं, मैं तो इतना बड़ा बिजनेसमैन भी नहीं हूं कि आंकड़े गिनकर बता सकूं। पर चार साल बताएंगे क्योंकि हर सरकारें अपने टैन्योर में इस तरह के समारोह करती हैं और उसका नेट रिजल्ट कितना रहता है, वह देखने की बात है। उसके लिये तो इतना ही मेरा कहना है कि ईज ऑफ बिजनेस हम करेंगे तो लोगों को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित कर पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ा मामला मैं उठाना चाहूंगा। मैं कृषि की बात करूंगा। आप राइजिंग राजस्थान में कृषि के क्षेत्र को भी जोड़ो। हमारे पश्चिमी राजस्थान से सारा माल जीरा, वगैरह जितना भी होता है वह गुजरात जाता है। हमारे यहां की मंडियां भीलमाल हो, रानीवाड़ा हो, वहां सैलरी देने के भी सरकार के पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं इस बारे में सोचा जाता है? क्या इससे बिजनैस डवलप नहीं होगा?

नगरपालिकाओं में मास्टर प्लान बन गये। नगर पालिका के मास्टर प्लान में दो-तीन साल पहले अप्रूव्ड कॉलोनियों में अब नीचे बैठे हुए लोग उसके अन्दर रास्ते निकाल रहे हैं। आपकी सरकार ने पिछले बजट में कहा था कि इसको हम इजी करेंगे, डिसेंट्रलाइज करेंगे,

जयपुर फाइल नहीं आए, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होगी। अभी तक तो मुझे उस चीज का अता-पता नहीं है, अगर कोई कर सकें तो मुझे बता दें।

सबसे बड़ी चीज, जो मैं सरकार की नजर में लाना चाहता हूं, वी.सी. से तो आप छुटकारा दिलाओ। जब देखो यह छोटे कर्मचारी, पटवारी, ग्राम सेवक को फोन करते हैं वह कहते हैं कि वी.सी. में बैठे हैं। सारे दिन अधिकारी उस वी.सी. में बैठे रहते हैं। इससे जनता को तकलीफ होती है, जनता के काम नहीं होते हैं। इस तरफ भी सरकार ध्यान दें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री संजीव कुमार।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय सभापति महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपनी बात रखने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। 31 जनवरी, 2025 को माननीय राज्यपाल महोदय हमारे बीच पधारे और 8 करोड़ राजस्थानियों की सुख-समृद्धि की कामना के साथ उन्होंने इस पवित्र सदन में अपना अभिभाषण पेश किया, हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। पिछले तीन दिन से पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी। निश्चित तौर से राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री, माननीय श्री भजनलाल जी की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। पहले ही साल में समिट का आयोजन करके 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश की एक मजबूत बुनियाद रखी गयी। निश्चित तौर से एक साल का यह कार्यकाल हमारी सरकार का बेमिसाल रहा है। हमारा राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है। किसानों को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाये हैं।

jyg/rtm/06.02.25/19.30/4d

राजस्थान की पूर्व मुख्य मंत्री, श्रीमती वसुन्धरा राजे जी के नेतृत्व में तत्कालीन राज्य सरकार ने पूर्वी राजस्थान को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना का जो विजन प्रस्तुत किया था, उस ईआरसीपी योजना को धरातल पर उतारने का कार्य करके हमारी वर्तमान सरकार ने यह साबित कर दिया है कि हमारी सरकार वादों पर नहीं, बल्कि काम करने में विश्वास करती है। माननीय प्रधान मंत्री, हमारे देश के यशस्वी नेता, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की पहल पर हमारी सरकार हरियाणा तथा राजस्थान के मध्य हुए समझौते के आधार पर सीकर, चूरू और झुंझुनूं जिलों में यमुना का पानी लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

माननीय सभापति महोदय, पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की किसानों के हित में एक शानदार योजना रही है। हमारी राज्य सरकार ने किसान हित में मजबूत कदम बढ़ाते हुए इस योजना के साथ मुख्य मंत्री किसान सम्मान निधि योजना को जोड़कर इस योजना को प्रारम्भ करके प्रदेश के किसानों

को अतिरिक्त दिये जाने का प्रावधान किया है, यह प्रदेश के किसानों के हित में एक शानदार कदम है।

माननीय सभापति महोदय, सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत गोपालक परिवारों को प्रति परिवार एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, पंजीकृत गोशालाओं को देय अनुदान में भी दस परसेंट की बढ़ोतरी करके गोमाता की सेवा करने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया। पशु पालकों को सम्बल देने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ये किसान और पशु पालकों के हित में एक शानदार कदम रहा है। किसानों के हित की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान की वर्तमान सरकार ने वर्ष 2024-25 के दौरान गेहूं के समर्थन मूल्य पर 125 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देकर किसानों को सम्बल प्रदान करने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, इन सारी योजनाओं से साबित होता है कि राजस्थान की वर्तमान भजन लाल जी की सरकार किसान के हित में लगातार काम कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने एक सोच के साथ कि देश के हर घर में शुद्ध पानी नल के द्वारा पहुंचायेंगे, शुद्ध जल देने का काम करेंगे, इस तरह की एक महत्वाकांक्षी योजना देश के यशस्वी प्रधान मंत्रीजी ने चालू की थी लेकिन पिछली सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते लगातार इस योजना को प्रारम्भ करने में भी अनावश्यक विलम्ब किया गया और इसके साथ-साथ पिछली सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते मैं स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूं कि राजनीतिक द्वेषता की वजह से जनता के साथ भेदभाव किया गया और अनेक ढाणियों को घरों को पेयजल से वंचित रखने का काम करके पिछली कांग्रेस की सरकार ने जनता के हितों के साथ कुठाराघात करने का काम किया है। इस जल जीवन मिशन योजना में भारी अनियमितताएं हुईं, भारी भ्रष्टाचार हुआ, अमानक सामग्री का इस्तेमाल हुआ, मैं हमारे पीएचईडी मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा जो यहां पर विराजमान हैं, इस तरह के जो मामले विशेषकर हमारे जिले में खूब हुए, इनकी जांच करवायी जाये।

माननीय सभापति महोदय, निश्चित तौर पर अब मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधान मंत्रीजी का कि जल जीवन मिशन योजना के समय को 2028 तक बढ़ाने का जो काम किया है, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जिले से, हमारे क्षेत्र से जो वंचित रह गये हैं, जो घर वंचित रह गये, ढाणियां वंचित रह गयी, उनके लिये जो रिवाइज स्कीम बन कर आ रही है उनको आप शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का काम करेंगे ताकि वंचित घरों को, वंचित ढाणियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की माननीय देश के प्रधान मंत्रीजी की सोच को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर सके।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस की गत सरकार ने युवा वर्ग और नौजवानों के हितों के साथ कुठाराघात किया। हमारे राजस्थान की परीक्षा प्रणाली का एक बहुत बड़ा नाम देश भर में होता था कि राजस्थान में साफ-सुथरी परीक्षाएं होती हैं, आरपीएससी का बहुत बड़ा

नाम पूरे देश के अन्दर था, लेकिन पिछली सरकार ने निश्चित तौर से राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को धूमिल करने का, उसको दागदार करने का काम किया है। पेपर लीक और नकल की घटनाओं से प्रदेश की परीक्षा प्रणाली से हमारे नौजवानों का विश्वास उठ गया है, हमारी वर्तमान सरकार के सख्त निर्णयों से पेपर लीक व नकल माफिया पर अंकुश लगा है, न केवल अंकुश लगा है बल्कि अनेक पेपर माफियाओं को जेल में भेजने का काम भी किया है। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान सरकार के समय में यह भी कहना चाहूंगा कि पेपर लीक के कारण एक भी प्रतियोगी भर्ती परीक्षा स्थगित नहीं हुई।

माननीय सभापति महोदय, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पांच-पांच नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये हैं, इनके साथ-साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का भी मान और सम्मान बढ़ाने के लिए उनके मानदेय में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। घुमंतू, अर्द्ध घुमंतू, गाडिया लोहार और कालबेलिया वर्ग के लोगों को प्रदेश में भूखण्ड आवंटित कर उनको सम्बल प्रदान करने का काम किया है। हमारी सरकार ने प्रदेश में 51 राजकीय विद्यालयों का नामकरण अमर शहीदों के नाम पर करके शहीदों के परिवारों का सम्मान किया है। वरिष्ठ नागरिकों की धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना संचालित की जा रही है। अब तक योजना में 40 ट्रेनों का संचालन का 33 हजार से अधिक यात्रियों को विभिन्न तीर्थ स्थलों की योजना करवायी गयी है। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, समय का आप बता रहे हैं।

श्री सभापतिः आपका समय दस मिनट अलोटेड है, सूची बहुत लम्बी है।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय सभापति महोदय, कर्जा माफी के नाम पर, बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर कांग्रेस ने जनता को भ्रमित करके पिछले पांच साल यहां शासन किया। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले, यहां तक तो ठीक है लेकिन इनके नाम पर हमारे भादरा विधान सभा क्षेत्र में बालिका माध्यमिक विद्यालयों को बंद करने का काम पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने किया है, इसकी भी समीक्षा की जानी चाहिए।

श्री सभापतिः श्री पितराम सिंह काला।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय सभापति महोदय, भादरा विधान सभा क्षेत्र में 14 बारानी गांवों को और इसके साथ-साथ नोहर विधान सभा क्षेत्र के गांवों को सिंचाई से जोड़ने का पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 100 करोड़ रुपये का जो बजट प्रावधान किया लेकिन आज तक वो 100 करोड़ के बजट का पता नहीं चला, न वित्तीय स्वीकृति हुई, न प्रशासनिक स्वीकृति हुई, न तकनीकी स्वीकृति हुई, यह मैं कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के दिये गये अभिभाषण के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में बोलने के लिए मुझे सुअवसर दिया इसके लिए दिल की

गहराइयों से धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो 44 पेज का है, उसमें 168 बिन्दु हैं, उनमें अनुसूचित जातियां जिनकी पापुलेशन इस प्रदेश में 17 प्रतिशत है, एक शब्द भी नहीं कहा, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

MLS/RTM/06.02.2025/19:40/4e

मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग कहेंगे भी क्यों। ये वे लोग हैं, जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की शव यात्रा निकाली थी। इन्हें एससी, एसटी के लोगों से नफरत है, इसलिए उनके कल्याण की बात न तो कभी इन्होंने की है और न आगे करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के गृह मंत्री जी, जिन्होंने बार-बार केन्द्र-केन्द्र कहा कि डॉ. अम्बेडकर, अम्बेडकर, अम्बेडकर, अम्बेडकर, अम्बेडकर, अम्बेडकर, एक बार नहीं 6 बार की यह फैशन बन गयी है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यह अम्बेडकर कोई फैशन नहीं है। भगवान बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज और क्या है कि इनकी जो विचारधारा है, यह इस देश में विचारधारा का संघर्ष है, विचारधारा को आगे बढ़ानी की बात है, यह डॉ. भीमराव अम्बेडकर और उसके उत्तराधिकारी करना चाहते हैं, आप लोग यह नहीं चाहते कि वह विचारधारा इस देश में, इस प्रदेश में फैले और अनुसूचित जाति का कल्याण हो।

अभी पैरा संख्या 4 में माननीय प्रधान मंत्री का आपने जिक्र किया है कि मजबूत हाथों में देश सुरक्षित है। आज का मैं भास्कर और राजस्थान पत्रिका पढ़ रहा था, उनके अन्दर बड़ी-बड़ी हैडिंग्स छपीं, मैं साथ ही लेकर आया हूं और यह लिखा है कि भारतीयों को अमेरिका की सेना के विमान से किस प्रकार से हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालकर यहां भेजा गया है। इससे शर्मनाक वाकया सन् 1947 के बाद देश आजाद होने के बाद से आज तक नहीं हुआ। इससे अच्छा तो जिम्बाब्वे था, जिसने यह कह दिया कि हम हमारे नागरिकों को ससम्मान वापस लेकर आएंगे और उन्होंने अमेरिका के उस विमान को अपने देश में नहीं उतरने दिया, अपने नागरिकों को सम्मान सहित अपने विमान से लेकर आये। हमारे देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा?

आगे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप युवाओं की परीक्षा की बात करते हैं। आप लोग स्वीकार नहीं करते कि परीक्षा सही हुई है। अभी जो पिछले दिनों आरएएस की परीक्षा हुई थी, नवलगढ़ में बलवन्तपुरा गांव है, उस स्कूल में प्राइवेट का सेंटर था। वहां प्रश्न पत्र खोले गये। उस कक्षा में, जिसमें खुला लिफ़ाफ़ा गया, वहां के विद्यार्थियों ने यह कह दिया कि हम परीक्षा नहीं देंगे और 10 के 10 सारे परीक्षार्थी बाहर निकल गये। वहां के कलक्टर रामावतार मीणा को आदेश निकालना पडा और एडीएम को जांच दी गयी कि किस प्रकार से पेपर आउट हुआ है। इसके बावजूद भी आप पेपर आउट नहीं मान रहे हैं, यह आपकी

हठधर्मिता नहीं तो और क्या है?

इसके अलावा, आपके पैरा संख्या 7 में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बारे में लिखा है। जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, उन्हें आप जमीन फ्री में दे रहे हैं, लेकिन आपकी यूआईटी के द्वारा जो उद्योगपतियों को व्यक्तिगत रूप से जमीन अलॉट कर रहे हैं, वह डीएलसी की डबल रेट से अलॉट कर रहे हैं और उसके ऊपर भी 20 परसेंट सरचार्ज लगा रहे हैं। यह किस प्रकार का न्याय है? आप खुद सदन में बैठे हैं, इस पर विचार-विमर्श करें।

इसके अलावा, यमुना जल समझौता है। इसके अन्दर बार-बार आपके द्वारा जिक्र किया जा रहा है कि सीकर, झुंझुनूं और चूरू को पानी उपलब्ध कराया जायेगा। मैं पिलानी से बिलॉन्ग करता हूं और आपको यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा पानी की कहीं किल्लत है तो वह पिलानी के अन्दर है। आपने 17 तारीख को फरवरी के अन्दर समझौता किया, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी दौरा किया और कहा कि हम 4 महीने के अन्दर डीपीआर बनाएंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं, यहां मंत्री महोदय भी बैठे हैं, आज तक वह डीपीआर नहीं बनी है, 14 महीने हो गये। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का क्या होगा?

इसके अलावा, वहां जो किसान हैं, यमुना जल की मांग के लिए वे 14 महीने से धरने पर बैठे हैं। आप कम से कम डीपीआर तो बनाएं, जिससे लोगों को यह मालूम पड़े कि आगे क्या होना है और क्या नहीं। हालांकि, इसमें होना कुछ नहीं है। केवल और केवल यह समझौता गुमराह करने वाली बात है। हरियाणा की सरकार ने यह कहा है कि यदि बरसात के समय बाढ़ आयेगी और अवशेष पानी बचेगा तो हम देंगे, अन्यथा पानी नहीं देंगे। आप इसका हर बार गुणगान कर रहे हैं कि हमने यह कर दिया, यह कर दिया। इसमें कुछ नहीं होना है। यह प्रदेश का दुर्भाग्य है।

माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं। पिछली बार जब बजट की बात हुई थी तो मैंने इसी सदन में कहा था कि पिलानी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। जिस प्रकार से बीमार आदमी होता है, उसके अन्दर सबसे सीरियस आदमी होता है उसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है, तो पिलानी की स्थिति पानी के अन्दर आईसीयू के तहत है। माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा था कि आपके पिलानी विधान सभा क्षेत्र में जितने ड्राइड ट्यूबवैल्स हैं, उनके अगेंस्ट मैं सारे सैंक्शन कर दूंगा तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूं, 6 महीने के अन्दर आपने एक ट्यूबवैल सैंक्शन नहीं किया? इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है इस प्रदेश के लिए?

माननीय मंत्री महोदय, इसी के साथ, आपने जो 5 ट्यूबवैल्स विधान सभा क्षेत्र के अन्दर दिये थे, मेरे यहां आज तक एक ट्यूबवैल आपने सैंक्शन नहीं किया। यह बड़े शर्म की बात है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि पिलानी की जनता पानी के अभाव में पलायन को मजबूर है। आप प्राथमिकता से इस पर कार्य करें। आपने वहां मीटिंग की थी।

सीकर, चूरू, झुंझुनूं के सारे अधिकारियों को बुलाया था और यह कहा था कि मुझे 3 दिन में डीपीआर बनाकर दें। ईस्ट पिलानी के कुम्भाराम से जोड़ने का मैं काम करूंगा। धन्य हैं वे अधिकारी जिन्होंने 3 दिन में 35 करोड़ 83 लाख रुपये की वह डीपीआर बनाकर माननीय मंत्री महोदय को दे दी, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तक उस डीपीआर पर कोई काम नहीं हुआ।

इस सदन में कथनी और करनी में कितना अन्तर है, आप लोग देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने जो घोषणाएं की थीं, उसका 85 प्रतिशत पूरा कर दिया। आप खुद देख सकते हैं कि एक परसेंट कार्य इन्होंने नहीं किया है। आज वहां की जनता पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रही है। ट्यूबवैल्स दिन-प्रतिदिन सूखते जा रहे हैं। गांव में पीने के लिए पानी नहीं है। सभापति महोदय, ढाणियों में हजार-हजार रुपये में एक टैंकर आता है तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि उस क्षेत्र की इस समस्या को प्राथमिकता से लिया जाये तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

सभापति महोदय, मंत्री जी यहां बैठे हैं, आपके माध्यम से मैं पानी की बात करना चाहूंगा। अमृत-2 योजना के अन्दर इन्होंने यह कहा था कि मैं पिलानी और चिड़ावा के लिए 10 करोड़, 8 करोड़ की योजना सैंक्शन करता हूं। अभी 6 महीने व्यतीत होने के बाद में 1 रुपये का कार्य पिलानी विधान सभा क्षेत्र में नहीं किया है। इससे बड़े दुर्भाग्य और शर्म की बात क्या हो सकती है? पैरा संख्या 40 में यह लिखा गया है कि झुंझुनूं में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कर दी। जब आपकी सरकार बनी थी, उससे पहले 50 परसेंट कार्य तो हो गया था। कम से कम राज्यपाल महोदय से असत्य तो मत बुलवाओ सदन के माध्यम से। पूरे राजस्थान की जनता सुन रही है।

पैरा संख्या 60 के अन्दर किसानों की खुशहाली की बात की गयी है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पिलानी विधान सभा क्षेत्र में किसानों को फसल का जो मुआवजा दिया जाता है, वह अब तक भी बाकी पड़ा है, जल्दी से जल्दी वह मुआवजा दिया जाये। रिश्वत की बात। खेतड़ी एसडीएम 20 बीघा रिश्वत लेते पकड़ा गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का क्या होगा? इतनी-इतनी बड़ी रिश्वतें चल रही हैं। किसान का इंतकाल बिना पैसे के नहीं होता है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

पैरा संख्या 96 के अन्दर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गयी है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा। शिक्षा मंत्री महोदय, सुनिये यहां पर। आपने जब यहां जोइन किया था शिक्षा मंत्री के रूप में तो यहां नामांकन 99.30 लाख था और आज वह घटकर 75 लाख रह गया है। 24 लाख का नामांकन घट गया। इससे बड़ी विफलता इस सरकार की कोई हो नहीं सकती। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। यशस्वी

प्रधान मंत्री भाई नरेन्द्र जी मोदी ने और हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी की डबल इंजन की सरकार ने जो भी वादे किये हैं, उन्हें निभाया है।

mkd/rtm/06.02.2025/19:50/4f

हमारी सरकार वादों पर नहीं, बल्कि काम करने पर विश्वास करती है। पूर्वी राजस्थान के कैनाल प्रोजेक्ट ने यह सिद्ध किया है कि पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे के नेतृत्व में तत्कालीन राज्य सरकार ने पहली बार इस योजना के माध्यम से पूर्वी राजस्थान को सरसब्ज बनाने का महत्वाकांक्षी विजन प्रस्तुत किया था, लेकिन दुर्भाग्य से विगत सरकार के समय राजनीतिक लाभ के कारण इस योजना को अटकाया गया। हमारी सरकार ने इस रामसेतु जल लिंक परियोजना संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल परियोजना को धरातल पर क्रियान्विति करने की दिशा में मजबूत पहल की है।

राज्य सरकार की प्रथम वर्षगांठ पर माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सानिध्य में इस परियोजना के मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट का आदान प्रदान किया गया था। इस सुअवसर पर प्रदेश की जीवनदायिनी नदियों पार्वती-कालीसिंध और चम्बल के पवित्र जल को रामजल सेतु कलश में प्रवाहित किया गया। परियोजना के साकार होने से समृद्धि और खुशहाली के नये युग की शुरुआत होगी। पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी की पेयजल जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। राजस्थान सरकार मध्य प्रदेश के साथ मिलकर इस परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए संकल्पित है और 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर परियोजना का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

हमारी सरकार ने अब तक 1 लाख 10 हजार कृषि कनेक्शन किसानों को दिये हैं तथा 5 लाख 6 हजार से अधिक घरेलू कनेक्शन जारी किये गये हैं।

बजट में हमारी सरकार ने 5 वर्षों में 4 लाख राजकीय नौकरियां देने की घोषणा की है। मुझे प्रसन्नता है कि 1 वर्ष में 59 हजार 236 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 1 लाख 72 हजार 990 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है, जिससे स्पष्ट है कि हमारी सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। बीते एक वर्ष के दौरान बारां, बांसवाड़ा, झुंझुनूं, नागौर एवं सवाई माधोपुर में राजकीय क्षेत्र में कुल 5 नये मेडिकल कॉलेज खोले गये हैं। निजी क्षेत्र में जोधपुर में 2 तथा कोटा में 1 नया मेडिकल कॉलेज प्रारम्भ किया गया है। इन नये कॉलेजों में एमबीबीएस की 850 सीटों की बढ़ोतरी हुई है।

सरकार का एक साल, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे भजन लाल जी ने ऐसी सरकार दी है, जिसके तहत एक साल में ऐसे कार्य किये हैं, जो हमेशा राजस्थान याद रखेगा। जो भी बजट दिया है, वह क्रियान्विति की ओर अग्रसर है। अभी हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि सरकार को बने 14 महीने हो गये हैं, लेकिन बजट को कितना समय हुआ है, बजट को मात्र 6 या 7 माह हुए हैं। अब 7 माह में, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में उन्होंने कोई भेदभाव नहीं

किया, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को बजट दिया है, चाहे पेयजल के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में बजट दिया है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं पिछली बार विपक्ष में था, आपकी सरकार में, आपने हमें एक रुपये का भी बजट नहीं दिया और जब हाड़ौती में बजट दिया जाता था तो शान्ती धारीवाल द्वारा ऐसी दीवार बना दी जाती थी कि वह बजट झालावाड़ पहुंचता ही नहीं था। आज मुझे हमारे मुख्य मंत्री जी पर बड़ा गर्व है कि उन्होंने भेदभाव नहीं किया और प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में बजट गया।

विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि आप कहते हो कि कुछ नहीं किया तो आप गिन लो हर काम हमारी सरकार ने किया है। सरकार का एक साल, बेमिसाल रहा है। संकल्प पत्र की 65 फीसदी घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। गरीब परिवारों के लिए 450 में सिलेंडर दिया, पेट्रोल-डीजल में 2 प्रतिशत वैट कम करके पेट्रोल-डीजल सस्ता किया। पीएम किसान निधि को 6 हजार से बढ़ाकर 8 हजार रुपये किया। शेखावाटी पेयजल समस्या के लिए यमुना जल समझौता, सरकार द्वारा किया गया है। पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों के लिए पीकेसी, ईआरसीपी समझौता किया गया है, पेपर लीक की जांच के लिए एसआइटी का गठन किया गया है, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है, मीसा बंदियों के लिए पेंशन की शुरुआत की गई है और प्रधान मंत्री मातृत्व वन्दन योजना की राशि भी सरकार द्वारा बढ़ाई गई है। लखपति दीदी योजना की पहल हमारी सरकार ने की है।

ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रिकॉर्ड एमओयू किये हैं। पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया, जो कि पहली बार पहले की सरकारों से ज्यादा सफल रहा है। राइजिंग समिट में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, जो जल्दी ही धरती पर उतरते हुए दिखाई देंगे।

प्रवासी राजस्थानियों के सम्मान के लिए प्रवासी दिवस मनाने की घोषणा हमारी सरकार ने की है। युवाओं के रोजगार को प्राथमिकता में रखते हुए दो वर्ष का परीक्षा कलेंडर पहले ही जारी किया गया है। आपकी सरकार में तो पेपर लीक हुए हैं।

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर परण तक एक लाख रुपये देने की घोषणा हमारी सरकार ने की है। राजस्थान को आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए एक साथ 10 पॉलिसियों को मंजूरी हमारी सरकार ने दी है व अन्य विभागों में अनेक अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है, पहले साल ही उपलब्धियों में 1.24 लाख से अधिक नौकरियां। पेपर लीक माफिया के ऊपर कार्रवाई।

पूर्वी राजस्थान नई परियोजना के सम्बन्ध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। सरकार ने अपने पहले साल में ही जयपुर में निवेश शिखर सम्मेलन किया और 34 लाख करोड़ के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये, यह राजस्थान की अर्थव्यवस्था को बढ़ाकर 350 अरब डॉलर करने के सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में बढ़ा काम माना जा रहा है। जिससे सरकार के इस साल के बजट में पूंजीगत विभाग में 35 प्रतिशत की वृद्धि होगी और

आप कहते हो कि सरकार ने कुछ नहीं किया।

अभी तो और बाकी है, लेकिन चार साल अभी और बाकी हैं। चार साल में, आप भी तो हमारी तरफ कहते थे, मैं आपकी तरफ और उधर भी कहूंगा। माननीय सभापति महोदय, अभी तो सरकार के चार साल बाकी हैं और एक साल में जितनी भी घोषणाएं सरकार ने की हैं, वे धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही हैं। इन चार सालों के अन्दर आप और हम यहीं हैं। हम वापस अगली बार भी इस ओर बैठेंगे और आप वापस उस ओर बैठेंगे। यह मैं आपसे वादा कर रहा हूं, क्योंकि धरातल पर उतरती हुई जो योजनाएं नजर आएंगी, जनता के बीच हम जायेंगे और जनता के हर वादे को पूरा करेंगे और हमारी भजन लाल सरकार कृत संकल्प है। जय हिन्द, जय भारत, जय-जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्रीमती सुशीला।

श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (नोखा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की 16वीं विधान सभा के तृतीय सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो उपलब्धियां पढ़वाई गई हैं, वैसा धरातल पर कुछ नहीं है। विगत एक वर्ष में इस पर्ची सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है, केवल जनता के साथ छलावा किया गया है। प्रदेश की जनता आज अपने आपको ठगा-सा महसूस कर रही है, इस सरकार ने केवल हमारी विगत सरकार की योजनाओं का नाम बदलने के सिवाय कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है और ना ही प्रदेश के विकास के लिए कोई नई जनकल्याणकारी नीति व योजना बनाई है।

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी।

Bhs/Rtm/06.02.25/20.00/4g

श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (नोखा): अभिभाषण में कहा गया है कि सरकार ने आधारभूत चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए कुल 12 चिकित्सालयों को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया है। इस सन्दर्भ में मेरा कहना है कि यह चिकित्सालय तो हमारी विगत कांगेस सरकार ने ही क्रमोन्नत कर दिये थे। वर्तमान सरकार ने तो अपनी वाहवाही लूटने के लिए परिवर्तित बजट में इनकी पुन: घोषणा कर डाली।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा के जिला चिकित्सालय की बात करूं तो इसको क्रमोन्नत करने की घोषणा तो पूर्व में ही कांग्रेस की गहलोत सरकार की बजट घोषणा 2021-22 में की जा चुकी थी। उक्त बजट घोषणा के अनुसरण में जिला चिकित्सालय, नोखा के लिए जारी वित्तीय स्वीकृति के क्रम में जिला चिकित्सालय, नोखा के भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 13.9.2023 को हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जारी कर दी थी। इस स्वीकृति के अनुसरण में जिला चिकित्सालय, नोखा के भवन निर्माण हेतु अल्पकालिक ई-टेंडरिंग निविदा भी 14.2.2024 को जारी हो चुकी थी परन्तु यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण व शर्मनाक है कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उक्त निविदा को

महज एक शिकायती पत्र के आधार पर अपरिहार्य कारणों का हवाला देकर अपने पत्र क्रमांक 4566 दिनांक 5.3.3024 द्वारा निरस्त कर दिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस सरकार के आधारभूत चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए यह उपलब्धि हासिल की है।

सभापति महोदय, अभिभाषण में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 2699 करोड़ रुपये की बीमा क्लेम की वितरण की बात कही गयी है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगी कि राज्य का किसान बीमा क्लेम तो दूर की बात है अब अपनी फसल खराबे के सर्वे कराने के लिए भी तरस रहा है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा सहित पूरे बीकानेर जिले के किसानों की बात करूं तो हमारे यहां के किसानों की खरीफ 2024 के अन्तर्गत मूंगफली व अन्य फसलों को खड़ी फसल में अतिवृष्टि के चलते फसल की कटाई के पश्चात चक्रवात के चलते भारी नुकसान हुआ है। बीकानेर जिले के कई पटवार मण्डलों में सरकार के सम्बन्धित विभागों ने इन किसानों को फसल खराबे की रिपोर्ट तक तैयार नहीं की और न ही इन्हें फसल खराबे का मुआवजा दिया गया है। बीकानेर जिले के किसान खरीफ 2024 के अन्तर्गत मूंगफली की फसल कटाई के पश्चात चक्रवात के चलते बरबाद हुई फसल के फसल खराबे की सूचना बीमा कम्पनी को दर्ज करवाने का प्रयास करते रहे परन्तु बीमा कम्पनी ने इनके फसल खराबे की सूचना तक दर्ज नहीं की। ऑनलाइन सूचना दर्ज कराने के लिए कई दिनों से किसान एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के दूरभाष नम्बर 20852150 व कृषि कृषक पोर्टल हैल्प लाइन नम्बर 14447 पर दूरभाष से सम्पर्क करते रहे लेकिन उक्त नम्बरों पर इनके फसल खराबे की शिकायत दर्ज नहीं की गई।

सभापति महोदय, अभिभाषण में राजीविका परियोजना के तहत लाखों महिलाओं को आजीविका गतिशील से जोड़ने की बात कही गई। सच्चाई यह है कि इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आते ही राजीविका में कार्यरत राजस्थान प्रोफेश्नल रिसोर्स पर्सोनेल की सेवाएं समाप्त कर दी। वह कार्मिक योजना हितार्थ स्वयं सहायता समूह बनाने में अपना अहम रोल अदा करते रहे थे। अभिभाषण में युवाओं में खेल प्रतिभाओं को निखारने व खेल कूद को प्रोत्साहन देने की बात कही गयी है। इस सन्दर्भ में सरकार की उपलब्धि यह रही कि इसने आते ही सर्वप्रथम हमारी विगत सरकार कांग्रेस सरकार ने जो राजस्थान क्रीड़ा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम 2017 के संशोधित नियम 2020 के तहत प्रदेश के राष्ट्रीय अन्तरराष्ट्रीय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिता में पदक विजेताओं व उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य सरकार की सेवाओं में बिना पारी नियुक्ति देने का काम शुरू किया था, उसको रोक दिया गया।

सभापति महोदय, अभिभाषण में युवाओं को रोजगार विगत एक वर्ष में 60,236 नियुक्तियां देने की बात कही गई है, जिन पदों पर ये नियुक्तियों की बात कर रहे हैं वे भर्तियां तो हमारी सरकार द्वारा निकाली गई थी। यह सरकार तो अभी तक अपनी भर्तियों की घोषणा ही कर रही है। युवाओं के रोजगार के सम्बन्ध में तो इनकी उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही प्रदेश की पांच हजार युवाओं की सेवाएं समाप्त कर उन्हें बेरोजगार करने

की रही है।

सभापति महोदय, अभिभाषण में प्रदेश में राज्य सौर ऊर्जा संयंत्र सोलर संयंत्रों के स्थापित करने की बात कही गयी। इन संयंत्रों के चलते हमारे बीकानेर जिले में रेगिस्तान के वृक्ष खेजड़ी की अन्धाधुन्ध कटाई हो रही है। वह सोलर कम्पनियों द्वारा की जा रही है। यदि राज्य सरकार इस कटाई को तत्काल रुकवाने का काम नहीं करेगी तो पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस खेजड़ी को बचाने के लिए अमृता देवी जैसों ने अपने जीवन को न्योछावर कर दिया और उसी खेजडी को आज हम सब काटने में लगे हुए हैं।

सभापति महोदय, किसानों को जमीन का मुआवजा मिलना चाहिये जो यह सौर प्लांट चल रहे हैं वो किसान धरना दे रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आपसे विनती है कि उन किसानों को मुआवजा दिलाया जाये। धन्यवाद।

सूचना

जयपुर स्थित वार्ड नं. 78 में नगर निगम की निर्माणाधीन दीवार गिरने से कारित क्षति

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन है। आदर्श विधान सभा क्षेत्र में नगर निगम की एक दीवार बन रही थी दिल्ली रोड पर नागतलाई में वार्ड 78 में और वह दीवार कुछ मकानों पर गिर गयी है तो मैं गुजारिश करता हूं कि इस पर तुरन्त एक्शन लिया जाये। मंत्री महोदय बैठे हुए हैं और यू.डी.एच. का मसला है और नगर निगम की दीवार बनते हुए काफी सारे मकानों पर गिर गई, मकान क्षतिग्रस्त हो गये और ऐसी सम्भावना भी है कि कोई दब सकता है।

श्री सभापति: आ गया संज्ञान में। श्री कालूराम।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री कालूराम (डग): माननीय सभापति महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो हमारे राजस्थान में पिछली सरकार ने पांच साल में कुछ काम नहीं किया और जो एक वर्ष की सरकार है हमारी भजन लाल जी की सरकार ने जो महत्वपूर्ण कार्य किये हैं वो बहुत सारी बातें इसमें कही गई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्वी ईस्ट कैनाल हमारी पूर्वी राजस्थान नहर हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी सिंधिया ने इसको लागू करने के लिए एक योजना बनाई थी। बाकी कांग्रेस गवर्नमेंट के आने के बाद इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया और बार-बार गहलोत साहब कहते हैं कि हम चिट्ठी लिख रहे हैं केन्द्र में मोदी जी को और चिट्ठी के माध्यम से ईस्ट कैनाल को हम शुरू करेंगे। बाकी पांच साल से इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इससे राजस्थान के किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ। पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों का यह प्रोजेक्ट अब सम्माननीय भजन लाल जी ने बनाया है। इसमें 17 जिलों को इसका फायदा मिलेगा और इस कालीसिंध चम्बल परियोजना से करीब चार लाख हेक्टेयर

भूमि सिंचित होगी और तीन करोड़ आबादी को इससे पेयजल की सुविधा मिलेगी। इस परियोजना के बनने से पूरे राजस्थान में खुशहाली आयेगी और राजस्थान में पानी का हम देख रहे हैं कि राजस्थान सूखाग्रस्त रहता है हमेशा। बाकी भगवान की कृपा से इस साल बारिश भी अच्छी हुई है और यह योजना चालू होने के बाद राजस्थान एक बहुत हरा भरा राजस्थान बनेगा और बहुत ही खुशहाली राजस्थान में आयेगी।

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने एक लाख दस हजार से अधिक कृषि कनेक्शन अभी दिये हैं एक साल के अन्दर-अन्दर। ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले सालों में जो हम देखते थे कि 8-8 घंटे, 7-7 घंटे लाइट कटती थी। जब हम लाइटों के बारे में पूछते थे तो बताते थे कि कोयला खतम हो गया। हमारे पास कोयला नहीं है। एक ही बात कहते थे कि कोयला नहीं है। आज लाइट की यह स्थिति है कि पूरे राजस्थान में किसानों को 6 घंटे लाइट मिल रही है और कई जिलों में दिन में लाइट मिल रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि 2027 तक पूरे राजस्थान में हम दिन में बिजली देंगे ताकि किसान रात में खेती और पाणत नहीं कर सकते इसलिये हमारा दिन में बिजली देने का पूरा विचार है।

Kas/rtm/06.02.2025/20.10/4h

हमारी पिछली सरकार ने किसानों को प्रोत्साहन देने के लिये जो छूट दी थी, उसको पिछली सरकार ने ढाई साल से बंद रखा और लास्ट में उन्होंने वह छूट लागू की। किसानों को अब नये कनेक्शन मिल गये हैं। विगत सरकार में कुसुम योजना चलाई गई थी। सम्माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने कुसुम योजना के माध्यम से किसानों को कनेक्शन देने के लिये कुसुम योजना चलाई थी, उस योजना को राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पूरी तरह फेल कर दिया और उस कुसुम योजना के माध्यम से कोई कनेक्शन नहीं हुए।

सभापति महोदय, जल जीवन मिशन के माध्यम से सम्माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 27 हजार करोड़ रुपये राजस्थान को दिये। उस जल जीवन मिशन की आज क्या हालत है। आज कई सदस्य कह रहे थे कि जल जीवन मिशन में पानी नहीं आ रहा, हमारे नल में पानी नहीं आ रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पांच साल में आपने जल जीवन मिशन के माध्यम से क्या किया? पांच साल आपकी सरकार थी, आपको पैसे मिले, लेकिन न तो आपने टंकी बनाई, न पाइप लाइन डाली और आंकड़े बताने के लिये कनेक्शन जारी कर दिये और उसका भुगतान हम आज उठा रहे हैं। आज हमारे कई ग्रामीण क्षेत्रों में पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने न तो टंकी बनाई और न ही पाइप लाइन डाली। इसमें ठेकेदारों ने इतना भ्रष्टाचार किया है, अब हमारी सरकार एक-एक करके उसका बदला लेगी। जल जीवन मिशन योजना एक बहुत बड़ी योजना सम्माननीय प्रधान मंत्री जी की थी। प्रधान मंत्री जी ने सोचा था कि गरीब किसानों को, गरीब लोगों को पानी मिले, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस योजना को पूरी तरह फैल कर दिया।

सभापति महोदय, किसानों के लिये हमारी सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं

चलाई हैं। किसानों के लिये इस बार हमारी सरकार ने ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये पीएम किसान योजना के तहत करीब 21,932 सौर ऊर्जा के पम्प स्थापित किये हैं। इसी प्रकार से कई क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के माध्यम से प्लांट लग रहे हैं, इससे किसानों को दिन में बिजली मिलेगी और इससे किसान खुशहाल रहेगा। पशु पालकों के लिये करीब 400 करोड़ रुपये देकर पशु मंगल बीमा योजना शुरू की है। पशु पालको के लिये नि:शुल्क मोबाइल वैन की शुरूआत की गई है, इसमें 1962 नंबर डायल करके किसान इसका लाभ उठा सकते हैं और इसमें करीब 3 लाख पशुओं का उपचार हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपको युवाओं के बारे में बताना चाहता हूं कि पहले हर साल पेपर लीक होते थे। जब हमारे क्षेत्र के युवा तैयारी करके परीक्षा देने जाते थे तो हर साल पेपर लीक हो जाते थे। पिछले एक साल में एक भी परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ।

मेडिकल में आपने क्या किया, मेडिकल में हमारी वसुंधरा जी ने भामाशाह कार्ड चलाया था, उसका नाम बदल कर आपने चिरंजीवी कार्ड कर दिया। सम्माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड चलाया था, उस आयुष्मान कार्ड को आपने राजस्थान में पांच साल में लागू नहीं किया। अगर पांच साल पहले वह आयुष्मान कार्ड लागू हो जाता तो राजस्थान की जनता आस-पास के क्षेत्र में इलाज करा सकती थी। मेरा क्षेत्र इंदौर और गुजरात से लगा हुआ है। हमारे क्षेत्र के लोग इलाज कराने के लिये वहां जाते हैं तो उनको पहले वहां आयुष्मान कार्ड का फायदा नहीं मिलता था, आज आयुष्मान कार्ड का फायदा मिल रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हमारे क्षेत्र की जनता को, गरीब युवाओं को इसका बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। हमारी सरकार ने मेडिकल में कई प्रकार की सुविधाएं दी हैं। हमारी सरकार ने 5 नये मेडिकल कॉलेज खोले हैं। इससे एमबीबीएस की 850 सीटें बढ़ी हैं और 43 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया है, उसमें मेरा क्षेत्र भी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र डग में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है, यह सम्माननीय भजन लाल जी सरकार की देन है। इस सरकार में कोई भेदभाव नहीं किया गया, सभी विधायकों को 5-5 आंगनबाडि़यां, 5-5 पशु चिकित्सालय, 5-5 ट्यूबवैल, 10-10 हैंड पम्प, इससे पहले 20-20 हैंड पम्प, 5-5 करोड़ की मिसिंग लिंक, नोन पेचेबल सड़कें दी गई हैं। हमारी सरकार ने जो पहले साल में बजट दिया है ....(व्यवधान).... हर क्षेत्र में ट्यूबवैल खुदे हैं, हर क्षेत्र में हैंड पम्प लगे हैं और आने वाले समय में माननीय मंत्री जी को आप फिर तैयार कर के दो, अभी इस बजट के बाद आपको फिर मिलने वाला है।

शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल खुले हैं। ....(व्यवधान)....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री कालूराम (डग): इतना दिया है कि कभी नहीं मिल सकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भवानी मंडी में राजगढ़ डैम से 24 करोड़ रुपये की परियोजना लागू की गई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में महाविद्यालय खोला गया। मेरे क्षेत्र में डैम की डीपीआर तैयार हो चुकी

है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उस डीपीआर की इस बजट में घोषणा करें, ताकि इस क्षेत्र की जनता को उससे फायदा मिल सके। हमारे क्षेत्र में जो विकास की गंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बहाई है, वह निरंतर बहती रहे। हमारी सरकार ने 32,254 पदों पर नियुक्तियां दी हैं और 91,800 पदों की भर्तियां प्रक्रियाधीन है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को 6000 रुपये मिलते थे। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उसमें 2000 रुपये बढ़ाये हैं और आने वाले समय में 2000 रुपये और बढ़ेंगे, इस प्रकार से 6000 का 12000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को मिलेगा, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आपने एक रुपया बढ़ाने का काम नहीं किया। मुख्यमंत्री सम्मान निधि के नाम से सभी किसानों के खातों में दो-दो हजार रुपये जा रहे हैं। पिछली सरकार ने एमएसपी तक नहीं बढ़ाई। हमारी सरकार ने सोयाबीन, चना, मसूर, गेहूं में एमएसपी बढ़ाकर किसानों को कई प्रकार के फायदे दिये हैं। हमारी सरकार राजस्थान में इस-इस प्रकार से काम कर रही है।

श्री सभापति: श्री दीन दयाल।

श्री कालूराम (डग): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दीन दयाल (दौसा): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी और दौसा की देव तुल्य जनता को धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहां विधान सभा में चुनकर भेजा। सभापति महोदय, मैं दौसा विधान सभा क्षेत्र से अभी उप चुनाव में जीत कर आया हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कई विषयों पर जिक्र हुआ, पानी, बिजली, शिक्षा। कुछ बिन्दुओं पर मैं सदन में बात रखना चाहूंगा। हमारे यहां सबसे बड़ी पानी की समस्या है, जिसके लिये गत सरकार में सम्माननीय दौसा सांसद जो आपके यहां मंत्री थे, उनके प्रयासों से ईसरदा प्रोजेक्ट पूरे जिले के लिये स्वीकृत हुआ।

श्रीमान, दौसा शहर में करीब 75 परसेंट पाइप लाइनों का कार्य पूरा हो चुका है, करीब 25 परसेंट कार्य बाकी है। शहर में पाइप लाइनों से सड़कें इतनी क्षतिग्रस्त हो गई हैं कि शहर बदसूरत हो गया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करें, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में टूटी हुई रोडों को सही करने का टेंडर भी हुआ है।

Msk/rtm/06.02.25/2020/4j

उसके साथ ही मैं निवेदन करता हूं कि गांवों में भी जल्द से जल्द इस कार्य के लिए टेण्डर स्वीकृत किया जाये। माननीय सभापति महोदय, मेरा आप लोगों से एक और निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुण्डल ऐसा कस्बा है, जो शहर से 20 किलोमीटर की दूरी है। मेरा निवेदन है कि वहां पर बिजली विभाग का ए.ईएन. कार्यालय खोला जाये। उस क्षेत्र में हमारी कन्याओं/बच्चियों को दौसा आना पड़ता है, मैं एक कन्या महाविद्यालय की मांग करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में नांगल राजावतान, लवाण, सैंथल, कुण्डल बड़े कस्बे हैं। इनके अन्दर मेरा आप लोगों से निवेदन है कि गोशालाओं को खोलने की इजाजत दी जाये। मैं

मानता हूं कि दौसा विधान सभा क्षेत्र के साथ-साथ आप सभी सम्माननीय विधायकों की समस्या होगी, वह चरागाहों में बहुत से लोग निवास कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले आबादी भूमि का विस्तार कम था। धीरे-धीरे परिवार बढ़े, धीरे-धीरे जनसंख्या बढ़ी, वे लोग धीरे-धीरे मकानों को आगे बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे और कई जगह वे चरागाह में स्थापित हो गये। मैं मानता हूं कि कोई सैकड़ों सालों से है, कोई 50 साल से है।

मैं सदन के माध्यम से निवेदन करता हूं कि आप लोग ऐसा कोई प्रस्ताव लायें, ताकि वह आबादी भूमि में कंवर्ट हो जाये, जिससे वे बेघर नहीं हो। कई बार आरटीआई के तहत शिकायत हो जाती है तो कई बार उनको बेघर होना पड़ता है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप सरकार के माध्यम से ऐसा कोई प्रस्ताव लायें, ताकि वे घर उजड़ने से बचें।

उसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बाण गंगा, ढूंढ नदी जैसी बहुत-सी नदियां बहती हैं, उनके अतिक्रमण तो है ही, उसके अलावा अर्से से कई लोगों ने बहाव क्षेत्र के आसपास श्मशान घाट बना दिये हैं, अब उनके लिए कोई कार्य स्वीकृत नहीं हो सकते। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग ऐसा कोई प्रस्ताव लायें, ताकि उनका आवंटन हो और उनमें विकास कार्य किया जाये। महोदय, आप लोगों से निवेदन है कि मेरे यहां पर पपलाज माता और नई का नाथ धाम, दो बड़े धाम हैं, मैं मानता हूं कि जहां पर लाखों की संख्या श्रृद्धालु आते हैं। पपलाज माता से नांगल राजावतान, नांगल राजावतान से लवाण होते हुए, नई का नाथ धाम तक एक स्टेट हाई-वे 78 की मांग करता हूं।

श्रीमान जी, विधान सभा क्षेत्र के अन्दर स्कूलों में कई जगह तो बहुत ज्यादा शिक्षक हैं और कई जगह बहुत कम शिक्षक हैं। जहां बारहवीं की क्लास हैं, वहां आठ-दस में ही काम हो रहा है और कई जगह बहुत ज्यादा हैं। मैं मानता हूं कि आप लोगों को इसमें भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। श्रीमान जी, हमारे यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या है। विधान सभा क्षेत्र के कई गांवों के अन्दर बन्दरों का बहुत बड़ा आतंक है। ग्राम पंचायतों के पास ऐसी कोई निजी आय नहीं है, ताकि वह बन्दरों को पकड़ा सके। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि पंचायतों को ऐसे निर्देशित करे, ताकि कोई भी मद से उनको पकड़ा जाये।

श्रीमान जी, एक बहुत बड़ा वाकया है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। लवाण कस्बा है, पंचायत समिति लवाण है, जो काफी अर्से से है। उसके अन्दर अभी ट्रांसफरों का बहुत बड़ा वाकया हुआ, जो मैं बताता हूं। वहां पर अभी मेरी वाइफ प्रधान है। इन ट्रांसफरों के अन्दर एक ऐसा वाकया हुआ है कि वहां पर किसी को वी.डी.ओ. का चार्ज दे रखा था, उसको भी वहां से हटा दिया गया। मेरे वहां से सात सेक्रेटरी, सात ग्राम विकास अधिकारी, 14 ग्राम पंचायतों में से 7 ग्राम विकास अधिकारी दौसा से रवाना कर दिये। कोई बात नहीं, आपका काम है, ट्रांसफर करना। आप करें, लेकिन मैं यह मानता हूं कि कम से कम उन पर लगा तो दें। आपके यहां जयपुर से भेज दें, उनको खाली तो मत रखो।

श्रीमान जी, एक निवेदन और है। अभी भांकर जी यहां पर बात कर रहे थे, जातिगत

ट्रांसफरों की। मैं आपको बता दूं, दौसा के अन्दर अभी बहुत से ऐसे ट्रांसफर हुए हैं। हमारे एक डीईओ, सीताराम शर्मा जी थे, जो 15 दिन पहले ही जॉइन हुए थे, मैं यह मानता हूं कि 10-15 दिन बाद ही उनको यहां से रवाना कर दिया। उसके अलावा मेरे पास एक बहुत बड़ा विषय है, जो मैं आपको बता दूं। एक ऐसी लिस्ट है, जो जातिगत बात करते हैं, यह बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र की है। जिसके अन्दर आठ ट्रांसफर हुए हैं, आठों के आठों गुर्जर समाज से हैं।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): सारी पोस्टिंग ही उनकी है।...(व्यवधान)...

श्री दीन दयाल (दौसा): टांकड़ा जी, आप बैठे हो, सुनो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): ये टारगेटली हैं। आठ के आठ आदमी एक लाइन से।...(व्यवधान)...

श्री दीन दयाल (दौसा): ये देखो, आठ के आठ। यह जातिगत द्वेषता है। मेरे पास लैटर है।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): जाने वाले कितने आदमी हैं। आपने जाने वालों की लिस्ट देखी तो जाने वाले थे ही वो ही। जो 25 की लिस्ट थी, जाने वाले आठ थे तो समाज के आठ लोग गये हैं। यह पुरानी का सरकार ...(व्यवधान)...

श्री दीन दयाल (दौसा): महेन्द्र सिंह जी गुर्जर, राकेश गुर्जर, अजय सिंह गुर्जर, कमल गुर्जर, मनीष गुर्जर, सीमाबाई गुर्जर, सोनल गुर्जर, सीतादेवी गुर्जर.. ये सारे नगर पालिका से हुए हैं। इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो। द्वेषतापूर्वक किसी जाति को आप टारगेट नहीं बना सकते हो। ट्रांसफर, पोस्टिंग करना आपका काम है। ट्रांसफर, पोस्टिंग खूब करो, लेकिन किसी समाज को आप जातिगत टारगेट नहीं कर सकते हो। टांकड़ा जी, आप बैठो हो ना आप इन्हीं की बदौलत बैठे हो, मेरे को सब कुछ पता है।

श्री सभापति: श्री लादू लाल पितलिया।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): खजूरिया श्याम की जय, टांटगढ़ वाले काला गौरा गौरा भैरूनाथ भगवान की जय। माननीय सभापति महोदय, मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति जी, जब से हमारी भाजपा की सरकार राजस्थान में बनी है। माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के कुशल ने नेतृत्व में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारी सरकार को बने एक साल हो गया है। उसमें हमारे संकल्प पत्र की लगभग 70 प्रतिशत घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। राजस्थान के जन कल्याण के लिए जो उपलब्धियां हमारी सरकार ने हासिल कीं, मैं आपके समक्ष बताना चाहता हूं कि गरीब परिवारों के लिए साढ़े चार सौ रुपये में घरेलू गैस सिलेण्डर सरकार द्वारा दिया जा रहा है और पेट्रोल-डीजल में भी 2 प्रतिशत रेट कम की है। पीएम किसान योजना में 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 हजार रुपये किया गया है, वह हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। शेखावाटी पेयजल समस्या के लिए यमुना जल समझौता सरकार के द्वारा किया गया है। पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों के लिए ईआरसीपी

समझौता किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी राजस्थान की जनता के लिए ईआरसीपी की योजना के माध्यम से राजस्थान को समृद्ध बनाने का विजन हमारी सरकार ने पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में शुरूकिया था।

mdp/rtm/06.02.2025/20:30/4k

लेकिन दुर्भाग्यवश विगत सरकार के समय राजनीतिक लाभ के कारण जनता को गुमराह किया गया था तथा इस ईआरसीपी की योजना को अटकाया गया था। जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आयी, हमारे भागीरथ माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा ने सबसे पहले इसे राम जल सेतु लिंक परियोजना के रूप में धरातल पर क्रियान्वित करने की दिशा में नींव रखी है। पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया तथा एंटी गैंगस्टर टॉस्क फोर्स का भी गठन किया गया है। मीसाबंदियों के लिए पेंशन की शुरूआत की गयी है। प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना की भी राशि सरकार द्वारा बढ़ाई गई है। लखपती दीदी योजना की भी पहल की गई है। ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रिकॉर्ड एम.ओ.यू. किया है। पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया, जो कि पहले की सरकारों से ज्यादा सफल रहा। राइजिंग समिट में 35 लाख करोड़ के एम.ओ.यू. हुए, जो जल्द ही धरातल पर उतरते हुए दिखाई देंगे।

प्रवासी राजस्थानियों के सम्मान के लिए 'प्रवासी दिवस' मनाने की भी घोषणा की गयी है। युवाओं के रोजगार को प्राथमिकता पर रखते हुए दो साल का परीक्षा कलेण्डर जारी किया गया है। हमारे माननीय मंत्री महोदय के द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी के जन्म पर एक लाख रुपये की राशि देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। राजस्थान को आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए एक साथ दस पॉलिसी को मंजूरी दी गयी है। विभिन्न विभागों में अनेकों अभ्यर्थियों को नियमित नियुक्ति दी गयी है। पहले साल में ही 1 लाख 24 हजार से अधिक नौकरियां राजस्थान के युवाओं को दी गयी है।

(समय: बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

हमारी सरकार ने अपने पहले साल में ही जयपुर में शिखर सम्मेलन किया और 34 लाख करोड़ के समझौतों पर हस्ताक्षर किये, जिससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था को बढ़ाकर 350 अरब डालर करने के सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने की अनुगामी पहल की गयी है। मुख्य मंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की, जिसमें दुधारू गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंटनी का बीमा किया जाता है। कोपरेटिव सोसायटी के माध्यम से गौ पालक कार्ड योजना शुरू की, जिसमें पशुपालकों को पशु खरीदने व पशुओं के कार्य हेतु एक लाख रुपये का बीमा बिना ब्याज लोन दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट 2024 में मेरी विधान सभा सहाड़ा को भी 13 महत्वपूर्ण विकास कार्यों की सौगातें प्रदान कीं, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की कुछ बड़ी समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान में सारे विधायकों को 5 करोड़ रुपया दिया जाता है विकास के लिए। मेरा ही एक साल का बजट 5 करोड़ रुपये का सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में है। मैं भी विकास का काम करता हूं। जितनी सरकार की योजनाएं चलती हैं, अब मेरी योजनाएं आज आपको बताता हूं।

सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में गौ माता किधर भी बीमार हो जाती है तो 15 साल से मैं उसको हॉस्पिटल पर ले जाकर उसका इलाज कराता हूं। 2008 से मेरी योजना चल रही है और नंबर दो गौ माता को पानी पीने के लिए, हमारे मेवाड़ में पो बोलते हैं, कोई ठेली बोलते हैं। गौ माता को पानी पीने के लिए मेरे सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, नोहरे के बाहर, खेतों के बाहर, बाड़ों के बाहर, जो भी किसान भाई फोन करता है उसके गांव में निशुल्क मेरे ट्रेक्टर द्वारा मैं पो भिजवाने का काम लगभग 15 सालों से कर रहा हूं। सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में गौ माता, पूरी विधान सभा क्षेत्र में गौ माता को निशुल्क खाखला पूरे गांव-गांव के अन्दर मेरी तरफ से मैं भिजवा रहा हूं 15 सालों से ताकि मेरी गौ माता भूखी नहीं रहें। बेंच की जो योजना है, टेबल और कुर्सी बैठने की, वह भी मेरी योजना चल रही है। पंखे, जो पूरी सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में पंखे की योजना भी चल रही है। सरकारी स्कूल या प्राइवेट, भगवान के कोई से भी धार्मिक स्थान, उधर सभी जगह मेरे पंखे की योजना चल रही है और मेरे पंखे का कलर है भगवा। एक ही कलर है भगवा और सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में आप जब भी कोई भी पधारेंगे तो भगवा कलर की मेरी निशानी जरूर मिलेगी, गांव-गांव हर किलोमीटर पर।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय सदस्य, समय हो गया है।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): एक मिनट। और भी बहुत योजनाएं हैं। पूरी विधान सभा क्षेत्र में, पूरी स्कूलों में नि:शुल्क नोट बुक की योजना भी चल रही है मेरी। मैं नि:शुल्क राशन भी वितरण किया हूं। डेली मेरी गाडी के अन्दर राशन रहता है। मैं गरीब किसान भाईयों के उधर भी जाता हूं तो खाली नहीं जाता हूं। पानी की टंकी और स्टेंड, जो पूरी विधान सभा क्षेत्र में, हर धार्मिक स्थान, हर स्कूल, चौराहे, बस स्टेंड, सभी पर मिलेगी मेरी पानी की टंकी। कोई भी साथी, जनता मेरी विधान सभा में गुजरेगा, अगर उनको दिन में लगे कि मेरे को पानी पीना है तो तैयार मिलेगा, हर जगह पानी की टंकी मिलेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकरलाल डेचा।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बोलो जय-जय श्री राम। गौ माता की जय।

श्री शंकरलाल डेचा (सागवाड़ा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

साथ ही मेरे सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र की जनता की ओर से भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं एक पंक्ति से, मोदी जी की एक कविता है, उससे चालू करूंगा-

यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है,
असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है,
तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो,
यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है,
कुछ ऐसा नहीं जो कर न सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा न सको,
तुम उठ जाओ, तुम जुट जाओ, सामर्थ्य को अपने पहचानों,
कर्तव्य को अपने सब जानो, भारत का यह अनमोल समय है,
यही समय है, सही समय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता ने हमारी जनकल्याणकारी भावना पर आस्था रखकर भ्रष्टाचार मुक्त शासन स्थापित करने तथा राजस्थान को अग्रणी विकसित राज्य बनाने के संकल्प में विश्वास जताते हुए हमें जनादेश प्रदान किया है। एक साल के कार्यकाल में हमारी सरकार ने सुराज संकल्प की सिद्धि के लिए पूरे मनोयोग से कार्य किया। विकसित एवं उन्नत राजस्थान की संकल्पना को मूर्त रूप देने में सफल हुए। राज्य को अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास व सबका कल्याण की सोच के साथ अथक परिश्रम कर अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का सतत प्रयास किया जा रहा है।

Ans/rtm 20.40 4l 06.02.2025

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार की अदूरदर्शी सोच तथा गलत नीतियों के फलस्वरूप राजस्थान को विरासत में बहुत बड़ा कर्ज भार मिला था। गत सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कुल ऋण भार लगभग दुगना होकर वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के अनुसार 5 लाख 19 हजार 781 करोड़ रुपये हो गया था और राज्य का डेबिट जीएसडीपी अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों में, पंजाब के बाद अधिक था। इसके साथ ही, वर्ष 2023-24 के अन्त में राज्य में प्रति व्यक्ति ऋण, वर्ष 2017-18 में 36 हजार 880 से बढ़कर 70 हजार 800 रुपये हो गया, जो कि पिछली सरकार की अदूरदर्शी सोच का परीणाम था।

पूर्ववर्ती काग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश जहाँ एक ओर विपरीत वित्तीय स्थिति में आ गया था, वहीं दूसरी ओर गलत नीतियों, भ्रष्टाचार, लचर कानून व्यवस्था, कुशासन एवं तुष्टिकरण के कारण प्रदेश के विकास की गति भी मंद हो गई थी। इन चुनौती पूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के सहयोग के साथ-साथ, हमारी सरकार की ठोस कार्य योजना, सुशासन एवं कठिन परिश्रम से प्रदेश को सतत विकास के मार्ग पर ले जाने का प्रयास किया ।

हमारी सरकार आधारभूत संरचना के विकास, दूर-दराज के क्षेत्रों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों

में चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार आदि सुविधाओं की पहुँच तथा वंचित वर्गों हेतु अतिरिक्त सहायता, सामाजिक सुरक्षा पर समान रूप से ध्यान देकर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य कर रही है।

पिछली काग्रेस सरकार के सम्पूर्ण कार्यकाल के दौरान कुप्रबंधन एवं भ्रष्टाचार के चलते राज्य में लगातार बिजली संकट की स्थिति बनी रही और इससे वागड भी अछूता नही था, परन्तु माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से सागवाडा मे 220 किलो वाट का नया जीएसएस स्थापित हुआ एवं विद्युत की समस्या का समाधान हुआ इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।

साथ ही प्रदेश की जनता में भी यह विदित है कि गत काग्रेस सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ना सिर्फ भारी भ्रष्टाचार हुआ एवं गुणवत्ता सम्बन्धी भी बहुत अधिक शिकायतें प्राप्त हुई, बल्कि परियोजना के इम्प्लीमेंटशन की गति भी अत्यधिक धीमी थी, उसका उदाहरण है कि पिछले 4 वर्षो से सागवाडा विधान सभा में 353 गांव 212 गाँवों की योजना का पूर्ववर्ती काँग्रेस सरकार के कार्यकाल मे प्रारम्भ ही नहीं की ओर सागवाडा की जनता को मोदी जी का सपना था की शुद्ध जल मिले, उससे महरूम रखा और उन्होंने इस परियोजना को उदयपुर के प्रोजेक्ट मे डाल दिया जो की सागवाडा की जनता के साथ कुठाराघात किया। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है, भजनलाल जी की सरकार बनी, तब से इस योजना में गति मिली एवं हर घर को नल से जल उपलब्ध होने वाला है।

माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री जी की पहल पर अब हमने केन्द्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ईआरसीपी परियोजना रिवर लिकिंग प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया है एवं पिछले समय उसका शिलान्यास कार्य भी हुआ। राज्य एवं केन्द्र सरकार के मध्य एमओयू को साइन कर कार्य प्रारम्भ करने का मार्ग प्रशस्त किया है। सदन के माध्यम से मैं ईआरसीपी परियोजना को त्वरित गति से इम्प्लीमेंट करने की दिशा में, इस महत्वपूर्ण कदम को उठाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, माननीय केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, विपक्ष बार-बार आरोप लगाता है कि यह सरकार पर्ची वाली सरकार है, पर मैं कहना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पेपर लीक वाली सरकार थी, भ्रष्टाचार वाली सरकार थी, होटलों मे समय बिताने वाली सरकार थी। राजस्थान के इतिहास में पहली बार एक नारा बुलन्द हुआ, रीट का पेपर कहां मिलेगा, रीट का पेपर कहां मिलेगा, नाथी तेरे बाडे में, नाथी तेरे बाडे में। यह स्थिति हमारे युवाओं के साथ की है। मैं माननीय हमारे मुख्य मंत्री भजनलाल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो काम किया है, बहुत ही अच्छा काम चल रहा है, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है ...(व्यवधान)...

भर्ती परीक्षायें समयबद्ध आयोजित कराने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आदि का वार्षिक भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। कौनसी परीक्षा कब आयोजित होगी एवं कब रिजल्ट आयेगा उसका कैलेंडर जारी कर समयबद्ध परीक्षा एवं

कार्यक्रम हो रहे। जिससे परीक्षार्थीयो मे नई उम्मीद जगी है।

भजनलाल जी की सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र-छात्राएं विद्यालय में हीन भावना से ग्रस्त न हो तथा उन्हें भी शिक्षा हेतु आवश्यक स्कूल बैग, किताबें तथा यूनिफॉर्म उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को कक्षा एक से आठवीं तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा नौ से बारहवीं तक की छात्राओं को प्रति वर्ष विद्यार्थी एक हजार रुपये की सहायता प्रदान की है, जिससे बच्चों में निजी शिक्षण संस्था की तरह वातावरण नहीं बने।

श्री अध्यक्षः यह आईपैड है, पेपर रखने वाला स्टेण्ड नहीं है। कई लोगों ने इसको स्टेण्ड बना लिया है।

श्री शंकरलाल डेचा (सागवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय पिछली सरकार मे वागड की उपेक्षा हुई थी एवं वागड मे कोई विकास नहीं हुआ था, जिससे वागड की जनता में काफी रोष था, परन्तु हमारी सरकार के पिछले बजट मे वागड को विशेष सौगात दी, जिससे वागड की जनता में एक नई उम्मीद जगी है। काग्रेस सरकार ने शिक्षा स्वास्थ्य एवं पानी की समस्या को बंटाधार कर दिया था। इसको लेकर पिछले बजट मे माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं वित्त मंत्री महोदया ने उस घाव पर मरहम लगाने का प्रयास किया।

श्री अध्यक्षः श्री गोपीचंद मीणा।

श्री शंकरलाल डेचा (सागवाड़ा): बजट मे भी वागड की जनता को हमारी सरकार से काफी अपेक्षाए है। वागड का युवा इस उम्मीद में है कि अबकी बार वागड को इससे भी अच्छा फायदा होने वाला। इसके साथ ही जय-जय राजस्थान।

श्री अध्यक्षः विराजिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है, आज की कार्यसूची के अंतिम वक्ता है गोपीचंद जी जहाजपुर से माननीय विधायक। इसके पश्चात स्वादिष्ट भोजन कक्ष क्रमांक 115 में आपका इंतजार कर रहा है। सबके लिए।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम महोदय के अभिभाषण में केन्द्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार की सभी विभागीय योजनाओं, स्कीम्स, नवाचारों का माननीय प्रधान मंत्री जी नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी भजनलाल जी के साथ हमारे मंत्री परिषद ने लोक महत्व एवं राज्य हित में अविस्मरणीय सफलतम परिणाम के साथ, एक वर्ष के कार्यकाल में अर्जित उपलब्धियों का, हम सभी सदस्यों के ज्ञान अर्जन हेतु संक्षिप्त एवं सुन्दर प्रस्तुतीकरण है। साथ ही विकसित भारत, विकसित राजस्थान की परिकल्पना को पूरा किया जाता है। माननीय मुख्य मंत्री जी के आर्शिवाद से मेरे विधान सभा

क्षेत्र जहाजपुर में एक वर्ष के कार्यकाल में सौग़ातें दी गई है, निम्न सौग़ातें हैं।

हमारे जहाजपुर में जनजाति समाज के उत्थान के लिए बालिका छात्रावास व बालक छात्रावास दिया। हमारे जहाजपुर में बालिकाओं की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कन्या महाविद्यालय खोला गया। कोटड़ी में महाविद्यालय खोला गया। जहाजपुर में पीएचसी अम्बरगढ़ खोला गया। जहाजपुर में सीएचसी को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया गया। जहाजपुर में सब्जी मण्डी व फली मण्डी की घोषणा की गई, जमीन आवंटन हो गई और कार्य भी शुरू हो गया है। जहाजपुर और कोटड़ी में खेल स्टेडियम दिये गये। युवाओं को रोजगार के लिए रीको पार्क स्वीकृत किया गया है। क्षतिग्रस्त सड़कें थी, 100 करोड़ की लागत की नवीन सड़कें दी, जिसके कार्यादेश जारी हो गए हैं, कार्य शुरू हो गया। माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा शिलान्यास कर दिया गया। हमारे जहाजपुर में अमृत मिशन-2, पांच साल तक भारत सरकार की राशि आई उसको पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा जानबूझकर रोका गया, माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर अब उसकी स्वीकृति जारी हो गई है।

VPS-RTM-06.02.2025-20.50-4m

33 के.वी.ग्रिड का शिलान्यास कर दिया गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का और मेरे जहाजपुर, मेवाड़, भीलवाड़ा और राजस्थान प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में हमारे यहां पर ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और इस एक वर्ष के कार्यकाल में वह जितनी भी बजट घोषणा की थी, वे कार्य शुरू हो गये हैं। एक वर्ष के कार्यकाल में हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी घोषणा पत्र था उसके 55 प्रतिशत लक्ष्य हमने पूरे कर लिये हैं। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्रीजी के नेतृत्व में जो प्रधान मंत्री आवास योजना जो गरीबों के मकान के लिए दी गयी है उसका पोर्टल भी चालू कर दिया गया है। जो चुनाव में वादा किया था, वह पूरा हो गया है। खाद्य सुरक्षा पोर्टल बंद था उसको भी हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में उसका भी शुभारंभ कर दिया गया है। एक वर्ष में श्री भजन लालजी की सरकार ने हमारी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, श्रमिकों सहित हर वर्ग के लिए उनके जीवन स्तर में बहुत अच्छा सुधार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य भाटीजी, इधर से नहीं जाते हैं।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय मुख्य मंत्रीजी के विशेष प्रयास से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट के सफल आयोजन ने राजस्थान प्रदेश को विश्व के औद्योगिक पटल पर अंकित कर दिया है। वर्तमान एवं आने वाले वित्तीय वर्षों में प्रदेश की जी.डी.पी. में वृद्धि होना निश्चित है। प्रतिभा एवं कौशल से परिपूर्ण प्रदेश के ऊर्जावान युवाओं को रोजगार के नये अवसर मिलने वाले हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जहाजपुर क्षेत्र में पानी की समस्या है, उस पानी की समस्या के लिए विशेष मेरा आग्रह है और पानी की

समस्या को हमारे मुख्य मंत्रीजी ने समझा है, हमारी सरकार ने समझा है। भाजपा सरकार ने पानी के महत्व को समझा है और अपने भागीरथी प्रयासों से माननीय प्रधान मंत्रीजी एवं मुख्य मंत्रीजी ने ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट का नाम बदल कर राम जल सेतु लिंक परियोजना रखा गया और एक स्वर्णिम युग का शिलान्यास कर दिया है इस योजना को लाकर। विगत कांग्रेस सरकार ने अपने आपसी विवाद में उलझे होने के कारण इस योजना को डम्प कर दिया था, इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। योजना को आगे नहीं बढ़ने दिया। विगत कांग्रेस सरकार की मैं भर्त्सना करता हूं एवं हमारी सरकार ने इस परियोजना का नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना रखकर योजना को मजबूती से प्रदान किया है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भीलवाड़ा और मेवाड़ में ऐतिहासिक काम किये हैं जो एक वर्ष में ही धरातल पर उतर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो राम जल सेतु लिंक परियोजना है, भीलवाड़ा जिले को भी मैं इससे जोड़ने की माननीय मुख्य मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा में पानी की समस्या है तो इस योजना को भीलवाड़ा से भी जोड़ा जाये। ब्राह्मणी नदी को या दूसरी नदी को भी जोड़ा जाये चम्बल नदी से या माही नदी से जोड़ा जाये, भीलवाड़ा को गम्भीरी बांध से होते हुए जोड़ा जाये ताकि हमारे वहां पर भी जल समस्या का समाधान हो सके।

माननीय प्रधान मंत्रीजी की सोच सदैव बड़ी ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी रही है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने की विशाल योजना का लाभ जन-जन तक पहुंचाने की बजाए विगत सरकार के जन स्वास्थ्य मंत्री ही नहीं अपितु पूरी सरकार, भ्रष्ट सरकार, कांग्रेस सरकार ने, अभियंताओं, अधिकारियों एवं संवेदकों के मार्फत करोड़ों रुपये के आर्थिक घोटाले किये, भ्रष्टाचार किया और योजना को कचरे में डाल करके रखा, जानबूझकर राजनीतिक दुर्भावना से काम नहीं होने दिया और हमारी सरकार के आते ही मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में हमारे आदरणीय मंत्रीजी कन्हैयालाल जी चौधरी के नेतृत्व में एक वर्ष में ही युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए जल जीवन मिशन योजना के लम्बित कार्य को नये आयाम देने का काम किया है। मैं हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः मैंने कहा कि यह स्टैंड नहीं है। माननीय सदस्य, यह स्टैंड नहीं है। यह आईपैड है। उस पर आप पेपर रखकर पढ़ रहे हो। या तो आप आईपैड को खोलकर पढ़ें। स्टैंड बनाएंगे तो यह टूट जायेगा। दबाव डालेंगे तो यह टूट जायेगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): साहब, यह टू इन वन है।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सरकार तो कोयले की कमी का रोना रोती रही और नित्य यह अखबारों में आता रहा है कि प्रदेश की विद्युत उत्पादन इकाइयों में सात दिन, पांच दिन या दो दिन का ही कोयला शेष रहा है। विद्युत उत्पादन इकाइयों में कोयले की कमी बताकर बाहर से अरबों रुपये की महंगी बिजली खरीद कर सरकार ने बिजली कम्पनियों के घाटे को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया और बहुत बड़ा आर्थिक घोटला करते हुए भ्रष्टाचार किया कांग्रेस सरकार ने जो जांच का विषय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार की जांच करने की मांग मैं सदन के माध्यम से करता हूं। हमारी सरकार ने आते ही प्रदेश की विद्युत उत्पादन इकाइयों के लिए कोल उत्पादन राज्यों से, माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लालजी ने सौहार्दपूर्ण सम्पर्क स्थापित किया। विगत एक वर्ष से आज तक कोल की कमी बाबत कोई कोई खबर अख़बार में नहीं छपी है। आज प्रदेश की विद्युत उत्पादन इकाइयां अपनी निर्धारित विद्युत उत्पादन क्षमता के अनुरूप निर्बाध रूप से संचालित हो रही हैं। पी.एम. कुसुम योजना में भी राजस्थान प्रदेश नम्बर वन पर रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने पांच साल तक पंचायतों के विकास को रोका है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भीलवाड़ा में राजनीतिक दुर्भावना से रोका और चुनाव के समय जाते-जाते उन्होंने कितनी ही घोषणाएं कर दीं। मोबाइल बांटने की घोषणा कर दी, पुलिया की घोषणा कर दी, सड़कों की घोषणा कर दी और सरपंचों को बुलाकर आचार-संहिता के समय में उनको बुलाकर उनके सिर में दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह भाटे रख दिये कि ये ले जाओ और गांव में ले जाकर चिपका देना और काम एक पैसे का, एक फूटी कौड़ी का नहीं दिया है। फर्जी बाड़ा तरीके से उन्होंने उसका लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता ने भी भीलवाड़ा जिले में सात की सात सीटें भाजपा के पक्ष में दी और उनके सिर में भाटे चिपका दिया जनता ने भी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी का राजस्थान प्रदेश के सारे सरपंचों ने आकर धन्यवाद और आभार प्रकट किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली, पेपर आउट, नकल, फर्जी डिग्री प्रकरणों को हमारी सरकार ने गंभीरता से लेकर पूरा मजबूत एक्शन के साथ दोषियों को सलाख़ों के पीछे डाल दिया, उनकी सम्पत्ति कुर्क कर ली गयी, अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिये गये, एस.आई.टी. का गठन किया गया। कठोर नियमों के तहत पेपर आउट माफियाओं और फर्जी डिग्री माफियाओं में भय पैदा हुआ है और प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं में पात्र युवा वर्ग में सरकार के प्रति विश्वास कायम हो चुका है। विगत एक वर्ष में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन सरकार द्वारा निष्पक्ष रूप से किया जा रहा है। हमारी सरकार ने एक वर्ष के दौरान 60 हजार नियुक्तियां दी हैं और आने वाले समय में लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय भजन लालजी ने नया कलैंडर जारी किया है, उसमें भी हमने जो चुनावों में वादा किया, उससे कई गुणा अधिक नौकरियां, भर्ती करेंगे, हमारी सरकार की ऐसी योजना है। हर वर्ग संतुष्ट है।

हमारे जनजाति समुदाय के लिए माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने 1000 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है और जनहित के कल्याण का काम किया है। बहुत सारा ऐतिहासिक काम हुआ है, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश की आठ करोड़ जनता जन-जन माननीय मुख्य मंत्रीजी से, भाजपा सरकार से, मोदीजी से खुश है और आने वाले समय में यह हमेशा के लिए जिस तरह गुजरात में, मध्यप्रदेश में एक तरफ बैठते हैं, ऐसे ही इसी तरह आने वाले समय में राजस्थान में भी ये 25 साल तक विपक्ष में

बैठेंगे, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः सदन की कार्यवाही 07 फरवरी, 2025 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 20.57 बजे शुक्रवार, दिनांक 07 फरवरी 2025 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

....